नवम माला, खंड 8, अंक 1

मंगलवार, 7 अगस्त, 1990
16 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 7 अगस्त, 1990/16 श्रावण, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (1)	6	"निधम" के स्थान पर "निधन" पढ़िये।
	8	तारांकित प्रश्न संख्या के बाद "1 से 8" पढ़िये।
81	2	"प्रो० राम गणेश कपासे" के स्थान पर "प्रो० राम गणेश कापसे" पढ़िये।
82	16	"राजवीर सिंह" के स्थान पर "श्री राजवीर सिंह" पढ़िये।
114	8	"औवधो" के स्थान पर "औषधों" पढ़िये।
126	3	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतःस्थापित करिये।
137	नीचे से 3	"रसावन" के स्थान पर "रसायन" पढ़िये।
139	11	"संयंत्रो" के स्थान पर "संयंत्रों" पढ़िये।
173	नीचे से 3	"(क) और (क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
180	नीचे से 8	"श्री हरीश रावत" के स्थान पर "श्री हरीश रावत" पढ़िये।
185	नीचे से 5	"श्री तेज नाराण सिंह" के स्थान पर "श्री तेज नारायण सिंह" पढ़िये।
301	नीचे से 5	"श्री पी०एस०थामस" के स्थान पर "श्री पी०सी० थामस" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 1, मंगलवार, 7 अगस्त, 1990/16 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
नियम सम्बन्धी उल्लेख	1—5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5—18
*तारांकित प्रश्न संख्या :	1—3
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—201
तारांकित प्रश्न संख्या : 4 से 20	18—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 74 और 76 से 234	29—197
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	201—205
सभा पटल पर रखे गए पत्र	205—209
स्थगन प्रस्ताव	209—300
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता	
श्री वसन्त साठे	209
श्री भवानी शंकर होटा	224
श्री जसवन्त सिंह	227
श्री एच० के० एल० भगत	233
श्री अमल दत्त	239
श्री सूर्य नारायण यादव	244
श्री राजीव गांधी	245
श्री ए० अशोक राज	261
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	263
श्री भोगेन्द्र झा	266
प्रो० मधु दण्डवते	271

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य 300—301

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

रबड़ (संशोधन) विधेयक 301—302

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अरंगिल श्रीधरन 301

कार्य-मंत्रणा समिति 302

तेरहवां प्रतिवेदन

नौवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अकबर, श्री एम० जे० (किशनगंज)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री जे० पी० (चांदनी चौक)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अतिन्दर पाल सिंह, स० (पटियाला)

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर० (तिरुचेन्दूर)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अन्बारासु, श्री इरा (मद्रास मध्य)

अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)

अम्बरी, श्री लेइता (अरुणाचल पूर्व)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अर्गल, श्री छबिराम (मुरैना)

अली, श्रीमती सुभाषिनी (कानपुर)

अवेद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)

अहमद, श्री अनवार (उन्नाव)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी (नासिक)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (नई दिल्ली)

इ

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारदगा)

ए

एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचुर)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगिरि)

ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारिया, श्री गुलाब चन्द (उदयपुर)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमांडर, श्री मोहम्मद हसन (लद्दाख)

करेदुला, कुमारी कमलाची (भद्राचलम)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कापसे, प्रो० राम गणेश (ठाणे)

कावडे, डा० वेंकटेश (नान्देड़)

कामसन, प्रो० मिजिनलुंग (बाह्य मणिपुर)

कालका दास, श्री (करोलबाग)

कालवी, श्री कल्याण सिंह (बाड़मेर)

कालीमुथु, डा० के० (शिवकाशी)

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी (बुलढाना)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुंडू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह (गाजीपुर)

कृपाल सिंह, श्री (अमृतसर)

कृष्ण, श्री जी० (दमुक)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)

केसरी लाल, श्री (घाटमपुर)

कोंतल, श्री राम कृष्ण (अनकापल्ली)

कोटड़िया, श्री मनुभाई (अमरेली)
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश (अदूर)
कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (दुर्ग)

ख

खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल (राजगढ़)
खटीक, श्री शंकर लाल (सागर)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपर)
खां, हाजी जी० एम० (मुरादाबाद)
खान, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खालसा, श्रीमती बिमल कौर (रोपड़)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

ग

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गंगाधर, श्री एस० (हिन्दूपुर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)
गुडाविल्ली, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह (राजनंदगांव)
गोखले, श्री विद्याधर (मुम्बई उत्तर मध्य)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे (चिकमगलूर)

च

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कांति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्रीपेरुम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चांद राम, श्री (हरदोई)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई (पाटण)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चेन्नीथाला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियापुर)
चौधरी, श्री देसई (रोसेड़ा)
चौधरी, श्री राम प्रसाद (खलीलाबाद)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौहान, श्री प्रभातसिंह (कैरा)

ज

जग पाल सिंह, श्री (हरिद्वार)

जटिया, श्री सत्य नारायण (उज्जैन)

जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर० (तिरुनेलवेली)

जमुना, श्रीमती जे० (राजामुन्द्री)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जसवन्त सिंह, श्री (जोधपुर)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाटव, श्री थान सिंह (बयाना)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जामोद, श्री शशिभाई (भावनगर)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जावाली, डा० बासवराज (गुलबर्गा)

जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)

जू देव, श्री दिलीप सिंह (जांजगीर)

जेना, श्री श्रीकांत (कटक)

जोरावर राम, श्री (पलामाउ)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी० जे० (दमण और दीव)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

डोरे, श्री राजा अम्मान्ना नायक (रायचूर)

ढ

ढाकणे, श्री बबनराव (बीड)

त

तम्बि दुरै, डा० (करूर)

तस्लीमुद्दीन, श्री (पूर्णिया)

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास (खंभात)

तारीफ सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)

तिवारी, श्री जनार्दन (सीवान)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तोपदार, श्री तरित बरन (बैरकपुर)

त्यागी, श्री के० सी० (हापुड़)

थ

थापा, श्री नन्दू (सिक्किम)

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपुझा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरट, श्री एस० बी० (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दानवे, श्री पुंडलीक हरि (जालना)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहाण्डी)

दासगुप्त, डा० बिप्लब (कलकत्ता दक्षिण)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्री नरसिंहराव (भिण्ड)

देव बर्मन, श्री के० बी० के० (त्रिपुरा पूर्व)

देब, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवरायन, श्री बी० (रासिपुरम)

देवी लाल, श्री (सीकर)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
देशमुख, श्री सुधाम दत्तात्रेय (अमरावती)

ध

धनखड़, चौ० जगदीप (झुन्झुनू)
धवन, श्री हरमोहन (चंडीगढ़)
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार (हमीरपुर)
ध्यान सिंह, श्री (फिरोजपुर)

न

नन्दी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नाईक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नायक, श्री नकुल (फूलबनी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरि)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेगी, श्री सी० एम० (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (बिल्हौर)

प

पंडियन, श्री डी० (मद्रास उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल सिंह (कैराना)
पचेरवाल, श्री गोपाल (टोंक)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री अर्जुनभाई (बलसाड़)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री मदुभाई एम० (आनन्द)
पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह (सिवनी)
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई (साबरकंठा)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास (गोधरा)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
परास्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री बापूराव (जबलपुर)
पलनीसामी, श्री के० सी० (तिरुचेन्गोडे)
पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडे, श्री राजमंगल (देवरिया)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव (इरन्डोल)
पाटिल, श्री एस० टी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री बासवराज (कोप्पल)
पाटिल, श्री यशवन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणि, श्री रवि नारायण (देवगढ़)
पांडेय, प्रो० यदुनाथ (हजारीबाग)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पाल, श्री एम० एस० (नैनीताल)
पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलेप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पेरुमान, डा० पी० वल्लाल (चिदम्बरम)
पैंचालैया, श्री पी० (नेल्लौर)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री आर० एस० (नालन्दा)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम प्रदीप, श्री (नवादा)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उडीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फर्नान्डीज, श्री जौस (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय)
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंगाली सिंह, डा० (हाथरस)
बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्दावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसात)
बागा रेड्डी, श्री एम० (मेडक)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बानखेले, श्री किसनराव बापूराव (खेड)
बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाला, डा० असीम (नवद्वीप)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराज, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर (लुधियाणा)
बेंजामिन, श्री एस० (बपतला)
बेग, श्री आरिफ (बेतूल)
बेग, श्री युसुफ (मिर्जापुर)
बेगा राम, श्री (गंगानगर)
बेहेरा, श्री भजमन (ढेंकानाल)
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बोपचे, डा० खुशाल परसराम (भण्डारा)
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको (बड़ौदा)
ब्रह्म दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भजन लाल, श्री (फरीदाबाद)
भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भागेय गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)
भाटिया, श्री राम सेवक (जालौन)
भारतीय, श्री सन्तोष (फर्रुखाबाद)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)

भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव (सतारा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मक्कासर, श्री शोपत सिंह (बीकानेर)

मणवर, श्री बलवन्त (पोरबन्दर)

मनेम्मा, श्रीमती टी० (सिकन्दराबाद)

मन्टोष, श्री पाल आर० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मराडी, श्री साइमन (साहमन)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मलिक, श्री मंगाराज (भद्रक)

मलिक, श्री सत्यपाल (अलीगढ़)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार (दिल्ली सदर)

मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाडीक, श्री वामनराव (मुम्बई दक्षिण मध्य)

महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)

महेश्वर सिंह, श्री (मंडी)

माडे गौडा, श्री जी० (मांडया)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (तरनतारन)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

मायकर, श्री गोपालराव (पणजी)

मायावती, कुमारी (बिजनौर)

मारक, श्री सनफोर्ड (तुरा)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)

मिश्र, श्री बालगोपाल (बोलनगीर)

मिश्र, श्री राज मंगल (गोपालगंज)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, डा० किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री नन्दलाल (सलुम्बर)

मुंजारे, श्री कंकर (बालाघाट)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)

मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द (क्योंझर)

मुथिया, श्री आर० (पेरियाकुलम)

मुन्नन खां, श्री (बलरामपुर)

मुरलीधरण, श्री के० (कालीकट)

मुलतान सिंह, चौधरी (जलेसर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)

मेघवाल, श्री कैलाश (जालौर)

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)

मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र (मुम्बई उत्तर पूर्व)

मैथ्यू, श्री पलाई के० एम० (इदुक्की)

मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० पाकीर (मयीला दुतुराई)

मोहम्मद शफी, श्री (श्रीनगर)

य

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, डा० एस० पी० (सम्भल)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री जनार्दन (गोड्डा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)
यादव, श्री मित्रसेन (फैज़ाबाद)
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि (मधेपुरा)
यादव, श्री राम कृष्ण (आज़मगढ़)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री रामजीलाल (अलवर)
यादव, श्री शरद (बदायूं)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सहरसा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (सीतामढ़ी)
यादवेन्द्र दत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
राउतराय, श्री नीलमणि (पुरी)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राजदेव सिंह, श्री (संगरूर)
राजवीर सिंह, श्री (आंवला)
राजू, श्रीमती उमा गजपति (विशाखापट्टनम)
राजू, श्री एम० एम० पल्लम (काकीनाडा)
राजू, श्री एस० विजय राम (पार्वतीपुरम)
राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन० जे० (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राठौर, डा० भगवान दास (खुर्जा)
राणा, श्री काशीराम छबीलदास (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, चौ० (अम्बाला)
राम बाबू श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामकृष्ण, श्री वाई० (कोलार)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदास, डा० आर० (टिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरी)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (आरा)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रमण्णा (कासरगोड)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री लालबाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हरधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री आर० गुंडू (बंगलौर दक्षिण)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)
राव, श्री० के० राम मोहन (बोब्बिली)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)

राव, श्री बी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)
राव, श्री श्रीनिवास (नालगोंडा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री हरीश (अलमोड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० नरसा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री राजमोहन (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लोधी, श्री गंगा चरण (हमीरपुर)

व

वघेला, श्री शंकरसिंह (गांधीनगर)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खीरी)
वर्मा, श्री एस० सी० (भोपाल)
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद (बेतिया)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बी० राजरवि (पोल्लाची)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
विजयराघवन, श्री ए० (पालघाट)
विश्वनाथम, डा० (श्रीकाकुलम)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (पेड्डापल्ली)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वेकारिया, श्री एस० एन० (राजकोट)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्कोडी)
शकीलुर्रहमान, डा० (दरभंगा)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री धर्म पाल (उधमपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शास्त्री, श्री अनिल (वाराणसी)
शास्त्री, श्री कपिल देव (सोनीपत)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई (बनासकांठा)
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी (कच्छ)
शिंगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवनकर, प्रो० महादेव (चिमूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई (जूनागढ़)
शेखर, श्री एम० जी० (धर्मपुरी)
श्रीकांतय्या, श्री एच० सी० (हसन)
श्रीनिवासन, श्री सी० (डिण्डिगुल)
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ (पटना)

ष

षण्मुखम, श्री पी० (पांडेचेरी)

स

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (मुजफ्फरनगर)
समद, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

सरताज सिंह, श्री (होशंगाबाद)

सरवर हुसैन, श्री (बुलन्दशहर)

सरोज, श्री सरजू प्रसाद (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साठे, श्री वसन्त (वर्धा)

सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या (शोलापुर)

सान्याल, श्री माणिक (जलपैगुडी)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

साय, श्री ए० लरंग (सरगुजा)

साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)

सारण, श्री दौलत राम (चुरू)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

सिंगम, श्री वासवपुन्नय्या (तेनाली)

सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे (गुना)

सिंह, श्री अजय (आगरा)

सिंह, श्री आनन्द (गोंडा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्रीमती उषा (वैशाली)

सिंह, प्रो० एन० तोम्बी (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री ललित विजय (बेगूसराय)

सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)

सिंह, श्री तेज नारायण (बक्सर)

सिंह, श्री धनराज (मुंगेर)

सिंह, श्री धर्मगज (शाहाबाद)

सिंह, श्री के० मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री मानधाता (लखनऊ)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)

सिंह, श्री रामदास (गिरिडीह)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री लोकेन्द्र (दमोह)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सुखेन्द्र (सतना)

सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हर गोविन्द (अमरोहा)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सिंह देव, श्री ए० एन० (आस्का)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)

सुंदरराज, श्री एन० (पुडुकोट्टाई)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुच्चा सिंह, बाबा (भटिंडा)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुर. श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)

सूबेदार, श्री (राबर्ट्सगंज)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)

सेमा, श्री शिकिहो (नागालैंड)

सेलमथ, श्री कांसी पम्मीर (चेंगलपट्टु)

सेल्वारासु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह (कुरुक्षेत्र)

सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)

सोढ़ी; श्री मानकूराम (बस्तर)

सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)

हरीश पाल, श्री (मेरठ)

हर्षवर्धन, श्री (महाराजगंज)

हान्डू, श्री प्यारे लाल (अनन्तनाग)

हीरा भाई, श्री (बांसवाड़ा)

हेत राम, श्री (सिरसा)

होटा, श्री भवानी शंकर (सम्बलपुर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री रवि राय

उपाध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

सभापति तालिका

डा० तम्बि दुरै

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री जसवन्त सिंह

श्री निर्मल कांति चटर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी

अपर सचिव

श्री के० सी० रस्तोगी

श्री सी० के० जैन

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा रक्षा, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास, अन्तरिक्ष मंत्रालयों विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मन्त्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
वित्त मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
गृह मंत्री	श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद
उद्योग मंत्री	श्री अजित सिंह
वाणिज्य और पर्यटन मंत्री	श्री अरुण कुमार नेहरू
विदेश मंत्री	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री	श्री आरिफ़ मोहम्मद खान
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री	श्री दिनेश गोस्वामी
रेल मंत्री	श्री जार्ज फर्नान्डीज
शहरी विकास मंत्री	श्री मुरासोली मारन
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री नाथू राम मिर्धा
पर्यावरण और वन मंत्री	श्री नीलमणि राउतराय
सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री पी० उपेन्द्र
श्रम और कल्याण मंत्री	श्री राम विलास पासवान
वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	श्री शरद यादव

राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री मनुभाई कोटाड़िया

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रशीद मसूद

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरंगिल श्रीधरन
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भागेय गोवर्धन
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भजमन बेहेरा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चिमनभाई मेहता
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री हरि किशोर सिंह
पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मेनका गांधी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० एम० जी० के० मेनन
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग विभाग में राज्य मंत्री	श्री नीतीश कुमार
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० राजा रमन्ना
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम पूजन पटेल
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सत्यपाल मलिक
उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री	श्री श्रीकांत जेना
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुबोध कांत सहाय
कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा

उप मंत्री

रेल मंत्रालय में उप मंत्री	श्री अजय सिंह
वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री	श्री अनिल शास्त्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले तथा खेल विभाग में उप मंत्री	श्री भक्त चरण दास
संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री	चौ० जगदीप धनखड़
कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री	श्रीमती ऊषा सिंह

लोक सभा

मंगलवार, 7 अगस्त, 1990/16 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

1. मेजर डी० डी० खनोरिया (कांगड़ा)
2. श्री लालबाबू राय (छपरा)

11.01 म० पू०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आज हम दो महीने बाद मिल रहे हैं। मुझे सदन को अपने पांच भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, देवेन्द्र सतपथी, सी० नन्जप्पा, जी० एम० दीक्षित और सी० एम० पुनाचा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के विजयवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चट्टोपाध्याय 'भारत कोकिला' श्रीमती सरोजिनी नायडू के भाई थे। उनके पिता श्री अघोरेन्द्रनाथ हैदराबाद में निजाम कालेज के संस्थापक प्रधानाचार्य थे। श्री चट्टोपाध्याय एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे और स्वतन्त्रता आन्दोलन में वे कई बार जेल गए।

श्री चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संगीतमय कवितायें लिखीं जिसमें विचारों की गम्भीरता तथा विशेष आकर्षण है जिसने लाखों पाठकों का मन मोहित कर लिया है। उनके उन्नीस काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 1965 में उन्होंने एक्सपो-67 और मोन्ट्रीयल-30 दो विश्व कवि सम्मेलनों में भाग लिया और भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व किया।

पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित श्री चट्टोपाध्याय को, सिनेमा जगत में हमेशा उनके अभिनय और गीतों के लिए स्मरण किया जाता रहेगा। वह एक अच्छे वक्ता के रूप में दूरदर्शन भी आए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए उन्होंने अनेक विषयों पर मनोरंजक फीचर लिखे।

वह एक चित्रकार भी थे। उनकी कृतियों में सौन्दर्य की छाप और जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त होता है। उनकी चित्रकारी "नाना" नाम से प्रकाशित हुई।

श्री चट्टोपाध्याय योग्य सांसद थे तथा सभा की कार्यवाही में रुचि लेते थे और सभा में उनके भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना जाता था।

23 जून, 1990 को 92 वर्ष की आयु में उनका बम्बई में निधन हो गया।

श्री देवेन्द्र सतपथी 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उड़ीसा के ढेंकानल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सतपथी पेशे से पत्रकार थे। उन्होंने अनेक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1967-68 के दौरान वह भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा के उपाध्यक्ष रहे। 1968-69 के दौरान 'आल इंडिया पोस्टल इम्पलाइज यूनियन क्लास फोर एंड पोस्टमैन, उड़ीसा सर्कल' के अध्यक्ष भी रहे। श्री सतपथी ने गांधी स्मारक निधि के अन्तर्गत कार्यरत गांधी तत्व प्रचार संस्था में संगठनकर्ता के रूप में कार्य किया, साथ ही वह श्री अरविन्दो सोसाइटी, पांडिचेरी के सदस्य भी थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री सतपथी ने भारत सेवक समाज और अरविन्दो स्टडी सर्कल के लिए उड़ीसा में अनेक शिविरों और राहत कार्यों का आयोजन किया।

26 जून, 1990 की रात को 61 वर्ष की आयु में श्री सतपथी का भुवनेश्वर में देहान्त हो गया।

श्री सी० नन्जप्पा 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने संयुक्त मद्रास राज्य के नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री नन्जप्पा व्यवसाय से डाक्टर थे और वह अनेक सामाजिक तथा अन्य संगठनों में विभिन्न हैसियतों से सम्बद्ध रहे। वह अनेक वर्षों तक म्यूनिसिपल कांउसिल, कोयम्बटूर के सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे।

वह एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा 1941 में गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह भी किया। वह कई बार जेल भी गये।

88 वर्ष की आयु में 21 जुलाई, 1990 को कोयम्बटूर में श्री नन्जप्पा का निधन हो गया।

श्री जी० एन० दीक्षित 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1952-57 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे।

वह पेशे से वकील थे, उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा अनेक बार जेल गए।

श्री दीक्षित कर्मठ राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह विश्वविद्यालय अनुदान समिति, उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे और वस्त्र मिलों संबंधी समिति, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखीं।

वह एक योग्य सांसद थे। श्री दीक्षित सभा की कार्यवाही में बहुत रुचि लेते थे और उन्होंने इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया।

2 अगस्त, 1990 को 83 वर्ष की अवस्था में श्री दीक्षित का देहान्त हो गया।

श्री सी० एम० पुनाचा भूतपूर्व मैसूर राज्य के मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र से 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह 1945 में तत्कालीन कुर्ग विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। बाद में वह 1947-51 की अवधि के दौरान संविधान सभा और अंतिरम संसद के सदस्य रहे। इसके बाद वह अप्रैल, 1964 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए।

श्री पुनाचा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे उन्होंने स्वाधीनता के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अनेक बार जेल गए।

श्री पुनाचा 1952-56 के दौरान तत्कालीन कुर्ग राज्य के मुख्यमंत्री थे और नव निर्वाचित कर्नाटक राज्य के मंत्रिमंडल में उन्होंने अनेक विभागों का कार्यभार संभाला।

श्री पुनाचा एक योग्य प्रशासक थे और उन्होंने 1966-69 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनेक विभागों का सफलतापूर्वक कार्यभार संभाला। उन्होने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया।

श्री पुनाचा ने अनेक स्थानों की यात्रायें की थीं और 1959-63 के दौरान वह भारतीय व्यापार निगम के अध्यक्ष रहे। 1960 में। उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों में भेजे गए एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और 1961 में जापान को भेजे गए राज्य व्यापार निगम के शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक योग्य सांसद थे। उन्होने सदन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री पुनाचा का 80 वर्ष की आयु में 3 अगस्त, 1990 को गोनीकोप्पल (कर्नाटक) में निधन हो गया।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक और सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान स्वरूप थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, आगरा के अंदर हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचारों के कारण···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, यह प्रश्न-काल है। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, मैं आपको प्रश्न-काल में इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह समय इस सवाल को उठाने का नहीं है। इसलिए आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप फिर खड़ी हो रही हैं, मैंने आपको बैठ जाने के लिए कहा है। आप अपने दल की नेत्री हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने प्रश्न काल के निलंबन का प्रस्ताव रखा है ताकि मूल्य सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर, जो हमने प्रस्तुत किया है, तत्काल विचार किया जा सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रश्न काल के निलम्बन तथा हमारे स्थगन प्रस्ताव को शुरू करने सम्बन्धी प्रश्न पर सभा का मत मालूम किया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : सरकार द्वारा वृद्धि के सवाल पर किसी भी शक्ल में बहस के लिए तैयार है। आप जैसा निर्णय करें, क्वश्चन आवर के पहले लें, या बेहतर हो क्वश्चन आवर के बाद लें। क्वश्चन आवर को अभी इस वक्त स्थगित करें, यह निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं लेकिन हम बहस के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, उस स्थिति में हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रश्न काल के तुरंत बाद इस पर विचार कीजिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कोई और निवेदन नहीं सुनूंगा, आप पहले बैठ जाएं। सारा हाऊस ऐक्साईटिड है, सारा देश ऐक्साइटिड है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० एन० रेड्डी।

श्री बी० एन० रेड्डी : प्रश्न संख्या 1 ···(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं। प्रश्न काल के समय मैं कुछ और नहीं सुन रहा हूं, प्रश्न काल चलने दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुपादस्वामी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे।

[हिंदी]

श्री राम लाल राही : आपको सुनना चाहिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मना नहीं किया है, मैं समय पर सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं मैं प्रश्न काल के बाद सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, अभी गुरुपादस्वामी जी रिप्लाई दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के ऊपर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, वह एक खेदजनक बात है। यह बहुत गम्भीर मामला है। यह सरकार बिल्कुल हृदयहीन सरकार है और बिल्कुल अनकनसर्ड हैं।···(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अवसर पर प्रधान मन्त्री जी को यहां सदन में उपस्थित होना चाहिये था। ऐसे में हाऊस कैसे चलेगा और कौन हमारी बात सुनेगा।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। आज उनका राज्य सभा में प्रश्न काल है। वह दूसरे सदन में प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं।···(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

*1. श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले जनता, उद्योगपतियों आदि की राय मांगी गई थी और उस पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में हाल ही में जारी किये गये विनियमों का पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर हाल ही में किये गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व होगा।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों में यह उपाय शामिल हैं—केन्द्रीय-राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सवारियों में पेट्रोलियम और डीज़ल की खपत में कटौती। राज्य सड़क परिवहन निगम, रेलवे, बिजली घर जैसे थोक उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी खपत में 10% की कटौती करें। कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र आपूर्ति पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राज्यों में मिट्टी के तेल का आबंटन पिछले वर्ष की सहमति प्राप्त 7% की वृद्धि की तुलना में मानसून ब्लाक 1990 (जुलाई-अक्तूबर) के लिए 4% की वृद्धि पर सीमित कर दिया गया है। खुदरा बिक्री केन्द्र रविवार को केवल प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुले रहेंगे और उनसे कहा गया है कि अन्य दिनों में वे प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कार्य करें। शहरी क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर स्थित सभी बिक्री केन्द्र और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं की 20 कि०मी० की परिधि के अन्दर आने वाले सभी केन्द्र उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अधीन आते हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : जब मूल्य वृद्धि के बारे में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था तो इन्हें जनमत जान लेना चाहिए था और पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वास्तव में काफी हद तक बढ़ गए हैं। मूल्यों में वृद्धि के कारण हम आज बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही आम जनता और उद्योगपतियों से राय क्यों नहीं ली।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस प्रश्न का पेट्रोलियम-मूल्यों से जरा भी सम्बन्ध नहीं है। मेरे माननीय मित्र वित्त मन्त्री द्वारा लगाए गए शुल्क से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़े हैं और इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बी० एन० रेड्डी : मेरे द्वारा मांगे गए विवरण नहीं दिए गए हैं। क्या आप इन्हें बताने की कृपा करेंगे?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, कुछ विवरण पहले ही दिया जा चुका है। 21 जून को मन्त्रालय द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग को कम करने के लिए अनेक उपाय का विवरण देने वाली अधिसूचना जारी की गई थी। हमने पेट्रोल पम्पों की कार्यावधि के घण्टों पर प्रतिबन्ध लगाया है। ये अब सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक खुलते हैं···(व्यवधान)···रविवार को भी कुछ समय तक इन्हें बन्द रखा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक उपाय मन्त्रालय द्वारा किए गए हैं। हमने सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों से, उपभोग में 20 प्रतिशत कटौती करने का निवेदन किया है। विशेष रूप से हमने रेल मन्त्रालय से 10 प्रतिशत की कटौती करने के लिए कहा है। इसी प्रकार हमने राज्य सरकारों से भी उपभोग में 20 प्रतिशत कमी करने को कहा है।

हमने सड़क परिवहन और बिजली बोर्डों पर 10 प्रतिशत कटौती लागू करने के लिए कहा है। हम इन उपायों के प्रभावों की जांच कर रहे हैं और इन अनेक उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में कुछ समय लगेगा।

श्री सनत कुमार मंडल : 'ओपेक' देशों द्वारा एक बैरल तेल का लक्ष्य मूल्य तीन डालर बढ़ाए जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने और भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले मुख्य देश कुवैत पर इराक के आक्रमण के कारण इसकी आपूर्ति में सम्भावित रुकावट के कारण यहां अब पेट्रोलियम मन्त्रालय किस प्रकार न केवल क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव करता है बल्कि उपभोग में भी बचत करना चाहता है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह सही है कि हाल ही में ओपेक देशों ने पेट्रोलियम मूल्य 21 डालर प्रति बैरल तक बढ़ा दिए हैं। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल 9500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। परन्तु वित्त मन्त्रालय ने हमारे लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता 6400 करोड़ रुपये तक प्रतिबन्धित की है। यही रकम पिछले वर्ष भी निर्धारित की गई थी। यदि हमें इस प्रतिबन्ध का पालन करना है तो हमें पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग अब से काफी कम करना होगा। पेट्रोलियम मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय के साथ यह मसला उठाया है। हम और अधिक विदेशी मुद्रा के आबंटन के लिए निवेदन कर रहे हैं। हम स्थिति पर प्रतिदिन नजर रख रहे हैं परन्तु मुझे खेद है कि अन्तर्राष्ट्रीय तेल की स्थिति बड़ी नाजुक और अस्थिर है। मुझे डर है कि पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में कटौती करने के लिए हमें और अधिक कड़े उपाय करने पड़ सकते हैं ··(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डालें। आप इस तरह मन्त्री महोदय से उत्तर नहीं पा सकते। आपको अवसर मिलेगा। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पिछले वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत और पेट्रोल की 14 प्रतिशत थी। यदि यही वृद्धि दर इस वर्ष भी जारी रही तो हमें लगभग 8800 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। वित्त मन्त्रालय ने हमें इस वर्ष केवल 6400 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनुमति दी है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले वर्ष मांग में कुल वृद्धि 8.2 प्रतिशत थी। यदि मुझे वित्त मन्त्रालय द्वारा दी गई सीमा का पालन करना पड़ा तो मांग में 8 प्रतिशत वृद्धि को पूरा करने की अपेक्षा मांग में एक प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी। अब यह तस्वीर सामने आ रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह सरकार पहले किसी चीज को लागू कर देती है और तत्पश्चात् उस पर विचार करती है। इन्होंने बड़े जोर-शोर के साथ पेट्रोल पम्पों को रविवार बन्द करने और अन्य दिनों प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खोलने की घोषणा की। सर्वप्रथम इन्हें एक काम करना चाहिए। जब प्रधानमन्त्री जी मालदीव की यात्रा पर गए तो इन्हें वहां दो विमान लेकर नहीं जाने चाहिए थे। मेरा खयाल है कि विमान पेट्रोल से चलते हैं। जबकि हम पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोल की खपत कम करने के उपायों का समर्थन करते हैं, क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि इनके अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, सायं सात बजे के बाद प्रतिदिन पेट्रोल की काला बाजारी होती है। रविवार को काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है और आटो रिक्शा और टैक्सी वाले सायं सात बजे के बाद ठीक या गलत तरीके से ग्राहकों को ठगते हैं। दिखावे की अपेक्षा इन्हें पेट्रोल और पट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए सुविचारित कार्यक्रम के साथ आगे आना चाहिए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। मैं अपने मित्र को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इसके प्रति काफी गम्भीर हैं। यह एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है।

कालाबाजारी के विशेष प्रश्न के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि इस कमी की स्थिति में, कुछ हेराफरी और काला बाजारी होती ही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखें। मन्त्री महोदय, आप कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमने इस स्थिति को भांप लिया है और हम सम्पूर्ण वितरण की निगरानी कर रहे हैं। हम कालाबाजारी को बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। हमने काला बाजारी रोकने के सभी उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत सीरीयस हैं। सीरीयस इतने हैं कि इसको लागू करने से पहले किसी से बात नहीं की, किसी पोलिटिकल पार्टी से या किसी से भी बात नहीं की।···(व्यवधान)···पिछले दो महीने में इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इस तुगलकी-आर्डर के कारण ही ब्लैक मार्केट बढ़ी है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार पर पुनर्विचार करने के लिए या संसद के विभिन्न दलों से पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्थिति से निपटने के लिए हमने सभी उपाय किए हैं। हमने सूची बनाई है। अभी पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। हमने उचित सूचियां बनाना सुनिश्चित किया है। हम मांग को पूरा कर रहे हैं। यदि अब भी हेराफेरी हो रही है तो इन्हें रोकने के लिए हम सभी कदम उठायेंगे।

श्री हरिन पाठक : हेराफेरी अब भी जारी है। तीन माह बीत चुके हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने क्या कदम उठाए हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि माननीय सदस्य कोई प्रकरण विशेष मेरी जानकारी में लाएं तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा ...(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने सवाल किया था, क्या सरकार इसको रिव्यू करने के लिए कुछ पोलिटिकल पार्टीज से विचार-विमर्श करने जा रही है ? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमने हाल ही में अर्थात् 21 जून, 1990 को ये उपाय किए हैं। इनका प्रभाव जानने के लिए हमें दो-तीन माह और प्रतीक्षा करनी चाहिए।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने यथासम्भव राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी चिन्ता समझता हूं परन्तु आप कृपया मन्त्रीजी को उत्तर देने दें।

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी : दो-तीन माह के पश्चात हम सारी स्थिति की समीक्षा करेंगे। हम इन उपायों के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। यदि कोई आवश्यकता हुई तो हम अवश्य ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां राजकीय व्यय को घटाकर आप घाटे के बजट और विदेशी व्यापार में सन्तुलन की समस्या से साथ-साथ निपट रहे हैं। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पादों में कटौती और अधिक होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि आधे पेट्रोलियम का उपभोग सरकारी क्षेत्र में होता है।

(1) मैं जानना चाहता हूं कि उपलब्ध पेट्रोलियम के कितने भाग का उपभोग सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों द्वारा किया जाता है। (2) उस उपभोग को घटाने में वह कितना सफल हुआ है; और (3) क्या वे दूसरों की खपत पर रोक लगाने से पहले अपने पर रोक लगाने जा रहे हैं ?

उस सीमा तक, क्या वे सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में पेट्रोलियम की राशनिंग करने जा रहे हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : देश में तेल क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यह कार्यवाही कुछ समय तक चलेगी और दो या तीन महीनों के बाद हम सारी स्थिति का अवलोकन करेंगे और उचित कदम उठाएंगे ...(व्यवधान)।

श्री अमल दत्त : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर देने से पहले मन्त्री महोदय प्रश्न को समझ लें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न विशेष का उत्तर देने की कोशिश करें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : केन्द्रीय सरकार पेट्रोल और डीजल की मांग को कम करने की दृष्टि से सरकारी गाड़ियों में 1990-91 में, 1989-90 के मुकाबले 20 प्रतिशत उपभोग में कमी

करने के प्रस्ताव के रूप में प्रथम कदम उठाती है। सभी मुख्य मन्त्रियों से 1989-90 के मुकाबले पेट्रोल और डीजल के उपभोग में 20 प्रतिशत कटौती करने सम्बन्धी निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया है···(व्यवधान)।

श्री हरिन पाठक : *सही स्थिति क्या है ? (व्यवधान)*

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : *वह सही स्थिति जानना चाहते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 53.52 मिलियन टन है। वर्ष 1990-91 में मांग···(व्यवधान)।*

श्री कमल नाथ : यह क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आप सही तस्वीर चाहते हैं। इसलिए, मैं आपको तस्वीर दे रहा हूं।···(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने पैट्रोलियम पदार्थों के उपभोग पर रोक लगाने के लिए जो वित्तीय और वास्तविक कदम उठाए गए हैं। उनके बारे में विस्तार से बताया है। मैं सोचता हूं कि मेरे पुराने और योग्य साथी द्वारा प्रस्तुत विचार बहुत सही हैं। मेरे अनुमानों के अनुसार पैट्रोलियम पदार्थों के कुल उपयोग का लगभग 70 प्रतिशत स्वयं सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है। अगर ये आंकड़े सही नहीं हैं तो आप इनमें सुधार कर सकते हैं। माननीय मन्त्री अब बता रहे हैं कि यह लगभग 50 प्रतिशत है। अब, मेरा मुद्दा यह है कि सही आंकड़ों की बहस में पड़े बिना—इसका कितना सरकारी उपभोग है और कितना निजी उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है ? अब माननीय मन्त्री कहते हैं यह 50% है, चाहे यह 60% हो अथवा 70%, ये सभी वित्तीय और वास्तविक नियन्त्रण हमें सीधे प्रभावित करते हैं। इससे नागरिक सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां तक सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उपभोग की बात है, क्या इस बात की जांच कराई गई है; पिछले छः महीनों से वह किस प्रकार इसका उपभोग कर रहे हैं, और पिछले तीन महीनों में उनकी उपभोग योजना क्या रही है ? यदि 'क' प्रतिशत की कोई अनिवार्य कटौती है; तो क्या वास्तव में उस 'क' प्रतिशत को लागू किया गया है ? यह एक भाग है।··· (व्यवधान)

दूसरा भाग यह है : माननीय मन्त्री ने हमें सूचना दी है कि वे रेलवे को अपने उपभोग में कटौती करने के लिए कह रहे हैं। मैं सोचता हूं कि रेलवे को ऐसा कहना एक खतरनाक सुझाव है। ···(व्यवधान)···यदि आप रेलवे को कटौती करने के लिए कहते हैं तो भीड़ बढ़ जाएगी। कहीं तो कमी होगी ही, चाहे वह सामान के यातायात में हो अथवा कुछ और। क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी ?

तीसरा पहलू है : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य हमें सूचित करें कि इस समय हमारी गैस का कितने प्रतिशत जल रहा है, क्योंकि गैस भी, आखिरकार एक पेट्रोलियम पदार्थ है। गैस का जलना एक अनुत्पादक उपभोग है। गैस के जलने से इसके उपभोक्ताओं को एक संभावित पेट्रोलियम पदार्थ से वंचित होना पड़ रहा है। गैस के जलने से एक साथ रुपये और डॉलर दोनों में नुकसान हो रहा है।

माननीय मन्त्री ने यह भी कहा है कि यह हमारे सामने एक गम्भीर स्थिति है। क्या वे कृपया इन तीनों पहलुओं का, रेलवे को ध्यान में रखते हुए, जवाब देंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सबसे पहले मैं अंतिम प्रश्न का जवाब दूंगा।···(व्यवधान)··· हाल ही के अनुमान के अनुसार, 1994 में 98.13 मिलियन घन मीटर गैस उपलब्ध होगी।···(व्यवधान) ··उन्होंने इसके लिए प्रश्न में पूछा है—1999-2000 में 122.27 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध होगी और 1999-2000 में 122.27 मिलियन क्यूबिक मीटर; और 'बम्बई हाई' में ही, 17 मिलियन क्यूबिक गैस जल रही है;···(व्यवधान)·· कृपया धैर्य रखें। हम 'बम्बई हाई' में ही 1800 रुपये करोड़ रु० मूल्य की गैस जलाकर नष्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक आपराधिक व्यर्थ है, एक राष्ट्रीय अपव्यय है; और हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे 4 या 5 वर्षों में इसका जलना शून्य हो जाएगा और इस सम्बन्ध में मेरे मन्त्रालय द्वारा एक योजना बनाई जा रही है। जब मैंने कार्यभार सम्भाला था तो तब ऐसी योजना कोई नहीं थी। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए, कि भविष्य में गैस जलकर व्यर्थ न हो, कदम उठा रहा हूं और हम एक योजना बना रहे हैं और इसे गैस पर आधारित उद्योगों से जोड़ देंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में, उन्होंने कहा है कि रेलवे के उपभोग में कटौती करना गलत है। हमने रेलवे के लिए 10% कटौती का सुझाव दिया है और अन्य केन्द्रीय सरकार उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए मैंने 20% कटौती का सुझाव दिया है। यदि किसी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं तो हम इसे बदल देंगे।

इन कदमों के उठाए जाने के बाद इसके प्रभाव के सम्बन्ध में, हम अवलोकन कर रहे हैं। दो या तीन महीनों के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैं सदन को याद कराना चाहूंगा कि ये कदम भविष्य में तेल क्षेत्र में संकट को रोकने के लिए उठाए गए हैं।

मैंने यह पहले ही कर दिया है और मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ताकि जागरूकता आए। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उद्योग और कृषि की विकास की गति रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि इससे उद्योग किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। मैं चाहता हूं कि अनावश्यक उपभोग समाप्त हो जाए; फालतू उपभोग समाप्त हो जाए और बरबाद नहीं हो। तेल के उपभोग में अत्यधिक फिजूलखर्ची हो रही है।

इसलिए, मैं सोचता हूं कि सदन मेरे साथ सहमत होगा कि हमें पैट्रोल की फिजूलखर्ची से बचना चाहिए।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने पैट्रोलियम के बारे में नीति निर्धारित की है क्या उस नीति पर फिर से विचार करेंगे? इस नीति के बनने से एकदम लोगों के दिल और दिमाग में ऐसी धारणा पैदा हो गई है कि शायद पैट्रोल की कमी आने वाली है। कमी को महसूस करके हर आदमी कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। दो महीने पहले अनाउंस किया गया था कि पैट्रोल की राशनिंग हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि राशनिंग के नाम से ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। उसके बाद टाईम पर पाबन्दी लगा दी कि सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सिनेमा और रविवार को खुला नहीं रहेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल 1989 में जून-जुलाई में पैट्रोल की खपत कितनी थी और 1990 में जून-जुलाई में पैट्रोल की खपत कितनी थी ? कितनी बचत हुई ? जो नया संशय लोगों के दिल और दिमाग में पैदा कर दिया है, क्या इसे दूर करने की कृपा करेंगे ? इस पर दोबारा से विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या अब मैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, आंकड़े दे सकता हूं ।···(व्यवधान)

***अध्यक्ष महोदय** : आप उनके प्रश्न के अन्तिम भाग का जवाब दें ।*

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वर्ष 1985-86 में पैट्रोलियम पदार्थों का उपभोग 45.867 मिलियन टन था जो 1989-90 में, पिछले वर्ष 53.82 मिलियन टन था; वर्ष 1990-91 में अनुमानित उपभोग 58.74 मिलियन टन होगा । फिर आपने घाटे के बारे में पूछा है । वर्ष 1990-91 में, घाटा 9.49 मिलियन टन होगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, यह अनुमानितः 14.48 मिलियन टन होगा । आपने इन आंकड़ों का विवरण जानना चाहा है । मेरे पास इन आंकड़ों का विवरण नहीं है । मैं आपको वे आंकड़े बाद में दूंगा···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री चावड़ा ।

(व्यवधान)

रेल गाड़ियों का देरी से चलना

*2. **श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहसाना-पाटन, मेहसाना-चाणस्मा और मेहसाना-तारंगा हिल सैक्शन, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे में सभी पैसेंजर रेल गाड़ियां समय से नहीं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयले की अपर्याप्त सप्लाई इस स्थिति के लिए कहां तक उत्तरदायी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) जी नहीं । तथापि, रेल इंजनों के लिए कोयले की सप्लाई गड़बड़ा जाने तथा बाद में रतलाम-गोधरा खण्ड पर माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने की गम्भीर दुर्घटना, जिससे गाड़ियों का सीधा चालन लगभग 84 घण्टे तक अवरुद्ध रहा, के कारण कोयले की कमी के परिणामस्वरूप मेहसाना-पाटन, मेहसाना-चाणस्मा और मेहसाना-तारंगा हिल खण्डों पर चलने वाली 13 जोड़ी सवारी गाड़ियों में से 6-6-90 से 17-6-90 तक (दोनों दिनों सहित) 4 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थीं ।

(घ) सामान्यतया ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं ।

श्री सोमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : ये शाखा रेलवे लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं जानता हूं कि इन लाइनों पर रेलें हमेशा अनियमित चलती हैं। इसके दो कारण हैं : और यह दो कारण मेरे दो पूरक प्रश्न होंगे।

रेलवे ने एक ठेकेदार को काम पर लगाया है जो रेल इंजन में कोयले का लदान करने वाले मजदूरों को उचित मजूरी नहीं देता जिसके परिणामस्वरूप रेलें समय के अनुसार नहीं चलतीं। महोदय, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि इंजन में कोयला डालने के काम में लगे हुए मजदूरों को उचित वेतन देने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम उस प्रश्न की बात कर रहे हैं जब 13 जोड़ी रेल गाड़ियों में से, जो उस क्षेत्र में चल रही थीं, 4 रेल गाड़ियों को ग्यारह दिन तक रद्द करना पड़ा। रतलाम-गोंधा लाइन पर हमारी कुछ विशेष समस्याएं थीं, जिनके कारण ये रेल गाड़ियां रोकनी पड़ीं। वहां एक मालगाड़ी, जो कोयला ले जा रही थी, पटरी से उतर गई। मार्ग साफ करने में तीन दिन से ज्यादा समय लगा और इस कारण उस पूरे सेक्शन में उस विशेष छोटी लाइन से इंजन के कोयले की आपूर्ति का सारा कार्यक्रम गड़बड़ा गया। इसका ठेकेदार से, कोयले के लदान या ढुलाई से, या कोयले के लदाई या ढुलाई के कार्य में लगे हुए मजदूरों और ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सोमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, रेलवे ने एक ऐसा ठेकेदार रखा है, जो मजदूरों को बिल्कुल वेतन नहीं देता।

[हिंदी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी प्रश्नोत्तर काल में बीच में नहीं उठता। लेकिन अभी मुझे जो सूचना मिली है कि वैसा कभी हिन्दुस्तान की संसद के इतिहास में नहीं हुआ कि संसद के कम्पाउण्ड के भीतर कुछ लोग माइक्रोफोन लेकर नारे लगाते हुए गेट नम्बर एक पर खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं। हमारे साथी अभी वहां से आए हैं और उन्होंने बताया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हमको पता लग गया है और मैं पता करवा रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर कांग्रेस पार्टी ने यह किया है तो यह परम्परा बहुत गलत है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ऐसा मामला है कि जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती...(व्यवधान)।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष इसके खिलाफ कार्यवाही करें। ...(व्यवधान)...आप उसकी निन्दा करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक गम्भीर मसला है और इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हां, श्री चावड़ा? आप अपना प्रश्न रखें।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : 'सी० बी० एस०' रेलवे—गायकवाड़-बड़ौदा स्टेट रेलवे के स्टीम इंजिन अभी भी इस लाइन पर चल रहे हैं। कई बार ये पुराने इंजिन खराब हो जाते हैं और इसी कारण रेल गाड़ियाँ देर से चलती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री पुराने इंजिनों को बदलकर उनकी जगह नए इंजिन लाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : पुराने स्टीम इंजनों को बदलने की एक योजना है और उस योजना पर कार्य हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राघवजी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल रेलवे में कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो 365 दिन में सारे 365 दिन लेट चलती हैं। क्या मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लेट चलने का कारण एनेलेसिस करें और उनके टाइम टेबल का परिवर्तन करें ताकि वे ठीक समय पर चलें वरना हमेशा ही वह लेट चलती हैं। अन्यथा कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर अमल करेंगे।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखता है। ट्रेनों की अनियमितता के अतिरिक्त वहां कई और समस्याएं भी हैं। आजकल, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेहसाना में एक आंदोलन चल रहा है। 10 अगस्त को लगभग 10,000 लोग एक रेल रोको आन्दोलन में भाग लेने जा रहे हैं। समस्या यह है कि ये रेल पटरियां लगभग पचास वर्ष पहले बिछाई गई थीं; शहर का प्रवेश मार्ग बहुत ही छोटा है और शहर में प्रवेश करने के लिए लोगों को दो तीन घण्टे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम रेलवे से मार्ग को चौड़ा करने के लिए कह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे एक 'ओवर ब्रिज' बनाने जा रहे हैं या रेलवे के खर्च पर मार्ग को चौड़ा कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इससे रेल गाड़ियों की समय की पाबन्दी के कार्यक्रम में और बाधा पहुंचेगी।

आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

***3. श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को कम कीमत वाली आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई नए उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पैमाने पर औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों की

सांठगांठ को, जो उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार जनता को उचित और उपयुक्त मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा करते समय निर्माताओं के लिए उचित लाभ को भी सुनिश्चित किया जाता है। क्लोरप्रोमेजिन थियोरिडाजाइन, ट्रिफ्लूपेराजिन, एमिट्रप्टिलीन, इम्प्रामाइन, ट्रप्रोलिडाइन, पोलिमिक्सिन बी० सल्फेट, फ्लूसिनोलोन, एसिटोनाइड, आक्सीफेड्रिन, ट्राइमिनोलोन आदि पर आधारित अनेक सूत्रयोगों की कीमतें हाल ही में कम कर दी गई हैं। विद्यमान औषध नीति की समीक्षा भी की जा रही है और औषधों को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जायगा।

(ग) ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) विदेशों से बड़े निर्माताओं द्वारा खरीदी गई प्रपुंज औषधों/कच्चे माल की कीमतों को निरन्तर मानीटर किया जाता है।

(2) जब कभी अधिक मूल्य के बीजक बनाने का मामला सरकार की जानकारी में आता है तो कानून के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से कीमतें प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं कि आयात प्रतियोगी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सवाल मैंने पूछे थे उनका जवाब इन लिखित जवाब में नहीं है। मैंने यह मालूम करना था सरकार से कि जो जीवन आवश्यक दवायें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कराने के लिए नई सरकार क्या कोई नई नीति निर्धारित करने की कोशिश कर रही है या नहीं ? जवाब में दिया गया है कि हम लोग दामों पर बड़ी जबर्दस्त रोक लगा रहे हैं और कुछ दाम कम हुए हैं। असलियत यह है कि पिछले दो साल के अन्दर करीब-करीब हर दवा के दाम बढ़े हैं और यहां तक कि सौ प्रतिशत, दो सौ प्रतिशत और तीन सौ अस्सी प्रतिशत तक दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसका मैं पूरा ब्योरा मंत्री महोदय को दे सकती हूं, अगर वह चाहें तो। पिछले सत्र के दौरान हमारे कुछ ओ. एन. जी. सी. के अधिकारीगण तीन दिन की हड़ताल करने की सोच रहे थे और हमारे मंत्री जी शेर की तरह दहाड़े तथा उन पर "एसमा" द्वारा रोक लगाकर हड़ताल तुड़वाना चाहते थे। इस देश में गरीब जनता को मारने वाली जो ड्रग्स कम्पनीज और मल्टी नेशनल कार्पोरेशन हैं जिन्होंने एक होकर कारटल बनाया हुआ है वे पूरे देश को ब्लैकमेल कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पर आयें, आपके दो सवाल हैं।

श्रीमती सुभाषिनी अली : उनकी प्रस्तावित हड़ताल थी उससे पहले कोई समझौता हुआ था 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में, हम जानना चाहेंगे कि उस समझौते में मंत्री महोदय ने उन लोगों की और निर्माताओं की कौन-कौन-सी शर्तें मानी हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, मैं माननीय सदस्या से सहमत हूं कि आवश्यक औषधियां और जीवन रक्षक औषधियां महत्वपूर्ण हैं और उनका उत्पादन सुनिश्चित करना चाहिए··· (व्यवधान)···हमारी सरकार द्वारा किए इस वायदे को ध्यान में रखते हुए, कि उपभोक्ताओं को आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएं, मैंने यह प्रक्रिया स्वयं शुरू की, मैंने खुद इसका प्रारम्भ किया···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों को मिलती नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इजाजत नहीं दी, आप बैठें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रश्नकर्त्ता से मेरी असहमति नहीं है···(व्यवधान) जैसे ही मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला, मैंने लगभग 21 जीवन रक्षक औषधियों को मूल्य नियंत्रण में सम्मिलित किया। बाद में···(व्यवधान)।

श्री माधवराव सिंधिया. सदन के सामने की बेंचों में क्या गैस की लपट भड़क रही है··· (व्यवधान)।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति करता हूं। मुझे उनसे, ऐसी टिप्पणी की आशा नहीं थी ··(व्यवधान)।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे मजाक में लें··· (व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं 21 जीवन रक्षक औषधियों को पहले से ही मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित कर चुका हूं। बाद में, मंत्रालय के पुनरावलोकन के बाद, हमने पांच अन्य ऐसी औषधियों को मूल्य नियंत्रण में सम्मिलित किया। कुल मिलाकर, लगभग 26 औषधियां मूल्य नियंत्रण में सम्मिलित की गई हैं। इन्हें शामिल करने के परिणामस्वरूप लगभग 164 दवाइयों के मूल्य कम किए गए। यह सत्य है कि कुछ औषधि निर्माता बहुत ज्यादा मूल्य वसूल कर रहे हैं। उसके लिए मेरे विभाग में एक स्थायी समिति है जो सारे मामले को देखती है। अगर माननीय सदस्य कुछ और सुझाव दे सकें, तो मैं निश्चय ही इस पर ध्यान दूंगा।

श्रीमती सुभाषिनी अली : पहले प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल अपर्याप्त है। प्रश्न है उपभोक्ताओं को उचित दामों पर आवश्यक औषधियों उपलब्ध कराना। इस वर्ष काला बाजार के 20,000 नए

मामले प्रकाश में आये हैं। उस औषधि की बाजार में कमी है। काला मोतिया विरोधी दवाई की भी कमी है। तपेदिक निरोधक दवाई की भी कमी है। गरीब लोगों को जकड़ने वाले सभी रोगों की दवाइयों की कमी है। उन आवश्यक औषधियों की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए और उन्हें उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है?

मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 100 दवाइयों के मूल्य नियंत्रित किये जा रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा नई औषध नीति की घोषणा किए जाने से पूर्व 343 दवाइयों के मूल्य नियंत्रित किए जा रहे थे। यह कहने से कुछ नहीं होता कि आपने 20 या 25 दवाइयों को सम्मिलित किया है, और इस प्रकार जहां तक आवश्यक औषधियों का संबंध है मूल्य नियंत्रण वास्तव में लागू किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उनका मंत्रालय उपभोक्ताओं को उचित दामों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हालांकि औषधियों का वितरण स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हम भी उत्पादन का कार्य देख रहे हैं। जब भी दवाइयों की कमी होती है, उसे दूर करने के लिए त्वरित उपाय किए जाते हैं। अगर माननीय सदस्या कम आपूर्ति का कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाएंगी, तो मैं निश्चित रूप से उस पर गौर करूंगा···(व्यवधान)···जब तपेदिक निरोधी औषधि और दूसरी औषधियों की कम आपूर्ति का मामला हमारे सामने लाया गया, तो हमने इनकी आपूर्ति सुचारू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए गए···(व्यवधान)···राज्य सरकारों को भी ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे औषधियों की आपूर्ति उचित रूप से नियंत्रित हो सके और वितरित की जा सके।···(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : माननीय मंत्री ने उन विशेष दवाओं के बारे में पूछा है जिनकी कमी है। वास्तव में प्रश्न कम आपूर्ति का नहीं है बल्कि उचित मूल्यों पर आपूर्ति का है क्योंकि कम आपूर्ति शब्द यह दर्शाता है कि इनकी कालाबाजारी की जा रही है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर मुझसे सहमत होंगे। मंत्री जी ने दवा कम्पनियों से देय राशि वसूल करने के लिए जो कदम उठाया है वह उचित है। मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने जो कदम उठाया है और दवा कम्पनियों द्वारा देय राशि को वसूल करने का समय भी, इन कम्पनियों द्वारा उत्पादन में कमी किए जाने के कारण हो सकते हैं, जिससे इनकी कमी हुई है। क्या यह सच है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह बहुत स्पष्ट है कि उत्पादन में बिल्कुल कमी नहीं हो सकती। स्थानीय क्षेत्रों में कमी के कुछ मामले हैं जिनकी वजह है वितरण ठीक न होना और अनियमित वितरण। हमने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि वे इन आवश्यक औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को देख रहा है और यह मेरे मंत्रालय से संबद्ध नहीं है और इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, आज की प्रश्नों की सूची में प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 18, दोनों औषधियों के मूल्यों में वृद्धि से सम्बन्धित हैं। माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यद्यपि 21 जून को एक बैठक हुई थी परन्तु अभी तक वे कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाये हैं। उसके बाद जुलाई महीने में एक बैठक हुई थी, उसके बावजूद भी बाजार में विभिन्न औषधियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आयी है। मेरा प्रश्न यह है कि 21 जून और जुलाई महीने में

हुई बैठकों के बावजूद औषधियों के मूल्यों में कमी न आने के क्या कारण रहे, क्या मंत्री जी उसकी जानकारी सदन को देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में तेल की खोज हेतु ड्रिलिंग कार्य

[हिन्दी]

*4. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में तेल की खोज हेतु ड्रिलिंग कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा क्या वहां पर गैस भी मिली है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितनी मात्रा में गैस मिलने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का वहां पर चल रहे ड्रिलिंग कार्य में तेजी लाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में अब तक 5 गहरे कूप और पांच संरचनात्मक कूप खोदे गए हैं जिनमें वाणिज्यिक तौर पर कोई गैस नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ज्वालामुखी क्षेत्र में फिलहाल कोई खुदाई नहीं हो रही है। तथापि, हिमाचल प्रदेश में चंगरतलाई-1 स्थान को निकट भविष्य में खुदाई हेतु निर्धारित किया गया है ।

उद्यमियों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

*5. श्री के० एस० राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी व्यापारिक तथा औद्योगिक गृहों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में विशेष रूप से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियमों से सम्बन्धित नीतियों में और छूट की मांग की है;

(ख) क्या उन्होंने स्वदेशी उद्यमियों को विदेशी निवेशकर्ताओं के समकक्ष प्रोत्साहन देकर उन्हें बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो मांगी गई छूट और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापारिक और औद्योगिक गृहों की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एसोचेम) तथा फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ इन्डस्ट्री (फिक्की) अन्य बातों के साथ-साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और विदेशी विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 में परिवर्तन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में परिवर्तन के बारे में

(i) उपक्रमों के पर्याप्त विस्तार तथा नए उपक्रमों की स्थापना से सम्बन्धित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धाराएं 21 तथा 22 पूर्णतः समीचीन नहीं है और इन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

(ii) अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत "परिसम्पत्तियों के मूल्य", "अन्तर्सम्बन्धित उपक्रमों", "समूह", "सहयुक्त व्यक्तियों" तथा "सम्बन्धी" की परिभाषाओं का सुव्यवस्थीकरण तथा सरलीकरण।

(iii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के गैर पंजीकरण की प्रतिक्रिया तथा गैर पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुमति दी जाने की 60 दिन की समय सीमा के निर्धारण का सरलीकरण किया जाना चाहिए।

(iv) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अनुमोदनों के बाहुल्य से बचना चाहिए तथा सभी पहलुओं का समावेश करने के लिए एक उपयुक्त प्रारूप तैयार करना चाहिए।

(v) 10 से अधिक अन्तर्सम्बन्धित उपक्रमों में निदेशक के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीमा बढ़ाकर 20 कर देनी चाहिए।

(vi) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू करना चाहिए, विशेषकर जहां उपभोक्ता का हित निहित है।

(vii) अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की आधार सीमा को 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये और अधिष्ठायी उपक्रमों के लिए ऐसी सीमा को 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक ऊपर बढ़ाने के लिए संशोधन।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 में परिवर्तन के बारे में

(i) मानदण्डों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने चाहिए जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों में शाखा कार्यालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन देगा।

(ii) समुद्रपारीय व्यापार कार्यालयों को भारतीय वार्ता बैंकों द्वारा वित्त के दीर्घतर अवधि के लिए नौभार का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए।

(iii) भारतीय बैंकों को भारत में उसी बैंक के मुख्यालय द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा में से समुद्रपार कार्यालयों को बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति होनी चाहिए।

(iv) विदेशी मुद्रा के अर्जन को और दृढ़ करने के लिए बाहर से मुद्रा भेजने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। देश में उपार्जित विदेशी मुद्रा को देश में ही रखने तथा फिर से निवेश करने हेतु विदेशी पार्टियों के लिए प्रोत्साहन भी आरम्भ किए जा सकते हैं।

(v) गैर-आवासियों को राइट शेयर जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं लेनी चाहिए।

(vi) विदेशी साझेदार को बोनस शेयर जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता स्वयमेव होनी चाहिए।

(घ) एसोचेम तथा फिक्की द्वारा दिए गए सुझाव सरकार ने नोट कर लिए हैं तथापि वर्तमान समय में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजधानी में बिजली की कमी

*6. श्री आर० गुन्डू राव :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जून और जुलाई, 1990 के दौरान बिजली सप्लाई की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई थी;

(ख) क्या अधिकांश क्षेत्रों में नागरिकों को एक दिन में बीस घंटे से भी अधिक समय तक बिजली के बिना रहना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने और उत्तरदायित्व नियत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) जून तथा जुलाई, 1990 के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल मिलाकर बेहतर रही। यह कहना उपयुक्त नहीं है कि अधिकांश इलाकों में नागरिकों को सामान्यतः कई-कई घण्टों के लिए विद्युत सप्लाई के बिना रहना पड़ा। उच्च दाब सप्लाई एवं ट्रांसफार्मरों के ठप्प हो जाने, तारों (कन्डक्टर्स) के टूटने, केबिलों में खराबी आ जाने, प्रणाली पर क्षमता से अधिक भार पड़ने आदि के कारण कुछ क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा था। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) ने नेटवर्क की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्युत सप्लाई में इस प्रकार के व्यवधान, विशेष रूप से गर्मियों में क्षमता से अधिक भार होने के कारण उक्त व्यवधान अपरिहार्य है। तथापि, व्यापक निवारणात्मक अनुरक्षण उपाय करके और किसी इलाके में विद्युत सप्लाई बन्द होने की अवस्था में विद्युत सप्लाई पुनः चालू करने हेतु ब्रेकडाउन दलों को शीघ्र तैनात करके डेसू द्वारा विद्युत सप्लाई में कथित व्यवधान को कम से कम करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

विद्युत चालित रेल इंजनों का आयात

*7. श्री केशव प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा वर्ष 1987 में तीन फेज वाले विद्युत चालित रेल इंजनों के आयात के लिए दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और इसी बीच सम्बन्धित कम्पनियों ने इनके मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत चालित रेल इंजनों का आयात करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त ऋण को अब तक उपयोग में न लाए जाने के कारण एशियाई विकास बैंक को यदि कोई "कमिटमेंट" प्रभार दिया गया तो वह कितना है; और

(घ) इन रेल इंजनों के आयात के सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि ऋण पर दिसम्बर, 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन वास्तविक रूप में ऋण नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1993 तक लेने का कार्यक्रम बनाया गया था। निम्नलिखित कारणों से तीन फेज वाले बिजली रेल इंजनों के लिए ऋण लेने में अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना है :—

(i) चूंकि ये रेल इंजन अति आधुनिक हैं, इसलिए इनके मूल्यांकन तथा चयन में समय लगता है।

(ii) जब निविदाओं के मूल्यांकन का काम अग्रिम चरण में था तब योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने इसकी आवश्यकता समझी।

(iii) प्रस्थापनों की वैधता 31-3-1990 को समाप्त हो गई थी।

(iv) एशियाई विकास बैंक ने सुझाव दिया था कि संशोधित निविदाएं आमन्त्रित की जाएं।

(v) संशोधित निविदाएं प्राप्त हो जाने तथा उनके मूल्यांकन के बाद ही मूल्य में अन्तर का पता लग सकेगा।

(ग) ऋण न ली गई राशि पर दिसम्बर, 1989 तक "कमिटमेंट" प्रभार के रूप में लगभग 7,67,050 अमरीकी डालर की राशि ऋण खाते में समायोजित कर दी गई है।

(घ) रेल इंजनों की खरीद को शीघ्र अंतिम रूप देने के उद्देश्य से इस मामले पर एशियाई बैंक के साथ निकट समन्वय बना हुआ है।

बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

*8. श्री वामनराव महाडीक :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी के लिए अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार चुनी गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इनके चयन का मानदण्ड क्या है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुमानतः कितनी पूंजी निवेश किया जायेगा और इससे कितनी बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का इन कम्पनियों के काम-काज पर और इनके द्वारा लिए जाने वाले प्रभारों पर कोई नियंत्रण होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विद्युत की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकता एवं संसाधनों की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटीज के निवेश को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी के प्रोत्साहन हेतु सरकार ने निर्णय लिया है बशर्ते निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटा सके। कुछ प्राइवेट पार्टियों ने इस सम्बन्ध में रुचि भी व्यक्त की है लेकिन कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्राइवेट पार्टियां "लाइसेंसधारी" अथवा "विद्युत उत्पादन कम्पनी" के रूप में भाग ले सकती हैं। बिजली सम्बन्धी कानून के प्रावधान तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों, जिनकी शर्तों के अनुसार प्रशासनात्मक मानदण्डों के आधार पर सरकार द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा, के अनुसार टैरिफ तथा प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा।

विदेशी साम्य-पूंजी निवेश हेतु उद्योगों का चयन

[हिन्दी]

***9. श्री हर्षवर्धन :**

श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों का चयन कर लिया है जिनमें विदेशी कम्पनियों को 40 प्रतिशत साम्य-पूंजी का निवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले एककों को इस सूची से बाहर रखा जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फाल्का के लिए वायुदूत सेवा

***10. श्री गुमान मल लोढा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रनकपुर के विकास को देखते हुए फाल्का को वायुदूत सेवा से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या भावी योजना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था ठप्प हो जाना

[अनुवाद]

*11. डा० ए० के० पटेल :

श्री मानी भट्टाचार्य :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1990 को समस्त पूर्वी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई व्यवस्था के पूर्णत: ठप्प हो जाने के कारणों की कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र ग्रिड में अथवा देश में अन्य स्थानों पर इस प्रकार का संकट रोकने/पुन: न होने देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) 26 जून, 1990 को पूर्वी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई के फेल हो जाने से सम्बन्धित कारणों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने विद्युत के फेल होने के लिए अपर्याप्त विद्युत उत्पादन, ग्रिड में व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त प्रतिपूर्ति अभिक्रिया, अपर्याप्त पारेषण और संचार सम्बन्धी सुविधाएं, भार प्रेषण के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी आदि कारणों को उत्तरदायी ठहराया है।

पूर्वी क्षेत्र तथा देश में अन्य किसी भी क्षेत्र में ग्रिड फेल होने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में ये शामिल हैं; भार प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विद्यमान विद्युत पारेषण सम्बन्धी पद्धति का सख्ती से पालन करना, क्षेत्रीय ग्रिड प्रचालन का प्रभावकारी समन्वयन, पारेषण/परिणमन क्षमताओं को सशक्त बनाना, पारेषण प्रणाली अवयव के फेल होने का विश्लेषण करना और भार प्रेषण एवं टेलीमीटरी प्रणालियों को सशक्त बनाना आदि।

मराठवाड़ा में छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु निगम की स्थापना

[हिन्दी]

*12. श्री पुंडलिक हरी दानवे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा में छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक पृथक निगम का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार से इस परियोजना हेतु डिबेंचर जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे डिबेंचर जारी करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि वह आमान परिवर्तन परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए डिबेंचर जारी करके धन जुटाना चाहती है। रेलें इस बात

के लिए सहमत हो गई थीं कि यह अंशदान रेलवे के वार्षिक योजना परिव्यय के अलावा तथा इससे पूर्णतः भिन्न होगा तथा इसके परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान या डिबेंचरों के ऋणमोचन अथवा किसी भी रूप में रेलों की कोई अतिरिक्त वित्तीय दायिता नहीं होगी। इस आधार पर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच वित्त मन्त्रालय ने एक पत्र में यह मत प्रकट किया है कि यदि इन परियोजनाओं को योजना से इतर डिबेंचर जारी करके वित्त पोषित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुरोध स्वीकार करने के लिए केन्द्र सरकार को ऋण कार्यक्रम में उसी सीमा तक कटौती करने के लिए सहमत होना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने का एक मात्र उपाय यह है कि इन परियोजनाओं के लिए रेलों के योजना परिव्यय के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान किया जाए।

रेल दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

*13. डा० असीम बाला :

प्रो० यमुनाथ पांडे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 से अब तक माह-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कुल कितने लोग घायल हुए/मारे गए;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया;

(घ) रेलवे को इससे कुल कितनी हानि हुई;

(ङ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान भारतीय रेलों पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

महीना	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
दिसम्बर, 1989	39
जनवरी, 1990	43
फरवरी, 1990	41
मार्च, 1990	45
अप्रैल, 1990	44
मई, 1990	39
जून, 1990	44

(ख) इन दुर्घटनाओं में 223 व्यक्तियों की जानें गयीं तथा 631 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

(ग) इस अवधि के दौरान 91 व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में 38.85 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है लेकिन यह राशि आवश्यक रूप से इस अवधि के दौरान हुई दुर्घ-

टनाओं से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, रेलों ने अनुग्रह राशि के रूप में 13.80 लाख रुपये का भुगतान किया है।

(घ) रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान 20.62 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ङ) मानवीय गलती (रेल कर्मचारी तथा अन्य), उपस्करों की खराबी, शरारती गतिविधियों, आदि जैसे विभिन्न कारणों से ये दुर्घटनायें हुई थीं। इस अवधि के दौरान 134 रेल कर्मचारियों को दण्ड दिया गया।

(च) दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए रेलों ने एक व्यापक अभियान चला रखा है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(i) मानवीय प्रयास में सहायता के लिए तकनीकी उपकरणों का अधिष्ठापन;

(ii) अचल और चल परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण स्तर में सुधार;

(iii) गहन और बार-बार निरीक्षण;

(iv) नाजुक संरक्षा कोटियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की मनो-तकनीकी जांच सहित उनके कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना; और

(v) गाड़ियों को चलाने वाले तथा गाड़ियों को पास करने वाले कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देना।

रेलवे बोर्ड में अधिकारियों का स्थानांतरण

[हिन्दी]

*14. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के किसी कर्मचारी/अधिकारी को एक ही शाखा में तैनात रखने के लिए अधिकतम वर्षों की संख्या के बारे में कोई नियम/आदेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड इस नियम/आदेश का पूर्णतया पालन कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड कार्यालय में रेलवे ग्रुप "ए" सेवाओं के अधिकारियों की तैनाती 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर जहां प्रशासनिक हित में इनको बनाए रखना अपेक्षित होता है, रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और अनुभाग अधिकारियों को एक अनुभाग में 4-5 वर्षों तक कार्य करने के बाद वहां से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) सामान्यत: रेलवे ग्रुप "ए" के अधिकारियों के मामले में कार्यावधि सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जाता है। अनुभाग अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक सतत प्रक्रिया है जो प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

मारुति वाहनों की उत्पादन लागत

[अनुवाद]

*15. श्री भवानी शंकर होटा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग द्वारा निर्मित विभिन्न वाहनों की उत्पादन लागत कितनी है तथा इनका पृथक-पृथक बिक्री-मूल्य कितना है;

(ख) मारुति उद्योग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने वाहनों का उत्पादन किया गया तथा कितने-कितने वाहन सरकार तथा इसकी एजेन्सियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचे गए; और

(ग) इन्हीं वाहनों का अन्य देशों में बिक्री-मूल्य कितना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) अपने वाहनों के उत्पादन की लागत बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है। तथापि, वर्ष 1989-90 के दौरान प्रति वाहन शुद्ध औसत लाभ (कर-पूर्व) 2858 रुपये (शुद्ध ब्याज आय रहित) के लगभग था। विभिन्न मारुति वाहनों का मूल्य निम्नलिखित है :—

मॉडल	कारखाने से निकलते समय का मूल्य (उत्पाद शुल्क सहित)
कार स्टैण्डर्ड	रुपये 99,984.00
कार वातानुकूलित	रुपये 1,20,921.00
ओमनी	रुपये 1,00,194.00
ओमनी वातानुकूलित	रुपये 1,23,187.00
जिप्सी सॉफ्ट टॉप	रुपये 1,33,637.00
जिप्सी हार्ड टॉप	रुपये 1,45,591.00
जिप्सी वातानुकूलित	रुपये 1,71,006.00

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा सरकार को बेचे गए एवं अपने अभिकरणों को बेचे गए वाहनों के आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में उत्पादित एवं डी० जी० एस० एण्ड डी० रेट कान्ट्रैक्ट के तहत बेचे गए वाहनों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादित वाहनों की संख्या	डी० जी० एस० एण्ड डी० रेट कान्ट्रैक्ट के तहत बेचे गए वाहनों की संख्या
1987-88	92,630	1,770
1988-89	1,05,547	2,547
1989-90	1,17,521	2,744

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

मॉडल स्टेशन

*16. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और इनमें से कितने स्टेशन आदिवासी क्षेत्रों में हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात में कितने मॉडल स्टेशनों को मंजूरी दी गई और इनमें से कितने स्टेशनों का निर्माण पूरा हो गया तथा कितने स्टेशनों का निर्माण पूरा किया जाना शेष है; और

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्र में दाहोद स्टेशन को भी मॉडल स्टेशनों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए 67 स्टेशनों को चुना गया था। एक स्टेशन आदिवासी क्षेत्र में पड़ता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश में 7 स्टेशन और गुजरात में 3 स्टेशन चुने गये थे। मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक स्टेशन पर कार्य पूरा हो गया है।

(ग) जी नहीं।

सीमेंट की कालाबाजारी

[हिन्दी]

*17. श्री जनार्दन तिवारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ सीमेंट विक्रेताओं द्वारा सीमेंट की कालाबाजारी किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा दोषी पाये गए सीमेंट विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग के विकास के लिए विगत में सरकार द्वारा की गयी नीति संबंधी कई शुरुआतों के परिणामस्वरूप देश ने सीमेंट उत्पादन में लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है तदनुसार, तारीख 1-3-1989 से सीमेंट से पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया था। इस प्रकार इस समय सीमेंट के मूल्य व वितरण पर सरकार को कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। किंतु, खुदरा बिक्री के स्तर पर मुनाफाखोरी पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से सीमेंट व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करके आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि पर रोक लगाने की समय-समय पर सलाह दी गई है।

औषध उद्योग संघ आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

[अनुवाद]

*18. कुमारी उमा भारती : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 जून, 1990 को उद्योग संघों, औषध-विक्रेताओं तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा का ब्योरा क्या है और उसमें क्या निर्णय लिये गये;

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी; और

(घ) क्या मूल्य-नियंत्रण के प्रयोजनार्थ आवश्यक औषधों की श्रेणी के संबंध में कोई निर्णय लिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक के दौरान औषध नीति के संबंध में अनेक विषयों पर चर्चा की गई थी जिसमें अनेक इच्छुक वर्गों ने अपने विचार प्रस्तुत किए गे।

(ग) और (घ) बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। फिर भी, औषध नीति की समीक्षा करते समय, जो अभी प्रगति पर है, उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

एयरबस इण्डस्ट्री द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स को धमकी

*19. श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

श्री बक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस इंडस्ट्री ने इंडियन एयरलाइन्स को धमकी दी है कि इस समय टौलूज में "हैंगर" में खड़े ए-320 विमानों की डिलीवरी लेने का कोई आश्वासन न देने के कारण उसके विरुद्ध संविदा भंग का मुकदमा चलाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा लिए गये निर्णय का ब्यौरा है; और

(ग) क्या एयरबस इंडस्ट्री इस विमान में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) इंडियन एरलाइन्स ने ए-320 विमान-बेड़े के परिचालन में काफी खराबियां अनुभव की है। उसने बार-बार होने वाली इन खराबियों की समस्या को एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ उठाया है।

कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन

*20. श्री के० प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य मार्च, 1991 की निर्धारित तारीख के अनुसार पूरा हो जाएगा;

(ख) जोड़-खोल के कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं;

(ग) क्या इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) हालांकि लाइन को मार्च, 1991 तक चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा वन भूमि सौंपे जाने में विलम्ब, कुछ ठेकेदारों की विफलता श्रमिकों के बीमार पड़ने तथा इस वर्ष बेमौसमी वर्षा होने के कारण कुछ कार्य पिछड़ गए हैं।

(ख) परियोजना के कोरापुट-मचकुंडगुडा खंड को चालू कर दिया गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। जून, 1990 तक परियोजना पर हुए कार्य की समग्र प्रगति 63% है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा क्षमता में विस्तार किया जाना

1. श्री कैलाश मेघवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मनी में सुजुकी की मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है तथा निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इससे देश में रोजगार के अनुमानतः कितने अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

2. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के प्रभावशाली ढंग से उपयोग हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि नहीं, तो ऊर्जा की बचत एवं इसके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या वैकल्पिक कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ग) ऊर्जा के संरक्षण और इसके दक्षतापूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नीति में ये बातें शामिल हैं :—

(1) ऊर्जा के अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मांग-प्रबन्ध में बेहतर सुधार करना;

(2) ऊर्जा का संरक्षण करने और सभी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अपव्यय को रोकने हेतु सांविधिक अनिवार्यता सहित प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन सम्बन्धी एक प्रभावी प्रणाली लागू करना;

(3) विद्यमान विद्युत उत्पादन यूनिटों में से चयनित यूनिटों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता का बेहतर समुपयोजन करना;

(4) भार वक्र (लोड कर्व) को बराबरी पर लाने और विद्युत की व्यस्ततमकालीन मांग में कमी करने हेतु विद्युत के अधिक युक्तिसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना;

(5) विद्युत उत्पादन क्षमता और पारेषण एवं वितरण प्रणाली के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना;

(6) ऊर्जा के वैकल्पिक प्रकारों की सापेक्ष दुर्लभता दर्शाने वाली और निवेश की सम्भाव्यता को बढ़ाने वाली तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली मूल्य नीति तैयार करना; और

(7) तेल एवं तेल उत्पादों की खपत में कमी करने, विद्युत उत्पादन और सड़क एवं रेल परिवहन में ईंधन सम्बन्धी दक्षता को बढ़ाने तथा अधिक दक्षतापूर्ण ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने सम्बन्धी उपाय करना।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

करुणा मूलक आधार पर रोजगार

3. श्री सूबेदार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से जून, 1990 तक रेलवे में कुल कितने तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के, नैमित्तिक श्रमिक और अस्थायी कर्मचारी ड्यूटी के समय स्वाभाविक मौत और दुर्घटना के कारण मरे हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ग) इन मृतकों के परिवारों के कुल कितने आश्रितों को करुणा मूलक आधार पर रोजगार दिया गया और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति थे;

(घ) कितने मामलों में मृतकों के परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने मामले हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) जनवरी, 1988 से जून, 1990 तक की अवधि से सम्बन्धित सूचना रेलों/उत्पादन यूनिटों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[हिन्दी]

4. श्री राम सजीवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे, झांसी डिवीजन के बांदा सेक्शन पर चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान जीर्ण शीर्ण गोदाम हटाकर जन सुविधाओं के लिए एक नया प्लेटफार्म और एक ऊपरि पुल के निर्माण करने का विचार है;

(ख) क्या वर्तमान गोदाम के पश्चिम की ओर एक नये गोदाम का निर्माण करने का भी विचार है;

(ग) क्या नये प्लेटफार्म के प्रवेश और निर्गम स्थानों को उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्टेशनों के परिवर्धन/परिवर्तन से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर किये जाते हैं जो धन की उपलब्धता तथा अन्य स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। तदनुसार स्टेशन पर सुधार सम्बन्धी कतिपय निर्माण कार्य हाथ में हैं।

रेलवे की माल ढुलाई की वृद्धि दर

[अनुवाद]

5. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वित्तीय वर्षों (1988-89 और 1989-90) के दौरान रेलवे की माल ढुलाई की वृद्धि दर में कमी आई है;

(ख) इन दो वर्षों के दौरान माल ढुलाई की वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार का माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ चुने हुये माल की ढुलाई की दरों को कम करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1988-89 तथा 1989-90 में राजस्व उपार्जक माल यातायात की वृद्धि दर क्रमशः 4.08 प्रतिशत तथा 2.60 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) चुनिंदा कार्गो के लिये माल भाड़ा दर में आम कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षेत्रीय रेलों को जहां कहीं आवश्यक हो स्टेशन से स्टेशन तक घटी दरें निर्धारित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा की जा सके।

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन

[हिन्दी]

6. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किये जाने और कब तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी हां। खजुराहो, सतना और सिद्धि (सतना-रीवा को छोड़कर) के रास्ते ललितपुर और सिंगरौली और महोबा खजुराहो के बीच नयी बड़ी लाइन के लिए 1989-90 में अनुमोदित नया सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। आशा है, सर्वेक्षण कार्य जून, 1992 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टाटानगर और धनबाद के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

7. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार टाटानगर और धनबाद के बीच सीधी यात्री रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

लघु उद्योग एककों का समूह गठित करना

[हिन्दी]

8. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग एककों का एक समूह गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या लघु उद्योग एककों का समूह गठित करके इन लघु उद्योगों द्वारा निर्मित किसी विशेष उत्पाद को विशेष ब्राण्ड के अंतर्गत बेचा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सरकार को लघु औद्योगिक एककों का समूह बनाये जाने के बारे में किसी नये प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। किन्तु, एन० एस० आई० सी० ने इसी प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने वाले लघु उद्योगों की क्षमता और सामर्थ्य को एक करके और फिर उत्पादों को

निविदाओं व अन्य सामान्य माध्यमों के जरिये सरकारी विभागों और अन्य जरूरतमन्द क्षेत्रों में बेचकर लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन में पहले ही एक सहकारिता दृष्टिकोण अपना लिया है। इस विचार को हस्त-निर्मित कागज, लेखन-सामग्री, टापिओका स्टार्च, हौज़री,-पंखों, जी० एल० एस० लैम्प, टेलीविजन आदि के मामले में आजमाया गया है।

(ख) एक ही प्रकार के उत्पाद क्षेत्रों के लघु एककों के समूह को एक सहकारिता में बदलकर उत्पाद को एक सामान्य ब्रांड नाम से बेचा जा सकता है।

(ग) एन० एस० आई० सी० ने पूर्वी क्षेत्र में एन० आई० सी० ब्रांड नाम से उत्पादों की बिक्री करके पंखों, जी० एल० एस० लैम्प के लिए पूर्वी क्षेत्र में तथा हस्त-निर्मित कागज, टोपिओका स्टार्च, टेलीविजन के लिए दक्षिणी क्षेत्र में विपणन सहायता दी है।

इब ताप बिजलीघर

[अनुवाद]

9. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में इब ताप बिजलीघर को अन्यत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) 210-210 मेगावाट की चार यूनिटों वाली इब घाटी ताप विद्युत परियोजना का राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन किये जाने हेतु योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में स्वीकृति दी गई थी। यूनिट 1 एवं 2 क्रियान्वयनाधीन हैं। परियोजना के स्थल को बदले जाने के सम्बन्ध में प्राधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उन्नत किस्म के चूल्हों से सम्बन्धित कार्यक्रम

10. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत किस्म के चूल्हों से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुभारम्भ के पश्चात् ऐसे कितने चूल्हे लगाये गये हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने चूल्हे लगाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उन्नत चूल्हा कार्यक्रम दिसम्बर, 1983 में शुरू किया गया था और तब से मार्च, 1990 के अन्त तक पूरे देश में करीबन 84 लाख उन्नत चूल्हे लगाये जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 18.27 लाख उन्नत चूल्हे लगाने का लक्ष्य है।

पहलेजा से दिघा के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण

[हिन्दी]

11. श्री लाल बाबू राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने के लिए पहलेजा से दिघा (बिहार) के बीच गंगा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण कार्य के लिए एक योजना दो दशकों से लम्बित पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का, इस पुल का निकट भविष्य में निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पटना के निकट गंगा नदी पर रेल पुल के लिए इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है । परियोजना पर आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

केरल में रेलों में वाटरकूलर

[अनुवाद]

12. श्री ए० विजयराघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में किसी रेलगाड़ी में वाटरकूलर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिल्ली तथा नई दिल्ली से प्रारम्भ होने वाली कुछ गाड़ियों में परीक्षण के तौर पर जल शीतक लगाये गये थे, केरल की गाड़ियों सहित अन्य गाड़ियों में इस सुविधा का विस्तार करना इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जल शीतक किस तरह से काम करते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन कोयला खान क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई

13. श्री परसराम भारद्वाज : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कम्पनियों द्वारा कोयला खान क्षेत्रों में एकीकृत जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से तथा नलकूपों, पम्पों और कुंओं के माध्यम से पेय जल की सप्लाई हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कोयला खान क्षेत्रों में नियमित सप्लाई बंद होने की स्थिति में पेय जल की सप्लाई हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली की रेलवे कालोनियों में जन सुविधाएं

14. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत-सी रेलवे कालोनियों में पुराने और खाली मकान हैं और ऐसी कई कालोनियों में बिजली, सफाई, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पेय जल आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले में जांच कराने और सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

15. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक को ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला खानों से कोयले की सप्लाई में अकारण देरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) रायचुर ताप विद्युत गृह कुछ समय से कम कोयला के भंडारों के साथ परिचालन मे है। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के कोयले की आवश्यकताओं को पूर्णत: पूरा नहीं किया जा सकता है। अन्य कोयला क्षेत्रों से रेल, रेल-सह-समुद्र मार्गों तथा सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति करके इस कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी महीनों में इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के बारे में विवाद

16. श्री हाराधन राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयला खनन परियोजना के लिए भूमि अर्जन के बारे में विवाद थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के रानीगंज क्षेत्र में इन विवादों को हल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने वर्ष 1980-81 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत 5551.862 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 156 प्रस्ताव भेजे, जिसने उपमण्डल तथा जिला स्तर पर दो स्थलीय चयन समितियों का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने से पूर्व, जांच किए जाने के लिए गठन किया। दिनांक 2-8-1989 से स्थलीय चयन समितियों का गठन किए जाने से केवल दो मामलों का जो कि बंसरा (भाग) तथा सोनपुर बजारी (भाग) परियोजनाओं के प्रस्तावों के अंतर्गत आते थे, रानीगंज कोयला क्षेत्रों के अंतर्गत निपटाया गया है, जबकि सोनपुर बाजारी परियोजना के मामले में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण भूमि का वास्तविक कब्जा लिया जाना संभव नहीं हो सका। इस संबंध में मुख्य विवाद, पुनर्वास पैकेज को लेकर है, जिसको पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ सोनपुर बाजारी ओपनकास्ट परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के मामले में विचार-विमर्श किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया गया था और इस संबंध में आदेश 31-5-1990 को जारी किए गए थे।

तालचेर स्टेशन (उड़ीसा) को नया रूप देना

17. श्री रवि नारायण पाणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य के तालचेर स्टेशन को नया रूप देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस स्टेशन को नया रूप देने सम्बन्धी निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कागज संयंत्र को फिर से चालू करना

18. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से रुग्ण और बंद पड़ी दो कागज मिलों को, अर्थात् सेवा पेपर मिल, कोरापुट एण्ड टीटागढ़ पेपर मिल को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) जहां तक मैसर्स सेवा पेपर्स लि० का सम्बन्ध है, कम्पनी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखा है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 21 मई, 1990 को हुई सुनवाई में कंपनी को अधिनियम की धारा 3 (1) (ओ) के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने आई० एफ० सी० आई० को मैसर्स सेवा पेपर्स लि० के लिए एक पुनर्स्थापना/पुनः चालू करने की योजना तैयार करने के लिए संचालक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

जहां तक टीटागढ़ पेपर मिल्स का सम्बन्ध है, यह कम्पनी भी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है। जैसा अधिनियम में अपेक्षित है, कम्पनी ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को जून, 1987 में लिखा है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपनी अंतिम सुनवाई 3-7-1990 को की और अपने आदेशों को आरक्षित रखा।

सांची, मध्य प्रदेश के लिए विमान सेवाएं

[हिन्दी]

19. श्री राघव जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांची के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां पर पर्यटकों की सुविधा हेतु विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवाएं कब से शुरू कर दी जायेंगी तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) वायुदूत के पास उपलब्ध विमान क्षमता और अन्य संसाधनों को वजह से इस समय मध्य प्रदेश में नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

पैरेक्सीलीन के बारे में बी० आई० सी० पी० रिपोर्ट

[अनुवाद]

20. श्री सुधाम देशमुख : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1990 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "यूनिफा प्राइस, ओ० जी० एल० इम्पोर्ट फॉर पैरक्सीलीन लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें उल्लिखित बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और क्या सरकार का इसे सभा पटल पर रखने का विचार है; और

(ग) बी० आई० सी० पी० द्वारा इस संबंध में अब तक कितनी रिपोर्टें तैयार की गई हैं तथा क्या इन्हें सभा पटल पर रखा गया था और यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार को नोट कर लिया है। बी० आई० सी० पी० ने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। विभिन्न मदों के उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने हेतु बी० आई० सी० पी० जब भी आवश्यक होता है लागत अध्ययन करती है। ऐसी रिपोर्ट का उपयोग सरकार में निर्णय करने के लिए किया जाता है।

उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करना

21. श्री डी० अमात : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु किन प्रमुख निजी और सरकारी क्षेत्र के एककों ने जनवरी, 1990 के पश्चात् आवेदन किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उसकी नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उड़ीसा सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने लाइसेंस मंजूर किये गए ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 1-1-1990 से 31-7-1990 की अवधि के दौरान उड़ीसा में उद्योग लगाने के लिए 22 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन (राज्य सरकारी क्षेत्र से प्राप्त 3 को मिलाकर) प्राप्त हुए। इनमें से, दो आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा आशय पत्र मंजूर कर दिये गये हैं। शेष 20 आवेदनों में से, 5 अस्वीकृत कर दिये गये हैं और 15 प्रक्रिया के विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सरकार की नई औद्योगिक नीति अभी कार्यान्वित की जानी है।

गैस उपभोक्ताओं के लिए बीमा पालिसी

22. श्री राम मोहन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "थर्ड पार्टी बीमा" के बदले उपभोक्ताओं हेतु साधारण बीमा पालिसी शुरू करने के लिए विभिन्न रसोई गैस उपभोक्ता संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा से जमशेदपुर तक शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाया जाना

23. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा से जमशेदपुर (टाटानगर) तक शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भविष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए हावड़ा और जमशेदपुर (टाटानगर) के बीच खण्ड की पहचान की गई है। बहरहाल, संसाधनों की कमी और परिचालनिक तंगियों के कारण फिलहाल इस प्रकार की गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

केरल में कराप्परा और कुरियारकुट्टी पनबिजली परियोजनाएं

24. श्री टी० बशीर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत कराप्परा और कुरियार कुट्टी पनबिजली परियोजनाओं के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस निर्णय पर पुनः विचार करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) पर्यावरणीय सम्बन्धी कारणों से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय संबंधी प्रभाव के साथ-साथ पालघाट क्षेत्र की समग्र जल एवं विद्युत संबंधी आवश्यकता की जांच करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व से 1987 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। वर्ष 1989 में प्रस्तुत की गई

अपनी रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को इस परियोजना को नया रूप देना होगा। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् तकनीकी-आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना को स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विस्तार की योजना

25. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की इसका विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन प्रत्येक नई परियोजनाओं में कितनी-कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) 1990-91 से शुरू की जाने वाली विस्तार परियोजनाओं के लिए आई० पी० सी० एल० के प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

परियोजना	कुल अनुमानित लागत (रुपये/करोड़)
1. बड़ोदा कम्पलैक्स, गुजरात	
(1) बुटाडाइन एक्सट्रैक्सन प्लांट (रिवैम्प)	36
(2) पोली-बुटाडाइन रबर विस्तार	104
(3) प्रोपिप्रोपीलीन विस्तार	99
(4) इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स (संयुक्त उद्यम)	78
2. नागोथाने कम्पलैक्स, महाराष्ट्र	
(1) महाराष्ट्र गैस क्रैकर विस्तार	109
(2) एच० डी० पी० ई० संयंत्र विस्तार	93.5
(3) वायर एण्ड केबल कम्पाउंड (चरण-II)	28
3. गंधार पेट्रोकेमिकल कम्पलैक्स, गुजरात	2665

बिहार में गोबर गैस से बिजली का उत्पादन

[हिन्दी]

26. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में गोबर गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करके इस क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) गोबर गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इत्यादि जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए अनेक कार्यक्रमों को बिहार राज्य की नोडल एजेन्सी बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी के सहयोग से शुरू किया गया है। बायोगैस विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना को, जिसमें परिवार आकार के बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है, 1981-82 से बिहार में कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें उत्तरी बिहार भी शामिल है। 1990-91 के लिए बिहार राज्य में 5,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिस्त्रियों, तकनीशियनों, उपयोगकर्ताओं आदि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और केन्द्रीय आर्थिक सहायता तथा अन्य प्रोत्साहनों को देने के लिए उपाय किए गए हैं। पुसा, समस्तीपुर में एक प्रादेशिक बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्य कर रहा है। उत्तरी बिहार सहित बिहार राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया गया है।

राजस्थान में रसोई गैस एजेन्सियां

27. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रसोई गैस एजेन्सियां आबंटित की गईं;

(ख) क्या आबंटित एजेंसियों की आवधिक जांच की जाती है;

(ग) क्या राजस्थान में रसोई गैस एजेन्सियों में कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिले-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इस वर्ष कितनी गैस एजेन्सियां स्वीकृत करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में 47 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपे आबंटित की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन तेल कंपनियां जिलावार विवरण नहीं रखती हैं। सूचना एकत्र करने में निहित समय और श्रम वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होगा। प्राप्त सभी शिकायतों की जांच संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है तथा आवश्यक होने पर विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत उपचारी कारंवाई की जाती है।

(ङ) 31 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना तैयार की गई है। तथापि डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के पूर्व होने वाली विभिन्न कारंवाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं होगा कि उनमें से कितनी चालू वर्ष के दौरान आबंटित कर दी जायेंगी।

बम्बई और राजकोट के बीच विमान सेवा

[अनुवाद]

28. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बम्बई और राजकोट तथा बम्बई और जामनगर के बीच एक दैनिक उड़ान तथा राजकोट-उदयपुर और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें स्थगित कर दी हैं;

(ख) क्या इन सभी सैक्टरों पर अर्थक्षम संचालन के लिए पर्याप्त यातायात था; और

(ग) उपरोक्त सैक्टरों पर विमान सेवा पुन: आरम्भ करने के बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बम्बई-राजकोट-बम्बई और बम्बई-जामनगर-भुज-बम्बई सैक्टरों पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवा की आवृत्ति को घटा दिया गया है और दिल्ली-उदयपुर-राजकोट सेवा को बन्द कर दिया गया है।

(ख) बम्बई-राजकोट और बम्बई-जामनगर-भुज सैक्टरों पर उतना पर्याप्त यातायात है जितना परिचालनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये आवश्यक है।

(ग) ए-320 विमानों के परिचालन शुरू किये जाने पर उपलब्ध विमान क्षमता के साथ ही बन्द की गयी सेवा की आवृत्ति पुन: शुरू की जा सकेगी।

बम्बई हाई में तेल के लिए दूसरा टर्मिनल

29. डा० वेंकटेश काबडे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-हाई के दूसरे तेल टर्मिनल का निर्माण कार्य आरम्भ होने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस टर्मिनल से एक शाखा मराठवाड़ा और विदर्भ के पिछड़े क्षेत्र को उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मराठवाड़ा में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने के बारे में उनके मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) बम्बई अपतटीय क्षेत्र से उत्पादित तेल और गैस के स्थानांतरण के लिये दूसरे टर्मिनल का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यदि बम्बई अपतट से कच्चे तेल और गैस अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त हुई और दूसरे टर्मिनल की आवश्यकता प्रतीत हुई तो ऐसे प्रस्ताव पर सही समय पर विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले को विमान सेवा से जोड़ना

30. श्री हरि शंकर महाले :
　　श्री किसनराव बापूराव बानखेले :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कौन से जिलों को अब तक राज्य की राजधानी से विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या 1990-91 के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले को राज्य की राजधानी से विमान संपर्क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) महाराष्ट्र राज्य के 30 जिलों में से, नीचे दिये गये जिलों के लिये विमान सेवाएं नहीं हैं :—

अहमद नगर, अमरावती, बान्दरा, भीर बुलढाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जलगांव, जेलना, लतूर, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, थाने, तरभाना, वर्धा, यावतमाल ।

विमान क्षमता की कमी के कारण रत्नगिरी, शोलेपुर, नासिक और ओसमानाबाद के लिये वायुदूत की सेवाएं फिलहाल अस्थायी तौर पर बन्द कर दी गई हैं ।

(ख) से (घ) इण्डियन एयरलाइन्स को किसी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है । तथापि, वायुदूत ने नीचे दिए गये स्टेशनों को अपनी आगामी योजना में विमान सेवा से जोड़ने के लिये चुना है :—

चन्द्रपुर, जलगांव, लतूर, अमरावती और सांगली ।

अन्य जिलों में या तो इण्डियन एयरलाइन्स/वायुदूत द्वारा विमानों के प्रचालन करने योग्य हवाई अड्डे नहीं हैं अथवा हवाई अड्डे बिल्कुल ही नहीं हैं । प्रत्येक जिले मुख्यालय में हवाई अड्डे का निर्माण शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।

ढंलवा लोहे की स्लीपर प्लेटों को खरीदने की प्रणाली को कारगर बनाना

31. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले ढंलवा लोहे के स्लीपर खुली निविदा प्रणाली द्वारा खरीदे जाते थे, किन्तु अब इस प्रणाली को बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बदली गयी इस प्रणाली का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमित निविदाओं के कारण ढंलवा लोहे के स्लीपर प्लेटों की रेलवे को होने वाली सप्लाई के सम्बन्ध में कदाचारों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सही प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिये इस स्थिति की पुनरीक्षा करने का विचार है, ताकि रेलवे को ढंलवा लोहे के स्लीपरों की सप्लाई में बरती जाने वाली अनियमितताओं और कदाचारों को दूर किया जा सके ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां ।

(ख) केवल अपेक्षित सुविधाएं रखने वाली अनुमोदित पार्टियों/प्रतिष्ठित निर्माताओं को सीमित निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) और (घ) जी हां, दो व्यक्तियों से, जिन्होंने अपना पदनाम अथवा पता नहीं दिया है जिससे कि उनसे आगे पूछताछ की जा सके ।

(ङ) सी० आई० स्लीपर प्लेटों की खरीद की नीति की समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी उद्योग में विकास अवरुद्ध हो जाना

32. श्री राम नाईक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की खादी का उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है तथा इस बारे में समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी का उत्पादन इस प्रकार रहा है।

	(रु० करोड़ में)
1986-87	218.06
1987-88	227.51
1988-89	235.35

(ख) आने वाले वर्षों में खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/करने का विचार है :

(1) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिये गये ऋण बजट संबंधी सहायता से प्राप्त ब्याज मुक्त होते हैं।

(2) खुदरा बिक्री पर विभिन्न किस्म की खादी पर छूट उपलब्ध है।

(3) उत्पाद-शुल्क से छूट।

(4) के० वी० आई० सी० नये मॉडल के उन्नत चर्खों की व्यवस्था करता है।

(5) तकनीकी विशेषज्ञों का प्रावधान।

(6) खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन।

(7) बिक्री-केन्द्रों, चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से विपणन सहायता।

(8) के० वी० आई० सी० के बहु-विधा प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिये खादी कारीगरों को प्रशिक्षण।

खादी उत्पादन में सुधार और वृद्धि करने के लिए कदम उठाना एक सतत प्रक्रिया है।

पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

33. श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री नन्दलाल मीणा :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन जिलों को औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है;

(ख) ऐसे जिलों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वहां कितने उद्योग स्थापित किए गए और इन उद्योगों में से कितने उद्योग बन्द हो गए हैं; और

(ग) किसी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का क्या मानदण्ड है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) संलग्न विवरण-1, जिसमें देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या व नाम दिए गए हैं और संलग्न विवरण-2, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पिछड़े जिलों को जारी किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या दी गई है । आशय पत्र जारी होने के बाद उत्पादन आरम्भ करने से पहले औद्योगिक एककों के लिए अलग-अलग अवधि की एक परिपक्वता अवधि होती है । इन एककों के बन्द हो जाने के बारे में केन्द्र द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड ये हैं—प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन, जो इस बात पर निर्भर है कि वह जिला प्रधानतः खाद्यान्न/नकद फसल का उत्पादक है, कृषि कामगारों का आबादी में अनुपात, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों की वैकल्पिक संख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, आबादी के संबंध में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी के संबंध में रेल मार्ग की लम्बाई ।

विवरण-1

देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश (14)	—	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डपाह, करीमनगर, खम्मान, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नैल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम और वारंगल ।
बिहार (18)	—	भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामऊ, पुर्निया, सहरसा, संथाल परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादाह, गया, भोजपुर, बेगुसराय, मुंगेर, खगरिया और माधेपुर ।
गुजरात (11)	—	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, महसाना, पंचमहल, साबरकांठा, सुरेन्द्रनगर और डंग ।
हरियाणा (4)	—	भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ ।
केरल (7)	—	अलेप्पी, कनौनोर, मालापुर, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वायनाड और इदुक्की ।
कर्नाटक (11)	—	बेलगांव, बिदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और टुमकुर ।
मध्य प्रदेश (36)	—	बालाघाट, बस्तर, बेटुल, बिलासपुर, भींड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार देवास, गुना, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोने, मंडला, मंदसौर, मौरेना, नरसिमहापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर,

		रफनगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, सिवोनी, शाहजापुर, शिवपुरी, सिधी, सुरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और नया सेहोसी जिला।
महाराष्ट्र (14)	—	औरंगाबाद, भान्द्रा, भीर, बुलधाना, चन्द्रपुर, कोलाबा, धूलिया, जलगांव, नन्देड, ओसनाबाद, परभानी, रत्नागिरी, येओत्मल और गढ़चीरोली।
उड़ीसा (8)	—	बालासोर, बोलनगिर, धेनकनल, कालाहांडी, केओंझार, कोरापुट, मयूरभांज और फुलबनी।
पंजाब (5)	—	भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और संगरूर।
राजस्थान (16)	—	अलवर, बन्सवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, डुंगारपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू, झालवाड़, जोधपुर, नागपुर, सीकरी, सिरोही, टोंक और उदयपुर।
तमिलनाडु (9)	—	धर्मपुरा, कन्याकुमारी, मदुराई, नार्थ अरकोट, रामानाथपुरम, साउथ अरकोट, थानोबूरे, त्रिचूरपल्ली और पुदीकोटई जिला।
उत्तर प्रदेश (41)	—	अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायू, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मोराबाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्ना, उत्तर काशी, कानपुर, देहात, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुलतानपुर।
पं० बंगाल (13)	—	बंकुरा, बीभान, वर्धवान, कूच-बेहर, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मलदा, मिदनापुर, मुरशीदाबाद, नदिया, पुरूलिया और पं० डींजपुर।
असम	—	सम्पूर्ण राज्य
हिमाचल प्रदेश	—	सम्पूर्ण राज्य
जम्मू और कश्मीर	—	सम्पूर्ण राज्य
मणिपुर	—	सम्पूर्ण राज्य
मेघालय	—	सम्पूर्ण राज्य
नागालैण्ड	—	सम्पूर्ण राज्य
सिक्किम	—	सम्पूर्ण राज्य
त्रिपुरा	—	सम्पूर्ण राज्य
अरुणाचल प्रदेश	—	सम्पूर्ण राज्य

गोवा	—	सम्पूर्ण राज्य
मिजोरम	—	सम्पूर्ण राज्य
अण्डमान और निकोबार	—	सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश
दादर और नगर हवेली	—	सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश
दमन और दीव	—	सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश
पाण्डिचेरी	—	सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश
लक्षद्वीप	—	सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश

नोट : जिला/क्षेत्र वह जिला/क्षेत्र शामिल होगा जो इसके पुनर्गठन/से पूर्व 1-10-70 को विद्यमान था। इन जिलों में से निकाले गए क्षेत्र बाद में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र बने रहे।

विवरण-2

वर्ष 1987, 1988, और 1989 और 1990 (मई तक) के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1987		1988		1989		1990 (मई तक)	
		आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आ. प.	औ. ला.	आ. प.	औ. ला.	आ. पत्र	औ. ला.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	55	22	47	17	43	14	16	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	—	1	1	—	—
4.	असम	12	3	12	—	5	3	—	—
5.	बिहार	6	—	8	2	5	1	1	—
6.	दादर और नगर हवेली	3	2	2	2	4	—	1	—
7.	दमन और द्वीव	1	1	3	—	3	2	—	—
8.	गोवा	6	7	11	4	12	3	—	—
9.	गुजरात	25	26	36	15	68	16	18	8
10.	हरियाणा	13	5	10	4	14	5	3	1
11.	हिमाचल प्रदेश	22	3	25	2	17	4	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	जम्मू और कश्मीर	10	4	12	1	9	5	2	—
13.	कर्नाटक	37	14	21	8	17	10	8	3
14.	केरल	9	3	12	1	6	3	—	1
15.	मध्य प्रदेश	44	12	52	15	39	19	19	5
16.	महाराष्ट्र	62	20	89	25	80	21	41	8
17.	मणिपुर	—	—	3	1	5	—	—	1
18.	मेघालय	1	—	—	—	2	1	—	—
19.	मिजोरम	1	—	1	—	—	—	—	—
20.	नागालैण्ड	1	1	—	—	—	—	—	—
21.	उड़ीसा	8	4	7	1	13	—	2	—
22.	पाण्डिचेरी	12	1	7	4	6	4	3	1
23.	पंजाब	8	2	9	4	13	3	10	—
24.	राजस्थान	42	7	31	4	23	10	5	2
25.	सिक्किम	—	1	—	—	—	—		—
26.	तमिलनाडु	68	14	46	15	49	16	21	15
27.	त्रिपुरा	—	—	1	1	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	59	23	86	20	105	25	39	11
29.	प० बंगाल	25	9	15	6	13	7	1	3
30.	राज्य दर्शाया नहीं गया/ एक से अधिक राज्य	5	7	4	1	1	3	2	1
	योग	536	192	551	153	553	175	200	67

राष्ट्रीय एअरलाइंस कम्पनियों को लाभ/हानि

34. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री गंगा चरण लोधी :
श्री ए० विजय राघवन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और पवनहंस को हुए लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन सभी निगमों को अधिक लाभप्रद और कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए संगठनों को हुआ लाभ/हानि इस प्रकार थी :—

संगठन	1987-88	1988-89	1989-90 (करोड़ रुपयों में)
एयर इंडिया	(—43·41)	43.31	70.00*
इंडियन एयरलाइंस	30.10*	10.68*	(—20.10*)
वायुदूत	(—7.62)	(—8.47)	(—5.41)
पवन हंस लिमिटेड	(— 6.69)	(—4.94)**	(—)8.31**

*अनंतिम

**वर्ष 1988-89 के दौरान 1.99 करोड़ और वर्ष 1989-90 के दौरान 7.67 करोड़ रुपयों को निकालने के बाद, जिनकी आगे व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ख) इन संगठनों की कार्य कुशलता और लाभकारिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उन्हें कार्य करने की अधिक स्वायतत्ता प्रदान करना।
2. यातायात की मांग के अनुरूप विमानों की समयावली निश्चित करना और यात्री/समग्र भार गुणक में वृद्धि करना।
3. आन-टाइम निष्पादनों का बारीकी से निरीक्षण करना।
4. यात्रियों के आरक्षण, चैक-इन, उड़ान-सूचना, सामान हैण्डलिंग, खान-पान आदि के क्षेत्र में यात्री सेवाओं में सुधार।
5. वायुदूत को अधिक क्षमता वाले विमानों द्वारा मध्यम और लम्बी दूरी के प्रचालनों की अनुमति देकर कम दूरी वाले खर्चीले क्षेत्रों में होने वाले घाटों को कम करने का प्रस्ताव किया गया है।
6. वायुदूत से यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने मार्ग संरचना का पुनर्गठन करे और अपने नेटवर्क को फैलाने के बदले सुदृढ़ बनाएं।
7. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ परामर्श करके पवन हंस लिमिटेड के कार्य-कलापों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

दैनिक यात्रियों को रेल पास की सुविधा

[हिन्दी]

35. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल मगध एक्सप्रेस में अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों को रेल पास की सुविधा देती है;

(ख) क्या बिहार में बक्सर से पटना के लिए दैनिक यात्रियों को मगध एक्सप्रेस में रेल पास सुविधा नहीं दी जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बक्सर और पटना के बीच दैनिक यात्रियों को रेल पास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सीजन टिकट धारियों को अलीगढ़ से दिल्ली तक मगध एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने की अनुमति है ।

(ख) गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण सीजन टिकट धारियों को बक्सर और पटना के बीच मगध एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं है ।

(ग) और (घ) जी नहीं, चूंकि इससे लंबी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी जो कि वांछनीय नहीं है और बक्सर और पटना के बीच दैनिक यात्रियों के लिए वैकल्पिक गाड़ियां उपलब्ध हैं ।

मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवायें

36. **श्री रेशम लाल जांगड़े :** क्या **नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर, जगदलपुर और अन्य मार्गों पर वायुदूत सेवायें मई, 1990 से अब तक प्रत्येक माह नियमित थीं और यदि नहीं, तो कितने दिनों तक इनका संचालन नहीं हुआ;

(ख) उपर्युक्त मार्गों पर उक्त अवधि के दौरान वायुदूत सेवा का संचालन किन सप्ताहों में प्रतिदिन हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन सप्ताहों में भोपाल अथवा दिल्ली के लिए निर्धारित वायुदूत के विमानों ने उसी दिन उतरने के तत्काल बाद जबलपुर अथवा रायपुर के लिए उड़ानें भरीं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वायुदूत भोपाल बेस से सप्ताह में छ: दिन अपनी सेवाएं परिचालित करता है। तथापि, विमान की अनुपलब्धता के कारण 12-7-90 से 29-7-90 तक की अवधि के दौरान कोई उड़ान परिचालित न हो सकी । 1 मई, 1990 से 11-7-90 और 30 से 31 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान दिनों की संख्या, जब उड़ानें रद्द की गईं, निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	उड़ान	दिनों की संख्या
1.	भोपाल-रीवा-सतना-खुजराहो और वापसी	5
2.	भोपाल-जबलपुर-रायपुर- जगदलपुर और वापसी	3
3.	भोपाल-इंदौर-जयपुर और वापसी	4
4.	भोपाल-जबलपुर-बिलासपुर-रायपुर-नागपुर और वापसी	3
5.	भोपाल-गुना-दिल्ली और वापसी	3

(ग) निम्नलिखित अवधियों के दौरान अवतरण के तत्काल पश्चात् उसी दिन भोपाल से जबलपुर और रायपुर के लिए उड़ानें परिचालित की गईं :—

1 से 5 मई, 1990

9 से 12 मई, 1990

14 से 31 मई, 1990

1 से 21 जून, 1990

23 से 29 जून, 1990

8 से 11 जुलाई, 1990

30 से 31 जुलाई, 1990

हरियाणा में पेट्रोल/डीजल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां

37. **श्री कपिल देव शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में रसोई गैस की एजेंसियां, पेट्रोल एवं डीजल पम्प आबंटित करने के लिए कुछ और अधिक स्थानों का सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां आबंटित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) स्थान-वार किन-किन एजेंसियों और डीलरशिपों का विज्ञापन निकालने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार उक्त एजेंसियों की डीलरशिप आबंटित करते समय अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को वरीयता देगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विकास करने हेतु स्थानों का पता लगाने के लिए तेल उद्योग द्वारा आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(ख) तेल विपणन कंपनियां सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड से प्राप्त हुई सिफारिशों के आधार पर पेट्रोल/डीजल के डीलरों की नियुक्ति करती है। आयु शैक्षिक योग्यता, निवास श्रेणी, आयु आदि सम्बन्धी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन करते समय तेल चयन बोर्ड निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है :—

(i) व्यक्तित्व

(ii) व्यापारिक योग्यता/सिल्समैनशिप

(iii) वित्त का प्रबन्ध करने की क्षमता और सुविधाएं मुहैया कराने का सामर्थ्य

(iv) पूरे समय डीलर के रूप में कार्य करने की तत्परता; और

(v) सामान्य आकलन और अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियां

(ग) पहले ही आयोजनागत खुदरा बिक्री केन्द्रों में से समालखा में केवल एक खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए विज्ञापन दिया जाना है।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्र/एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के सम्बन्ध में मौजूदा नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अपेक्षित योग्यता रखने वाले शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त कर सकते हैं हालांकि उन्हें कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

हावड़ा और नैहाटी के बीच यात्री गाड़ी सेवा

[अनुवाद]

38. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के हावड़ा और नैहाटी के बीच एक यात्री रेलगाड़ी सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यह यात्री सेवा आरम्भ न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गयी है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और ई० एम० यू० स्टाक की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

नोपाड़ा-गुनुपुर रेल लाइन पुनः चालू करना

39. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आए तूफान के कारण नौपाडा-गुनुपुर छोटी रेल लाइन को कितनी क्षति हुई;

(ख) इस लाइन के मरम्मत-कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस लाइन में रेलगाड़ियां पुनः चलाने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नौपाडा-गुनुपुर खंड पर 11-5-90 को काशीनगर और लुहुरी पी० एच० के बीच तटबंध में दरार पड़ गई थी जिसके कारण लगभग 15,000 रुपये की क्षति हुई।

(ख) और (ग) तटबंध की पहले ही मरम्मत कर दी गई है और 14-5-90 को लाइन पुनः चालू कर दी गयी थी।

इंडियन एयरलाइंस में भर्ती

40. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ए-320 विमानों की उड़ानें स्थगित किये जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस में नयी भर्ती पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो ए-320 विमानों का संचालन करने वाले कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है; और

(ग) इन्डियन एयरलाइंस इन कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) क्योंकि इंडियन एयरलाइंस ए-320 विमानों के परिचालनों को बन्द करने के कारण भारी हानि उठा रही थी, अतः मई, 1990 में यह निर्णय किया गया था कि किसी पद का सृजन न किया जाये और कोई नयी भर्ती न की जाए। तथापि, इस शर्त में उस समय छूट दी जा सकेगी यदि पद का भरा जाना परिचालनों की संरक्षा, यात्रियों की सुविधा अथवा अन्य अनिवार्य कारणों से इनके हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

कोयम्बटूर से मद्रास के लिए विमान सेवा

41. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर से मद्रास होकर बंगलौर जाने वाली विमान सेवाओं की संख्या को सात दिन से घटाकर सप्ताह में तीन दिन कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण और औचित्य है; और

(ग) उक्त वायुमार्ग पर विमान सेवाएं पुनः सात दिन चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) ए-320 विमानों के परिचालनों को बन्द करने के परिणामस्वरूप विमान क्षमता की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स ने मद्रास-बंगलूर-कोयम्बटूर सेवा की दैनिक आवृत्ति को घटाकर सप्ताह में चार बार की सेवा कर दिया है।

(ग) ए-320 परिचालनों के पुनः शुरू किये जाने के बाद, पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने पर ही बन्द की गई आवृत्ति को पुनः बहाल किया जा सकेगा।

राज्यों में "डबल बैरल कनेक्शन" जारी करना

[हिन्दी]

42. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में "डबल बैरल कनेक्शन" जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) एल० पी० जी० वितरकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे वार्षिक नामांकन के अनुसार उपभोक्ताओं को डबल बॉटल कनैक्शन (डीबीसी) जारी करें। ऐसे कनैक्शन जारी करने के लिए कम आपूर्ति वाले मार्गों के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, जब एल० पी० जी० की आपूर्ति में रुकावट होती है तो नये डबल बॉटल कनैक्शनों को जारी किया जाना स्थिति के सामान्य होने तक अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है।

नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच कुछ नई रेलगाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

43. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

श्री पी० सी० थामस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बारहों महीने यात्रियों की अत्यधिक भीड़ रहती है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इस रूट पर कुछ नई रेलगाड़ियां चलाकर अथवा इस रेलगाड़ी में पर्याप्त संख्या में सवारी डिब्बे जोड़कर यात्रियों की परेशानियों को कम करने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) केरल एक्सप्रेस बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है जिसमें सामान्यतः आरक्षित स्थानों का पूरा उपयोग होता है तथा कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ख) और (ग) दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 1-5-90 से जम्मू तवी-मंगलोर/तिरुच्चिरापल्ली के बीच (बरास्ता निजामुद्दीन) एक नई साप्ताहिक गाड़ी नवयुग एक्सप्रेस चलाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

करजान और मोती कोरल के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को पुनः चलाना

[हिन्दी]

44. श्री काशीराम छबीलदास राणा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी रेल लाइन पर करजान और मोती कोरल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को बन्द करने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और इस रेलगाड़ी को पुनः चलाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मियागाम करजण तथा मोती कोरल के बीच चल रही दो जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 193/194 तथा 233/234 मिश्रित गाड़ियां किसान आंदोलन के कारण मार्च, 1987 में रद्द कर दी गई थीं। यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए 233/234 मिश्रित गाड़ी को पुनः चला दिया गया था तथा उसका नम्बर बदलकर 421/422 कर दिया गया था। गाड़ियों की यह जोड़ी मियागाम करजण तथा मोती कोरल के बीच यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती है। दूसरी गाड़ी को पुनः चलाना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है।

लाइसेन्स-मुक्त उद्योग

[अनुवाद]

45. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लाइसेंस से मुक्त किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : लाइसेंसमुक्त पंजीकरण योजना के अधीन गैर-एम०आर० टी० पी०/गैर-फेरा कंपनियों के लिए और एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियों के लिए लाइसेंस मुक्त किये गये उद्योगों की सूचियां क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गयी हैं।

विवरण-1

बल्क औषधियों और इनके निरूपणों सहित गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर-फेरा कंपनियों के लिए लाइसेन्स मुक्त किए गए उद्योगों की सूची

1. लोहे की ढली वस्तुएं अर्थात् विशेष मिश्रधातु लोहे की ढली वस्तुएं, धातुवर्ध्य लोहे की ढली वस्तुएं और एस० जी० लोहे की ढली वस्तुएं, स्पंज लोहा और पेलेटाइजेशन।

2. विद्युत चाप (आर्क) भट्टी में इस्पात गलाकर इस्पात के ढांचों को विंडो सेक्शन, टेलिग्राफिक चैनल, लिफ्ट रेल आदि जैसे रोल्ड उत्पादों में तबदील करना जिन्हें सामान्यतया हल्के ढांचों के रूप में जाना जाता है, के अलावा इस्पात के ढांचे।

3. वैद्युत उपकरण :—

(क) सौर, वायु-शक्ति, बायो गैस सहित बायो-गैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति और समुद्र शक्ति जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने वाले उपकरण।

(ख) 20 एम० डब्लू० और कम के स्टीम टरबाइन और मिनी माइक्रो हाइडेल प्रणालियां, उपकरण।

(ग) पावर और डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर कैपासिटर, स्विच गैयर, वैद्युत मोटर और जी० एल० एस० लैम्प।

(घ) डीजल जनित्रण सेट।

4. इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे।

5. आटोमोटिव सहायक-सामान।

6. साइकिलें।

7. रबड़ मशीनें, छपाई मशीनें, जूते की मशीनें, मांस और मुर्गी पालन सम्बन्धी मशीनों सहित औद्योगिक मशीनें।

8. मशीनी औजार।

9. कृषि सामान।

10. विविध मैकेनिकल और इंजीनियरी उद्योग :—

(क) प्लास्टिक मोल्डेड वस्तुएं,

(ख) हाथ के औजार, छोटे औजार और काटने के औजार,

(ग) प्रेशर कुकर, कटलरी और स्टील फर्नीचर,

(घ) सभी प्रकार की लालटेनें,

(ङ) ईंधन बचाने वाले स्टोव,

(च) 10 सेंटीमीटर से बड़े वाटर पम्प।

11. औद्योगिक सिलाई की मशीनें।

12. निम्नलिखित कार्यालय उपकरण :

(1) गुणन और पुनः उत्पादन उपकरण,

(2) वर्ड प्रोसेसर,

(3) कैश रजिस्टर/बीजक मशीनें,

(4) डिक्टाफोन,

(5) माइक्रो-फिल्मिंग/माइक्रो फिशरीडर।

13. सर्जिकल, औद्योगिक और वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट।

14. औद्योगिक और चिकित्सा गैसें।

15. निम्नलिखित औषधियां/अन्तर्वर्ती औषधियां :—

रिफामपिसीन

डैपसोन

क्लोफाजाइमीन

प्राइमाक्वीन

ई० एम० एम० ई० (ययेक्सी मेथिलीन मैलोनिक इस्टर)

नेवेलडाइमीन

इंसुलीन

कैंसर रोधी औषधियां

विटामिन बी 6

नोरेजेस्ट्रल

पिपैरेजिन

स्वदेशी अनुसंधान द्वारा विकसित नई बल्क औषधियां

16. कागज और लुगदी—

(क) कृषि अवशेष, रद्दी और खोई से लिखने, छापने और लपेटने का कागज,

(ख) बिनौले पर के छोटे रेशे की लुगदी।

17. डिब्बा बंद फल और वनस्पति उत्पाद, प्रोटीन और संसाधित खाद्य, वनस्पति पर आधारित दूध छुड़ाने के खाद्य, समुद्री उत्पाद और मवेशियों का चारा।

18. वनस्पति तेल—

(क) बिनौलों को छोड़कर छोटे बीजों से तेल/खली को निचोड़ने का विलायक (सालवेंट)

(ख) धान की भूसी का तेल।

19. साबुन और श्रृंगार-सामग्री—

(क) साबुन, श्रृंगार सामग्री, इत्र और प्रसाधन सामग्री।

(ख) आई० एस० आई० मानकों के डिटरजेंट।

20. चमड़े की वस्तुएं।

21. शल्य और औषधीय रबड़ उत्पाद।

22. कांच का सामान।

23. मिट्टी का सामान—

(क) रिफ्रैक्ट्रीज और फर्नेस लाइनिंग ईंटें।

(ख) चीनी मिट्टी पॉटरी और सफाई का सामान।

(ग) एच० टी० इन्सुलेटर

(घ) टाइलें

(ङ) ग्रैफाइट मृत्तिका।

24. इन्सुलेटिंग बोर्ड जिप्सम बोर्ड, दीवार बोर्ड और अन्य।

25. लिथो छपाई सहित छपाई।

26. रोलर आटा चक्की उद्योग।

27. रसायन उद्योग—

1. रिकवरी रूट से एल्यूमिनियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट 2. ब्रोमिन 3. लोह/फेरिक नमक (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित के अलावा) 4. हाइड्रोजन परऑक्साइड 5. मैगनीशियम नमक (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित के अलावा) 6. सोडा राख (मानक विलायक प्रक्रिया) 7. फार्मेट रूट से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	अकार्बनिक भारी रसायन
8. टिटेनियम डाइआक्साइड (ऐनाटेज और रूटाइल दोनों ग्रेड) 9. कैस्टर तेलों पर आधारित रसायन 10. फुरफुरल 11. मैटाफिमाक्सी	कार्बनिक भारी रसायन

12. बेंजिलडिहाइड
13. मेथेनल
14. पेंटाइरीथ्रिटोल

फोटोग्राफिक रसायन सहित बढ़िया रसायन विविध रसायन:

15. फिनोल और एसेटोन पर आधारित रसायन
16. नपथेफेट, आक्टोएट, लिनोलिएट, आदि जैसे शोषी रंग
17. कम्पनी की विनिर्माण प्रक्रिया में निकलने वाले गंदे पानी/ठोस अवशेष/गैसीय स्राव से प्राप्त रसायन
18. सह-उत्पादों अथवा उप-उत्पादों के रूप में प्राप्त रसायन

28. कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग
29. औषध उद्योग :
 1. एस्पिरिन
 2. डाइगोएक्सीन
 3. लाइड्रोक्लोथायाराइज़ड
 4. आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड
 5. थाइएसेटाजीन
 6. तुलब्यूटामाइड

पैरा एमिनो सैलिसाइक्लिक एसिड (पी० ए०एस०) और नमक:

 7. पी० ए० एस० एसिड
 8. पी० ए० एस० सोडियम
 9. कैलिशियम पी० ए० एस०
 10. कैलिशियम बी०पी०ए०एस०

 11. क्लोरऐम्फेनिकॉल
 12. अमीडियाक्वीन
 13. क्लोरोक्वीन
 14. डिएथिल कार्बामाइजीन साइट्रेट
 15. फूरूसेमाइड
 16. ग्लिसरीन ट्राइनट्रेट
 17. थलिल सल्फाथायोजोल
 18. प्रिडिनसोलीन
 19. ईथर एनाएस्थेटिक
 20. हैलीथीन

21. थयोपेंटल
22. लीडोकाइन
23. प्रोकेन
24. नाइट्रस आक्साइड
25. इबुप्रोफन
26. क्लोरफिनिमाइन
27. ऐपिनेफीन
28. मेर्बेंटाजोल
29. बिफैनियम हाइड्रोक्सी नेफ्थएट
30. मेट्रोओनिडाजोल
31. एमपिसीलीन
32. सल्फामेथोक्साजोल
33. ट्राइमेथोपरीन
34. एरिथोसीन
35. एथम्बुटोल
36. पिराजिनमाइड
37. ग्राइसेओपुलवीन
38. हाइड्राक्सी कोबालामीन/साइनेकोबालामीन
39. डेक्सट्रान
40. आइसोसोरबाइड डाइनट्रेट
41. प्रोपरा-नोलाल
42. वेरापामिल
43. हाइजलाइजीन
44. मेथाइल डोप
45. नियोमाइसीन
46. बैसिट्रासीन
47. बीटामैथासोन
48. बेंजोइल बेंजोएट
49. सल्फा-सिटामाइड'
50. पिलोकारपीन

51. होमाट्रोपीन
52. क्लोरहेक्सिडीन
53. केट्रिमाइड
54. पैराक्लोर मैटाक्लीसेनोल
55. प्रोमेथाजीन
56. डेक्सामेथासोन
57. एथीनाइल एस्ट्रोटिओल
58. नोरेथिसटरीन
59. ग्लाइबेंकलामाइड
60. क्लोरपरोपामाइड
61. निओस्टिगामाइन
62. सुएक्सोमथीनियम सक्सीनाइल कोलीन क्लोराइड
63. एरगोमेट्रीन/मेथाइल एरगोमेट्रीन
64. आक्सीटोसीन
65. एमिट्रिपोटिलीन
66. इमिपरामीन
67. टरिलओपेराजीन
68. एमिनोफ्लीन/थीओफ्लीन
69. सलबुटामोल
70. एफीड्रीन
71. विटामिन ए
72. विटामिन डी
73. विटामिन सी
74. पैनटोथनेट
75. फैरस साल्ट
76. क्लोरपरोमाइजीन
77. हाइड्रोक्सेक्सीन.थीओफिलीन
78. डेक्सीसाइक्लीन
79. डाइजीपाम
80. सेफैलेएक्सीन

81. सेफैराडीन

82. सेफैलोराइडीन

30. वॉयर ड्राईंग उद्योग

31. ऑटोमोबील टॉयर और ट्यूब उद्योग

विवरण-2

एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त किए गए पिछड़े क्षेत्रों के लिए उद्योगों की सूची

भाग 1—(केन्द्र द्वारा घोषित किसी पिछड़े देश में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस मुक्त किए गए परिशिष्ट – 1 उद्योग)

1. कच्चा लोहा।
2. ढली और गढ़ी वस्तुएं।
3. वैकल्पिक ऊर्जा के साधन और प्रणालियां।
4. ट्रांसमिशन लाइन टावर।
5. स्टार्टर सहित वैद्युत मोटरें।
6. आन्तरिक दहन इंजन।
7. इलैक्ट्रानिक उपकरण।
8. आटोमोटिव उपकरण, पुर्जे और सहायक सामान।
9. प्रदूषण नियंत्रक उपकरण।
10. प्रक्रिया पम्प।
11. अवशेष के पुनः उपयोग के लिए प्रक्रिया उपकरण।
12. रसायन प्रक्रिया संयंत्र।
13. रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित मशीनें :—
    (क) रूपटर डिस्कें
    (ख) विशेष वायवीय अंशांक
    (ग) कार्बेट पम्प
    (घ) अपकेन्द्रिक गैस कम्प्रेसर
14. वायु कम्प्रेशर
15. औद्योगिक वाल्व
16. डेरी उद्योग के उपकरण अर्थात समस्थितिकरण यंत्र
17. मशीन के औजार
18. औजार कक्ष उत्पाद

19. खनिज तेल/प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग और उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनरी
20. विशेष रूप से तेल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता सहित एककों के लिए 10,000 डी० डब्लू० टी० क्षमता वाले यन्त्रीकृत पालयुक्त जहाज
2 . स्पंज लोहा और पौलेटाइजेशन
22. 20 मेगावाट और कम की स्टीम टरबाइनें और मिनी माइक्रो हाइडेल प्रणालियां/उपकरण।
23. पावर और डिट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर केपिसीटर और स्विच गेयर
24. डीजल जनित्रण सेट
25. इलैक्ट्रानिक उपकरण
26. औद्योगिक मशीनें
27. प्लास्टिक मोल्डेड वस्तुएं
28. (क) जिगें, फिक्सचर, औजार और विशेष प्रकार की डाइयां और कासलेंड टूलिंग
    (ख) कटिंग, और फार्मिंग टूल, पद्धति और डाइयां एवं खनन के औजारों जैसे इंजीनियरिंग उत्पादन के साधन।
29. आंतरिक कंबसशन इंजनों पर आधारित 10 सेंटी मीटर से कम के वाटर पम्प
30. उच्च प्रौद्योगिक पुनरुत्पादन और गुणन उपकरण
31. वर्ड प्रोसेसर
32. इलैक्ट्रानिक रजिस्टर/बीजक मशीनें
33. डिक्टाफोन
34. माइक्रो फिल्मिंग/माइक्रो फिश रीडर
35. स्ट्रीलाईजरों, इनक्यूबेटरों जैसे शल्य चिकित्सा के उपकरण
36. जल मीटर, भाप मीटर, वैद्युत मीटर आदि
37. वैज्ञानिक उपकरण
38. चिकित्सा गैसें
39. (क) बड़ी मात्रा में तरल नाइट्रोजन, कार्बन डायोक्साइड आदि जैसी प्रशीतकर (रेफरीजरेंट) गैसें
    (ख) आर्गन और अन्य दुर्लभ गैसें
    (ग) औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिए टनमान संयंत्र।
40. कृषि अवशेष, रद्दी और खोई से लिखने, छापने और लपेटने का कागज
41. बिनौले पर के छोटे रेशे की लुगदी
42. वनस्पति तेल :—

(क) बिनौलों को छोड़कर छोटे बीजों से तेल/खली को निचोड़ने का विलायक साल्वेंट

(ख) धान की भूसी का तेल।

43. आई० एस० आई० मानकों के डिटर्जेन्ट

44. रिफ्रैक्ट्रीज और फर्नेस लाइनिंग ईंटें

45. एच० टी० इन्सुलेटर।

46. ग्रेफाइट मृतिका।

47. जिप्सम बोर्ड, दीवार बोर्ड और अन्य।

48. डिब्बा बन्द फल और वनस्पति उत्पाद, प्रोटीन और संसाधित खाद्य वनस्पति पर आधारित दूध छुड़ाने के खाद्य समुद्री उत्पाद और मवेशियों का चारा।

49. ऑटोमोबील टॉयर और ट्यूब उद्योग।

चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

[हिन्दी]

46. श्री मगनलाल मीणा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में किन-किन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के अन्तर्गत किन्हीं सब-डिवीजनों को अलग से औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आदिवासी-बहुल प्रतापगढ़ सब-डिवीजन को चित्तौड़गढ़ जिले में औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार है?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़े माने गए जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसमें आदिवासी जिले/क्षेत्र शामिल हैं। चूंकि जिला चित्तौड़गढ़ मानदण्ड पूरे नहीं करता था, इसलिए इसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया गया था। इस समय किसी और जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश (14)	—	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डपाह, करीमनगर, खम्मान, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नैल्लौर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम और वारंगल।
बिहार (18)	—	भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामऊ, पुर्निया, सहरसा, संथाल परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगुसराय, मुंगेर, खगरिया और माधेपुर।
गुजरात (11)	—	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, महसाना, पंचमहल, साबरकांठा, सुरेन्द्रनगर और डंग।

हरियाणा (4)	—	भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ ।
केरल (7)	—	अलेप्पी, कनोनौर, मालापुरम्, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वायनाद और इडुक्की ।
कर्नाटक (11)	—	बेलगांव, बिदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और टुमकुर ।
मध्य प्रदेश (36)	—	बालाघाट, बस्तर, बेटूल, बिलासपुर, भींड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होसंगाबाद, झाबुआ, खरगोने, मंडला, मंदसौर, मौरेना, नरसिमहापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रजनगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, सिवोनी, शाहजापुर, शिवपुरी, सिधी, सुरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और नया सेहोसी जिला ।
महाराष्ट्र (14)	—	औरंगाबाद, भान्डा, बिमीर, बुलधाना, चन्द्रपुर, कोलाबा, धूलिया, जलगांव, नन्देड़, ओसमाबाद, परभानी, रत्नागिरी, येओतमल और गढ़चीरोली ।
उड़ीसा (8)	—	बालासौर, बोलनगिर, ढेनकनल, कालाहांडी, केओनझार, कोरापुट, मयूरभांज और फुलबनी ।
पंजाब (5)	—	भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और संगरूर ।
राजस्थान (16)	—	अलवर, बन्सवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, डुंगारपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू, झालवाड़, जोधपुर, नागपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर ।
तमिलनाडु (9)	—	धर्मपुरा, कन्याकुमारी, मधुराई, नार्थ अरकोट, रामानाहपुरम, साउथ अरकोट, थानोवूरे, त्रिचूपल्ली और पुदीक्कोटई जिला ।
उत्तर प्रदेश (41)	—	अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवारिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, ऊना, उत्तर काशी, कानपुर, देहात, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, और ननीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुलतानपुर ।
प० बंगाल (13)	—	बँकुरा, बीरभान, बर्धमान, कूच-बेहर, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मलदा, मिदनापुर, मुरशीदाबाद, नदिया, पुरुलिया, और पं० दीनपुर ।
असम	—	सम्पूर्ण राज्य

हिमाचल प्रदेश	—	सम्पूर्ण राज्य
जम्मू और कश्मीर	—	सम्पूर्ण राज्य
मणिपुर	—	सम्पूर्ण राज्य
मेघालय	—	सम्पूर्ण राज्य
नागालैंड	—	सम्पूर्ण राज्य
सिक्किम	—	सम्पूर्ण राज्य
त्रिपुरा	—	सम्पूर्ण राज्य
अरुणाचल प्रदेश	—	सम्पूर्ण राज्य
गोवा	—	सम्पूर्ण राज्य
मिजोरम	—	सम्पूर्ण राज्य
अण्डमान और निकोबार	—	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
दादर और नगर हवेली	—	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
दमन और द्वीव	—	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
पाण्डिचेरी	—	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
लक्षद्वीप	—	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र

नोट — जिला/क्षेत्र में वह जिला/क्षेत्र शामिल होगा जो इसके पुनर्गठन से पूर्व 1-10-70 को विद्यमान था। इन जिलों में से निकाले गए क्षेत्र बाद में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र बने रहे।

गोआ-दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सेवा में सुधार

[अनुवाद]

47. प्रो० गोपालराव मायकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी आरंभ की गयी गोआ-दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी के सम्बन्ध में जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ख) क्या सरकार को इसकी सेवा में सुधार के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गोवा-दिल्ली एक्सप्रेस में स्थान ग्रहण का उपयोग सन्तोषजनक है।

(ख) जी हां।

(ग) पेंट्री कार की व्यवस्था करने, कुछ और अधिक मार्गवर्ती स्टेशनों पर ठहरावों की व्यवस्था करने, सतारा में कोटा बढ़ाने, सानवोरडेम में कोटा आबंटित करने और गोआ एक्सप्रेस के लिए कोल्हापुर से मिरज तक मेल लेने वाली गाड़ी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं। सतारा में कोटा बढ़ाने और सानवोरडेम में कोटा आबंटित करने के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव कार्यान्वित कर दिए गए हैं लेकिन अन्य सुविधाओं की फिलहाल व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

अमीरात द्वारा त्रिवेन्द्रम के लिये विमान सेवा

48. श्री सुरेश कोडीकुन्नील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के किन्हीं देशों ने भारत सरकार से त्रिवेन्द्रम तक विमान सेवा शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमीरात को त्रिवेन्द्रम तक के लिये विमान सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) कतार, बहरीन और यू० ए० ई० की सरकारों ने त्रिवेन्द्रम से और त्रिवेन्द्रम के लिये उड़ानें परिचालित करने हेतु उनकी एयरलाइनों को अनुमति देने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया है। तथापि, इनकी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि मौजूदा द्विपक्षीय हवाई सेवा व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त एयरलाइनों को त्रिवेन्द्रम "प्वाइण्ट ऑफ काल" के रूप में उपलब्ध नहीं है।

मुम्बई से केरल विमान उड़ान

49. श्री पी० सी० थामस : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई से केरल तक क्रमशः वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान, विमान द्वारा कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) इनमें से कितने यात्री विदेशों से आए थे;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल हवाई अड्डे पर विमान उड़ानों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट हवाई अड्डों पर दिन और रात के समय और अधिक विमानों के अवतरण की सुविधायें हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जहां तक इंडियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है, इसके द्वारा वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के दौरान परिचालित सैक्टर पर मुम्बई से केरल तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और इनमें से विदेशों से आये यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या	विदेशों से आये यात्रियों की संख्या
1987-88	2,14,623	1,08,414
1988-89	2,25,731	1,05,574
1989-90	2,25,819	1,06,057

वायुदूत मुम्बई और केरल के बीच कोई उड़ान परिचालित नहीं करती है। एयर इंडिया के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जहां तक इंडियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है, केरल के स्थानों के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की उसकी कोई योजना नहीं है। क्षमता की कमी के कारण, वायुदूत भी वर्तमान आवृत्ति को बढ़ाने तथा नई सेवाएं परिचालित करने की स्थिति में नहीं है। एयर इंडिया के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) कालीकट और तिरुअनन्तपुरम् दोनों हवाई अड्डे रात्रि परिचालन के लिए उपयुक्त हैं और इन हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुविधायें पहले ही उपलब्ध हैं। कोचीन हवाई अड्डे पर एप्रन तथा टैक्सी-ट्रैक का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाने वाला है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

50. **श्री मित्रसेन यादव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पहले कुछ रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया था; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ख) क्या फैजाबाद और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी इन मानदण्डों के अन्तर्गत स्टेशनों की उक्त श्रेणी में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां। सरकार के निर्णय के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों को ऐसे उपयुक्त स्थलों जैसे क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, महत्त्वपूर्ण जंक्शन और विशेष महत्व वाले अन्य स्थानों पर स्थित स्टेशनों को चुनने की सलाह दी गई थी जिनका विकास आदर्श स्टेशन के रूप में किया जा सके। क्षेत्रीय रेलों की सिफारिशों के आधार पर 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्टेशनों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी यातायात के स्तर में वृद्धि के कारण आवश्यकता पड़ती है तो इस सम्बन्ध में कार्य शुरू किए जाते हैं जो धनराशि की उपलब्धता और अन्य स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।

उत्तर रेलवे के श्रेणी-II के अधिकारियों की मांगें

[अनुवाद]

51. **श्री वाददेन्द्र दत्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के श्रेणी-II के अधिकारियों की मांगों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के अधिकारियों की मांगे समय-समय पर उनके सेंट्रल फेडरेशन और इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन के माध्यम से प्राप्त होती हैं जिन पर विचार किया जाता है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है;

(ख) उत्तर रेलवे सहित भारतीय रेलों के श्रेणी-II के अधिकारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) वेतनमानों और पदोन्नति की सम्भावनाओं के मामले में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के अधिकारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना अर्थात् समान कार्य के लिए समान वेतन;

(ii) भारतीय रेलों के ग्रुप "बी" (श्रेणी-II) राजपत्रित संवर्ग की पुनर्संरचना और उनके कैरियर के लिए योजना तैयार करना;

(iii) वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए सामंजस्य तालिका बहाल करना;

(iv) ग्रुप "ए" संवर्ग की संख्या में कारगर हिस्सा देते हुए चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 23.11 में के अन्तर्गत दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(v) ग्रुप "बी" और उच्चतम ग्रुप "सी" संवर्ग के वेतनमानों के आबंटन में असंगति को दूर करना।

(ग) इन सभी मुद्दों पर समय-समय पर विचार किया गया है और स्थिति से फेडरेशन को अवगत कराया गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा घटिया माल की खरीद

[हिन्दी]

52. श्री बालेश्वर यादव :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा घटिया माल को खरीद के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) क्या इस मामले से सम्बद्ध लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) घटिया सामग्री की खरीद के सम्बन्ध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्राप्त कतिपय शिकायतों के बारे में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का सतर्कता विभाग सम्पूर्ण मामले की जांच कर रहा है। यदि किसी कर्मचारी को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही जांच-पड़ताल के तथ्यों के आधार पर निर्भर करेगी।

कोयले पर रायल्टी में वृद्धि

53. श्री राजमंगल मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्रत्येक वर्ष कुल कितने मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को प्रति मीट्रिक टन कितनी रायल्टी दी जाती है;

(ग) क्या अन्य खनिजों पर रायल्टी बढ़ा दी गई है जबकि कोयले पर रायल्टी में वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार की कोयला खानों से हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है—

वर्ष	उत्पादन (आंकड़े मि० टन में)
1985-86	54.32
1986-87	59.07
1987-88	64.47
1988-89	66.95
1989-90	63.83

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न ग्रेड के कोयले के लिए निर्धारित की गई रायल्टी की दरें, जो कि 13-2-1981 से लागू होंगी, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कोयले पर रायल्टी की दरों को कुछ राज्य सरकारों द्वारा, जिसमें बिहार भी शामिल है, उच्च उपकर/लेवी लगाए जाने को दृष्टिगत करते हुए संशोधित नहीं किया गया है।

विवरण

13-2-1981 से लागू कोयले पर रायल्टी की दरें

(i) ग्रुप I कोयला :

(क) कोकिंग कोयला

इस्पात ग्रेड-I

इस्पात ग्रेड-II 7 रु० प्रति टन

वाशरी ग्रेड-I

(ख) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला

(ii) ग्रुप-II कोयला :

(क) कोकिंग कोयला वाशरी ग्रेड-II कोकिंग कोयला वाशरी ग्रेड-III (ख) अर्ध-कोकिंग कोयला ग्रेड-I अर्ध-कोकिंग कोयला ग्रेड-II (ग) गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-ए गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-बी (घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का आर० ओ० एम० कोयला	6.50 रु० प्रति टन

(iii) ग्रुप-III कोयला :

(क) कोकिंग कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-सी	5.50 रु० प्रति टन

(iv) ग्रुप-IV कोयला

गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-डी गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-ई	4.30 रु० प्रति टन

(v) ग्रुप-V कोयला :

गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-एफ गैर-कोकिंग कोयला ग्रेड-जी	2.50 रु० प्रति टन

(vi) ग्रुप-VI कोयला :

आंध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला (सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०)	5.00 रु० प्रति टन

स्पष्टीकरण—इस मद के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रत्येक ग्रेड के कोयले का विनिर्दिष्टकरण कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 1945 की धारा 3 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार होगा।

गाजीपुर-जौनपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

54. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवहन की स्थिति सुधारने तथा उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु गाजीपुर-जौनपुर (बरास्ता औरिहर) मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस क्षेत्र में रेल परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) केवल औंड़िहार-गाजीपुर-छपरा मीटर लाइन खंड को ही बड़ी लाइन में बदलने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस क्षेत्र में वाराणसी-भटनी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है और हाल ही में खोल दिया गया है। इससे इस क्षेत्र में रेल सुविधाओं में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास केन्द्र

55. श्री जनक राज गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्वीकृति दी है; और

(ख) इन औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने नई विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में दो विकास केन्द्रों को मंजूरी दी है, जो इस प्रकार है :—

विकास केन्द्रों का नाम	जिला
(1) संभा	जम्मू
(2) गंदरबल	श्रीनगर

केन्द्र सरकार ने अभी जम्मू और कश्मीर सहित इस योजना के तहत मंजूर किये गये किसी विकास केन्द्र के लिए निधियां नहीं दी हैं।

बिहार में कोयला मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

[हिन्दी]

56. श्री बसई चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला उद्योग का मुख्यालय इस राज्य से बाहर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इसे बिहार में कब तक स्थानांतरित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) बिहार की अधिकांश राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का प्रबंधन सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा किया जाता है जिनके मुख्यालय बिहार में क्रमशः रांची तथा धनबाद में स्थित हैं। बिहार की कुछ राष्ट्रीयकृत कोयला खानें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत कार्यरत हैं जिसका मुख्यालय संकतोड़िया (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। उक्त सभी तीनों कम्पनियां कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियां हैं और कोल इंडिया लि० एक धारक कम्पनी है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है।

उपर्युक्त तीनों सहायक कम्पनियों के अलावा कोल इंडिया लि० की 4 अन्य सहायक कंपनियां हैं अर्थात् केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची (मुख्यालय) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, नागपुर (मुख्यालय), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर (मुख्यालय) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, सिंगरौली (मुख्यालय)।

इस समय कोल इंडिया लि० के कलकत्ता मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड से रेलवे कम्प्यूटरीकरण का कार्यभार अपने हाथ में लेना

[अनुवाद]

57. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड से रेल यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण का कार्यभार अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड से उक्त कार्यभार को अपने हाथ में लेने से रेल विभाग को कितना शुद्ध लाभ होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कंप्यूटर मेंटेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार यात्री आरक्षण प्रणालियों का अनुरक्षण कर रही है। पांचवें स्थान अर्थात् सिकन्दराबाद में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'ई० सी० आई० एल०" द्वारा हार्डवेयर का और क्रिस (रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र) द्वारा साफ्टवेयर का अनुरक्षण किया जा रहा है। एक दीर्घकालिक नीति के रूप में, रेलें साफ्टवेयर का स्वयं अनुरक्षण करना चाहती हैं जिससे साफ्टवेयर में संशोधन करना अधिक आसान होगा तथा जिसके अधिक किफायती होने की भी संभावना है।

महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

58. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में गैस पर आधारित और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित प्राकृतिक गैस बम्बई के निकट स्थित अप-तट तेल क्षेत्रों से उपलब्ध की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में और गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम और क्षमता	के० वि० प्रा० में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	ट्रॉम्बे जीटीसीसी ता० वि० केन्द्र (1 × 120 मे० वा० जीटी + 1 × 60 मे० वा० एसटी) ग्रेटर बॉम्बे	जनवरी, 1990	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति जैसी सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद स्कीम के सम्बन्ध में औपचारिक तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।
2.	धबोल जीटीसीसी (4 × 120 मेवा जीटी 2 × 140 मे० वा० एसटी) जिला रत्नागिरी	मार्च, 1989	के० वि० प्रा० द्वारा अन्य मूल्यांकन एजेंसियों के परामर्श से स्कीम की जांच की जा रही है और अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने तथा आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध होने के बाद ही इनके सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।
3.	उरण जीटीसीसी विस्तार चरण-1 तथा 2 (2 × 130 मेवा जीटी + 1 × 150 मेवा एसटी)	जून, 1990	
4.	धबोल गैस आधारित ता० वि० केंद्र यूनिट-1 तथा 2 (2 × 500 मेवा) जिला-रत्नागिरी	सितम्बर, 1988	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 23-2-89 को सलाह दी गई है कि परम्परागत गैस प्रचालित बॉयलरों में गैस का उपयोग कम दक्षतापूर्ण है और इसीलिए मितव्ययी नहीं है। स्कीमों के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। स्कीमों को राज्य प्राधिकारियों को वापिस भेज दिया गया है।
5.	ठकुराली गैस आधारित ता० वि० केंद्र, यूनिट-1 तथा 2 (2 × 210 मेगावाट)	सितम्बर, 1988	
6.	उरण गैस टर्बाईन चरण-3 (8 × 108 मेगावाट)	जून, 1984	गैस की उपलब्धता की पुष्टि न होने के कारण स्कीम को जनवरी, 1986 में राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय में नशीली औषधों के मामलों के संबंध में नियुक्त विशेष दल के निष्कर्ष

59. श्री कल्पनाथ सोनकर :

श्री मानवेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में नशीली औषधों के मामलों के बारे में नियुक्त किये गये विशेष दल के निष्कर्षों की पुनरीक्षा पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो पहले के निष्कर्षों और संशोधित निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अब तक की गई पुनरीक्षा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में ग्रस्तग्रस्त कम्पनियों द्वारा पूरे ब्यौरे एक बार उपलब्ध कराने पर इस प्रकार निर्धारित की गई राशियों में आगे और परिवर्तन होगा। वांछित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	कंपनी का नाम	विशेषज्ञ दल द्वारा 31-12-1983 तक अस्थाई रूप से निर्धारित राशि	पुनरीक्षा पश्चात 31-12-1983 तक निर्धारित अस्थाई राशि
1.	मे० फाइजर लि०	48 21	87.61
2.	मे० सिनामिड इंडिया लि०	389.06	536.91
3.	मे० हेक्सट (इंडिया) लि०	458.10	2491.05
4.	मे० अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि०	11.61*	11.61
5.	मे० जोहन वेयथ (इंडिया) लि०	133.45	173.02
	मे० ज्योफरी मेनर्स	28.37	28.37
6.	मे० इथनौर लिमिटेड	8.15	10.19
7.	मे० एम० जी० फार्मास्युटिकल्स	114.30*	205.36
8.	मे० तमिलनाडु डाडा फार्मा० लि०	15.59*	37.97
9.	मे० मेरिन्ड लि०	138.79*	781.58
10.	मे० फेको इंडियन फार्मा० लि०	11.02	14.02
	मे० ग्रीफोन लि०		

*निर्धारित किन्तु कम्पनी को सूचित नहीं की गई।

प्राकृतिक गैस को जलाया जाना

60. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री चित्त बसु :
श्री अमर रायप्रधान :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री बबनराव ढाकणे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है और यह कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस का जलाया जाना बन्द करने और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करने के लिए हाल ही में कोई गम्भीर प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग द्वारा यदि किन्हीं अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो वे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय जलाई जा रही प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत, उर्वरक और पेट्रो-रसायन परियोजनाओं में करने हेतु अपेक्षित पूंजी निवेश के, हाल ही में कोई अनुमान तैयार किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसे कोई निदेश जारी किए हैं कि बिना इसकी अनुमति के और अतिरिक्त गैस न जलाई जाएं; और

(छ) यदि हां, तो जारी किए गए निदेशों के पीछे क्या लक्ष्य है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) इस समय जलाई जा रही गैस की अनुमानित मात्रा लगभग 17 मिलियन घन मीटर प्रति दिन है जो इसके उत्पादन का लगभग 34 प्रतिशत है। 2768 रुपए प्रति 1000 घन मीटर के गैस के आकलित मूल्य के आधार पर इस प्रकार जलाई गई गैस का आर्थिक मूल्य लगभग 1800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई अपतटीय क्षेत्र में अनुषंगी गैस के संपीड़न और परिवहन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने हेतु एक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना पर लगभग 2002 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है और इस समय सरकार इस पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से वर्ष 1993-94 तक बम्बई अपतटीय क्षेत्र में गैस का जलाया जाना समाप्त हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस समय पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में संपीड़न क्षमता और पाइपलाइन में वृद्धि करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिससे इस क्षेत्र में दिसम्बर, 1991 तक गैस के जलाये जाने को कम किए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस पूर्वानुमान के आधार पर कि वर्ष 1994-95 तक गैस का प्रयोग बढ़कर 98 एम एम एस सी एम डी हो जाएगा, यदि वांछित निवेश तेल एवं गैस के क्षेत्रों के

विकास में और गैस के संसाधन, संपीड़न और परिवहन में किया जाता है तो अनुमान है कि बिजली, उर्वरक, पेट्रो-रसायन और इस्पात के क्षेत्रों में डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।

(च) और (छ) हाल में ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सलाह दी गई है कि नई परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य न्यूनतम मात्रा के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस को जलाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इस संबंध में सरकार से पूर्व अनुमोदन नहीं ले लिया जाता। उद्देश्य यह है कि ऊर्जा के इस बहुमूल्य अपरिवर्तनशील स्रोत को व्यर्थ होने से बचाया जा सके।

रणजीत सागर बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

61. **श्रीमती सुखबंस कौर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणजीत सागर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इन विस्थापितों को भूमि का मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) रणजीत सागर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

62. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए कोयला तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल ने वर्ष 1994-95 में 310.31 मि० टन कोयले का उत्पादन होने का प्रक्षेपण किया है। उक्त उत्पादन को विद्यमान खानों, विकासाधीन खानों तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली खानों के द्वारा प्राप्त किया जाना है।

ओपनकास्ट तथा भूमिगत दोनों ही तरह की कोयला खानों को आधुनिकीकृत किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में पहले ही उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं— ओपनकास्ट खानों में उच्च क्षमता की ड्रैगलाइनें, शावलों, डम्परों तथा ड्रिलों की तैनाती तथा भूमिगत खानों में रूफ बोल्टिंग, निरन्तर खनन क्रियाकलाप, पावर स्पोर्ट लांगवाल पद्धति, मल्टी स्लाईसिंग, ब्लास्टिंग गैलरी तथा हाईड्रोलिक खनन आदि। दूरसंचार की व्यवस्था में भी कोयला खानों में इलैक्ट्रानिकी का प्रगामी प्रयोग के जरिए सुधार किया जा रहा है। उक्त उपायों को मुख्यतः उत्पादकता में सुधार तथा कार्य कुशलता में वृद्धि किए जाने के लिए किया जा रहा है।

प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल का उत्पादन

[अनुवाद]

63. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल का उत्पादन करने संबंधी विधि की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में और क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस को मिट्टी के तेल और डीजल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) प्राकृतिक गैस से मैथानोल।

(3) मेथानोल से ओलेफिन।

(4) ओलेफिन से मध्य आसुत, यथा मिट्टी का तेल तथा डीज़ल।

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने मेथानोल से ओलेफिन और ओलेफिन से मिट्टी के तेल तथा डीजल तैयार करने के उत्प्रेरक विकसित किए हैं। प्राकृतिक गैस को मेथानोल में परिवर्तित करना एक सुस्थापित प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा विकसित उत्प्रेरकों को व्यापारिक स्तर पर प्रमाणित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, बी० पी० सी० एल० और डावी पावर गैस इण्डिया प्रा० लि० द्वारा संयुक्त रूप से बी० पी० सी० एल० रिफाइनरी, बम्बई में प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जाए। प्रयोगिक संयंत्र की लागत का अनुमान 6 करोड़ रुपए लगाया गया है और मिट्टी के तेल और डीजल की क्षमता एक टन प्रति दिन होगी।

बक्रेश्वर ताप परियोजना के लिए सोवियत संघ द्वारा सहायता

64. **श्री चित्त महाता :**
श्री चित्त बसु :
श्री अमर रायप्रधान :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर ताप परियोजना के लिए सोवियत संघ से प्राप्त सहायता उपलब्ध करा दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सोवियत संघ के सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में तैयार की जा रही कीमतों सहित विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर सोवियत प्राधिकारियों के साथ अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना को सोवियत सहायता जारी की जायेगी।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस का आगे तक चलाया जाना

[हिन्दी]

65. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र एक्सप्रेस को नागपुर से आगे गोंदिया तक चलाने की आवश्यकता और लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस सम्बन्ध में अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करेगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कोल्हापुर-नागपुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस का गोंदिया से/तक विस्तार करने की मांग की गई है जिसकी जांच की गयी लेकिन परिचालनिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण इसे कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन

[अनुवाद]

66. श्री कल्पनाथ राय :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्रीमती बासवराजेश्वरी :
श्री गंगाचरण लोधी :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मैथन ग्राम के 350 परिवारों को शहरों व ग्रामों के कूड़ा करकट और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग से प्रतिदिन आठ घंटे रसोई गैस प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैस और बिजली पैदा करने के लिए अन्य राज्यों में भी इस योजना के अन्तर्गत ऐसे और अधिक संयंत्र लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित योजनाओं और उनकी लागत का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मैथन गांव में स्थापित सामुदायिक बायोगैस संयंत्र में प्रतिदिन 6-8 घंटों के लिए 350 परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए बायोगैस की व्यवस्था है। गोबर का इस्तेमाल करके बायोगैस संयंत्र को चलाया जाता है।

(ख) जी, हां। सम्पूर्ण देश में संभावित स्थलों पर सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए एक योजना पहले से ही विद्यमान है। तथापि, संयंत्र का आकार और लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या उस गांव अथवा संस्था में उपलब्ध मुख्यतः गोबर और विष्ठा की

मात्रा पर निर्भर होती है। ये बायोगैस संयंत्र मुख्यतः खाना पकाने और जल को पम्प के जरिये निकालने के लिए गैस प्रदान करते हैं। अतिरिक्त गैस को, स्थान की आवश्यकताओं के आधार पर, बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की आंशिक वित्तीय सहायता से 900 संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए आठवीं योजना के दौरान 30.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्य के लिए राज्यवार लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि किसी राज्य में स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों की संख्या सम्बन्धित राज्य अथवा उसकी कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निर्धारित तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्थलों पर निर्भर होगी।

दिल्ली में बिजली की खपत और इसकी उपलब्धता

[हिन्दी]

67. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली की कुल कितनी खपत है और इसके अपने स्रोतों के माध्यम से कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में बिजली की कमी पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली में विद्युत की वर्तमान औसत खपत प्रतिदिन करीब 26 मिलियन यूनिट है। डेसू के अपने स्रोतों, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र का बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र भी शामिल है, से विद्युत का दैनिक उत्पादन करीब 17 मिलियन यूनिट है। शेष मांग की पूर्ति उत्तरी ग्रिड से बिजली प्राप्त करके की जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 × 67.5 मेगावाट क्षमता का राजघाट ताप विद्युत प्रतिस्थापन यूनिट हाल ही में चालू की गई है। विद्यमान गैस टर्बाइनों पर 3 × 30 मेगावाट की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट की अधिष्ठापना एवं बवाना में 800 मेगावाट संयुक्त साइकिल गैस-आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है बशर्ते कि संसाधन एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों। दिल्ली को, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दादरी में लगाई जा रही 840 मेगावाट की राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना से भी अपना हिस्सा प्राप्त होगा। दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० ट्रांसमिशन रिंग की अधिष्ठापना का कार्य, 220 के. वी. ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क के संवर्धन एवं रिहन्द-दादरी एच०वी०डी०सी० लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिनसे भी दिल्ली में भविष्य में भार (लोड) में होने वाली वृद्धि की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी।

कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

68. श्री शंकर सिंह वघेला : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष निकले हैं और देश में ज्वारीय बिजली की क्या सम्भावना है;

(ख) संशोधित सीमांकन के अन्तरण के लिए भू-सर्वेक्षण के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास छिद्रण कार्य के लिए विशेष प्रकार के जलपोत हैं और हन्सथाल की संकरी खाड़ी में पानी की तह में छिद्रण कार्य के लिए जांच/परीक्षण हेतु उनका उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना सम्बन्धी व्यवहार्यता रिपोर्ट का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन 1988-89 में किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समझता है कि परियोजना की लागत के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त अन्वेषण किए जाने चाहिए। देश में अब तक पता लगाई गई कम खर्चीली ज्वारीय विद्युत संभाव्यता 8000-9000 मेगावाट है।

(ख) संशोधित संरेखण को अंतरित करने के लिए भू-सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य "सर्वे आफ इण्डिया" द्वारा किया गया है। तथापि इन अन्वेषणों के परिणामों की अभी इस अभिकरण से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत में एक विशिष्ट "ड्रिलिंग" पोत उपलब्ध है और उसे इस समय विदेशी जहाजों को बंकर सप्लाई करने के लिए भारतीय तेल निगम के साथ तैनात किया गया है। हंसथाल संकरी खाड़ी में अक्तूबर-नवम्बर, 1990 से करीब तीन से चार महीने के लिए जल के अन्दर खुदाई करने के लिए इस पोत को उपलब्ध कराने के लिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

कोंकण रेल निगम

69. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेल निगम का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक पूंजी परिव्यय कितना है और इसमें केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों का कितना प्रतिशत हिस्सा है; और

(ग) बाण्ड से कितनी धनराशि एकत्र करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) निगम की इक्विटी पूंजी 250 करोड़ रुपये होगी तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता इस प्रकार है :—

केन्द्र सरकार	51%	128 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	22%	55 करोड़ रुपये
कर्नाटक	15%	37 करोड़ रुपये
गोवा	6%	15 करोड़ रुपये
केरल	6%	15 करोड़ रुपये

(ग) लगभग 950 करोड़ रुपये।

दिल्ली और मेरठ के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

70. **श्री हरीश पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली-मेरठ रेल लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल पथों का विद्युतीकरण का लक्ष्य

[अनुवाद]

71. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के अंत तक रेल पथों के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार यदि इनका कोई विद्युतीकरण किया गया है, तो उसका प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि रेल पथों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों में असाधारण रूप से कमी आयी है; और यदि हां, तो नये लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये हैं और किन-किन मार्गों का विद्युतीकरण करने का विचार किया गया है; और

(ग) विद्युतीकरण के लक्ष्यों में कमी आने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) 1989-90 के अन्त तक पहचान किये गये 12268 मार्ग कि०मी० में से 9225 मार्ग कि०मी० का विद्युतीकरण किया गया है जो 78.58 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 75.42 प्रतिशत है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अभ्यावेदन

72. प्रो० राम गणेश कपासे :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को मार्च, 1990 में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसिएशन तथा आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया बम्बई से कुछ ठोस सुझावों सहित कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में औषध नीति, 1986, जो इस समय चालू है, की पुनरीक्षा के संबंध में उद्योग संघ के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ अनेक मुद्दे शामिल हैं जैसे प्रपुंज औषधों के निर्यात और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की पुनरीक्षा, औ० मू० नि० आ०, 1987 का युक्तिकरण और सरलीकरण अनुपात मानदंड, अनुसंधान एवं विकास आदि। पुनरीक्षा की प्रक्रिया में इन्हें विचार में लिया जा रहा है।

रेल दुर्घटनाएं

73. श्री कड़िया मुण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें कितने यात्री मरे हैं;

(ख) रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिए मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ग) इस अवधि के दौरान रेल कर्मचारियों के कितने आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान कुल 1689 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में 389 यात्रियों की जानें गईं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पश्चिमी चम्पारन में प्राकृतिक गैस की खोज

74. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पश्चिमी चम्पारन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के शोभा-पट्टी परीक्षण स्थल पर प्राकृतिक गैस होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक उपयोग के लिए तथा वहां गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु का तूतीकोरिन बिजली केन्द्र

76. **श्री इरा अम्बारासु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु मे तूतीकोरिन बिजली केन्द्र को कोयले की कम सप्लाई के कारण हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र में पहले से ही पर्याप्त कोल भंडारों के कारण, हाल ही में लिंक कोयले की कम आपूर्ति किए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में अभी तक किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है।

मोटर वाहनों का उत्पादन

[हिन्दी]

77. **राजवीर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान मोटर वाहनों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो जिन मोटर वाहनों के उत्पादन में कमी आई है उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान मोटर वाहनों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मोटर वाहनों के उत्पादन में कमी की प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। दुपहिया वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसे निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

	1989 (जनवरी-मई)	1990 (जनवरी से मई)
यात्री कार	73,623	76,508
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन	31,887	39,049
हल्के वाणिज्यिक वाहन	19,150	23,546
दुपहिये	7,37,636	6,87,844
तिपहिये	37,562	39,594
जीप टाइप वाहन	14,717	17,693

स्रोत :—भारतीय ऑटोमोबील निर्माता संघ द्वारा यथा प्रस्तुत मई, 1990 के के लिए उत्पादन तथा बिक्री आंकड़े ।

दुपहिया के उत्पादन में श्रमिक अशांति और उसी समय कुछ एककों में उत्पादन बन्द होने के कारण अस्थायी बाधा आई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश

78. श्री हरीश रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना का अंत तक देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों के पीछे कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में प्रति दस लाख लोगों के पीछे किया गया पूंजी निवेश राष्ट्रीत औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेलवे सेक्टर में और अधिक पूंजी निवेश करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सातवीं योजना के उपन्तिम वर्ष तक आबादी के प्रति 10 लाख के हिसाब से औसत निवेश की राशि लगभग 25.16 करोड़ रुपए होगी ।

रेलवे की निवेश योजनाओं का उद्देश्य एकीकृत परिवहन तंत्र का विकास करना है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की रेल परिवहन संबंधी मांग पूरी की जा सके । न तो योजनाएं राज्य-वार तैयार की जाती हैं और न ही निवेश के आंकड़े राज्य-वार रखे जाते हैं ।

त्रिपुरा को एस० के० ओ० की सप्लाई

[अनुवाद]

79. श्री संतोष मोहन देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को "एस० के० ओ०" की सप्लाई में भारी कमी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वहां "एस० के० ओ०" की भारी कमी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) त्रिपुरा को एस० के० ओ० की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा संबंधी संसाधनों की गंभीर सीमितता के कारण सभी राज्यों को एस० के० ओ० के वर्धमान आवंटन के लिए इस वर्ष के वर्षाकालीन ब्लाक के लिए वृद्धि दर को कम करके केवल 4% तक कर दिया गया है जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 7% की वृद्धि की गई थी ।

मालगाड़ियों का दुर्घटनाग्रस्त होना

[हिन्दी]

80. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : *क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) जून, 1990 में बरेली जंकशन पर लोको शेड में कोई मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस दुर्घटना में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की विभिन्न परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि

81. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या ऊर्जा मंत्री 24 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग का अनुरोध किया गया है; और

(ख) इस समय राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अथवा राज्य बिजली बोर्डों की कौन-कौन-सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा प्रत्येक परियोजना के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और हाथ में ली जाने वाली विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत कार्यक्रम के लिए परिव्यय संबंधी विस्तृत विवरणों का पता, इनको अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा और इसलिए इस स्थिति में यह बता पाना सम्भव नहीं है कि किस सीमा तक विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी, आठवीं योजनावधि में पूरा करने के लिए लक्षित विदेशी सहायताप्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

आठवीं योजनावधि में चालू किए जाने के लिए लक्षित विदेशी सहायता प्राप्त निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)
1	2	3
	विश्व बैंक	
1.	कवास संयुक्त साइकल	4 × 100+2 × 100
2.	औरेया संयुक्त साइकल	4 × 112+2 × 102
3.	राष्ट्रीय राजधानी ता० वि० परि०	4 × 210
4.	फरक्का-2 ता० वि० के०	2 × 500
5.	तलचेर-2	2 × 500
6.	चंद्रपुर ता० वि० के०	2 × 500
7.	केरल विद्युत परियोजना	3 × 60
8.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-1	3 × 40+3 × 50
9.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-2	4 × 60
10.	उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना	6 × 55
11.	अपर इन्द्रावती एच० ई० पी०	4 × 150
12.	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना	4 × 250
13.	केन्द्रीय पारेषण परियोजना	1655 सर्किट कि० मी०
14.	रिहन्द पारेषण परियोजना	2596 सर्किट कि० मी०
	एशियाई विकास बैंक	
1.	उत्तरी मद्रास ता० वि० के०	2 × 210
2.	ऊंचाहार विस्तार ता० वि० के०	2 × 210
3.	रायलसीमा ता० वि० के०	2 × 210
	ओ० ई० सी० एफ०	
1.	पूर्वी गंडक ज० वि० प०	3 × 5
2.	हिराकुंड चरण-3 ज० वि० प०	1 × 37.5
3.	लोअर बोरपानी ज० वि० प०	2 × 50
4.	अनपारा "बी" ता० वि० के०	2 × 500

1	2	3
	5. सरदार सरोवर ज० वि० प०	5 × 50
	6. तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना	9 × 7.5
	7. कथलगुडी गैस टरबाइन	6 × 30+3 × 30
	8. श्रीसेलम बांया तट ज० वि० प०	6 × 150
	9. पुरूलिया पम्प्ड स्टोरेज (ई/एस)	875
	10. रायचूर ता० वि० के०	1 × 120
	11. घाटघर पम्प्ड स्टोरेज	2 × 125
	12. बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन	4 × 30
	13. उज्जैनी ज० वि० परि०	1 × 12
	14. गंधार गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल	613.9
	15. भवानी कट्टालई ज० वि० परि०	6 × 15
यू० एस० एस० आर०		
	1. विन्ध्याचल चरण-1 सु० ता० वि० परि०	6 × 210
	2. विन्ध्याचल चरण-2 सु० ता० वि० परि०	2 × 500
	3. कहलगांव ता० वि० के०	4 × 210
	4. टिहरी हाइड्रो कंप्लैक्स	2400
	5. कायमकुलम ता० वि० के०	2 × 2:0
	6. मंगलौर ता० वि० के०	2 × 210
	7. मैथान आर० बी० सी० ता० वि० के०	3 × 210
	8. बकरेश्वर ता० वि० के०	4 × 210
	9. विन्ध्याचल-बिना-नाग्दा पारेषण लाइन	870 सर्किट कि० मी०
स्वीडन		
	1. उरी ज० वि० परि०	4 × 120
फ्रांस		
	1. दुलहस्ती ज० वि० परि०	3 × 130
	2. यालहांका	6 × 20
यू० के०		
	1. नागार्जुन सागर एल० बी० सी० ज० वि० परि०	2 × 30

1	2	3
कनाडा		
	1. चमेरा ज० वि० परि० चरण-1	3 × 180
एफ० आर० जी०		
	1. दादरी	817
	2. उरण अपशिष्ट ऊष्मा	2 × 120

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं

82. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृत हेतु भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निगम द्वारा ऐसी प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित अब तक 262 ग्रामीम विद्युत सम्बन्धी परियोजनाएं स्वीकृत की है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 53.478 लाख रुपए ऋण राशि की 400 सौर फोटोवोल्टक पैनल्स वाली केवल एक परियोजना निगम के पास लम्बित है।

भारत और बंगलादेश के बीच रेल सेवा

[अनुवाद]

83. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश ने भारत में सिंहबाद तथा बंगलादेश में रोहनपुर के बीच दूसरी रेल सेवा को पुनः शुरू करने के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या सरकार को पेट्रोपोल (भारत) और बेनापोल (बंगलादेश) के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सिंहाबाद (भारत) तथा रोहनपुर (बंगलादेश) के बीच रेल लाइन को पुनः खोलने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

84. **श्री संजय लाल :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान सरकार ने भारतीय औद्योगिक एककों के सहयोग से कितने विदेशी औद्योगिक एककों को देश में नये उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी है और उनके द्वारा विदेशी पूंजी का कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशी औद्योगिक एककों के कितने अनुरोध अस्वीकार किए गये; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1-1-90 से 30-6-90 की अवधि के दौरान विदेशी इक्विटी निवेश की विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की संख्या और इन मामलों में अनुमत विदेशी इक्विटी निवेश की राशि नीचे दी गई है :—

स्वीकृत आवेदनों की संख्या — 115

स्वीकृत विदेशी इक्विटी निवेश की राशि—7504.47 लाख रु०

(ख) और (ग) 1-1-90 से 30-6-90 की अवधि के दौरान ऐसे 45 आवेदन अस्वीकृत किए गए थे। अस्वीकृति के कारणों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, उद्योग का गैर प्राथमिकता वाला स्वरूप, आयात की अधिक मात्रा, भुगतान की महंगी शर्तें, कम उत्पादन, कम इक्विटी आधार, प्रौद्योगिकी के अन्तरण का अभाव इत्यादि शामिल हैं।

विश्रामपुर कोयला खान, मध्य प्रदेश में भूमि के अर्जन पर मुआवजे का भुगतान

85. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विश्रामपुर कोयला खान के लिए जिन किसानों की भूमि का अर्जन किया गया है, उन सभी को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष भू-स्वामियों को मुआवजा कब तक प्रदान कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की बिसराम कोलियरी के लिए 43 व्यक्तियों से 53.270 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई थी। इस भूमि के लिए मुआवजे की राशि का मूल्यांकन तथा मुआवजा सरगुजा जिले के समाहर्ता (कलक्टर) द्वारा स्वीकृत किया गया था। 30 व्यक्तियों ने मुआवजे की राशि को स्वीकार कर लिया है। बकाया 13 व्यक्तियों ने मुआवजे की राशि को इस कथन के साथ स्वीकार नहीं किया है कि समाहर्ता द्वारा मंजूर की गई मुआवजे की राशि अपर्याप्त है। उक्त 13 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने तथा उन व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने पहले ही मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली है, दिसंबर, 1986 में जबलपुर उच्च न्यायालय में मुआवजे की अधिक अदायगी प्राप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिए जाने तक उक्त 13 व्यक्ति समाहर्ता द्वारा मंजूर की गई मुआवजे की राशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

कोयला उत्पादन में हानि

86. **श्री रामदास सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, मई और जून, 1990 के दौरान बिजली उपलब्ध न होने के कारण कोयला उत्पादन में हानि हुई है;

(ख) बिजली की सप्लाई न होने के कारण उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन में कमी और मशीनों को हुए नुकसान के कारण कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-जून, 1990 की अवधि के दौरान, पूर्वी क्षेत्र की खानों में विद्युत आपूर्ति में कमी होने के कारण कोयला के उत्पादन की क्षति हुई। दिनांक 25/26 जून, 1990 को पूर्वी क्षेत्र के ग्रिड में एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप कोयला खानों को दी जाने वाली विद्युत को आपूर्ति पर बड़ा बुरा असर पड़ा। इस क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण स्थिति और भी खराब हो गई। सभी कार्य-स्थलों पर (ई० को० लि०-31, भा० को० को० लि०-50, से० को० लि०-30) खानों के जलमग्न होने के कारण कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ चूंकि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने के फलस्वरूप पम्पों द्वारा जल निकासी का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में हुआ घाटे को नीचे दिया गया है—

महीना	कोयला उत्पादन में हुआ घाटा (लाख टन में)			
	ई० को० लि०	भा० को० को० लि०	से० को० लि०	कुल घाटा
अप्रैल, 1990	1.78	0.45	0.45	2.68
मई, 1990	2.96	0.45	0.65	4.06
जून, 1990	2.75	2.00	1.00	5.75

(ग) कोयला खानों को की जाने वाली विद्युत की आपूर्ति में सुधार लाए जाने के लिए किए जा रहे कुछ सुधारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं—

(1) विद्युत आपूर्ति की स्थिति का सतत अनुवीक्षण करने और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा कोल इंडिया लि० के मध्य गहन समन्वय करने ताकि कोयला कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत की आपूर्ति की जा सके।

(2) उत्तरी ग्रिड और उड़ीसा से दा० घा० नि० को विद्युत की अतिरिक्त आपूर्ति।

(3) कोयला कंपनियों के पास उपलब्ध लघु केपटिव विद्युत आपूर्ति यूनिटों का सतत संचालन।

(4) कोयला और गैर-कोयला आपूर्ति फीडरों को अलग किया जाना।

बंगलौर में एयर बस ए-320 की दुर्घटना की जांच-रिपोर्ट

[अनुवाद]

87. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री एच० सी०श्रीकान्तय्या :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एयर बस ए-320 की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखकर क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

88. **श्री अजीत कुमार पांजा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 से 31 जुलाई, 1990 तक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र निपटाए गए; और

(ग) उपरोक्त आवेदकों में से कितनों को आशय पत्र जारी किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) 1-12-1989 से 31-7-1990 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल से 46 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 7 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं और आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष 39 आवेदनों में से 11 नामंजूर कर दिए गए हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटा दिए गए हैं और 28 आवेदन कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

नासिक विमानपत्तन का विकास

89. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :**
श्री हरि शंकर महाले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक (महाराष्ट्र) में एक छोटा-सा विमानपत्तन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नासिक में बढ़ती हुए जनसंख्या और तेजी से औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस विमानपत्तन को एक राष्ट्रीय विमानपत्तन में विकसित करने का विचार है;

(ग) नासिक विमानपत्तन के विस्तार कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं है।

राजस्व की चोरी

90. **श्री के० चोक्का राव :**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे में भ्रष्टाचार के कारण रेल राजस्व की चोरी के कारण भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि होती है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष हैं और कौन-कौन से क्षेत्रों में राजस्व की चोरी होने का पता लगा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) अभी हाल में किराए और माल भाड़े में की गई वृद्धि से अनुमानतः कितनी धनराशि मिलने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) बिना टिकट यात्रा, बिना बुक किये गये सामान और पार्सल की ढुलाई, टिकटों की पुनः बिक्री/पुनः उपयोग, जाली टिकटों की बिक्री, परेषणों का कम तोल और खान पान संबंधी बिक्री का लेखा-जोखा न रखने, आदि के कारण रेलवे राजस्व की चोरी हुई है। इस प्रकार हुई चोरी की राशि बताना संभव नहीं है। इन कदाचारों के कारण राजस्व की चोरी से संबंधित विषय पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन इस विषय की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा इस पर निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) इस संबंध में जो कदम उठाये गये हैं उनमें बार-बार निरीक्षण बड़े पैमाने पर गहन जांच आदि सहित नियमित रूप से टिकटों की जांच जैसे उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, सतर्कता संगठन, उन क्षेत्रों में जहां चोरी होती है, निवारक जांच करता है और दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल करता है।

दोषी रेल उपयोगकर्ताओं से देय राशि वसूल की जाती है और कुछ मामलों में दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा भी चलाया जाता है।

अपराध सिद्ध हो जाने के मामले में दोषी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है।

(घ) 847 करोड़ रुपये।

बंगलौर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दर्जा बढ़ाना

91. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप के दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) क्योंकि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है, इसलिए सरकार किसी नये प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया गया निवेश

92. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की जिले-वार गैर-सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों के सहयोग में उद्योग स्थापित किए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक औद्योगिक एकक द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा (सरकारी क्षेत्र के अलावा) में उद्योग लगाने के लिए सातवीं योजना के दौरान स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की जिलेवार संख्या और उनमें प्रस्तावित निवेश नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	अचल परिसंपत्तियों में प्रस्तावित निवेश (रुपये लाख में)
1	2	3
बालासोर	7	9,868
बोलनगिर	1	597
मयूरभंज	1	346
ढेंकनाल	2	406
कटक	4	4,149

1	2	3
गंजम	2	89
पुरी	7	2,127
सम्बलपुर	2	726
सुन्दरगढ़	6	956
जिले का उल्लेख नहीं है	1	1,830

जारी किये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उनके ब्यौरे जैसे एकक का नाम तथा पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की मद(दें) और क्षमता, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मासिक समाचार-पत्र" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास

[हिन्दी]

93. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पैट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा क्या है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और माइक्रो/मिनी जल विद्युत जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए राज्य सरकारों/नोडल एजेन्सियों के साथ मिलकर समस्त देश में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ख) और (ग) सौर ऊर्जा प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों की स्थापना करना, सौर ऊर्जा प्रणालियों और उत्पादों के उपयोगकर्ताओं तथा निर्माणकर्ताओं के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान करना तथा ऐसी प्रणालियों के उपयोग में कर्मियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

रायल्टी की दरों में वृद्धि

94. श्री सी० डी० गामित : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्चे तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) रायल्टी की दर में कितनी वृद्धि की जाएगी और यह वृद्धि कब तक किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। रायल्टी की दर के संशोधन के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा उठाये गए मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे :

(i) रायल्टी में संशोधन तारीख 1-4-1987 से होना चाहिए;

(ii) रायल्टी कच्चे तेल की आंतरिक कीमत पर आधारित होनी चाहिए जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उत्पादों के लिए भुगतान की जाने वाली बाजार मूल्य के अनुसार निश्चित की गई हो जिसमें उपकर, कर तथा अधिभार शामिल हों;

(iii) रायल्टी में संशोधन हर दो वर्ष में किया जाना चाहिए;

(iv) रायल्टी की दर को संशोधित करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए; और

(v) स्पष्ट तथा विवेकपूर्ण सिद्धांत पर आधारित रायल्टी के संशोधन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) विभिन्न अभिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् तथा मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1-4-1987 से प्रभावी रायल्टी की दर को बढ़ाने का फैसला किया था। तथापि गुजरात के मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि रायल्टी के संशोधन के सम्पूर्ण मामले को एक समिति पुनः जांच के लिए सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। इस आग्रह की जांच की जा रही है।

दिल्ली में उद्योगों का पंजीकरण

[अनुवाद]

95. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फैक्टरियों और औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए एक नई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह किस तारीख से शुरू की गई; और

(ग) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए मंजूरी हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े थे ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले असंगत क्षेत्रों में जो औद्योगिक तथा वाणिज्यिक एकक 31-12-1989 को कार्य कर रहे थे उन्हें दिल्ली नगर निगम ने पंजीकृत करने का निर्णय लिया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने प्राप्त हुए कुल 31616 आवेदन पत्रों में से 30-6-90 की स्थिति के अनुसार कुल 1074 आवेदन पत्रों की जांच की है अर्थात 540 मामलों में पंजीकरण मंजूर किया गया है तथा 534 मामलों में आवेदन पत्र नामंजूर किए गए हैं।

माल गाड़ी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति

96. श्री आर एन० राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, 1990 को मंगला रेलवे स्टेशन (धनबाद) के निकट एक माल गाड़ी गोमो-गढ़वा-चोपन पैसेंजर गाड़ी से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(घ) उसमें कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ङ) दुर्घटना होने के क्या कारण हैं; और

(च) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में 22 व्यक्तियों की जानें गईं और 62 व्यक्तियों को चोटें आईं।

(ग) जी नहीं। मुआवजे के बारे में फैसला पटना के रेल दावा अधिकरण की खंडपीठ द्वारा किया जाना है। यह एक न्यायिक निकाय है। बहरहाल, रेलवे घायल यात्रियों को और मृत यात्रियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान कर चुकी है।

(घ) 1,88,10,450 रुपये।

(ङ) और (च) पश्चिमी क्षेत्र के रेल सुरक्षा आयुक्त, जो इस दुर्घटना की न्यायिक जांच कर रहे हैं, की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

फोटोग्रैफिक समान के लिए लाइसेंस समाप्त करना

97. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने ब्लैक एण्ड व्हाइट और कलर फिल्मों तथा पेपर, मेडिकल एक्सरे फिल्म्स, ग्रेफिक आर्ट फिल्म्स तथा सिनेमा फिल्मों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का फोटोग्रैफिक सामान के उत्पादन के लिए लाइसेंस समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) कच्चे माल की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, ऊपरी खर्चों में वृद्धि आदि के कारण एच० पी० एफ० को 31-3-1990 से निम्न उत्पादों के बिक्री मूल्य में संशोधन करना पड़ा, जो निम्न प्रकार है :—

ग्रैफिक आर्ट्स फिल्म्स	16 प्रतिशत
रोल फिल्म/रसायन	10 प्रतिशत
सिने कलर फिल्म (प्रॉजिटिव)	11 प्रतिशत
मैडिकल एक्सरे फिल्म्स	9 प्रतिशत
सिने (श्वेत-श्याम) फिल्म्स	10 प्रतिशत
सिने ध्वनि फिल्म्स (निगेटिव)	10 प्रतिशत

फिलहाल प्रकाश संवेदी वस्तुओं के उद्योग को अवलाइसेंसीकृत करने का कोई विचार नहीं है चूंकि एक्सरे फिल्म, ग्राफिक आर्ट फिल्म एवं सिनेमा फिल्म के समेकित निर्माण हेतु विभिन्न पार्टियों को आशय पत्र/लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

गांवों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

98. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बायो गैस और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने हेतु, विशेषकर गांवों में तैयार एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्रोतों से चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास इत्यादि जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के लिए अनुसंधान तथा विकास, प्रदर्शन और विस्तार सहित अनेक कार्यक्रमों को पहले से ही अपना समर्थन दे रही है। इनका कार्यान्वियन सम्पूर्ण देशों में राज्य सरकारों/नोडल एजेन्सियों के सहयोग से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम विकेन्द्रीकृत प्रकार के हैं और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं।

(ग) चालू वर्ष 1990-91 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों की स्थापना/कार्यान्वियन से बिजली के उत्पादन की अनुमानित क्षमता 450 लाख यूनिट प्रतिवर्ष है और बचाया गया अनुमानित इंधन जलावन लकड़ी की दृष्टि से प्रतिवर्ष 18 लाख टन के बराबर है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्प खोलना

[हिन्दी]

99. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के सहरसा जिले में सुपोल, वीरपुर, सोमवरशा सोरबाजार और बख्तियारपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नए पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सभी पेट्रोल पम्प कब तक खोले जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) तेल उद्योग नये खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानों का पता लगाने हेतु आवधिक सर्वेक्षण करता है। मानदंडों के अनुसार संभाव्य पाये गये स्थान को एक चरणबद्ध तरीके से वार्षिक विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। भावी विपणन योजना में शामिल करने के लिए उत्तरी बिहार के सहरसा जिले में बीरपुर बतनाला और त्रिवेणीगंज को विनिर्दिष्ट किया गया है।

दीघा-तामलुक रेलवे परियोजना

[अनुवाद]

100. श्री सुधीर गिरि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दीघा-तामलुक रेल लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य पर अब तक कुल कितने धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जून, 90 तक समग्र प्रगति 9.20 प्रतिशत रही।

(ख) जून, 90 तक 9.53 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ग) इसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्रम में इस परियोजना की स्थिति निर्धारित की जायेगी।

पंजाब में बिजली की वार्षिक क्षति

101. बाबा सुच्चा सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रेषण या अन्य कारणों से बिजली की कितनी वार्षिक क्षति हुई है; और इसका मूल्य कितना है;

(ख) प्रेषण में बिजली की क्षति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बिजली की चोरी/क्षति से संबंधित कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में पारेषण और वितरण हानियां, बस-बार पर उत्पादित ऊर्जा के मूल्य की लगभग 18 प्रतिशत आंकी गई है।

(ख) हानियों को कम करने के लिए विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक हानियों हेतु प्रणालीगत उत्तरदायी घटकों

का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य करना, वोल्टता संबंधी परिदृश्य में सुधार करने हेतु केपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी की रोकथाम के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर बॉक्स प्रतिष्ठापित करना तथा ऊर्जा की चोरी से संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना शामिल है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अंतर्गत ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने सतर्कता दलों का गठन किया है तथा बोर्ड अपनी पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने तथा इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें भी बना रहा है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1377684 प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की गई थी तथा ऊर्जा की चोरी के 13488 मामलों का पता लगाया गया था। जुर्माने के रूप में 65.95 लाख रुपए की राशि वसूल की गई थी।

बंगाल पोट्रीज लि० को पुनः चालू करना

102. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पोट्रीज लि० को पुनः चालू करने हेतु कुछ नये प्रस्ताव हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक लागू किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार को यथासंभव विद्यमान परिसंपत्तियों और श्रम बल का इस्तेमाल करने के लिए उसी स्थान पर एक नये एकक की स्थापना करने की संभावना के बारे में शीघ्र जांच करने के लिए कहा गया है। केन्द्र सरकार का मौजूदा निर्णय एकक की अजीव्यता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कोई और प्रबंध करना नहीं है।

मिट्टी मिश्रित सीमेंट की बिक्री

[हिन्दी]

103. **श्री राम लाल राही** :
श्री हरीश पाल :
डा० बंगाली सिंह :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में मिट्टी मिली हुई सीमेंट की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे भ्रष्ट तरीकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में अथवा देश के अन्य भागों में सीमेंट में मिट्टी मिलाए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) बढ़िया सीमेंट का विनिर्माण तथा बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1962 को वर्ष 1983 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, सीमेंट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न 1-7-1983 से अनिवार्य हो गया था। प्रत्येक निर्माता को बी० आई० एस० से परीक्षण व निरीक्षण कराये जाने की एक योजना का पालन करना होता है। तदनुसार, सभी सीमेंट निर्माताओं को उत्पाद की बिक्री करने से पूर्व सीमेंट पर ब्यूरो का मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए बी० आई० एस० से अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है।

रेलवे लाइनों को दोहरी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

104. श्री० पी० नरसा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ रेल लाइनों को दोहरी लाइन में बदलने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लाइनों को दोहरी लाइन में कब तक बदल दिया जायेगा तथा इस पर रेल सेवा कब से प्रारम्भ हो जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) दोहरी लाइन बिछाने संबंधी निर्माण कार्यों का ब्यौरा निर्माण, मशीन और चल स्टाफ कार्यक्रम भाग-II, 1990-91 में प्रत्येक रेलवे के अंतर्गत दिया गया है। यह पुस्तक बजट प्रलेखों के साथ प्रत्येक संसद सदस्य को दी जाती है।

(ग) दोहरी लाइन बिछाने संबंधी निर्माण कार्यों को पूरा करना एक सतत् प्रक्रिया है। 1989-90 के दौरान 162 कि० मी० दोहरी लाइन खोली गयी थी। 1990-91 में 477 कि० मी० और दोहरी लाइन खोलने की योजना है।

पंजाब में हवाई अड्डों का निर्माण

[हिन्दी]

105. स० अतिंदर पाल सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक हवाई अड्डे से प्रतिदिन कुल कितनी उड़ानें संचालित की जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का विद्यमान हवाई अड्डों के विस्तार तथा कुछ और अधिक हवाई अड्डों के निर्माण का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, हवाई अड्डों के रखरखाव पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(च) सभी हवाई अड्डों पर उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पंजाब के विभिन्न जिलों में 18 हवाई अड्डे हैं जो संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

(ख) जबकि इंडियन एयरलाइन्स अमृतसर हवाई अड्डे से होकर, दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर-जम्मू-श्रीनगर और वापसी मार्ग पर एक दैनिक उड़ान सेवा चला रही है, वायुदूत भी दिल्ली-लुधियाना और वापसी मार्ग पर एक दैनिक उड़ान का प्रचालन कर रहा है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं है ।

(ङ)

	(लाख रुपये) (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा० के हवाई अड्डों में)
1987-88	66.90
1988-89	59.71
1989-90	64.45
जोड़	191.06

(च) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित हवाई अड्डों पर अनुसूचित एयरलाइन प्रचालनों के लिये सभी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

विवरण

क्रम सं०	हवाई अड्डा	जिला
1	2	3
1.	आदमपुर	जालन्धर
2.	अमृतसर	अमृतसर
3.	[illegible]	पटियाला
4.	भटिण्डा	भटिण्डा
5.	[illegible]	लुधियाना
6.	फरीदकोट	फरीदकोट
7.	फिरोजपुर	फिरोजपुर
8.	गुरुदासपुर	गुरुदासपुर

1	2	3
9.	हलवारा	लुधियाना
10.	ज्वालापुर	पटियाला
11.	जालन्धर	जालन्धर
12.	खेमकरण	अमृतसर
13.	लुधियाना	अमृतसर
14.	नाभा	भटिण्डा
15.	नानकसर	फिरोजपुर
16.	पठानकोट	गुरदासपुर
17.	पटियाला	पटियाला
18.	सिरसा	भटिण्डा

डाल्टन गंज में रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या

106. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1990 में बिहार से डाल्टनगंज तथा मध्य प्रदेश में इटारसी, भुसावल सेक्शन पर उज्जैन के निकट, रेल दुर्घटनाओं में, अलग-अलग कितने लोगों की जानें गईं;

(ख) इनमें से प्रत्येक घायल व्यक्ति को अथवा मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा अथवा सहायता के रूप में कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु तथा इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जून, 1990 के दौरान डाल्टनगंज के निकट मंगरा स्टेशन, इटारसी-खंडवा खंड में दुलरिया और उज्जैन के निकट बिना चौकीदार वाले समपार पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

दुर्घटना स्थल	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1. मंगरा स्टेशन	22
2. दुलरिया स्टेशन	4
3. उज्जैन स्टेशन के निकट	1 (मेटाडोर वैन का ड्राइवर)

(ख) दुर्घटना स्थल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले रेल दावा अधिकरण द्वारा मुआवजे का

फैसला किया जाता है। यह एक न्यायिक निकाय है। तथापि, इन दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों तथा मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में 95,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) पश्चिमी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा डाल्टनगंज के निकट मंगरा स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच की जा रही है तथा रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दुलरिया स्टेशन पर हुई दुर्घटना के मामले में, गाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर तथा सहायक स्टेशन मास्टर, दुलरिया को जिम्मेवार ठहराया गया है।

उज्जैन के निकट दुर्घटना, मेटाडोर ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी।

इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाये जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(1) नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए स्वचल सिगनल क्षेत्र में घात लगाकर जांच करना।

(2) खास विश्लेषक जांच का अचानक प्रबंध।

(3) दृश्यता और सिगनलों की रोशनी पर निगरानी रखने के लिए बार-बार फुट प्लेट का निरीक्षण।

(4) यह सुनिश्चित करना कि ड्यूटी की पारियों के बीच रनिंग कर्मचारी उपयुक्त विश्राम करें।

(5) समपारों पर संरक्षा बढ़ाने तथा वहां दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न उपकरणों जैसे समपार फाटकों पर अनार्पाशन, स्टेशनों तक टेलीफोन कनेक्शनों, चेतावनी घंटियों, लिफ्टिंग बेरियरों, सड़क संकेतों आदि की व्यवस्था की गई है।

(6) बार-बार प्रचार अभियान चलाना ताकि समपारों पर एहतियात बरतने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित किया जा सके।

गौडा और पंजवाड़ा के बीच रेल सम्पर्क

107. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के गौडा जिले को पंजवाड़ा रेल हाल्ट से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात

[अनुवाद]

108. **श्री उदय सिंह राव नानासाहिब गायकवाड** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात को 200 मिलियन लीटर से बढ़ाकर लगभग 700 मिलियन लीटर करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए संभावित आधिक्य और उपलब्ध अवस्थापनाओं को ध्यान में रखते हुए 200 मिलियन लिटर अल्कोहल के निर्यात की अनुमति दी गई है। यदि ऐसी स्थिति हुई तो अधिक मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

हेलीकाप्टरों को किराये पर लेना

109. **डा० बंगाली सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन-किन देशों से हेलीकाप्टर किराये पर लिये हैं और इस पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या इन हेलीकाप्टरों का उपयोग पूर्ण रूप से उसी प्रयोजन के लिए किया गया है; जिस प्रयोजन के लिए ये किराये पर लिये गये थे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ हेलीकाप्टर वापस भेजे गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

110. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने कर्नाटक को मिट्टी के तेल और पेट्रोल की सप्लाई में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी के तेल और पेट्रोल की सप्लाई कितनी कम की गई है;

(ग) पहले कुल कितनी मात्रा में सप्लाई की गयी थी; और

(घ) अन्य राज्यों की सप्लाई में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क), (ख) और (घ) कर्नाटक को पेट्रोल की आपूर्ति में कटौती नहीं की गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा स्रोत में कठोर अड़चनों की वजह से मानसून ब्लाक के लिये सभी राज्यों को दिये जाने वाले मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि की दर को गत वर्ष के इसी अवधि के लिए सम्मत 7 प्रतिशत की अपेक्षा इस वर्ष मात्र 4 प्रतिशत की वृद्धि की सहमति दी गई है।

(ग) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान कर्नाटक को आपूर्ति की गई मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

मिट्टी का तेल	1988	— 398925 टन
	1989	— 420713 टन
पेट्रोल	1988-89	—188,000 टन
	1989-90	—216,000 टन

केरल में रसोई गैस की एजेंसियां

111. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्य पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में इस समय जिला-वार रसोई गैस की कितनी एजेंसियों कार्य कर रही हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : केरल में राज्यवार कार्य कर रही खाना पकाने की गैस की एजेंसिया :

राज्य	एजेंसियों की संख्या
1. ऐलीपि	11
2. कैनोर	7
3. कालीकट	10
4. अननाकूलम	32
5. इडूकी	3
6. कोटयाम	14
7. कसारकोड	4
8. मलापुरम	7
9. पालघाट	12
10. पथानामथिटा	8
11. त्रिवेन्द्रम	22
12. त्रिछूर	16
13. क्वीलोन	13
14. वयानाड	1
कुल	160

जम्मू और कश्मीर की पनबिजली परियोजनाएं

112. **श्री प्यारे लाल हाण्डू : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर की निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना का जिन राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को ठेका दिया गया है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम निम्नानुसार हैं :—

क्र० सं० परियोजना का नाम	प्रतिस्थापित क्षमता	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी/ठेकेदार
केन्द्रीय क्षेत्र		
1. दुलहस्ती	3×130 मे० वा०	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/टर्नकी आधार पर मैसर्स सी० ई० जी० ई० एल० ई० सी० के नेतृत्व में फ्रेंच कंसोर्टियम के द्वारा।
2. उरी	4×120 मे० वा०	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/मैसर्स स्केनस्का स्वीडन के नेतृत्व में स्वीडिश कंसोर्टियम के आधार पर क्रियान्वयन।
3. सलाल-दो	3×115 मेगावाट	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/मैसर्स एन० पी० सी० सी० एवं मैसर्स कर्मचन्द थापर ब्रदर्स (कोल सेल्स) लिमिटेड।
राज्य क्षेत्र		
4. कारगिल	3×1.25 मेगावाट	जे० एण्ड पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (जे० के० पी० डी० सी०)
5. अपर सिंध चरण-2	2×35 मेगावाट	जे० के० पी० डी० सी०
6. अपर सिंध चरण-2 (विस्तार)	1×35 मेगावाट	जे० के० पी० डी० सी०

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत

[हिन्दी]

113. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे, नागर विमानन और कृषि क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों की वार्षिक खपत कितनी-कितनी है;

(ख) क्या तेल कम्पनियां ने गैर-सरकारी और सरकारी परिवहन प्रणाली में सुधार करने और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में कारगर कमी करने के लिए कतिपय उपाय अपनाने के सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) रेल तथा नागर विमानन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक खपत नीचे दी गई है :—

(आंकड़े हजार टन में)

रेल में डीजल की खपत

1986-87	—	1309
1987-88	—	1375
1988-89	—	1440

विमानन क्षेत्र में विमानन टरबाइन ईंधन (ए० टी० एफ०) की खपत

1986-87	—	1603
1987-88	—	1654
1988-89	—	1713

कृषि क्षेत्र में खपत

कृषि क्षेत्र के लिए अलग से कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को प्रभावकारी ढंग से कम करने के लिए निजी तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था ने अन्य उपायों में से निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं :—

(1) पुराने तथा अक्षम वाहनों को चरणबद्ध रूप में हटाना।

(2) सक्षम डिजायन वाले वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(3) अच्छे चालकीय कला को प्रोत्साहन देना।

(4) आदर्श कार्यशालाओं की संकल्पना।

(5) सही रख-रखाव सारणी कार्यक्रम के बारे में जागरूकता का सृजन।

(6) जन जागृति योजना।

(7) सड़क की हालात में सुधार।

इन पर तथा अन्य संबंधित उपायों पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

बिलासपुर और कटनी के बीच रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों का पुनः लगाना

114. श्री ए० लरंग साय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामपुर और कटनी के बीच चलाई जाने वाली रेलगाड़ी जिसमें दिल्ली और भोपाल के लिए सवारी डिब्बे जोड़े जाते थे, 1 मई, 1990 से रद्द कर दी गई है;

(ख) क्या इस प्रकार सरगुजा जिले के 18 लाख लोगों को राज्य की राजधानी (भोपाल) और देश की राजधानी (दिल्ली) की यात्रा सुविधा से वंचित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त रेलगाड़ी पुनः चलाए जाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, विश्रामपुर और निजामुद्दीन/इन्दौर के बीच चल रहे स्लिप सवारी डिब्बों का चलाना बन्द कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनूपपुर में शंटिंग परिचालनों से उत्पन्न भारी कठिनाइयों के कारण, यह परिवर्तन किया गया था। तथापि, इन्दौर की ओर नर्मदा एक्सप्रेस और निजामुद्दीन की ओर उत्कल एक्सप्रेस, जिनके द्वारा ये स्लिप सवारी डिब्बे कर्षित किए जा रहे थे, में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की गयी है। यथापूर्व स्थिति को बहाल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मलेशिया से प्राप्त रेलवे ठेका

[अनुवाद]

115. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने मलेशिया की रेलवे से एक ठेका प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक प्रारंभ होने तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इरकान को अक्तूबर, 1988 में स्टेशन पलोह से सिंगापुर तक तथा सलिम नदी से सेरमबैन मुख्य लाइन तक 327 कि० मी० लम्बे रेल पथ के पुनर्स्थापन का ठेका मिला है। यह कार्य नवम्बर, 1988 में शुरू कर दिया गया था तथा जिसे 9 अप्रैल, 1992 तक पूरा किया जाना है।

(ग) परियोजना की लागत 181 मिलियन एम डालर है (मौजूदा मुद्रा विनियम की दर से हिसाब से 116 करोड़ रुपये)।

कोच रिपेयर फैक्टरी, भोपाल में गैस से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

116. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी, 1984 के पीड़ित लोगों का भोपाल में स्थापित की जा रही कोच रिपेयर फैक्टरी में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह आरक्षण किस अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और तत्संबंधी अन्य शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस फैक्टरी की परियोजना रिपोर्ट में विभिन्न श्रेणियों में कितने पद उपलब्ध कराये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा भोपाल गैस के शिकार व्यक्तियों को भोपाल स्थित सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने में नियोजित करने के मामले में विचार करने हेतु एक बारगी उपाय के रूप में निम्नलिखित रियायतें प्रदान की गई हैं :—

(1) 1984 की भोपाल गैस त्रासदी (गैस से प्रभावित व्यक्तियों) से प्रभावित व्यक्तियों को तरजीह दी जायेगी बशर्ते वे भोपाल स्थित डिब्बा मरम्मत कारखाने के लिए स्वीकृत पदों के प्रारंभिक भर्ती की कोटियों में 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती के लिए अन्यथा पात्र तथा योग्य हों। (शुरू में सितम्बर, 1988 में इसके लिए पदों के 33-1/3 प्रतिशत तक पद निर्धारित किए गए थे। इसे फरवरी, 1989 में एक विशेष रियायत के रूप में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था)।

(2) गैस से प्रभावित उन व्यक्तियों, जिन्होंने संबद्ध ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पाठ्यक्रम या प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हों, के मामले में भी उक्त 50 प्रतिशत पदों के लिए यथोचित रूप से विचार किया जायेगा।

(3) गैस से प्रभावित जिन व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सघन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, यदि वे उपयुक्त समझे जाते हों तो उन्हें अनंतिम रूप से चुन लिया जायेगा तथा शेष अवधि में प्रशिक्षण की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी। इनमें से केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुने गये उम्मीदवारों के पैनल में रखा जायेगा जो अन्ततः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

(4) चिकित्सा मानकों में सीमित छूट दी गयी है।

(5) ग्रुप "सी" और "डी" के पदों पर खुली भर्ती में अधिकतम 30 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दी गयी है।

प्रारम्भ में ये रियायतें 30-6-1990 तक वैध थीं। इन सुविधाओं के लिए जारी किए गए अनुदेशों की वैधता अवधि 31-12-1990 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) सवारी डिब्बा कारखाने की परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न कोटियों में लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

विभाग	ग्रुप "सी"	ग्रुप "डी"
सिविल	282	96
लेखा	86	34
विद्युत	40	3
सिगनल एवं दूरसंचार	53	13
यांत्रिक	38	16
जोड़	499	162

करनाल तेल शोधक कारखाने की स्थापना

[अनुवाद]

117. **श्री हेत राम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य मूलतः कब तक पूरा होना था;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और मूल लागत से कितनी अधिक धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में क्या बाधाएं हैं; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी) : (क) सितम्बर, 1984 में यथा अनुमोदित करनाल रिफाइनरी को पूरा करने का निर्धारित समय सितम्बर, 1989 था जैसा कि आरम्भ में परिकल्पना की गई थी।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने अब तक मुख्यतः रिफाइनरी के लिए जमीन के अधिग्रहण पर करीब 8 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में साधनों की सीमितता की वजह से यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा टाटा केमिकल्स लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा पूरा किया जाए। परियोजना के लिए सोवियत सहायता पर भी विचार किया गया था। सोवियत सहायता की शर्तों तथा कार्यक्षेत्र का जिसके तहत परियोजना के लिए तकनीकी तथा उपस्करण का चयन किया जाना है, फिलहाल मूल्यांकन किया जा रहा है। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इस परियोजना की लागत में संभावित वृद्धि तथा इसे पूरा करने के निर्धारित कार्यक्रम को इन ब्यौरों के तैयार हो जाने के बाद ही निश्चित किया जा सकेगा।

पेट्रोल की खपत तथा उसका आयात

[हिन्दी]

118. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में पेट्रोल का आयात किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई पेट्रोल और पेट्रोल के रूप में सीधे आयात की गई पेट्रोल की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उपभोग किया गया पेट्रोल	पेट्रोल का आयात
1987-88	2810	16
1988-89	3045	शून्य
1989-90	3484	"

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल के आयात हेतु व्यय की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1987-88	3.65
1988-89	—
1989-90	—

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

[अनुवाद]

119. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कम सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच० एम० टी० लिमिटेड, हैदराबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति

120. श्री अनादि चरण दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित एच० एम० टी० लिमिटेड में 1 जून, 1989 और 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार "क", "ख" और "ग" श्रेणियों में भर्ती और पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद बकाया पड़े हैं; और

(ख) आरक्षित पदों के पिछले बकाया पदों के भरने हेतु वर्ष 1989 के विशेष भर्ती अभियान तथा वर्तमान भर्ती अभियान के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई/पदोन्नतियां की गईं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का "बैकलॉग" निम्न प्रकार है :—

1-6-89	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
श्रेणी		
क.	18	9
ख.	10	17
ग.	—	5
30-6-90		
श्रेणी		
क.	18	9
ख.	11	17
ग.	1	5

पदोन्नति में कोई "बैकलॉग" नहीं है।

(ख) 1989 के दौरान विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत कम्पनी में श्रेणी "ख" में 28 अनु० जाति तथा 3 अनु० ज०जा० के उम्मीदवारों की भर्ती की गई। इनमें से श्रेणी ख में 2 अनु० जाति और 1 अनु० ज० जा० के उम्मीदवारों को एच० एम० टी० हैदराबाद में तैनात किया गया।

पंजाब और हरियाणा स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

121. श्री कमल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान और आगामी दो वर्षों के दौरान पंजाब और हरियाणा में उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर प्रस्तावित स्टेशन भवनों, प्लेटफार्मों, टर्मिनल भवनों के निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में टर्मिनल भवन

का कोई कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्लेटफार्मों तथा स्टेशन इमारतों से संबंधित निम्नलिखित निर्माण कार्य चल रहे हैं/करने की योजना है :—

क्रम सं० राज्य	कार्य की किस्म	स्टेशन	योजना
1. हरियाणा	स्टेशन की इमारत में परिवर्धन	जींद	रोहतक और जाखल के बीच दोहरी लाइन बिछाना, चरण-I
	अतिरिक्त प्लेटफार्म	किनाना, बिशनपुर जींद, बरसोला, घासा, नरवाना, धरोदी, धमतान साहिब, कालवन हाल्ट, टोहाना, हिम्मतपुर, पाटिल, जटोला जोड़ी सांपका, पटौदी रोड, इच्छापुरी	— यथोक्त— गढ़ी—हरसरू खलीलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना
	पटरी सतह वाले प्लेटफार्म	जींद शहर, कैथल, सफीदों, सिरसा, कोहंड	
	प्लेटफार्मों का विस्तार	गुड़गांव	
2. पंजाब	प्लेटफार्मों का विस्तार	बुढलाडा, बरेठा	

भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड द्वारा चश्मों की अच्छी किस्म के शीशों का उत्पादन

122. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड नजर के चश्मों के अच्छी किस्म के शीशों का उत्पादन करता है;

(ख) क्या यह फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में उपलब्ध शीशों के समान उत्तम है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड द्वारा इन शीशों का कुल उत्पादन देश में इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इन शीशों/लैंसों का आयात मूल्य कितना था ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड द्वारा आफ्थैल्मिक ग्लास का कुल उत्पादन देश की आफ्थैल्मिक ग्लास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ङ) आफ्थैल्मिक ग्लासों/लेंस ब्लैंकों के आयात का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक है।

विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग

123. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अधीन विदेशी व्यापार चिह्न को कोई अलग परिभाषा नहीं है। मौजूदा कानून के अधीन विदेशी व्यापार चिह्न के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते इसमें विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विचार अंतर्ग्रस्त न हो। किसी व्यापार चिह्न का प्रयोग, बिना पंजीकरण अथवा व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम द्वारा प्रदत्त संरक्षण के बिना पंजीकरण से पूर्व अथवा उसकी समाप्ति के बाद किया जा सकता है। तथापि, विदेशी सहयोग अनुमोदनों को मंजूरी देते समय, एक मानक शर्त लगाई जाती है कि आंतरिक बिक्री हेतु उत्पादों पर प्रयोग के लिए विदेशी ब्रांड के नामों की अनुमति नहीं दी जायेगी, यद्यपि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर उनके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी सहयोग के अनुमोदन की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

जेद्दाह से कालीकट के लिए सीधी उड़ान सेवा

124. श्री के० मुरलीधरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेद्दाह से कालीकट, बरास्ता बम्बई की उड़ान के लिए प्रति माह, औसतन कितने व्यक्ति यात्रा करते हैं;

(ख) क्या एअर इंडिया को मई, 1990 में जेद्दाह केरल मुस्लिम कल्चरल सेन्टर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जेद्दाह से कालीकट तक एक सीधी उड़ान आरम्भ करने का फैसला किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बम्बई से होकर जेद्दाह से कालीकट की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि जेद्दाह से कुछ यात्रियों का वहन विदेशी कम्पनियों द्वारा भी किया जाता है और कोई केन्द्रीकृत रिकार्ड

उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जेद्दाह केरल मुस्लिम कल्चरल सेन्टर सेंट्रल कमेटी, जेद्दाह, सऊदी अरब ने एयर इंडिया से जेद्दाह और कालीकट के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कालीकट हवाई अड्डा एयर इंडिया द्वारा किए गए विमान प्रचालनों को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है।

औषधों का मूल्य नियंत्रण

125. **श्री वसंत साठे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधों को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रक्रिया को उन मदों के मामले में भी अपनाया गया है, जिन्हें हाल ही में मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है;

(ग) क्या सभी औषधों को, जिनकी अवतरण लागत 50 लाख रुपये से अधिक है, मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार उक्त सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1986 में घोषित औषध और भेषज उद्योग के युक्तियुक्तकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और वृद्धि के उपायों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित औषधें श्रेणी-I में आती हैं जबकि केलकर समिति द्वारा अभिज्ञात अन्य आवश्यक औषधें श्रेणी-2 में हैं।

(ख) जी, हां। केलकर समिति द्वारा अनुशंसित मापदण्डों को श्रेणी-II में औषधों को शामिल करने के लिए अपनाया गया है।

(ग) से (ङ) मेरे द्वारा गठित स्थाई समिति प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों और औषधों को शामिल करने और शामिल न करने के खिलाफ उठाये गए मुद्दों पर पहले ही विचार कर रही है।

बंगलौर-मैसूर रेल लाइन को बदलना

126. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर आर बंगलौर के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इस परियोजना की मूल अनुमानिम लागत क्या थी और अंतिम अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने में और अधिक विलम्ब न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान।

(ख) 1979-80 में परियोजना की मूल अनुमानित 14 करोड़ रुपये थी तथा नवीनतम अनुमानित लागत 78.86 करोड़ रुपये है।

(ग) इस परियोजना के लिए 1989-90 के दौरान आबंटित की गई 17 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 1990-91 के दौरान 27 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जो काफी अधिक है।

पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की बचत

127. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पम्पों को रविवार और अन्य दिनों में निश्चित घंटे खोलने के परिणामस्वरूप पेट्रोल/डीजल की कितनी मात्रा की बचत हुई; और

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती करने के परिणामस्वरूप पृथक-पृथक रूप से इनकी बचत की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिए 21 जून, 1990 को घोषित किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व होगा।

राजस्थान के ताप विद्युत संयंत्र

128. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र को भीलवाड़ा जिले में मण्डलगढ़ में ही लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इष्टतम परिणाम प्राप्त करने तथा प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मंडलगढ़ में 3 × 210 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अगस्त, 1984 में प्राप्त हुआ था। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को जल और अन्य निवेश सुनिश्चित करने के लिए आगे जांच पड़ताल करनी है। तदनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवश्यक निवेश सुनिश्चित करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजने की सलाह दी गई थी। संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

सोलापुर से पुणे के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

129. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की ओर से सोलापुर से पुणे के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

मंगरा स्टेशन के समीप हुई दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति

[हिन्दी]

130. **श्री हरीश पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मंगरा स्टेशन के समीप और इटारसी के समीप दोलरिया स्टेशन के निकट 25 जून, 1990 को हुई दुर्घटनाओं की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन जांचों के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में क्रमशः कुल कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मरे;

(घ) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कुल कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में मंगरा स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। इस दुर्घटना में 22 व्यक्ति मारे गये तथा 62 व्यक्ति घायल हुए।

वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में दुलरिया स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच की गई है। उसके निष्कर्षों के अनुसार, रेल कर्मचारियों की गलती के कारण दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गए तथा 28 व्यक्ति घायल हुए।

(घ) और (ङ) अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। दुर्घटना स्थल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले रेल दावा अधिकरण की खंड पीठ द्वारा मुआवजे का फैसला किया जाता है। यह एक न्यायिक निकाय है। तथापि, रेलें घायल यात्रियों तथा मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में 95,000 रुपये का भुगतान कर चुकी हैं।

एटा-टूंडला शाखा लाइन की आर्थिक सक्षमता

131. **डा० महावीर सिंह शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एटा-टूंडला शाखा लाइन पर हो रहे घाटे को रोकने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, उत्तर रेलवे के

टूंडला-एटा खंड पर बरहन-एटा शाखा लाइन के घाटे को रोकने के लिए, पैसेंजर गाड़ियों का मिश्रित गाड़ियों से बदलाव, "केवल एक इंजन" प्रणाली को लागू करना, कर्मचारी लागत में कमी, बिना टिकट यात्रा पर काबू पाना, अलाभकर स्टेशनों और हाल्टों को बंद करना अथवा ठेकेदार द्वारा चालित हाल्टों आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

न्यू आजादपुर में नया रेल टर्मिनल

[अनुवाद]

132. श्री प्रतापराव बो० भोसले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का न्यू आजादपुर रेलवे स्टेशन पर नया रेल टर्मिनल बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) होलम्बी कलां, बिजवासन और आनन्द विहार में नये टर्मिनलों की योजना बनायी गयी है।

कानपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाना

133. श्री केशरी लाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के गैर-सैनिक हवाई अड्डे पर सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार, कानपुर के गैर-सैनिक हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार का कानपुर के लिए इंडियन एयरलाइंस की दैनिक उड़ान शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां तो, यह सेवा कब से शुरू हो जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) छोटे विमानों और उड़ान क्लब के लिए कानपुर सिविल एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) इस एयरपोर्ट का स्तर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

(ङ) कानपुर के लिए वहां से आने वाले वर्तमान यातायात इतना नहीं है कि दैनिक सेवा चलाई जाए।

भटिंडा और कांडला के बीच रेल लाइन

134. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा और कांडला के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब से शुरू होने की संभावना है और यह परियोजना कब तक पूरी होने की आशा है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि का परिव्यय रखा गया है और इसका संसाधन जुटाने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। इस कार्य को 1990-91 के बजट में शामिल किया गया है। इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) 1990-91 के दौरान इन परियोजना के लिए परिव्यय की राशि 19 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था सरकार के बजटीय समर्थन से की गयी है।

कानपुर-बांदा और बांदा-मानिकपुर सैक्शनों में "इन्टरलॉकिंग सिस्टम"

[हिन्दी]

135. **श्री राम सजीवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के कानपुर-बांदा और बांदा-मानिकपुर सैक्शनों में इन्टरलॉकिंग सिस्टम के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) कोई विलम्ब नहीं हुआ है, कार्य की संतोषजनक प्रगति हो रही है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) कार्य के पूरा होने की लक्ष्य तिथि 31-12-91 है।

(घ) 31-12-91 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

बांदा स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण

136. **श्री राम सजीवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी डिवीजन में बांदा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल के पहुंचमार्ग पर किया जा रहा कार्य अभी भी अधूरा है लेकिन रेलवे ने रेलपथ पर पुल खास का कार्य पूरा कर दिया है।

(ग) यह, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल के पहुंच मार्ग का कार्य (वर्तमान प्रगति-65 प्रतिशत) पूरा किये जाने पर निर्भर करेगा।

तेल क्षेत्रों का विकास

[अनुवाद]

137. **श्री वी० एन० रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नये तेल क्षेत्रों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—

I. **अपतटवर्ती**

(क) नई संरचनाएं

(i) नीलम

(ii) मुक्ता

(iii) पन्ना

(iv) रावा

(v) पीवाई-3

(ख) निम्नलिखित अंशत: विकसित संरचनाओं का आगे विकास हुआ—

(i) हीरा

(ii) बम्बई हाई (एल-II और एल-III)

II. **तटवर्ती**

(क) नई संरचनाएं

—बचराजी, नाडा गुजरात में

—नारीमनम, आदियक्कमंगलम— कावेरी में

—डेमुलगांव, विस्तार, खोराघाट, शालमारी, हैप्पन, डिकोम और कुमचई—
असम और अरुणाचल प्रदेश में

(ख) निम्नलिखित अंशतः विकसित संरचना का आगे विकास विकास हुआ : संधार

तालचेर से आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कोयले की सप्लाई

138. श्री बी० एम० रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तालचेर से आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश से 8वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले के संयोजन का लाभ लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—

(1) मुदानूर थर्मल पावर स्टेशन (2 × 210 मे० वा०)

(2) विजयवाड़ा विस्तार चरण-III (2 × 210 मे० वा०)

(3) विशाखापतनम थर्मल पावर स्टेशन (2 × 500 मे० वा०)

(4) मानुगुरू थर्मल पावर स्टेशन (2 × 500 मे० वा०)

मुदानूर थर्मल पावर स्टेशन को सिंगरेनी कोलयरीज कंपनी लि० की कोयला खानों से पहले ही कोयले का संयोजन प्रदान कर दिया गया है। विजयवाड़ा चरण-III थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयले का संयोजन उड़ीसा के ईब घाटी कोयला क्षेत्रों से निर्धारित कर दिया गया है। विशाखापतनम थर्मल पावर स्टेशन के मामले में, जिसको 500 मे० वाट की प्रथम यूनिट को वर्ष 1994-95 के अंत तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है, और चूंकि सिंगरेनी खानों से कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा, अतः प्रथम यूनिट के मामले में संयोजन पर या तो तालचर से अथवा उड़ीसा से ईब घाटी कोयला क्षेत्रों से संयोजन किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के शुरू से प्रभावी किया जाना है। सिंगरेनी क्षेत्रों में कोयला की मांग तथा उपलब्धता में निरन्तर कमी के कारण प्रस्तावित मानुगुरू थर्मल पावर स्टेशन को कोयले का संयोजन प्रदान किया जाना संभव नहीं हो सका है।

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां

139. श्री बी० एम० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश में नये पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में आयोजनागत खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का जिलावार ब्यौरा

जिला	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1	2	3
1. आदिलाबाद	1. आदिलाबाद	
2. अनन्तपुर	2. गूटी-II	
3. चित्तूर	3. पूंगनबार	
4. कुडापाह	4. चितवेल	
5. गोदावरी (पूर्व)	5. काकीनाडा	
	6. रावूलालेम (2 स्थान)	
6. गोदावरी (पश्चिम)	7. मादापाडू	1. कोयलगुडम
	8. गोपालपुरम	2. भीमावरम
	9. पल्लावरम	3. गन्नापावरम
7. गुंटूर		4. पिडीगुराल्ला
8. करनूल	10. मन्त्रालायम	
9 कृष्णा	11. जगयापेट	5. विजयवाड़ा (2 स्थान)
10. खमाम	12. कोथागुडम	
	13. असवारोपेट	
	14. कुनावरम	
11. करीमनगर	15. सिरचिला	
12. हैदराबाद	16. हैदराबाद (2 स्थान)	6. हैदराबाद (5 स्थान)
13. मेडक		7. पेटानचिरू
14. मेहबूबनगर	17. देवरकाडरा	
15. नालगोंडा		8. नालगोंडा
16. नेलूर		9. गूडूर
		10. तिरुपति
17. रनगेरेड्डी	18. मल्लापुरम	11. अल्वाल

1	2	3
	19. तूरका इमजाल	
	20. पेडाम्बरयेट	
	21. हैदराबाद-नागपुर हाईवे	
18. श्रीकाकूलम	22. भावनगन फिशिंग हारबूर	12. श्रीकाकूलम
	23. राजम	
19. विशाख	24. देवरापल्ली	13. गोपालपटनम
	25. विशाख (3 स्थान)	
	26. विजयपटनम	
20. वारांगल	27. मोडीकोंडा	
	28. इटरागरम	
	29. वीनावनाका	
21. विजयवाड़ा	30. इलूरू रोड	

ललितपुर स्टेशन पर उपरिपुल

[हिन्दी]

140. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ललितपुर रेलवे स्टेशन के सामने नई बस्तियों के स्थापित होने के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार इस पर आने वाली लागत को वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए इस सुविधा के लिए रेलवे को कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी में आवास समिति

141. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा झांसी में आवास समिति पांच वर्ष पहले पंजीकृत की गयी थी;

(ख) क्या इस समिति को भूमि आवंटित कर दी गयी है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति के लिए भूमि खरीदने की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है और इससे भूमि आवंटित कर दिए जाने के बाद समिति द्वारा निर्माण कार्य कब से शुरू करने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) झांसी स्थित बी० एच० ई० एल० संयंत्र के कुछ कर्मचारियों ने एक सहकारी समिति बनाई थी जो लगभग 6 वर्ष पहले पंजीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) समिति से भूमि की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से सम्पर्क किया था लेकिन समिति द्वारा परिषद की शर्तें पूरी न किये जाने के कारण भूमि का आवंटन नहीं किया गया। भूमि के आवंटन के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

धौली एक्सप्रेस के मार्ग में विस्तार करना

[अनुवाद]

142. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धौली एक्सप्रेस को उड़ीसा में भुवनेश्वर से बहरामपुर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समझौता

143. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1990 के शुरू में किसी पेट्रोलियम उत्पाद के लिए नेपाल के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1-7-1990 से पांच वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु नेपाल ऑयल कारपोरेशन, नेपाल के साथ करार पर 30-6-1990 को हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस करार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(i) 1-7-1990 से प्रभावी यह करार 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(ii) नेपाल ऑयल कारपोरेशन विदेशी सप्लायरों से एस० के० ओ०/एच० एस० डी० का आयात करता है जिसके लिए वे सीधे सप्लायर को भुगतान करते हैं।

(iii) नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा आयात किए गए उत्पाद इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा नामित भारतीय बंदरगाहों पर छोड़े जाते हैं।

(iv) इंडियन ऑयल कारपोरेशन नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा किए गए ऐसे आयातों के प्रति नेपाल ऑयल कारपोरेशन को उत्पाद की उतराई पूरी होने की तारीख को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर पर भारतीय रुपये में भुगतान करता है। पहले 50 प्रतिशत का भुगतान माल उतरने के तुरन्त बाद किया जाना है और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान इंडियन ऑयल कारपोरेशन के टैंकों में प्राप्त हुई वास्तविक मात्रा के आधार पर भराई के बिल की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाता है।

( ) नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन को समान कीमत वाले उत्पादों की सुपुर्दगी के आधार पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा एम० एस०, एच० एस० डी०, एस० के० ओ०, एल० पी० जी०, ए० टी० एफ०, एल० डी० ओ०, एफ० ओ०, बिटुमन, जे० बी० ओ०, एम० टी० ओ०, हेक्सेन और ल्यूब बेस तेल जैसे वांछित पेट्रोलियम उत्पादों की अदला-बदली करता है। इन उत्पादों की पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र तथा नेपाल के नजदीक स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन के विभिन्न भंडारण बिंदुओं से नेपाल ऑयल कारपोरेशन को सुपुर्दगी दी जाती है।

(vi) नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा आयातित उत्पादों को सुपुर्दगी के प्रति उपर्युक्त उत्पादों का विनिमय सहमति के आधार पर किया जाता है और यदि वर्ष के अंत में कोई असंतुलित होता है तो उसे अगले वर्ष में समायोजित किया जाता है।

(vii) नेपाल ऑयल कारपोरेशन के बेचे गए विभिन्न पी० ओ० एल० उत्पादों का मूल्य अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर-मार्च के लिए छमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है जो नेपाल ऑयल कारपोरेशन द्वारा क्रमशः अगस्त-जनवरी और फरवरी-जुलाई की पिछली छमाहियों के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत पर आधारित होते हैं।

(viii) विनिमय करार में नेपाल ऑयल कारपोरेशन को कोई मूल्य संबंधी सहायता शामिल नहीं होगी।

(ix) नेपाल ऑयल कारपोरेशन से क्रय करने और उसे बेचने पर सभी भुगतानों का लेन-देन भारतीय रुपये में किया जाता है और इससे देश को किसी तरह से विदेशी मुद्रा की हानि नहीं होती है।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण

144. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण औद्योगिकीकरण को सहायता प्रदान करने के कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में योजना आयोग के साथ जून, 1990 में कोई विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का सम्बन्ध है, ग्रामीण उद्योगों की सहायतार्थ निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

- ---आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है,
- —ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए योजना के तहत 205 करोड़ रुपये के बढ़ाये गये बजट का आबंटन,
- —आठवीं योजना के दौरान 1.5 लाख अतिरिक्त ग्रामों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्य क्षेत्र का विस्तार,
- — खादी तथा ग्रामोद्याम को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही सीमित करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधित किया गया है,
- —कम ब्याज दर पर धन का प्रावधान,
- —उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास,
- —खादी की बिक्री पर छूट,
- —कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में वरीयता देना,
- —ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों को खरीदने में वरीयता,
- --वित्तीय तथा राजकोषीय रियायतें देना।

(ख) जी हां। योजना आयोग में 21 जून, 1990 को आठवीं योजना तैयार करने के सम्बन्ध में ग्रामीण तथा लघु उद्योग इत्यादि सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक दल की एक बैठक हुई।

(ग) बैठक में लिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया।

दिल्ली के गैर नियमित क्षेत्रों में लघु उद्योग एककों की स्थापना

145. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के गैर नियमित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग एकक विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एककों को नियमित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित करने के बारे कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकांत जेना) : जी, हां।

(ख) से (घ) 1960 से 1979 तक उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए लागू की गयी नीति अनेक कारणों से असफल रही थी, जिनमें ये कारण शामिल हैं :—

असंगत क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से बड़ी संख्या में एककों का स्थापित होना, औद्योगिक कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर विघटन होना, ऐसे एककों द्वारा समुदाय को दी गयी लाभदायक सेवाओं की अनदेखी करने की कठिनाईयां उद्योगों के लिए वैकल्पिक स्थान का सृजन करने हेतु बड़े पैमाने में निवेश का आवश्यक होना, कामगारों के लिए आवास उपलब्ध कराना तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं देना और परिवहन की गंभीर बाधाओं का होना। दूसरी ओर दिल्ली प्रशासन ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में किसी और औद्योगिक क्षेत्र का विकास न करने का निर्णय लिया है। किंतु 31-12-1989 तक असंगत क्षेत्रों में स्थापित हुए औद्योगिक एककों का दिल्ली नगर निगम द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए तदर्थ पंजीकरण करने की अनुमति दी गयी थी कि इन उद्योगों में पर्याप्त विनिर्माणकारी कार्यकलाप तथा रोजगार अंतर्ग्रस्त हैं और अल्प समय में इनके कार्यकलापों को संगत क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने में कठिनाइयां थीं। निम्नलिखित वर्गों के उद्योग दिल्ली नगर निगम से तदर्थ पंजीकरण कराने के योग्य नहीं हैं।

(i) नियोजित कालोनियों अर्थात जो कालोनियां डी० एम० सी० अधिनियम, 1957 लागू होने के बाद विकसित की गयी हैं, अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ियों के बीच, कर्मचारी आवास कालोनियां तथा एन० डी० एम० सी० क्षेत्रों में स्थित एकक।

(ii) भू-तल के अतिरिक्त अन्य मंजिलों पर स्थित एकक

(iii) वे व्यवसाय जो प्रदूषणकारी/खतरनाक/हानिकारक हैं।

(iv) वे व्यवसाय जो स्वास्थ्य/आग की दृष्टि से खतरनाक हैं।

बक्रेश्वर विद्युत परियोजना के लिए सोवियत संघ से ऋण

146. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरेश्वर विद्युत परियोजना के लिये सोवियत संघ से पर्याप्त ऋण प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ से कितना ऋण प्राप्त होने की संभावना है और इससे इस परियोजना की अनुमानित लागत को कहां तक पूरा किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। सोवियत प्राधिकारियों के साथ तकनीकी बातचीत के बाद बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना को चरण-एक (3 × 210 मेगावाट) चरण दो (1 × 210 मेगावाट) के रूप में क्रियान्वित किए जाने के संबंध में प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यू० एस० एस० आर० से की जाने वाली आपूर्तियों एवं उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है और

परियोजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें लागत भी शामिल है। सोवियत संघ से मिलने वाली ऋण-राशि का पता यू० एस० एस० आर० के साथ अन्तिम करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चलेगा।

कर्नाटक में बायो गैस विकास कार्यक्रम

147. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में बायो-गैस के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि देने का विचार किया गया है; और

(ख) उसके अन्तर्गत लाए जाने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) के अन्तर्गत 1990-91 कर्नाटक राज्य सरकार को पारिवारिक बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 137.00 लाख रुपए की राशि देने का प्रस्ताव है जिसमें 65.00 लाख रुपए की पहली किस्त पहले ही स्वीकृत कर दी गई है।

(ख) बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत पारिवारिक बायो गैस संयंत्रों को कर्नाटक राज्य के सभी जिलों में स्थापित किया जा रहा है।

कोयला खानों में आग

148. **श्री हाराधन राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कौन-कौन-सी कोयला खानें आग लगने के कारण बंद हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आग से कितनी मात्रा में कोयले की हानि हुई;

(ङ) प्रभावित लोगों की कुल कितनी धनराशि की सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(च) इन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कितनी मुआवजा राशि प्रदान की है या प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1987 से अब तक की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को दो कोलियरियों, अर्थात् गिरीमिन्ट कोलियरी तथा चूसिक (आर) कोलियरी की न्यू चूसिक यूनिट, को आग लगने के कारण बंद करनी पड़ी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की दो अन्य कोलियरियां, मधुजोर कोलियरी की जे० के० यूनिट तथा दहुला कोलियरी की साउथ समला यूनिट भी लगातार गर्म होने अथवा आग लगने के कारण वर्ष 1989 के दौरान अल्पावधि के लिए बंद करनी पड़ी। इन दोनों कोलियरियों को अब पुनः चालू कर दिया गया है। भारत कोकिंग कोल लि० की वेस्ट विक्टोरिया कोलियरी में लगातार गर्म होने के एक मामले की सूचना मिली है और आग लगने के पूर्व इस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है।

(ख) और (ग) ई० को० लि० की उक्त चार कोलियरियों में लगी आग के संबंध में जांच की गई। इस जांच से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए :—

कोलियरी	निष्कर्ष
1. गिरीमिन्ट	आग संभवत: बिजली का खराबी से लगी और यह भारी टिम्बर सपोर्ट की वजह से और बढ़ गई।
2. न्यू घूसिक यूनिट	1960 और 1970 के दशकों में पैनेल की ठीक से भराई नहीं हुई थी। रुकावटों का निर्माण-कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं किया गया था।
3. मधुजोर कोलियरी की जे० के० यूनिट	पुराने "शोफ्ट आउट" पैनेल का लगातार गर्म होना।
4. बहुला कोलियरी की साउथ सामला यूनिट	पुराने सील्ड-आफ पैनेल का प्रारंभिक रूप में गर्म होना।

जांच से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, ई० को० लि० द्वारा इस क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की कड़ाई से जांच, पुराने उपकरणों की नियमित जांच, रुकावटों के नीचे की जगह की नियमित जांच, रुकावटों तथा प्रेशर बैलेन्सिग की नियमित रूप से मरम्मत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(घ) आग लगने के कारण गिरीमिन्ट कोलियरी में 3.6 मिलियन टन कोयला तथा घूसिक कोलियरी में 2 मिलियन टन कोयला फंसा पड़ा है। अन्य कोलियरियों में कोयले की कोई क्षति नहीं हुई।

(ङ) और (च) उक्त आगों के लगने की घटनाओं के कारण सम्पत्ति की कोई क्षति नहीं हुई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खानों का बन्द होना

149. श्री हराधन राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कौन-कौन-सी और कितनी कोयला खानें राष्ट्रीयकरण के बाद बन्द हो गई हैं और इनके बंद हो जाने से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं;

(ख) उनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक बंद हुई खान से कोयले का अनुमानत: कितना भण्डार है और इस कोयले का मूल्य कितना है;

(घ) क्या बंद पड़ी खानों में गैस, अग्निकांड तथा धसान रोकने हेतु स्थायी उपाय पूरे कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन खानों के बंद हो जाने से आसपास के क्षेत्र में लोगों के जीवन और संपत्ति पर प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बंद की गई कोयला खानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इन खानों में कार्यरत सभी श्रमिकों को अन्य चालू खानों में काम पर लगा दिया गया था।

(ख) खानों के बंद किए जाने के निम्नलिखित कारण थे—खनन योग्य भंडारों का खत्म होना, आग, कठिन भू-खनन परिस्थितियां, खानों का जलमग्न होना, आर्थिक रूप से अलाभप्रद खनन आदि।

(ग) अनुबंध में उल्लिखित खानों में खनन योग्य सभी संभारों का निम्नलिखित को छोड़कर खनन कर लिया गया है—भा० को० को० लि० की 2 भूमिगत खानों अर्थात् लैकडीह डीप तथा विक्टोरिया और ई० को० लि० की 5 खानों अर्थात् शकरपुर, गिरीमिन्ट, न्यू घुसिक, महावीर तथा कंकरटोला। भा० को० को० लि० की 2 खानों में शेष बचे भंडार 11.6 मि० टन होने का अनुमान है जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रु० है और ई० को० लि० में शेष बचे भंडार 23.2 मि० टन होने का अनुमान है जिसकी कीमत लगभग 700 करोड़ रु० है।

(घ) और (ङ) भा० को० को० लि० ने अपनी बन्द पड़ी सभी खानों में स्थायीकरण का कार्य पूरा कर लिया। ई० को० लि० ने, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जिनको सतलीय संरचनाओं को सपोर्ट देने के लिए छोड़ दिया गया है तथा जिनमें पूर्व में किए गए खनन कार्य अथवा भूगर्भीय अड़चनों के कारण नहीं पहुंचा जा सकता है, रेत भराई अथवा केविंग के जरिए अपनी सभी खानों में स्थायीकरण का कार्य पूरा कर लिया।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की उन कोयला खानों की सूची जिन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद बंद कर दिया गया था।

भारत कोकिंग लिमिटेड

1. केन्दुआडीह (भूमिगत), 2. लैकडीह डीप (भूमिगत), 3. तसरा ओपनकास्ट, 4. बेरा ओपनकास्ट परियोजना, 5. राजापुर ओपनकास्ट, परियोजना, 6. लक्ष्मी ओपनकास्ट परियोजना, 7. बसदेवपुर ओपनकास्ट परियोजना, 8. झुनकुन्दर परियोजना, 9. मुरलीडीह भूमिगत।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. संकतोड़िया, 2. पूर्वी जमेहारी, 3. रत्नीबती 5 और 6, 4. के० एम० एस० चलबलपुर, 5. खास चलबलपुर, 6. न्यू जमेहारी खास, 7. प्यारे सियरसोल (एक यूनिट), 8. दमोदा, 9. महावीर

सित ादा सी, 10. वेलकई दिशेरगढ़, 11. नार्थ बुक, 12. गोगला, 13. मन्दरबोनी 1, 2 और 4 पिट्स, 14. देवली, 15. ब्रोदमो, 16. बैंकसीमुलिया, 17. मधुसूदनपूर 1 तथा 2 पिट 18. ब्राइल राना, 19. सेन्ट्रल जमुरिया, 20. जोंत जानकी, 21. लालनांटया भूमिगत, 22. लालमंटया ओपनकास्ट, 23. छापापुर-i, 24. रानीपुर, 25. रतीबती ओपनकास्ट, 26. नवाकाजोरा ओपनकास्ट, 27. पुरुषोत्मपुर ओपनकास्ट, 28. चोरा ओपनकास्ट, 29. निमचा ओ० का०, 30. शिवपुर ओ० का०, 31. दुनारबंद ओ० का०, 32. राना, 33. न्यू मतप्राम, 34. अलकुशाम गोपालपुर, 35. बेनाली, 36. केन्दा/डोबराना ओ० का०, 37. महावीर ओ० का०, 38. दोराला, 39. शंकरपुर 40. गिरीमिन्ट, 41. न्यू घूमिक, 42. महावीर, 43. कंकरटोला 1 और 2.

रेलगाड़ियों के स्टापेज बनाने का प्रावधान

150. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अप और डाउन बोकारो मद्रास एक्सप्रेस, अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस और बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस को क्रमशः रेंगाली, बमारा और बेल पहाड़ स्टेशनों पर भी रोकने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को झादसगुडा तक चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीस बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्ति, कारोबार और लाभ

151. **श्री डी० अमात** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान तथा 1990 में अब तक की अवधि में बीस बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्ति, कारोबार और लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी औद्योगिक घराने ने उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत और वर्ष 1988-89 के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 20 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों का वर्ष 1988-89 (अप्रैल, 1988 से मार्च, 1989 तक समाप्त लेखा वर्ष) में उनकी परिसम्पत्तियों, कुल आय तथा कर पूर्व लाभ दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। वर्ष 1990 की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है, चूंकि 1990 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनियों के तुलन पत्र अभी तक देय नहीं हैं।

(ख) और (ग) जनजातीय उप-योजना क्षेत्र (टी० एस० पी०) के अंतर्गत समाविष्ट जिलों में स्थित बजाज, टाटा, मोदी तथा बांगुर औद्योगिक घरानों के वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 (जून, 1990 तक) के दौरान सात प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत और 1988-89 के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 20 सबसे बड़े व्यापारिक घरानों से संबंधित कम्पनियों का वर्ष 1988-89 (अप्रैल, 1988 से मार्च, 1989 तक समाप्त लेखा वर्ष) में उनकी परिसम्पत्तियों कर पूर्व लाभ तथा कुल आय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	औद्योगिक घराना	परिसम्पत्तियां	कुल आय (व्यापारावर्त सहित)	कर पूर्व लाभ
1.	बिड़ला	6974.06	6852 33	301.59
2.	टाटा	6621.38	6779.97	439.18
3.	रिलायंस	3241.24	1227.09	84.9
4.	जे० के० सिंघानियां	1828.75	1587.12	36.72
5.	थापर	1762.52	1493.43	49.72
6.	मफतलाल	1296.55	1687.86	88.49
7.	बजाज	1228.37	1169.59	60.61
8.	मोदी	1192.34	1823.27	15.56
9.	लार्सन एंड टुब्रो	1130.33	1214.31	56.94
10.	एम० ए० चिदंबरम*	1032.23	747.25	29.19
11.	टी० वी० एस० आयंगर	929.06	1080.90	58.57
12.	हिन्दुस्तान लीवर	924.85	2510.80	180.21
13.	ए० सी० सी०	909.13	730.01	(–) 23.96
14.	श्री राम	799.17	1128.72	(–) 2.78
15.	आई० टी० सी०	742.19	1796.95	66.58
16.	यूनाईटेड ब्रेवरीज	715.71	726.11	29.46
17.	आई० सी० आई०	674.46	1239.03	54.17
18.	बांगुर	657.41	771.96	(—) 15.11
19.	किर्लोस्कर	633.07	719.26	25.87
20.	वालचंद	625.75	686.20	20.33

नोट :—इसमें मद्रास पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० भी शामिल है जिसे 1985 में एम० ए० चिदंबरम समूह में सम्मिलित किया गया है।

विवरण-2

उड़ीसा राज्य में जनजातीय उप-योजना (टी० एस० पी०) क्षेत्रों के अंतर्गत समाविष्ट जिलों में नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 1989, 1989 तथा 1990 (जून, 1990 तक) के दौरान बड़े 20 औद्योगिक घरानों के एम० आर० टी० पी० उपक्रमों से प्राप्त प्रस्ताव

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	विनिर्माण की मद	स्थान	परियोजना लागत (लाख रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स मुकुन्द लिमिटेड (बजाज)	एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पादों के 15,000 टी० पी० वाई० के निर्माण के लिए इपीकोल के साथ संयुक्त क्षेत्र में नए उपक्रम की स्थापना	जिला अंगुल धेनकनाल	6400.00	26-6-90 को धारा 22(3) के अंतर्गत स्वीकृत
2.	मैसर्स मुकुन्द मुकन्द लि० (बजाज)	30,000 फैरो निकल के टी० पी० वाई०	जिला बेमनीपाल क्योंझर	15,600.00	26-2-90 को धारा 22(3)(क) के अंतर्गत अस्वीकृत
3.	मैसर्स मुकुन्द लि० (बजाज)	फैरोक्रोम के 50,000 टी० पी० वाई०	बैमनीपाल जिला क्योंझर	3,000.00	26-2-90 को धारा 22(3)(क) के अंतर्गत अस्वीकृत
4.	मै० टिस्को लि० (टाटा)	क्रोम कच्ची धातु (और) निर्माण के लिए 2,00,000 टी० पी० ए० से 3,00,000 टी० पी० ए० तक पर्याप्त विस्तार	सुकीन्डे कटक	2,230.00	15-5-1989 को धारा 22 के अंतर्गत स्वीकृत।
5.	मै० टिस्को लि० (टाटा)	फेरा मंगनीज के 30,000 टी० पी० ए० की वर्तमान लाइसेंस क्षमता में फेरो क्रोम के 15,000 टी० पी० ए०	जोध, जिला क्योंझर	शून्य	23-6-88 को धारा 22 के अंतर्गत स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6
6.	मै० मोदी पोन लि० (मोदी)	केपरोलेक्टम 1,00,000 टी० पी० ए० अमोनिया सल्फेट 4,00,000 टी० पी० ए०	रूरकेला	60,000.00	अभी तक सरकार के विचाराधीन है।
7.	मै० जयश्री केमिकल्स लि० (बंगूर)	कास्टिक-सोडा 12900 एम० टी० पी० ए० लिक्वीड क्लोरीन-11350 एम० टी० पी० ए० हाइड्रोक्लोरिक एसिड-33000 एम० टी० पी० ए० के निर्माण में पर्याप्त विस्तार को प्रभावित करना।	गंजम	1,402.00	अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

आठवीं योजना के दौरान बिजली का उत्पादन

152. **श्री डी० अमात** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में अलग-अलग ताप विद्युत और जल विद्युत का अनुमानतः कितने उत्पादन का लक्ष्य है;

(ख) आठवीं योजना अवधि से दौरान इस बारे में कौन-कौन-सी प्रमुख परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार किया गया है;

(ग) सातवीं योजना अवधि के प्रारम्भ में अलग-अलग ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों से कितनी बिजली का उत्पादन होता था;

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान, क्षेत्रवार ताप विद्युत और जल विद्युत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई; और

(ङ) सातवीं योजना के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में बिजली उत्पादन में कितनी कमी आई ?

उर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, वर्ष;दर-वर्ष आधार पर और प्रत्युत पिछले वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन तथा जोड़ी गई नई क्षमता, मांग आदि आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1990-91 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 271250 मि० यू० रखा गया है जिसमें 2[illegible].400 मि० यू० ताप विद्युत, 6850 मि० यू० न्यूक्लीय विद्युत तथा 6300 मि० यू० जल विद्युत शामिल है।

8 वीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना आयोग द्वारा 8वीं योजना के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही8 वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य और इस उद्देश्य हेतु स्थापित की जाने वाली प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बारे में पता चल पायेगा। तथापि, विद्युत संबंधी कार्य दल की सिफारिश के अनुसार लगभग 38,000 मे० वा० के क्षमता संवर्धन के आधार पर योजनावधि के अंत तक कुल 411586 मि० यू० विद्युत उत्पादन किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत संयंत्रों का उत्पादन क्रमशः 85545 मि० यू० तथा 315608 मि० यू० होगा।

(ग) सातवीं योजना के आरम्भ अर्थात् वर्ष 1985-86 के दौरान विद्युत उत्पादन 170037 मि० यू० था जिसमें 114119 मि० यू० ताप विद्युत, 4985 मि० यू० न्यूक्लीय विद्युत तथा 50933 मि० यू० जल विद्युत शामिल है।

(घ) 7वीं योजना के दौरान क्षेत्रवार एवं श्रेणीवार क्षमता-संवर्धन इस प्रकार रहा :—

क्षेत्र	7 वीं योजना के दौरान क्षमता संवर्धन (मे० वा०)			
	ता० वि०	ज० वि०	न्यूक्लीय	जोड़
1	2	3	4	5
उत्तरी	5891.0	999.165	235	7125.165
पश्चिमी	5994.0	492.935	—	6486.935

1	2	3	4	5
दक्षिणी	3610.8	1739.4	235	5585.2
पूर्वी	1470.0	483.5	—	1953.5
उत्तर-पूर्वी	138.3	112.15	—	250.65
अखिल भारत	17[illegible]04.[illegible]	3827 350	470	2140[illegible].45

(ङ) 7वीं योजना के अन्त (1989-90) में देश मे ऊर्जा की कमी का क्षेत्रवार ब्योरा इस प्रकार है :—

क्षेत्र	ऊर्जा की कमी (प्रतिशत)
उत्तरी	5.8
पश्चिमी	2.6
दक्षिणी	13.3
पूर्वी	15.0
उत्तर-पूर्वी	3.0
अखिल भारत	7.3

नेल्लोर ताप विद्युत एकक

153. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पुराने नेल्लोर ताप विद्युत एकक की मरम्मत और सुधार के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पुराने नेल्लोर ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रथम चरण में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर, राख संयंत्र एवं डी० एम० प्लांट की अधिष्ठापना एवं द्वितीय चरण में बायलरों पर के बॉयलर बैंक ट्यूब, बॉयलरों के बाल एवं रेस मिल्स एवं बाउल मिल्स तथा टर्बोविजरी उपकरणों के प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई है। चरण-1 एवं चरण-2 की कुल अनुमानित लागत 16.17 करोड़ रुपये है। इन स्कीमों का आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परीक्षण किया जा रहा है।

उर्वरकों और कीटनाशकों पर भाड़ा शुल्क

154. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा हाल ही में परिवहन शुल्क में की गई वृद्धि के कारण उर्वरकों और कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या इन कृषि संबंधी मदों को बढ़े हुए भाड़ा शुल्क से छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) अप्रैल और जून, 1990 के बीच उर्वरकों और कीटनाशकों के थोक मूल्य सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रेल भाड़ा संरचना में उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए पहले ही अपेक्षाकृत कम दर पर भाड़ा वसूल किया जा रहा है ।

कर्नाटक में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

155. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में आठवीं योजना के दौरान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने सीमेंट एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान राज्य में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में संगठित क्षेत्र में 30 सीमेंट संयंत्र (डी० जी० टी० डी० पंजीकरण के अधीन शामिल 24 एककों सहित) मंजूर किए गए हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 23.40 लाख मी० टन है और ये कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं इनमें से 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़े क्षेत्र में 5.40 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता कार्यान्वित होने की संभावना है ।

(ख) सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं पड़ा है ।

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

156. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजनावधि के दौरान राजस्थान में जिला-वार कितने गांवों में बिजली पहुंचाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : जिलेवार विद्युतीकरण कार्यक्रम को अंतिम रूप राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है । यद्यपि, आठवीं योजनावधि के दौरान

राजस्थान के संबंध में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कुल मिलाकर लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नांदेड़ में वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

157. डा० वेंकटेश काब्दे : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़ से मुम्बई के बीच वायुदूत सेवा रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नांदेड़ और बम्बई के बीच नियमित सेवा पुनः कब प्रारम्भ की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) वायुदूत पहले से ही बम्बई-औरंगाबाद-नांदेड़ और वापसी मार्ग पर सप्ताह में 4 दिन की सेवा चला रहा है।

बम्बई और नासिक के बीच वायुदूत/इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा

[हिन्दी]

158. श्री हरिशंकर महाले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और नासिक के बीच इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा बन्द कर दी गई है और उसके स्थान पर वायुदूत सेवा चालू की गई है, जिसमें कम यात्री यात्रा कर पाते हैं और इन उड़ानों का कोई निर्धारित समय भी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 16 अप्रैल, 1990 से इंडियन एयर लाइंस द्वारा एचएस-748 (एवरो) विमान सहित, बम्बई-नासिक मार्ग वायुदूत लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप वायुदूत लिमिटेड ने 17 अप्रैल, 1990 से इस मार्ग पर परिचालन प्रारम्भ कर दिए थे। विमान क्षमता में कमी तथा नासिक में विमान पट्टी की मरम्मत के कारण समय-समय पर वायुदूत सेवाओं को रोकना पड़ा।

राज्यों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

159. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस की प्रस्तावित मात्रा निम्नलिखित है :—

	(मिलियन घन मीटर प्रतिदिन)	
राज्य और बिजली परियोजनाएं	1990-91	1991-92
1	2	3
महाराष्ट्र		
टी० ई० सी० एच०—ट्राम्बे	1.5	1.5
एम० एस० ई० बी०—उरान	3.00	4.50
कुल	4.50	6.00
गुजरात		
ए० ई० सी०—अहमदाबाद	0.40	0.40
जी० ई० बी०—धुवारान	0.50	0.50
जी० ई० बी०—उतरान	0.25	0.25
जी० आई० पी० सी० एल०—भरूच	0.70	0.70
कुल	1.85	1.85
उत्तर प्रदेश		
एन० टी० पी० सी०—औरेया	2.40	2.40
एन० टी० पी० सी०—दादरी	0.50	3.00
कुल	2.90	5.40
राजस्थान		
एन० टी० पी० सी०—अंटा	1.60	1.70
दिल्ली		
डी० ई० एस० यू०	0.60	0.60
असम		
ए० एस० ई० बी०—एन० टी० पी० पी०	0.40	0.40
ए० एस० ई० बी०—एम० जी० टी० एस०	0.065	0.065
ए० एस० ई० बी०—मेबेला (लकवा) पी० एच-II		0.40
ए० एस० ई० बी०—नामरूप	0.80	0.80
कुल	1.265	1.665

1	2	3
त्रिपुर		
टी० एस० ई० बी०—बारामूरा	0.20	0.20
रोकिया पावर स्टेशन	0.15	0.15
कुल	0.35	0.35
आंध्र प्रदेश		
ए० पी० एस० ई० बी०—नरसापुर	0.4	0.4

वास्तविक गैस की आपूर्ति, उपर्युक्त यूनिटों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करेगी।

सीमेंट का उत्पादन

160. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित नए सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 1989-90 में प्रत्येक संयंत्र के लिए सीमेंट उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में सीमेंट की उत्पादन दर एवं खपत दर कितनी रही ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करके और मौजूदा सीमेंट संयंत्रों का विस्तार करके बड़े क्षेत्र में 52066 लाख मी० टन क्षमता का सृजन किया गया था। 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार सृजित क्षमता, कुल अधिष्ठापित क्षमता, वर्ष 1989-90 के लिए लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख मी० टन में)

क्र० सं०	एकक का नाम	राज्य	1987-88 से 1989-90 के दौरान सृजित क्षमता (लाख मी० टन में)	अधिष्ठापित क्षमता	लक्ष्य (1990-90)	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
	नए एकक					
1.	श्री राम सीमेंट वर्क्स	राजस्थान	2.00	2.00	2.09	2.07
2.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ गुजरात	गुजरात	10.00	10.00	5.28	4.23
3.	मैसूर सीमेंट लि०, झांसी (ग्राइंडिंग यूनिट)	उत्तर प्रदेश	3.60	3.60	—	4.81
	विस्तार					
1.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०, निम्बा हेड़ा	राजस्थान	4.00	15.40	15.04	15.45
2.	उदयपुर सीमेंट लि०	राजस्थान	2.00	6.00	4.35	4.38
3.	उड़ीसा सीमेंट, राजगंगपुर	उड़ीसा	1.24	5.25	6.46	6.05
4.	लारसन एण्ड टूब्रो लि०	महाराष्ट्र	11.09	22.18	18.30	18.79

1	2	3	4	5	6	7
5.	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० (विक्रम सीमेंट)	मध्य प्रदेश	5.00	10.00	11.93	11.87
6.	मैसूर सीमेंट, अम्मासंद्रा	कर्नाटक	1.30	7.00	4.71	4.75
7.	प्रियदर्शिनी सीमेंट	आंध्र प्रदेश	2.00	6.00	5.01	4.80
8.	ओरिएण्ट सीमेंट लि०	आंध्र प्रदेश	4.50	4.50	4.47	4.56
9.	आंध्र सीमेंट, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	2.50	5.00	5.00	2.61
10.	चेट्टिनाड सीमेंट, करूर	तमिलनाडु	2.00	6.00	3.67	3.76
11.	ए० सी० सी० लि०, मदुकाराई	तमिलनाडु	1.43	5.20	5.40	5.33
			52.66	108.13	91.71	93.46

(ग) वर्ष 1988-89 की तुलना में 1989-90 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 3.03 प्रतिशत अधिक हुआ। सीमेंट के उपयोग के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, 1989-90 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सीमेंट का प्रेषण (डिस्पैच) 2.97 प्रतिशत अधिक हुआ।

विमानपत्तनों को एक ही प्राधिकरण के नियंत्रण में लाना

161. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर नियंत्रण रखने वाले विभागों/प्राधिकरणों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का सभी विमानपत्तनों को एक ही प्राधिकरण के नियंत्रण में लाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत अंतर्राष्ट्रीय वितानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, रक्षा मन्त्रालय, राज्य सरकारें और निजी एजेन्सियां विभिन्न हवाई अड्डों का नियंत्रण करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

वायुदूत की उड़ानें

162. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मई, 1990 को वायुदूत की चालू उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायुदूत ने अपने कार्यालय देश भर में स्थापित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो वे राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या देश में वायुदूत के सभी आरक्षण कार्यालयों में वायुदूत की उड़ानें संबंधी समय सारणी उपलब्ध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 15 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार, वायुदूत लिमिटेड अपने छः परिचालनात्मक बेसों से प्रति सप्ताह 271 उड़ानें परिचालित कर रहा था।

(ख) और (ग) कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, भोपाल और गुवाहाटी में वायुदूत लिमिटेड के पूर्ण-विकसित कार्यालय हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं है।

महाराष्ट्र में बायो-गैस और सौर ऊर्जा का विकास

163. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बायो-गैस और सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों को लागू किया गया है;

(ख) महाराष्ट्र में स्थापित किए गए बायो-गैस और ऊर्जा संयंत्रों की जिले-वार संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में जिले-वार कितने गावों को इन संयंत्रों से लाभ हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

सौर जलाशय परियोजनाएं

164. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत से विद्युत उत्पादन की सौर जलाशय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गुजरात के भुज इलाके में लगाई जा रही सौर जलाशय परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सौर जलाशय परियोजना का विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सौर ताल परियोजनाओं को प्रक्रम ऊष्मा और गर्म जल की आपूर्ति के लिए अनुसंधान और प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं में 70.5 लाख रुपए से अधिक का परिव्यय शामिल है। कुल ताल क्षेत्र 6700 वर्ग मीटर से अधिक है।

सौर ताल एक कम तापमान वाला ऊष्मा का साधन है और फिलहाल इस साधन से विद्युत उत्पादन करना किफायती नहीं है।

(घ) 62 लाख रुपए से अधिक लागत पर 6000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 4 मीटर गहरे एक सौर ताल को प्रक्रम ऊष्मा की आपूर्ति के लिए एक अनुसंधान तथा प्रदर्शन परियोजना के रूप में भुज में विकसित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) तकनीकी संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अनुसंधान तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणामों को प्रक्रम ऊष्मा तथा गर्म जल सम्बन्धी प्रयोगों के लिए आगे इस्तेमाल किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

165. **श्री वी० एन० रेड्डी** :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राजा वाडियार :
श्री जे० चोक्का राव :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री मनोरंजन भक्त :
डा० जतिन्दर पाल सिंह :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन और उसके वितरण में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहनों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या मार्ग-निदेश जारी किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटाने एवं विद्युत की अधिकाधिक उपलब्धता बढ़ाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है । इस संबंध में मार्गवर्षी सिद्धांत विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहनों का अनुमोदन किया है—

—ऋण इक्विटी का अनुपात बढ़ाकर 4 : 1 कर दिया गया है।

—लाइसेंसधारियों के लिए लाभ की निर्धारित दर जो इस समय 12 प्रतिशत है, बढ़ाकर 15 प्रतिशत का अनुमोदन कर दिया गया है।

—प्रारम्भिक परियोजना तथा अनुवर्ती विस्तारों के लिए वास्तविक लागत (रिजर्व बैंक की वर्तमान दर से 1 प्रतिशत अधिक के स्थान पर) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण किए जाने की अनुमति दी गई है।

- लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि जो कि इस समय 20 साल है बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है तथा अनुवर्ती विस्तार के लिए प्रत्येक अवसर पर 20 वर्ष कर दी गई है ।

—एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट लाइसेंसधारियों को स्वीकृति प्राप्त करने की छूट दिये जाने का भी अनुमोदन किया गया है ।

—अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत परिव्यय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाए जायें तथा कम से कम 11 प्रतिशत प्रवर्तकों के अंशदान से जुटाए जायें ।

—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जैसे अथवा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की सहायता से प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों को विद्युत उत्पादन कम्पनियों के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है ।

—इस प्रकार की विद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रचालनात्मक मानदंडों तथा इष्टतम संयंत्र भार अनुपात जिसका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/सरकार तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई मूल राशि की अधिक दर के आधार पर आमलीकृत निर्धारित दो खंड वाले टैरिफ के आधार पर बिजली बेचने की अनुमति दी गई है ।

—यह आशा है कि विद्युत उत्पादन कंपनियों के दक्ष प्रचालन से उनके लाभ की दर में भी सुधार होगा।

—सभी लाइसेंसधारियों/विद्युत उत्पादन कंपनियों को विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा समेकित ग्रिड प्रचालन की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचालन करना होगा।

—विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार करने और देश में विदेशी निवेश सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार बनाने सम्बन्धी सामान्य नीति-ढांचे की सीमाओं के अन्तर्गत इस प्रकार की भागीदारी हेतु प्रावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि उदारता सम्बन्धी उपायों के एक अभिन्न भाग के रूप में, विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण को प्राप्त करने के लिए आवेदनों को निपटाने सम्बन्धी सिंगल प्वाइंट स्वीकृति हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया जाए। उक्त उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड में केंद्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के सचिवों को शामिल किया जायेगा और अपेक्षानुसार राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को सहयोजित किया जायेगा।

—संविदात्मक समझौते एवं मानकीकृत टू-पार्ट टैरिफ के आधार पर कैप्टिव विद्युत उत्पादन यूनिटों को अधिशेष विद्युत राज्य बिजली बोर्डों को बेचने/वितरित किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

—विद्युत अधिनियमों में शीघ्र ही आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

—निजी क्षेत्र की भागीदारी से सम्बन्धित प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही किए जाने के लिए विद्युत विभाग में एक विशेष सैल का सृजन किये जाने का भी प्रस्ताव है।

एरिथ्रोमाइसिन का उत्पादन

166. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एरिथ्रोमाइसिन की इसके रसायनों और इससे निर्मित होने वाले उत्पादों की मांग कितनी रही;

(ख) इनकी मांग को पूरा करने के लिए इनका स्वदेशी उत्पादन कितना हुआ और कितना आयात किया गया;

(ग) देश में एरिथ्रोमाइसिन, इसके रसायनों और इससे निर्मित होने वाले उत्पादों का प्रारम्भिक चरण से ही निर्माण करने वाले एककों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने देश को एरिथ्रोमाइसिन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध सीमा तक ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं—

(मी० टन)	1987-88	1988-89	1989-90
मांग	70	80	90
(*) उत्पादन	41.5	40.42	76.74
आयात	1.125	3.356	उपलब्ध नहीं है

(*) उत्पादन के ब्यौरे संगठित क्षेत्र तक सीमित हैं।

(ग) संगठित क्षेत्र में मै० अलेम्बिक कैमिकल्स, तमिलनाडु डाढा और एबट लैब्स इस समय एरिथ्रोमाइसिन के उत्पादन की सूचना दे रही हैं। उनको मूलावस्था से उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

(घ) 1989-90 में एरिथ्रोमाइसिन और इसके व्युत्पादों का उत्पादन 1988-89 के उत्पादन की तुलना में लगभग दुगुना हो गया है और चालू वर्ष में इसके उत्पादन में और सुधार होने की आशा है।

उपभोक्ता वस्तु उद्योग में विदेशी सहयोग

167. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तु उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति देती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उपभोक्ता वस्तु उद्योग में सहयोग के लिए कितनी विदेशी कम्पनियों को अनुमति दी गई और इसका क्या मानदंड है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण के लिए सामान्यतया विदेशी सहयोग, वित्तीय अथवा तकनीकी, आवश्यक नहीं है। तथापि, उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग पर विशेष परिस्थितियों में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है, यदि निहित प्रौद्योगिकी के स्वरूप, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा निर्यात आय की संभावना जैसे कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे सहयोग को उचित पाया जाता है।

उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	स्वीकृत विदेशी सहयोगों की संख्या
1987	28
1988	27
1989	24

मैसर्स एल० एम० एल० लिमिटेड

168. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० एम० एल० लिमिटेड, कानपुर द्वारा वाहनों की बुकिंग के तौर पर जनता से अब कुल कितनी जमा राशि एकत्रित की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजीकृत आवेदकों को न तो वाहन मिले हैं और न ही उनकी जमा राशि लौटाई गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय का पालन न किए जाने का क्या कारण है; और

(घ) क्या निजी कंपनियों द्वारा सार्वजनिक राशियों का दुरुपयोग करने के इसी प्रकार के कोई और मामले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में की गई प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) कंपनी ने जनवरी-फरवरी, 1983 में बुकिंग शुरू की थी। इसके द्वारा 23.19 लाख आवेदनों पर ग्राहकों से एडवांस (अग्रिम) के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि लगभग 116 करोड़ रु० थी। कंपनी के अनुसार, 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार इसमें से लगभग 82 करोड़ रुपए की राशि वापस/स्कूटर की बिक्री में समायोजित कर दी गई है।

(ख) मुख्य रूप से, बुकिंग रद्द करने पर अग्रिम धन (एडवांस मनी) लौटाने में देरी से संबंधित शिकायतें हुई हैं।

(ग) इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) अग्रिम धन के लौटाने में देरी से सम्बन्धित शिकायतें कुछ अन्य निजी कंपनियों के विरुद्ध भी हुई हैं। ऐसी शिकायतों को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु विनिर्माताओं के पास भेज दिया जाता है।

बुकिंग के लिए अग्रिम धन स्वीकृत करना ग्राहक और कंपनी के बीच अनुबंध बाध्यता मानी जाती है। तथापि, ग्राहक के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से, सरकार ने आटोमोबील विनिर्माताओं द्वारा अग्रिम धन की स्वीकृति और उसके उपयोग हेतु 9-12-88 को संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन

[हिन्दी]

169. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन पर कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ था तथा इस रेलवे लाइन के बिछाने पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक खर्च की गई धन-राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या उना तक रेलवे लाइन रेल परिचालन के लिए तैयार है और यदि हां, तो नांगल से आगे उना तक कब तक गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) नांगल डैम-तलवाड़ा बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में शुरू किया था। परियोजना की वर्तमान संशोधित लागत 100 करोड़ (लगभग) आने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) खर्च का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आंकड़े करोड़ रुपयों में
1981-82	0.10
1982-83	1.25
1983-84	0.95
1984-85	1.90
1985-86	0.50
1986-87	2.00
1987-88	4.01
1988-89	5.72
1989-90	7.00
1990-91 (अनुमानित)	5.00

परियोजना का पूरा होना धन की उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर निर्भर है।

(ग) नांगल डैम से उना तक रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

परियोजनाओं को मंजूरी देने संबंधी नियम

[अनुवाद]

170. श्री के० एस० राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने सम्बन्धी नियमों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमों में नई छूट विलम्ब आदि कम करने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में आशय पत्रों की स्वीकृति के लिए ऐसे प्रस्तावों के बारे में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रि मंडल समिति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है, निवेश सीमाएं 50 करोड़ रु० से बढ़ाकर 200 करोड़ रु० कर दी है, जिससे विलम्ब को कम किया जा सके।

पैराक्सलीन का उचित बिक्री मूल्य

171. श्री के० एस० राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पैराक्सलीन के बिक्री मूल्य के बारे में काफी विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बाई० आई० सी० पी०) से पैराक्सलीन का उचित बिक्री मूल्य निर्धारण करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने पैराक्सलीन के लिए क्या उचित मूल्य निर्धारित किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) इस विषय पर पहले पर्याप्त चर्चा हुई थी और इसके बाद राज्य सभा में 1-6-90 को आधे-घंटे की चर्चा भी हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) बी० आई० सी० पी० ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है।

सोनपुर बजारी खुली खान परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

172. श्री के० एस० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोनपुर बजारी खुली खान परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कितनी भूमि दी गई है अथवा देने की पेशकश की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने बेदखल लोगों के वास्ते पुनर्वास पैकेज योजना को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो पुनर्वास पैकेज योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (च) जुलाई, 1985 में सरकार द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० सी० एल०) की 192.96 करोड़ रु० की राशि के निवेश तथा 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की लक्ष्य क्षमता वाली सोनपुर बजारी ओपनकास्ट

परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यह परियोजना मार्च, 1991 तक पूरी की जानी थी। जुलाई, 1987 में इस परियोजना के लिए 114.8 मि० अमरीकी डालर के ऋण की मंजूरी दी गई।

इस परियोजना के लिए भूमि की कुल आवश्यकता 1205 हेक्टेयर की है जिसमें से (पहला चरण-10 वर्ष) के लिए 604 हेक्टेयर भूमि की तुरन्त आवश्यकता है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पहले ही 157 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों, जिन्हें सामान्यतः भू-वंचित कहा जाता है, द्वारा विरोध किए जाने के कारण शेष 447 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वर्ष 1986 से उक्त भू-वंचित व्यक्तियों के लिए एक आर्थिक पुनर्वास पैकेज पर विचार-विमर्श चल रहा है।

उक्त पुनर्वास पैकेज के संबंध में हाल ही में एक समझौता हुआ है। भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य उक्त पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) सोनपुर बजारी परियोजना के भू-वंचित व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने के लिए कुशल श्रेणी में 200 स्थान तथा अर्द्ध-कुशल श्रेणी में 100 स्थान (कुल 300 स्थान) आरक्षित रखे जाएंगे।

(2) भू-वंचित व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर उनकी कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उपयुक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी ताकि वे परियोजना के अन्य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास कर सकें।

(3) सभी भू-वंचित परिवारों को उचित आधारभूत सुविधाओं के साथ वैकल्पिक आवासीय स्थल उपलब्ध किए जाएंगे। प्रत्येक भू-वंचित परिवार को 2000 रु० स्थल स्थानान्तरण भत्ता और गृह निर्माण के लिए 5,000 रु० की एकमुश्त अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।

(4) अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए नकद मुआवजा की राशि को जिला अधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा कर दिया जाएगा ताकि भू-वंचित विस्थापित परिवारों को मुआवजे की अदायगी किए जाने में कोई विलम्ब नहीं हो।

(5) ऐसे परिवार जिसका एक सदस्य नियुक्ति पाने के हकदार नहीं है; को निम्नलिखित दरों पर निर्वाह भत्ते की अदायगी की जाएगी :

(क) ऐसे परिवार जो कि एक एकड़ तक भूमि से वंचित हुए हैं।	प्रति परिवार 300 रु० प्रति महीने की दर से तथा 100 रु० प्रति महीने की अनुग्रह की राशि की अदायगी।
(ख) ऐसे परिवार जो कि एक एकड़ से अधिक भूमि से वंचित हुए हैं।	प्रति परिवार 300 रु० प्रति महीने प्रति एकड़ की दर से किन्तु 1000 रु० प्रति महीने की अधिकतम सीमा तक तथा 100 रु० प्रति माह की अनुग्रह राशि की अदायगी।

निर्वाह भत्ते की राशि को 20 वर्षों के आधार पर पूंजीकृत कर दिया जाएगा और यह

राशि पश्चिमी बंगाल सरकार को उपयुक्त भू-वंचित व्यक्तियों में संवितरित किए जाने के लिए सुपुर्द कर दी जाएगी।

पुनर्वास पैकेज पर समझौता हो जाने के बावजूद भी ग्रामीणों द्वारा ई० को० लि० को भूमि पर वास्तविक रूप से कब्जा प्राप्त करने का विरोध किया जा रहा है। कोयला कंपनी अधिग्रहीत की गई भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ और आगे विचार-विमर्श कर रही है।

वायुदूत द्वारा रोमानिया के विमानों को किराए पर उड़ाया जाना

173. **श्री के० एस० राव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का विचार रुपये का भुगतान पर अनेक बी० ए०-III विमान किराए पर लेने के लिए रोमानिया क साथ एक व्यापार समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोमानिया से प्राप्त विमानों को किन-किन क्षेत्रों में उड़ाया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने वायुदूत को निदेश दिया है कि मुख्य मार्गों पर किराए में दी गई 10 प्रतिशत की छूट को वापस लिया जाए;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) किराए में दी गई छूट वापस लेने से वायुदूत की उड़ानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) वायुदूत कुछ लम्बी दूरी के सेक्टरों पर प्रचालन के लिए रूमानिया से कुछ बी० ए० सी०-III विमान पट्टे पर लेने का विचार कर रहा है। विमानों की संख्या, लीज की शर्तों और अदायगी के तरीके से संबधी प्रस्ताव के विवरणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) सरकार ने अभी तक वायुदूत लिमिटेड को ऐसे कोई निदेश नहीं दिए हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं हैं।

ए-320 विमान की बिक्री के लिए विश्वव्यापी निविदाएं

174. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री डी० एम० बनातवाला :
श्री माधवराव सिंधिया :
स० अतिन्दर पाल सिंघ :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा, चार नए ए-320 विमानों की बिक्री तथा उपयोग में न लाए जा रहे विमानों को पट्टे पर देने के लिए, आमंत्रित की गई विश्वव्यापी निविदाओं के उत्तर में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों के संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्योंकि मामला अभी भी इंडियन एयरलाइन्स के विचाराधीन है, इसलिए इस समय वाणिज्यिक ब्यौरों को बताना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

पेट्रोल/डीजल पम्पों को बन्द करना

175. श्री वामनराव महाडीक :
डा० ए० के० पटेल :
श्री यादवेन्द्र दत्त :
श्री राम सजीवन :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :
श्री कड़िया मुन्डा :
श्री इरा अन्बारासु :
श्री राजवीर सिंह :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री जी० एस० बासवराज :
श्री जे० चोक्का राव :
श्री नकुल नायक :
श्री दलीप सिंह भूरिया :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री सुधीर गिरि :
श्री राम लाल राही :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री कमल नाथ :
श्री पी० सी० थामस :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री कोडाकुन्नील सुरेश :
श्री सुरेन्द्र सिंह :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रविवार को आधा दिन पेट्रोल पम्प बन्द रखने के बारे में हाल ही में अनुदेश जारी किए हैं तथा अन्य दिनों को पेट्रोल पम्प बन्द करने तथा खोलने के लिए भी समय का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इस योजना के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या आवश्यक सेवाओं के लिए पेट्रोल तथा डीजल उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अनुदेशों के जारी किए जाने के बाद जनता को असुविधा होने तथा इन उत्पादन की कालाबाजारी होने के कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में आये हैं;

(च) इस योजना के लागू किए जाने के पश्चात् अब तक कितनी मात्रा में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हुई है;

(छ) क्या सरकार को इस योजना के लागू किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पाद की तेजी से बढ़ती हुई मांग और कठिन विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने और मितव्ययिता का वातावरण बनाने की दृष्टि से अनेक उपाय लागू किए हैं। इन उपायों के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व होगा।

(ग) अनिवार्य सेवाओं के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं। संशोधित समय सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) हाल ही में किए गए उपायों का प्रभाव बता पाना समयपूर्व होगा।

(छ) और (ज) मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच की जा रही है।

दक्षिण मध्य रेलवे में यात्री रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

176. श्री वामनराव महाडीक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में गोवा एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट रेल गाड़ियां चलाने के लिए वहां कई पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं अथवा उनके समय में परिवर्तन कर दिया गया गया है जिससे पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त क्षेत्र में पैसेंजर गाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, दक्षिण मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर पांच गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान समय में 2 मिनट से 41 मिनट के बीच तथा एक गाड़ी के समय में एक घंटा 3 मिनट से एक घंटा 16 मिनट के बीच परिवर्तन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

177. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के अत्यधिक संख्या में होने के कारण वहां प्रदूषण, बिजली, पानी की कमी आदि की समस्यायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक स्थापना-स्थलों का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं एवं अपनी-अपनी स्थानिक विकास योजनाओं, लोनिंग और नगर आयोजन संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हैं। फिर भी, उद्योगों के छितराव के उद्देश्य से सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापित करने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि जैसे कई प्रोत्साहन देती है।

एयर टैक्सियां चलाने हेतु आशय पत्र

178. **श्री वामनराव महाडीक** :
श्री बृज भूषण तिवारी :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एयर टैक्सी संचालकों को आशय पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं और इन पत्रों के जारी करने में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) इन्हें किस प्रकार के विमान चलाने की अनुमति दी गई है, इन विमानों को किन मार्गों पर चलाया जाएगा और इनकी समय सारणी क्या होगी; और

(घ) उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अनुमति प्रदान की गई है, इनमें अनिवासी भारतीयों प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) हवाई टैक्सी योजना के अंतर्गत तीन आवेदकों को अभी तक हवाई टैक्सी प्रचालक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और सिद्धांत रूप से अट्ठारह आवेदकों को अनापत्ति पत्र दिए गए हैं। आवेदकों को प्रमाण पत्र उनके द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर हवाई टैक्सी प्रचालित करने की उनकी क्षमता पर दिये जाते हैं। नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत कम से कम 15 सीट की क्षमता वाले फिक्स्ड विंग के विमान या हैलिकाप्टर हवाई टैक्सी के प्रचालनों के लिए प्रयोग में लाये जाने योग्य हैं। संबंधित हवाई अड्डा प्राधिकारियों की अनुमति से यह सेवा उन सभी हवाई अड्डों से परिचालित की जा सकती है जो अनुसूचित प्रचालनों के लिए खुले हों। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

उन आवेदकों के ब्यौरे जिन्हें हवाई टैक्सी प्रचालन परमिट दिया गया

भारत में उपलब्ध विमानों का उपयोग करने वाले प्रचालक

नाम	विमान का प्रकार	सीट क्षमता
(1) दिल्ली-गल्फ एयरवेज सर्विसेज प्रा० लिमिटेड नई दिल्ली।	इक्यूरील एस० एस-350 बी०	5
(क) मैनेकजी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।	बेल 47 जी-5	4
	डोर्नियर 228	18
अनिवासी भारतीयों की निधियों से आयात करने वाले प्रचालक		
(1) इंडिया इंटर नेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	एच० एस० 125	7

विवरण-2

उन आवेदकों के ब्यौरे जिन्हें सिद्धांत रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं

भारत में उपलब्ध विमानों का उपयोग चाहने वाले आवेदक

नाम	विमान का प्रकार	सीट क्षमता
1	2	3
1. मैसर्स टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) किंग एयर सी-90	7
	(2) सेसना टी/303	5

1	2	3
	(3) सेसना टी/310	4
	(4) बोनांजा ए-35	3
2. मैसर्स इन्डामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	(1) किंग एयर सी-90	4
3. मैसर्स इंडियन मैटल एण्ड फेरो ऐलाएस लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) सेसना	3
	(2) बेरन बी-55	5
	(3) चेतक हैलिकाप्टर चेतक ए-III	5
4. मैसर्स अपर्णा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) मौल्स एम-5	3
	(2) सेसना स्काई मास्टर पी-337-एच	
	(3) डोर्नियर-228	5
5. मैसर्स नैशनल एयरपोर्ट अथारिटी नई दिल्ली	(1) एच० एच०-748 वीटी-इएफक्यू वीटी-ईएफआर	19
	(2) डीसी-3 वीटी,सीटीवी	16
	(3) डोर्नियर-228 वीटी-इएनके वीटी-ईपीयू	15
6. मैसर्स जैकसन इंटरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) डोर्नियर-228	19

अनिवासी भारतीयों की निधियों से आयात करने वाले आवेदक

पार्टी का नाम	पंजीकरण संख्या और विमान के प्रकार	बैठने की क्षमता
1	2	3
1. मैसर्स एशियन फंड्स लि० नई दिल्ली	(1) बीच क्राफ्ट सुपर किंग-300	13—14
	(2) ब्रिटिश एयरोस्पेस 125-800	12—13
	(3) हेलिकाप्टर बेल 412 एसपी	14
2. मैसर्स डालमिया रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल (प्रा०) लि० नई दिल्ली	(1) टर्बो प्रॉप विमान	8—9

1	2	3
3. कैप्टन पी० पाण्डे, अनिवासी भारतीय, डेनमार्क	(1) मालिन फालरचिल्ड आई० बी० सी० एण्ड 300 फाल्कन जैट	नहीं दिया गया
4. मैसर्स एयर एशियाटिक लि० मद्रास	(1) एफ-27/एफ-50 (पट्टे पर) (फाइनेंस मॉडल)	40—50
5. मैसर्स लियोबूस स्टील इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	(1) बीच क्राफ्ट 1900 एयर किंग एयर एक्सीक्यूटिव लाइनर	14—16
	(2) —वही—	17
6. ट्रांस भारत एविएशन प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) जेट विमान (ट्विन इंजिन)	8—15
	(2) टर्बो प्रॉप विमान (ट्विन इंजिन)	7—18
7. ईस्टर्न इंडिया एयर टैक्सी सर्विस (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	(1) सेसना सीटेशन	7
	(2) फाल्कन एफ-20	15
8. मैसर्स फोनिक्स एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड, मद्रास	(1) बेल हेलिकाप्टर बी-206-बी	
	(2) एफ-50/एफ-27	50—40
9. मैसर्स जनरल मार्केटिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) टर्बो प्रॉप विमान	10
10. दी ईगल्स ऑफ भारत एयरवेज लिमिटेड, अहमदाबाद	(1) सेसना 421/बी (पहले ही खरीदे गए)	8
11. सकवै० लीडर सी० एल० खोसला, (सेवानिवृत्त) द्वारा लिंक इंडिया एयरवेज (पी०) लिमिटेड	(1) बाइटर (एपी-68-टीपी 600)	10
	(2) पी 68 सी एण्ड टी सी	6
	(3) पी 68 सी (आबजरवर)	6
12. स्कारिया इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली	(1) बोइंग विमान	100/140

पेट्रोल/डीजल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन सम्बन्धी स्वविवेकी कोटा

[हिन्दी]

179. श्री हर्षवर्धन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री को रसोई गैस और पेट्रोल/डीजल खुदरा केन्द्र आबंटित करने हेतु कोई स्वविवेकी कोटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत सात महीनों के दौरान इस कोटे से किए गए आबंटनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा पेट्रोल/डीजल डीलरशिपें अनुकम्पा के आधार पर भी दिए जाते हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान 24 पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 25 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गयी हैं।

कोंकण रेलवे परियोजना के लिए धनराशि

180. **श्री हर्षवर्धन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी सरकारों और रेल कम्पनियों ने कोंकण रेलवे परियोजना में रुचि दिखाई है तथा इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रामदास समिति की सिफारिशें

181. **श्री हर्षवर्धन** :
श्रीमती चेन्नुपति विद्या :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
प्रो० रघुनाथ पांडेय :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री एस० कृष्ण कुमार :
श्री मदन लाल खुराना :
प्रो० के० वी० थामस :
प्रो० रूपचंद पाल :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री पी० एम० सईद :
श्री एडुआर्डो फैलेरो :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :
श्री सुखेन्द्र सिंह :

श्री गंगाचरण लोधी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए-320 एयर बस से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए गठित रामदास समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसमें क्या सिफारिशें/टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा अन्य सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय (सूचकांक संख्या 621.13252 आर) में रख दी गई हैं।

(ग) अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

पाली स्टेशन पर पुल

182 श्री गुमान मल लोढा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाली स्टेशन रेलवे फाटक पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के परामर्श से वहां पुलिया, पुल या भूमिगत उपमार्ग का निर्माण करने का है ताकि यातायात अवरुद्ध होने से लोगों को असुविधा न हो ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) रेल यातायात के समय समपार को बंद करने से सड़क यातायात की कुछ रूकावटें होना अपरिहार्य है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने के लिए विधिवत सहमति देते हुए इस सुविधा हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रायोजित किए जाने के बाद ही रेलें इस मामले में कार्रवाई कर सकती हैं।

संसद सदस्यों का रसोई-गैस कनेक्शन कोटा

[अनुवाद]

183. डा० ए० के० पटेल :
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों द्वारा उनकी सिफारिश पर प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शनों के आवंटन संबंधी वर्तमान कोटा क्या है;

(ख) क्या इस कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) मौजूदा नीति के तहत प्रत्येक सांसद की सिफारिश पर प्राथमिकता के आधार पर प्रति वर्ष 24 एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किए जा सकते हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जलधारा योजना का वित्तपोषण

184. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जलधारा योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने पम्प-सैटों को चालू किया गया है;

(ग) पम्प-सैटों को चलाने के लिए सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सीमांत किसानों को बिजली की सप्लाई किस दर से की गई;

(घ) क्या इन पम्प-सैटों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त उपाए किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सूखा-प्रवण क्षेत्र हैं लेकिन उन्हें जलधारा योजना के लाभ नहीं मिले हैं तथा प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जलधारा कार्यक्रम के लागू किए जाने के लिए जिन 13 राज्यों को निर्धारित किया गया था उनमें से केवल 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल ने क्रियान्वयन हेतु स्कीम तैयार की है। तदुपरांत पश्चिम बंगाल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह कार्यक्रम लागू करने में अपनी असमर्थता जताई है क्योंकि जल उपलब्ध न होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में पम्पसेटों की कोई मांग नहीं है। इस योजना के तहत मार्च, 1990 तक उपलब्ध कराई गई धन-राशि एवं प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूखाग्रस्त इलाकों में पम्पसैट चलाने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर प्रयोज्य टैरिफ (बिजली दर) वही है जो राज्य में अन्य कृषि उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य है।

(घ) और (ङ) पम्पसैटों का रखरखाव स्वयं किसानों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(च) सूखाग्रस्त क्षेत्रों वाले सभी 13 राज्य इस कार्यक्रम हेतु पात्र थे। 8 राज्यों ने अभी तक जलधारा स्कीम का लाभ नहीं उठाया है। ये हैं बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर,

कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु । इन राज्यों के समक्ष मुख्य समस्या कार्यक्रम को लागू करने में राज्य बिजली बोर्डों की अरुचि है ।

विवरण

जलधारा स्कीम के सम्बन्ध में मंजूरी एवं संवितरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	मंजूर किए गए पम्पसैटों की संख्या	संवितरित की गई राशि 88-89 के दौरान	89-90 के दौरान	90-91 के दौरान	कुल संवितरित राशि	3/90 तक ऊर्जीकृत पम्पसैट
1.	आंध्र प्रदेश	5610	120.610	32.980	—	153.590	1805
2.	मध्य प्रदेश	3984	143.424	—	—	143.424	81
3.	उड़ीसा	3171	145.866	—	—	145.866	2407
4.	राजस्थान	2439	112.194	—	—	112.194	141
5.	प० बंगाल	2754	99.144	—	—	99.144	—
	जोड़	17958	621 238	32.980	—	654.218	4434

रेलवे बोर्ड में समयोपरि भत्ते का भुगतान

[हिन्दी]

185. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1989 से दिसंबर, 1989 तथा जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते एवं टैक्सी के किराए के भुगतान पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या इस शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक उक्त खर्चे में कुछ कटौती हुई है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1989 के दौरान व्यय			1990 के दौरान व्यय		
महीना	समयोपरि भत्ता (रुपये)	टैक्सी भाड़ा (रुपये)	महीना	समयोपरि भत्ता (रुपये)	टैक्सी भाड़ा रुपये
1. जनवरी	42,179	3,072	जनवरी	47,094	2,060
2. फरवरी	53,963	3,308	फरवरी	43,689	2,055
3. मार्च	55,359	3,637	मार्च	34,471	5,223
4. अप्रैल	59,469	4,233	अप्रैल	65,563	2,959
5. मई	53,482	2,790	मई	58,474	1,260
6. जून	65,066	3,678	जून	54,610	2,056
जनवरी से जून, 1989 तक की अवधि का जोड़	3,29,518	20,718	जनवरी से जून, 1990 की अवधि का जोड़	3,03,901	15,613
7. जुलाई	50,544	2,266			
8. अगस्त	60,900	2,372			
9. सितम्बर	54,494	3,112			
10. अक्तूबर	63,385	2,902			
11. नवम्बर	48,998	2,777			
12. दिसम्बर	45,994	2,434			
जुलाई से दिसम्बर 1989 की अवधि का जोड़	3,24,315	15,863			
वर्ष 1989 का कुल जोड़	6,53,833	36,581			

एयरबस ए-320 की उड़ानें पुनः प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

186. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल
श्री राम सजीवन :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री जी० एम० बनातवाला
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :
श्री एस० कृष्ण कुमार :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री हरीश रावत :
श्री एच० सी० श्रीकांतय्या :
श्री जी० एम० बासवराज :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री पी० एम० सईद :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री एडुआर्डो फंलीरो :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :
श्रीमती बासवराजेश्वरी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :
श्री हरिशंकर महाले :
श्री चित्त बसु :
श्री टी० बशीर :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री कल्पनाथ राय :
श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस ए-320 की उड़ानें पुनः प्रारम्भ करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और औचित्य क्या है;

(ग) इनकी उड़ानें कब तक प्रारम्भ की जाएंगी;

(घ) क्या सरकार ने एयरबस उड़ानें पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लेने से पहले यात्रियों की सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया है;

(ङ) क्या इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने विवाद ग्रस्त विमानों की उड़ानों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो उन्होंने एयरबस ए-320 को न उड़ाने के लिए किन आधारों पर आपत्ति की है, और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) एयर मार्शल रामदास की अध्यक्षता में ए-320 विमानों के सुरक्षित परिचालन के लिए इंडिया एयर-लाइन्स की तैयारी को स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टें दे दी हैं जिसमें समिति ने सिफारिश की है कि ए-320 विमानों को, समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात क्रमिक रूप से शामिल किया जा सकता है। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इंडियन एयर-लाइन्स आवश्यक कदम उठा रही है और समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतया तैयार है। ए-320 विमान बेड़े के परिचालन के शीघ्र ही क्रमिक रूप से शुरू होने की आशा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं है।

सीमेंट की उत्पादन लागत तथा बिक्री-मूल्य

187. **श्री भवानी शंकर होटा :**
श्री गंगा चरण लोधी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो सीमेंट नवम्बर, 1989 में उपभोक्ताओं को 70 रुपए प्रति बोरी के मूल्य पर प्राप्त हो रहा था, उसका मूल्य बढ़ाकर 85 रुपये से 95 रुपये तक हो गया था;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है;

(ग) सीमेंट की प्रति बोरी उत्पादन लागत कितनी है तथा इस समय उपभोक्ताओं के लिए इसका खुदरा बिक्री मूल्य कितना है;

(घ) क्या किसी सरकारी एजेंसी ने उत्पादन की लागतों के बारे में कोई स्वतन्त्र अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सीमेंट का खुदरा (फुटकर) मूल्य स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। दिसंबर, 1989 से सीमेंट के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) कोयला, रेल भाड़ा और बिजली शुल्क जैसे निवेशों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण सीमेंट के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट उद्योग को उपर्युक्त स्तर तक मूल्यों में कमी करने की सलाह दी गई है। कोयले की पर्याप्त आपूर्ति तथा रेल डिब्बों की उपलब्धता सुनिश्चित

करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह उद्योग उत्पादन अधिकतम कर सके और सीमेंट की उपलब्धता में सुधार हो सके। सरकार भी दैनिक आधार पर सीमेंट के मूल्यों की निगरानी कर रही है।

(ग) सीमेंट के उत्पादन की वास्तविक लागत हर कारखाने में अलग-अलग होती है जो अपनायी गई प्रक्रिया, संयंत्र की आयु, कोयला क्षेत्र से दूरी, बिजली शुल्क इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार उत्पाद की वास्तविक कारखानावार लागत से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। 24 महत्वपूर्ण केंद्रों पर सीमेंट के फुटकर मूल्य, जिसके लिए मूल्यों की मानिटरी की जाती है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा हाल ही में उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए इस उद्योग पर कोई स्वतंत्र विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, इसने उचित बिक्री मूल्य के द्रुतगामी अनुमान दिए हैं।

विवरण

(मूल्य रुपयों में)

क्र० सं०	शहर का नाम	19-4-90 की स्थिति के अनुसार मूल्य	11-5-90 की स्थिति के अनुसार मूल्य	26-7-90	27-7-90	के साथ भिन्नता 19.4	के साथ भिन्नता 11.5
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	दिल्ली	92—95	82	92—95	92—95	—	+13
2.	करनाल	90—92	82—84	93—95	92—95	+3	+11
3.	लुधियाना	92—95	85—86	90—95	90—95	—	+9
4.	चंडीगढ़	91—95	84	90—91	90—91	—4	+7
5.	जयपुर	82—85	79	81—82	81—82	—3	+3
6.	लखनऊ	95—100	83	88—92	88—92	—8	+9
7.	श्रीनगर	92—95	—	—	—	—	—
8.	शिमला	92—95	82	82—83	82—83	—13	+1
पूर्वी क्षेत्र							
9.	कलकत्ता	90—95	86—88	86—92	87—92	—3	+1
10.	पटना	98—100	80—85	88—94	88—94	—6	+9

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	भुवनेश्वर	88	80—82	84—88	84—88	—	+6
12.	गुवाहाटी	104—105	95—98	95—105	95—105	—	+7
पश्चिमी क्षेत्र							
13.	बम्बई	90—92	85—88	90—95	90—95	+3	+7
14.	भोपाल	75—77	72—75	76—78	76—78	+1	+3
15.	गोआ	79—80	79—80	78—84	78—84	+4	+4
16.	अहमदाबाद	87—90	79—81	79—85	81—85	—5	+4
17.	राजकोट	87—90	78—80	79—85	81—85	—5	+5
18.	बड़ौदा	87—90	78—80	79—85	81—85	—5	+5
19.	सूरत	87—90	78—80	79—85	81—85	—5	+5
दक्षिणी क्षेत्र							
20.	मद्रास	82—85	78—81	84—87	84—87	+2	+6
21.	त्रिवेन्द्रम	95—100	87—90	88—93	88—93	—7	+3
22.	बंगलोर	82—85	82—85	84—88	84—88	+3	+3
23.	हैदराबाद	72—75	72—75	80—82	80—82	+7	+7
24.	कालीकट	90—100	83—90	86—94	86—94	—6	+4

नोट :—दिखाई गई भिन्नता उल्लिखित अधिकतम मूल्यों के अनुसार है।

पीपलोद और लीमखेड़ा में भोपाल राजकोट और इन्दौर बम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का हाल्ट

188. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर और भोपाल के बीच भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस रेलगाड़ी नं० 269 और 1270 के कितने स्टाप हैं और ऐसे प्रत्येक स्टेशन की जनसंख्या और इन स्टेशनों का महत्व क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भोपाल-राजकोट और इन्दौर-बम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का पीपलोद और लीमखेड़ा स्टेशनों पर हाल्ट उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मेघनगर तथा भोपाल को छोड़कर तेरह। तथापि, जनसंख्या आदि के संबंध में रेलों द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। परिचालनिक सुविधा के हित में।

जलपाईगुड़ी और रांची के बीच नई रेलगाड़ी

189. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागानों में काम करने वाले बिहार के श्रमिकों के लिए जलपाई-गुड़ी और रांची के बीच एक रेलगाड़ी चलाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

मध्य प्रदेश में नई रेलगाड़ियां चलाना

190. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-85 से 31-12-89 के दौरान कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई गई और उनमें से कितनी रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश से होकर जाती हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में 1-1-85 से पहले चलाई जा रही पुरानी रेलगाड़ियों की 1-1-85 से किन-किन स्थानों पर रुकने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश में 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1989 के दौरान किन-किन स्थानों पर रेलगाड़ियों के रुकने के लिए स्वीकृति दी गई और बाद में उसे रद्द कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) चलाई गई 299 गाड़ियों में से 72 गाड़ियां मध्य प्रदेश को सेवित कर रही हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

191. श्री जनार्दन तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा मार्ग पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्ट कार्यकलापों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

192. श्री जनार्दन तिवारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सरकारी धन के गबन के लिए उसके मंत्रालय के कितने राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया है;

(ख) कितने मामलों में अब तक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है; और

(ग) कितने अधिकारियों को निर्दोष ठहराया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग मंत्रालय के सात राजपत्रित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था। किसी भी अधिकारी को सरकारी धनराशि के गबन के लिए निलंबित नहीं किया गया था।

(ख) कोई नहीं।

(ग) दो अधिकारियों को जांच के बाद दोष-मुक्त कर दिया गया था।

खाद्यान्न आदि रखने के लिए शेड

193. श्री जनार्दन तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों, दालों, आदि को खुले में न रख कर शेड में रखने और आवश्यक वस्तुओं पर किसी प्रकार का स्थान शुल्क न लगाए जाने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं को शेडों में रखने तथा उन पर स्थान शुल्क न लगाने के बारे में ग्रेन मर्चेंट्स एसोसियेशन, कांटिग एण्ड क्लीयरिंग एजेंट्स एसोसियेशन और दिल्ली, मद्रास, समतनगर और सूरत के कुछ अन्य परेषितियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) केवल क्षति होने वाली वस्तुओं से लदे माल डिब्बों को शेडों में खड़े करने के सभी प्रयास किए जाते हैं, तथापि, जहां अचानक भारी संख्या में भारी डिब्बों के प्राप्त होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं होता है वहां माल डिब्बों को इस तरह से खड़ा किया जाता है ताकि ट्रकों में इनकी सीधी उतराई करने में सुविधा हो, यदि ट्रकों में माल की उतराई नहीं हो पाती है और माल का खुले में भंडारण किया जाता है तो तिरपाल से उसे ढक दिया जाता है, सामान्य नियमों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के स्थान शुल्क लगाने में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड को हुआ घाटा

194. **श्री जनार्दन तिवारी :**
प्रो० महादेव शिवनकर :
श्री राम प्रसाद चौधरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने अन्य देशों में कितने ठेके लिए हैं;

(ख) इनमें से कितने ठेकों में इनके कार्यान्वयन के बाद घाटा उठाना पड़ा;

(ग) भारतीय मुद्रा में कितनी धन-राशि का घाटा हुआ तथा इसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना था;

(घ) क्या इन घाटों के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं तथा क्या जांच रिपोर्ट पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 20.

(ख) ई० पी० आई० को 9 परियोजनाओं में घाटा हुआ है।

(ग) इन परियोजनाओं में 77.73 करोड़ रुपए राशि का घाटा हुआ है जो ओवर ड्राफ्टों के ब्याज और सरकारी ऋण पर ब्याज को छोड़कर चालू दर पर 97.61 लाख कुवैती दिनार, 40.14 लाख इराकी दिनार, 1.67 लाख सऊदी रियाल के बराबर है।

(घ) और (ङ) ई० पी० आई० के प्रबंधन और कम्पनी के निदेशकों की समिति ने घाटे के विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण किया है। कारण इस प्रकार थे : अवाणिज्यिक विपणन, कुवैत में प्रतिकूल कार्य परिस्थितियां, कठोर स्थानीय कानून, ग्राहकों का अड़ियल व्यवहार, ईरान-इराक युद्ध, मानव-शक्ति, संयंत्र और मशीनों को प्रभावी ढंग से लगाने की असमर्थता, आदि। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कम्पनी की कार्य-प्रणाली को पुनः निर्धारण किया गया है तथा कम्पनी को समुद्रपार की किसी भी परियोजना को लेने के लिए कहा गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा फोटोग्राफी सामग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

[अनुवाद]

195. **कुमारी उमा भारती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि० ने फोटोग्राफी की सामग्री के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कंपनी द्वारा इस समय बनाई जाने वाली फोटोग्राफी सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(घ) कम्पनी द्वारा किन-किन मदों का आयात किया जाता है; और

(ङ) कंपनी इस सम्बन्ध में कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, कच्चे माल से फिनिशिंग स्टेज तक (समेकित उत्पादन) एवं जम्बो रूप (जम्बो कन्वर्शन) में आयातित सैमी-फिनिश्ड माल की फिनिशिंग से फोटोग्राफिक सामग्री का उत्पादन करती है। विभिन्न उत्पाद जो समेकित उत्पादन से समाहित हैं, वे सिनेमा फिल्म पासिटिव (श्वेत-श्याम) सिने-फिल्म साउन्ड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे (सी० टी० ए० आधारित), फोटोग्राफिक पेपर, पी० टी० एस० पेपर, अमेच्यर रोल फ़िल्म (श्वेत-श्याम) हैं। सिने कलर पासिटिव, कलर पेपर, पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे एवं ग्राफिक आर्ट फिल्म जैसे उत्पादों का जम्बो कन्वर्शन किया जाता है। एच० पी० एफ० फोटोग्राफिक रसायनों का उत्पादन भी करती है।

इस समय यह कंपनी पॉलिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे औद्योगिक एक्स-रे एवं ग्रैफिक आर्ट फिल्मों के समेकित निर्णय के लिए सुविधाएं स्थापित कर रही है जिसके अक्तूबर, 1991 तक पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है।

विभिन्न विमान सेवाओं के बीच प्रतियोगिता संबंधी नई नीतियां

196. **श्रीमती बेन्नुपति विद्या** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न विमान सेवाओं के बीच विशेषकर प्रमुख स्वदेशी मार्गों पर प्रतियोगिता की एक नई नीति अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों में इस नई नीति को लागू करने का विरोध करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस विषय पर उनकी यूनियन के नेताओं से कोई बातचीत की है; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार का मत है कि जनहित में और साथ ही दक्षता को प्रोत्साहन देने व ग्राहक संतुष्टि के हित में अन्तर्देशीय विमान सेवाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को शुरू करना वांछनीय है। इसके लिए वायुदूत को हाल ही मे कुछ मुख्य मार्गों पर भारतीय रुपये को अदायगी पर लीज पर लिये गए विमानों द्वारा परिचालित करने की अनुमति दी गई है। इससे वायुदूत के परिचालनों को आर्थिक साध्यता भी प्राप्त होगी। सरकार ने हवाई टैक्सी योजना के परिचालन में कुछ प्रतिबंधों को भी हटा दिया है, तथापि मौलिक शर्त है कि हवाई टैक्सी के परिचालन के लिए सरकार द्वारा कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के पीछे जो कारण हैं वे इंडियन एयरलाइन्स के संगठनों को पूर्णतया स्पष्ट कर दिए गए हैं। उन्हें यह बता दिया गया था कि इंडियन एयरलाइन्स मुख्य

अन्तर्देशीय वाहक रहेगी और सरकार इसके विकास के लिए पूर्ण समर्थन देगी, परन्तु यह मानना संभव नहीं है कि इसकी कोई भी किसी तरह भी प्रतिस्पर्द्धा न हो। उन्हें आगे यह भी बताया गया चूंकि यह एक नीति सम्बन्धी मामला है और इसमें जनहित का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः इसमें कोई समझौते का मसला नहीं है।

स्वदेशी उत्पादकों पर विदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तरण का प्रभाव

197. **श्रीमती चेन्नुपति विद्या :**

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

श्री धर्मन्ना बोन्डय्या सादुल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी सहयोग प्रौद्योगिकी अन्तरण और पूंजीगत सामान के आयात के बारे में उदार नीति अपनाने के कारण भारतीय-नामित सहयोगियों के माध्यम से देश में विदेशी उपभोक्ता उत्पादों की भरमार होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी के उक्त अन्तरण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है, ताकि यह अन्तरण केवल अनिवार्य क्षेत्र में ही हो; और

(ग) स्वदेशी उत्पादकों पर विदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तरण का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) हाल ही में 31-5-1990 को "लघु उद्योग एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति उपायों तथा औद्योगिक स्वीकृतियों हेतु कार्य-विधि में परिवर्तन" संबंधी एक दस्तावेज लोक सभा पटल पर रखा गया। इस दस्तावेज के पैरा 13, 14, 15 तथा 16 क्रमशः पूंजीगत माल, कच्चे माल तथा उपकरणों के आयात, विदेशी सहयोग और विदेशी निवेश से संबंधित हैं। इस समय नीति के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा नई नीति को कार्यान्वित करते समय विभिन्न पहलुओं जैसे भारतीय नाम के सहयोगकर्त्ता, केवल अनिवार्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के जरिये आने वाले संभावित विदेशी उपभोक्ता उत्पाद तथा पूंजीगत माल के आवश्यक आयात को ध्यान में रखा जायेगा।

उद्योगों में रोजगार अवसर

198. **श्रीमती चेन्नुपति :**

श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उद्योगों में प्रौद्योगिकी के नवीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो नई औद्योगिक नीति में विभिन्न उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों को देखते हुए उद्योगों द्वारा अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री

श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले पूंजी सघन उद्योगों के विकास से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने में बाधा आने की संभावना है। अतः हाल में घोषित नीति संबंधी उपायों में सरकार ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम्य, अति लघु और लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार की अधिक संभावना है। सरकार ने ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रीय निवेश राजसहायता देने का भी निर्णय लिया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे ग्रामीण उद्योगों को ज्यादा ऋण तथा विपणन सहायता दी जाए।

वायुदूत द्वारा डोर्नियर विमानों की उड़ानें पुनः चालू करना

199. **श्री के० प्रधानी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निकट भविष्य में उन विमान मार्गों पर वायुदूत सेवाएं पुनः आरंभ की जा रही हैं जिन पर डोर्नियर विमान सेवाएं संचालित की जाती थीं, जो गत वर्ष पुणे के निकट डोर्नियर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बन्द कर दी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या इन मार्गों पर डोर्नियर विमान चलाये जायेंगे अथवा कोई अन्य विमान चलाए जायेंगे; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वायुदूत का पिछले वर्ष पुणे के निकट डोर्नियर की दुर्घटना के बाद रोकी गई सेवाओं को पुनः शुरू करने का इरादा है। जबकि पहले की सेवाओं को पुनः शुरू करते समय मूल मार्ग के ढांचे को जारी रखना संभव नहीं होगा, तथापि, प्रत्येक सेवा पर यात्री भार की समीक्षा करते हुए प्रचालन का नया ढांचा निर्धारित किया जाएगा। इन सेवाओं को शुरू करने में कितना समय लगेगा, इस बारे में अभी बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) इसमें लगाये जाने वाले विमान किस प्रकार के होंगे, यह यातायात की मांग और इन सेवाओं को शुरू करते समय वायुदूत के पास उपलब्ध विमानों की किस्म पर निर्भर करेगा।

लिंक एक्सप्रेस को पुनः चलाना

200. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मिलाने के लिए विशाखापत्तनम से रायपुर तक लिंक एक्सप्रेस को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (क) विशाखापत्तनम रायपुर लिंक एक्सप्रेस निरन्तर चल रही है। तथापि, रायपुर-विजयनगरम खंड के बीच पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने और बाद में उसकी मरम्मत के कारण 1-4-1990 और 15-5-1990 के बीच यह गाड़ी रद्द की गयी थी।

दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना

201. **श्री राजमोहन रेड्डी :**
श्री चित्त महाता :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता पता लगाने के लिए एक अंतर्मंत्रालय दल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि यह दल अगस्त, 1990 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए भावी योजना

202. **श्री राजमोहन रेड्डी :**
श्री बालेश्वर यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के प्रयोग के साथ उसके उत्पादन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अगले दस वर्षों हेतु एक व्यापक गैस उपयोग नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापक गैस उपयोग की नीति के प्राचल की फिलहाल जांच की जा रही है।

लिम्का के उत्पादकों के विरुद्ध कार्यवाही

203. **श्री एन० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग ने हाल ही में लिम्का के उत्पादकों को इस झूठे और भ्रामक विज्ञापन को जारी रखने से कि लिम्का "बी० वी० ओ०" से रहित है, रोकने के लिए एकतरफा और अस्थायी निषेधाज्ञा की है;

(ख) क्या लिम्का के उत्पादकों ने गत तीन-चार महीनों के दौरान अपना बिक्री आदि बढ़ाने के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के नाम का भी दुरुपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार मार्किट में पार्ले (एक्सपोर्ट्स) के शीतल पेय की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने प्रतिवादी नामशः मैसर्स पारले (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड को शीतल पेय के निर्माण में बी० वी० ओ० के प्रयोग पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने के बारे में 22 मई, 1990 को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। दिनांक 6 जुलाई, 1990 के अनुवर्ती आदेश के द्वारा आयोग ने कम्पनी को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रचार अभियान में गलत तथा गुमराह करने वाले विज्ञापन दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक और एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। आयोग ने कम्पनी को उनके प्रचार अभियान में किसी भी रूप में ऐसा प्रतिवेदन देने से मना किया है जिसमें एम० आर० टी० पी० आयोग का नाम शामिल हो। दोनों मामलों में कम्पनी को जांच के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मामले आयोग के समक्ष 10 अगस्त, 1990 को सूचीबद्ध किए गए हैं। मामले में अग्रिम कार्रवाई आयोग के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करेगी।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ट्रांसफार्मरों और ओ० सी० बी० का जलना

204. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री पी० एम० सईद :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीने के दौरान दिल्ली में बिजली का संकट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत छह महीनों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ट्रांसफार्मरों और ओ० सी० बी० आदि में आग लगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य सहित तथा इनके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की शिकायतें हैं कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई ये मदें घटिया किस्म की थीं और इनका उचित प्रकार से रख-रखाव तक नहीं किया गया; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाए गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख)

दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति पिछले चार महीनों के दौरान कुल मिलाकर सन्तोषजनक रही।

(ग) से (घ) डेसू के अनुसार फरवरी-अप्रैल, 1990 के दौरान विभिन्न उप केन्द्रों पर कुछ विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गये थे। उनकी खरीद लागत करीब 2.00 करोड़ रुपये थी और उनका ह्रासित मूल्य 1.00 करोड़ रुपए था। मरम्मत – लागत 50.00 लाख रुपये से कम थी। ट्रांसफार्मरों एवं अन्य संबद्ध उपस्करों के निष्क्रिय हो जाने के लिए ओवरलोडिंग एवं लघु परिपथ आदि उत्तरदायी हैं न कि घटिया स्तर के उपस्कर। ट्रांसफार्मर, स्विचगियर एवं अन्य सम्बद्ध उपस्करों की खरीद डेसू द्वारा, आई० एस० एस०/अन्तर्राष्ट्रीय मानक एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समुचित प्रापण प्रक्रियाविधि के माध्यम से की जाती है। इस तरह सम्बन्धित पदधारियों के विरुद्ध इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जानी आवश्यक नहीं पाई गई है।

विमानों के पक्षियों से टकराव दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हानि

205. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री जी० एस० बासवराज :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री बबनराव ढाकणे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइस को पक्षियों के विमानों के टकराने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार ऐसी कितनी घटनाएं हुई और इनमें वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कारण वर्ष-वार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विमानों को चिड़ियों से टकराकर होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1988 में विमानों के पक्षियों से टकराने के 169 मामले हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 173 करोड़ रुपये की की हानि हुई थी (मरम्मत आदि के संबंध में) जबकि 1989 में भी पक्षियों के टकराने के 169 मामले हुए जिसके कारण मरम्मत आदि पर 5.91 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पक्षियों से टकराने के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(घ) विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंध समिति स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से सभी हवाई

अड्डों के इर्द-गिर्द 10 किलोमीटर की दूरी तक के वातावरण को पक्षियों को आकृष्ट करने वाली वस्तुओं से मुक्त रखने की कार्यवाई करते हैं।

रेल व्यय में मितव्ययता

206. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में व्यय घटाने और आय बढ़ाने के लिए विचार किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन अलाभकारी शाखा लाइनों को बन्द करने का है जिन पर रेलवे को प्रति वर्ष हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) रेलों पर यह सदैव प्रयास रहा है कि खर्च में कमी की जाने और आमदनी बढ़ायी जाए। खर्च कम करने के लिए अपनाये जा रहे कुछ विशिष्ट उपाय नीचे दिये गये हैं :—

1. अलाभप्रद शाखा लाइनों के कार्य संचालन की समीक्षा करना ताकि उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके।
2. फालतू कर्मचारियों को पुनः तैनात करने की योजनाओं सहित भाप शेडों और अन्य अनावश्यक गतिविधियों को बन्द करना।
3. ऊर्जा अर्थात् कोयले, डीजल और बिजली की खपत में बचत करना।
4. सड़क वाहनों की ईंधन की खपत पर अंकुश लगाना।
5. सामान्य प्रयोजनों के लिए भण्डार की मदों की खरीद की समीक्षा करना।
6. मात्रा और दरों की उपयुक्तता के विशेष संदर्भ में स्थानीय खरीद और गैर-भण्डार की मदों की खरीद पर नियंत्रण रखना।
7. विज्ञापन, मनोरंजन आदि जैसी मदों पर होने वाले खर्च पर अंकुश लगाना।

आमदनी बढ़ाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गयी है :—

1. बेहतर विपणन प्रयास।
2. आमदनी की चोरी को रोकना।
3. वाणिज्यिक दोहन के जरिए और अतिक्रमण को हटाकर/रोक लगा कर रेलवे भूमि से राजस्व बढ़ाना।
4. वाणिज्यिक प्रचार बढ़ाना; और
5. रेलवे स्टेशनों पर निजी खान-पान यूनिटों और स्टालों से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना।

(ख) नीति यह है कि केवल उन अलाभप्रद लाइनों, जहां परिवहन के पर्याप्त साधन

उपलब्ध हैं और जिनको बनाये रखना, उस क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं है, को बन्द करने पर विचार किया जाये। तथापि, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमान टैक्सी सेवाएं

207. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री पी० आर० कुमारमंगलम :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न हवाई मार्गों पर विमान टैक्सी सेवाएं चलाने वाले उद्यमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक उद्यमियों ने देश में विभिन्न मार्गों पर विमान टैक्सी सेवाएं चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को विभिन्न उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) निम्नलिखित पार्टियों को हवाई टैक्सी प्रचालकों के परमिट जारी किए गए हैं :—

(1) मैसर्स इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(2) मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(3) मैसर्स मैकेकजी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(ख) और (ग) जी, हां। अठारह अन्य आवेदकों को सिद्धांत रूप से अनापत्ति पत्र दिये गये जो संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

उन आवेदकों के ब्यौरे जिन्हें सिद्धांत रूप से अनापत्ति पत्र दिए गए
भारत में उपलब्ध विमानों का प्रयोग चाहने वाले आवेदक

नाम

1. मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. मैसर्स इम्कामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
3. मैसर्स इंडियन मेटल एण्ड फेरो एलायस लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. मैसर्स अपर्णा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. मैसर्स नेशनल एयरपोर्ट्‌स अथारिटी, नई दिल्ली।
6. मैसर्स वेंकसन इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।

अनिवासी भारतीय निधियों से विमान का आयात चाहने वाले आवेदक पार्टी का नाम

1. मैसर्स एशियन फंड्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. मैसर्स डालमिया रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड, नई, दिल्ली।
3. कैप्टेन पी० पांडे, अनिवासी भारतीय, डेनमार्क
4. मैसर्स एयर एमिएटिक लिमिटेड, मद्रास।
5. मैसर्स लियोड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई।
6. ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. ईस्टर्न इंडिया एयर टैक्सी सर्विस (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता।
8. मैसर्स फोनिक्स एयरलाइन्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास।
9. मैसर्स जनरल मार्केटिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० नई दिल्ली।
10. दी ईगल्स ऑफ भारत एयरवेज लिमिटेड, अहमदाबाद।
11. स्क्वे० लीडर सी० एल० खोसला, (सेवानिवृत्त) द्वारा लिंक इंडिया एयरवेज (प्रा०) लिमिटेड।
12. स्कारिया इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, लि०, नई दिल्ली।

राजस्थान में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

208. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यह विद्युत संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इन संयंत्रों की अनुमानित लागत और क्षमता क्या होगी; और

(घ) इन संयंत्रों के वित्त पोषण ढांचे और राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और संबंधित गैर सरकारी क्षेत्र के बीच हुए वित्तीय समझौते का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मैसर्स सेन्चुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि० ने सूचित किया है कि राजस्थान में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उनको लाइसेंस संबंधी अनुमति प्रदान की गई है। यह भी बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) की स्थापना से संबंधित कार्य उनको सौंपा गया है। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने यथोक्त कम्पनी के साथ किसी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था का समझौता नहीं किया है।

नई औद्योगिक नीति

209. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
प्रो० यदुनाथ पांडेय :
श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :
श्री इरा अंबारासू :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) नई नीति को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई नीति से उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण और निर्यात संवर्धन में कितनी सहायता मिलेगी और लघु एककों को कितना लाभ पहुंचेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 'लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति संबंधी उपायों तथा औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए कार्य-विधि में परिवर्तन" संबंधी एक पत्र 31-5-1980 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था। नीति संबंधी पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तार, दिशान्तरण, प्रोसेसिंग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात जोनों में लगाए जाने वाले एककों के संबंध में लाइसेंस से छूट देना एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है। नीति संबंधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

ए-320 एयरबसों को उपयोग में न लाये जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स को घाटा

210. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
प्रो० यदुनाथ पांडेय :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री हरीश रावत :
श्री मकुल नायक :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री ए० चार्ल्स :
श्री टी० बशीर :
श्री रामेश्वर प्रसाद :
श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत फरवरी में एयरबस ए-320 के एक विमान के बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इन विमानों को उपयोग में न लाये जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कुछेक अनुमानों के आधार पर ए-320 विमानों का परिचालन बंद किए जाने से 31 जुलाई, 1990 तक नकद बचत में जो नुकसान हुआ है, वह लगभग 60 करोड़ रुपये आंका गया है।

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) विमान-बेड़े के शेष विमानों का पूरा उपयोग ताकि सम्पूर्ण प्रणाली के भार गुणक में सुधार हो।

(2) एयर इंडिया से अतिरिक्त विमान पट्टे पर लेना।

(3) पूंजीगत और राजस्व व्यय पर कड़ा नियंत्रण।

सिकन्दराबाद के निकट रेल दुर्घटना

211. **श्री वासवेन्द्र दत्त :**
श्री उत्तम राठौड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद के निकट शंकरपल्ली और गुल्लगुड़ू के बीच 4 जून, 1990 को हुई रेल दुर्घटना में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) उक्त दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायलों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) इस दुर्घटना में 36 व्यक्तियों की जानें गयीं तथा 94 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। उसके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, रेल कर्मचारियों की गलती के कारण दुर्घटना हुई थी।

(ग) घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी और मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 2,28,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए स्वचल सिगनल क्षेत्र में घात लगाकर जांच करना।

(ii) खास विश्लेषक जांच का अचानक प्रबंध ।

(iii) दृश्यता और सिगनलों की रोशनी पर निगरानी रखने के लिए बार-बार फुटप्लेट का निरीक्षण ।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि ड्यूटी की पारियों के बीच रनिंग कर्मचारी उपयुक्त विश्राम करें ।

पन-बिजली की लम्बित पड़ी परियोजनाएं

212. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पन-बिजली परियोजनाएं मुकदमेबाजी के कारण राज्यों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों की वजह से लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन परियोजनाओं को केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राज्य सरकारों के सम्मुख वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं ।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं को, राज्य क्षेत्र में होने के नाते, राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं में शामिल करके वित्त पोषित किया जाता है ।

ए-320 एयरबस को पट्टे पर देना/बेचना

213. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ए-320 एयरबसों को पट्टे पर देने अथवा बेचने का कोई योजना थी;

(ख) क्या एयरबस उद्योग ने इन एयरबसों को बेचने अथवा पट्टे पर देने की विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं है ।

बिहार में बिजली की कमी

214. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1990 के अन्तिम सप्ताह के दौरान सम्पूर्ण बिहार राज्य बिजली की भारी कमी की चपेट में था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिजली संकट से इस राज्य में स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिनांक 25/26 जून, 1990 को पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड में ग्रिड संबंधी व्यवस्था के कारण और 220 के० वी० संथालडीह-चान्डील लाइन, जिसके द्वारा बिहार, फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और चूखा जल विद्युत परियोजना से अपने हिस्से की अधिकांश विद्युत प्राप्त करता है, की बन्दी के कारण बिहार की विद्युत आपूर्ति की स्थिति प्रभावित हुई थी।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० की सहयोगी कम्पनियों को अधिकांश विद्युत दा० घा० नि० द्वारा आपूर्ति की जाती है जिसका कार्यनिष्पादन भी ग्रिड में व्यवधान के कारण प्रभावित हुआ था।

अशोक पेपर मिल्स का राष्ट्रीयकरण

[हिन्दी]

215. श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मंत्री अशोक पेपर मिल्स का राष्ट्रीयकरण के बारे में 15 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में बिहार सरकार से मांगी गयी टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं और क्या अशोक पेपर मिल्स की रामेश्वर नगर एकक के राष्ट्रीयकरण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और क्या इसके शीघ्र ही कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक अनुदान दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या चीथड़ों से लुगदी तैयार करने के लिए एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और अपना निजी विद्युत उत्पादन करने पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल्स को पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बिहार सरकार से मांगी गयी टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अध्यादेश के मसौदा पर बिहार सरकार की टिप्पणियां मिल जाने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी। अशोक पेपर मिल्स लि० के रामेश्वर नगर यूनिट को पुनः चालू करने हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिए बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) मै० अशोक पेपर मिल्स लि० से वर्ष 1981 में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्ची लुगदी की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और

एक आन्तरिक विद्युत एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। कम्पनी का यह आवेदन पत्र वर्ष 1982 में नामंजूर कर दिया गया था। इस संबंध में इसके बाद कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) मैं० ठाकुर पेपर मिल्स मार्च, 1982 से बन्द पड़ी है। यह सूचना मिली है कि एकक को हो रही कठिनाइयां दूर करने के लिए बिहार राज्य सरकार से परामर्श करके प्रस्ताव तैयार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के प्रयास सफल नहीं रहे हैं।

समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन

216. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन के साथ-साथ बड़ी रेलवे लाइन बिछाने तथा इस रेलमार्ग को दोहरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धन-राशि प्रदान की गई है;

(ख) इन रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा वर्ष के अन्त तक क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इसी आवंटित धन-राशि से समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा सकरी-हसनपुर मीटर लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) समस्तीपुर से दरभंगा तक समानान्तर बड़ी लाइन के निर्माण के लिए 1990-91 के बजट में 4.09 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारम्भिक प्रबन्धक के कार्य हाथ में हैं।

(ग) मौजूदा समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सकरी से हसनपुर तक रेल लाइन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को पवन ऊर्जाचालित पम्पों तथा पवन-ऊर्जा से खेती के बारे में परियोजना प्रदर्शन

217. श्री तेज नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन चालित पम्प और पवन ऊर्जा से खेती परियोजनाओं की बिहार में प्रदर्शन हेतु स्थापना के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिहार के किन-किन जिलों में वर्ष 1990-91 के दौरान ये परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गया, रोहतक, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारन, हजारीबाग, रांची, भोजपुर तथा जहानाबाद सहित अनेक जिलों

में राज्य की नोडल एजेन्सी बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा अब तक 130 पवन पम्प लगाए गए हैं। उन्होंने एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया है और अकेले नालन्दा जिले में ही 40 पवन पम्प लगाए गए हैं।

एक पवन सर्वेक्षण परियोजना बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा हाथ में ली जा रही है। प्रदर्शन पवन फार्मों की स्थापना, सर्वेक्षण तथा अन्य तकनीकी बातों के परिणामों पर निर्भर होगी।

(ख) जिन जिलों में 1990-91 में पवन पम्प परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है उनमें नालन्दा, गया, नवादा, पूर्णिया, डुमका, भोजपुर, रोहतास तथा देवघर शामिल हैं।

अनुसूचित/जातियों अनुसूचित जनजातियों की महिला पायलटों की संख्या

218. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में इस समय महिला पायलटों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिला पायलटों की, अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए कोई केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र तथा किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इंडियन एयरलाइन्स में 10 महिला विमानचालक हैं और इसके अतिरिक्त 8 महिला प्रशिक्षु विमानचालक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की कोई महिला विमानचालक नहीं हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) मौजूदा फ्लाइंग क्लबों और इग्रुआ के पास उपलब्ध सुविधा सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

219. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षित बेरोजगारों के लिए राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का जिले-वार ब्यौरा क्या है जहां उक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री अीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) जहां इस प्रकार के प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं उनके जिलावार ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

1. केन्द्रीय औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

2. केन्द्रीय औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, जमशेदपुर (बिहार)

3. औजार कक्ष, अहमदाबाद (गुजरात)

4. औजार कक्ष, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

5. औजार कक्ष, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

6. आवश्यक तेलों हेतु प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र, कन्नौज (उ० प्र०)

7. राष्ट्रीय कांच प्रौद्योगिकी केन्द्र, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)

इंडियन एयरलाइन्स की यूनियनों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

[अनुवाद]

220. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को मान्यता प्राप्त छः यूनियनों ने 11 जुलाई, 1990 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तीन मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों ने 11-7-1990 की रात की शिफ्ट से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का और दो यूनियनों/एसोसिएशनों ने 11-12 जुलाई, 1990 की मध्य रात्रि से हड़ताल का आह्वान किया था।

(ख) यूनियनों द्वारा की गई मांगें थीं—

(1) संकट की स्थिति से निपटने के लिए तरीके ढूंढने के लिए सरकार प्रतिनिधि यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करे;

(2) बिना और विलम्ब किए ए-320 विमानों के प्रचालन के बारे में कड़ा निर्णय किया जाए;

(3) ए-320 विमानों के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने तक, इंडियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से विमान वेटलीज पर लेने से रोकना चाहिए;

(4) प्राइवेट उद्यमियों द्वारा भारत में वाणिज्यिक विमान यातायात पर रोक लगाई जानी चाहिए;

(5) वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और विदेशी वाहक कम्पनियों से वेटलीज पर लिए गए विमानों के प्रचालनों पर रोक लगानी चाहिए;

(6) वायु निगम अधिनियम, 1953 के अनुसार कुशल क्रियाकलापों के लिए इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग को प्राधिकार पुनः बहाल किया जाना चाहिए।

(ग) इंडियन एयरलाइंस का प्रबन्धक वर्ग यूनियनों/एसोसिएशनों के नेताओं से मिला और उन्हें हड़ताल न करने की सलाह दी। दिल्ली के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त भी हड़ताल रोकने के लिए उन्हें राजी करने के लिए यूनियनों से मिले। तथापि, ये सभी प्रयत्न व्यर्थ गए। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिजली के नए बिल

221. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा शुरू की गई बिजली के तीन बिलों वाली प्रणाली के बारे में हाल में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वसूल की गई अग्रिम राशि को वास्तविक खपत बिलों में समायोजित नहीं किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) डेसू के अनुसार यद्यपि बिल बनाने की त्रैमासिक प्रणाली का अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है फिर भी इस प्रणाली के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) डेसू के अनुसार, दो अनन्तिम बिलों पर की गई अदायगी, अगली बार बिल तैयार किए जाते समय विधिवत समायोजित कर ली जाती हैं। किसी भी विसंगति की दशा में, डेसू के सम्बन्धित कार्यालय में बिल प्रस्तुत करते समय आवश्यक अनुशोधन कर लिया जाता है।

(ग) डेसू की बिल तैयार करने की पहले ही द्विमासिक प्रणाली समाप्त करने के लिए निदेश दिए जा चुके हैं। दो माह के लिए प्रथम बिल वास्तविक खपत के आधार पर होगा तथा अगला बिल अनन्तिम आधार पर होगा।

रेल के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश

[हिन्दी]

222. श्री बालेश्वर यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यक्ति बिना रेलवे आरक्षण के रेल के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 में ऐसे कितने मामलों में अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण संवाहकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार इस बुराई पर नियंत्रण के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन उपायों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) इस तरह के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जनवरी, 1990 से जून, 1999 तक की अवधि के दौरान 40 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई/की गई है जिनमें कंडक्टर भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं—

(1) राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से अचानक जांच की जाती हैं तथा आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करते हुए पाए जाने वाले यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है तथा रेल अधिनियम के उपबंधों के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है।

(2) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने के मामले में जुर्माने की राशि 1-7-1990 से लागू रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत 20 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है।

(3) मिलीभगत के प्रमाणित मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली और लखनऊ में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

223. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूचियां हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा लखनऊ में प्रतीक्षा सूचियों में क्रमश: कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) सरकार ने प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों को गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) 1 जुलाई, 1990 को दिल्ली और लखनऊ में क्रमश: लगभग 5.09 लाख और 0.62 लाख व्यक्ति एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किए जाने की प्रतीक्षा सूची में थे।

(ग) देश भर में नए एल० पी० जी० कनैक्शन उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्य-क्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में जारी किए जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। उपलब्धता को उत्पादन और आयात में वृद्धि करके बढ़ाया जाता है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा हवाई टिकटों की खरीद

[अनुवाद]

224. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारी ट्रैवल एजेन्टों के माध्यम से हवाई टिकट खरीदते हैं;

(ख) क्या एयरलाइंस द्वारा ट्रैवल एजेंटों को ऐसी टिकटों पर भारी कमीशन दिया जाता है;

(ग) क्या इस लेन-देन में दोनों तरफ से सरकारी धनराशि ही खर्च होती है;

(घ) क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा संबंधित एयरलाइंस से सीधे ही टिकट खरीदने की बजाय किन्हीं अन्य स्रोतों से टिकट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) जारी किए गए ऐसे अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क), (घ), (ङ) और (च) इस आशय के आदेश हैं कि सरकारी कार्य के लिए सभी आरक्षण सीधे ही राष्ट्रीय एयरलाइनों से कराए जाएं। तथापि, वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को अनुमति दी है कि वे हवाई टिकट मैसर्स अशोक ट्रैवल एंड टूर्ज तथा मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कंपनी लि० नामक दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से बुक करा सकते हैं।

(ख) और (ग) "इयाटा" के विनियमों के अनुसार, अंतरर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बुकिंग करने वाले सभी ट्रैवल एजेन्ट बिक्री पर 9 प्रतिशत कमीशन पाने के हकदार हैं। अंतर्देशीय बिक्री के लिए इंडियन एयरलाइंस मूल किराये पर 5 प्रतिशत कमीशन और ईंधन अधिभार पर 2-1/2 प्रतिशत कमीशन देती है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

225. **श्री बसई चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह): (क) जी हां,

(ख) कार्य योजना तैयार की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य सतर्कता संबंधी गतिविधियों को विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ाना है—

(1) बुकिंग, आरक्षण, सामान/पार्सल, माल तथा खान पान जैसे जन सम्पर्क वाले विभागों में जहां जनता को क्षति पहुंचाई जाती है या उन्हें परेशान किया जाता है।

(2) जहां जनता के धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग/बरबादी या राजस्व की चोरी होने की संभावना हो।

(3) कर्मचारियों की भर्ती तथा चयन।

इन गतिविधियों में निवारक तथा दंडात्मक दोनों उपाय शामिल हैं, निवारक उपायों के नियमों/प्रक्रियाओं (कदाचार को रोकने या इसकी गुंजाइश कम करने के लिए) का सरलीकरण/आशोधन, सूचना इकट्ठी करना तथा निगरानी रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और भ्रष्टाचार बहुल क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील पदों पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों, पर्यवेक्षी अधिकारियों तथा जनता को बड़े पैमाने पर शिक्षित करना तथा उन्हें सतर्कता तथा नियमित और नैत्य जांचों में शामिल करना शामिल है, दंडात्मक उपायों में शीघ्रता से जांच तथा अनुशासनिक कार्यवारी करना और कदाचार तथा भ्रष्टाचार के प्रमाणित मामलों में निवारक दंड देना शामिल है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ नियमित तथा नैत्य संपर्क बनाए रखा जाता है जो रेलवे के सतर्कता कार्यों में सहायता करता है।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

226. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री संजय लाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक खपत का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी मात्रा में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी मात्रा के खपत का अनुमान है; और

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत से कमी के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप अब तक, उत्पादवार, क्षेत्रवार कितनी मात्रा में पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत से संबंधित आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) मांग को नियंत्रित करने के लिए 21 जून, 1990 को घोषित किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व होगा।

सीमेंट का मूल्य

227. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री मंजय लाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल-मई, 1990 में सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट के मूल्य कम के करने की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में जून-जुलाई माह के दौरान सीमेंट के मूल्य कम हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन सीमेंट उत्पादक एककों को, जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, विशेष निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में उचित मूल्यों पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस उपाय करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के अधिकतर उपभोक्ता केन्द्रों विशेषकर पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों में मई और जून के प्रारम्भ में सीमेंट के मूल्यों में गिरावट आई थी।

(घ) और (ङ) सर्वोत्तम उत्पादन सुनिश्चित करने एवं बाजार में अधिकतम सीमेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयले और रेल वैगनों की पर्याप्त आपूर्ति करके सीमेंट उद्योग को मूलभूत सहायता प्रदान करने हेतु प्रयासों में वृद्धि की जा रही है। इस सुविधा के सुनिश्चय के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे डीलरों रर कड़ी नजर रखें ताकि डीलर खुदरा स्तर पर लाभ न कमाएं। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अधिक मात्रा में सीमेंट खरीदने पर विचार करें और उचित खुदरा वितरण सुनिश्चित करें।

महाराष्ट्र में दहानू स्थित ताप बिजली घर की स्थापना

[अनुवाद]

228. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सबरबन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने महाराष्ट्र के दहानू में एक 500 मेगावाट का ताप बिजली घर स्थापित करने के संबंध में कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय समूहों सहित संबद्ध एजेन्सियों द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का पूरे मामले पर फिर से विचार करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) महाराष्ट्र, दहानु में 2 × 250 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने हेतु बम्बई सबरबन इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने प्रस्ताव रखा है। कुछ शर्तों के अधीन मार्च, 1989 में पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

(ख) और (ग) बम्बई पर्यावरणीय कार्य दल तथा दहानु तालुका पर्यावरणीय संरक्षण दल ने दहानु में इस परियोजनाओं के स्थापित किए जाने के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में क्रमशः सितम्बर, 1989 तथा जनवरी, 1990 में याचिकाएं दायर की हैं। पर्याभरण एवं वन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों के उल्लंघन के बारे में तदुपरांत जनवरी, 1990 और इसके बाद पर्यावरणीय संबंधी दलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 27-1-90 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना प्राधिकारियों से, दायर की गई याचिकाओं के बारे में निर्णय लिए जाने तक निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को रोकने के लिए अनुरोध किया गया था। दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पास किए थे कि प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के विरुद्ध याचिकादाताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर आगे विचार किए जाने के लिए भारत सरकार स्वतंत्र है।

(घ) इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जांच की गई है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दहानु में 500 मेगावाट का प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किया जाना पर्यावरणीय पहलुओं की दृष्टि से स्वीकार्य है।

ट्रोम्बे में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

229. **श्री उत्तम राठौर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ट्रोम्बे में 180 मैगावाट क्षमता का एक गैस-आधारित संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कार्य मै० टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी को सौंपा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उसे इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) ट्राम्बे में 180 मेगावाट (120 मेगावाट जी० टी० + 60 मेगावाट एम० टी०) का गैस-आधारित संयुक्त साइकल संयंत्र प्रतिष्ठापित करने हेतु मै० टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य प्राधिकारियों की सहमति से प्रस्तुत प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित किया गया है और ठीक पाया गया है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नागर विमानन प्राधिकरणों से स्वीकृति जैसी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद इस स्कीम को औपचारिक तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

औषध कंपनियों की देनदारियों का निर्धारण

230. श्री कल्पनाथ सोनकर :
श्री के० मानवेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध कंपनियों की देनदारियों के निर्धारण की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में अंतर्ग्रस्त कम्पनियों और अन्य कम्पनियों के संबंध में राशियां सही निर्धारित नहीं की गई हैं। अत: निर्धारित की गई राशियों की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया गया था। पुनरीक्षण की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

पंजाब में लागू योजनाएं

231. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से लघु, ग्रामीण और कृषि पर आधारित उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एक लाख तक के निवेश वाली ऐसी परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है जिसके संबंध में पंजाब सरकार ने ऋण की व्यवस्था पंजाब वित्तीय निगम द्वारा किए जाने का निर्णय किया था ?

उद्योग मंत्रालय में लघु एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

232. बाबा सुच्चा सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बिजली उत्पादक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब में नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिनांक 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार, पंजाब में विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. ताप विद्युत	क्षमता (मे० वा०)
भटिण्डा	440
रोपड़	840
2. जल विद्युत	
आनन्दपुर साहिब	134
मुकेरियां	207
शानन	110
लघु जल-विद्युत	401
अपर बारी दोआब नहर 1 तथा 2	60

(ख) अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान पंजाब में स्थित ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भारत अनुपात निम्नानुसार था :—

केन्द्र का नाम	संयंत्र भारत अनुपात (अप्रैल-जुलाई, 90 के दौरान)	
	लक्ष्य (प्रतिशत)	वास्तविक (प्रतिशत)
भटिण्डा	66.0	59.7
रोपड़	71.2	60.0
जोड़	69.4	59.9

ताप-विद्युत यूनिटों के विद्युत उत्पादन का विनियमन विद्युत की मांग के अनुसार किया जाता है। जल-विद्युत यूनिटों का प्रचालन प्रणाली मांग, जल की उपलब्धता तथा सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। समय-समय पर, प्रणाली मांग कम होने के कारण यूनिटों को बन्द करना पड़ता है। विद्युत उत्पादन यूनिटों की आयोजित/जबरन बन्दियों के कारण भी कम विद्युत उत्पादन होता है।

(ग) और (घ) पंजाब में आठवीं योजनावधि के दौरान भटिण्डा में चरण-3 के अंतर्गत 210 मे० वा० की एक यूनिट और रोपड़ चरण-3 में 210-210 मे० वा० की 2 यूनिटें स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है बशर्ते संसाधन तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, 8वीं योजना के दौरान उत्तरी क्षेत्र में स्थापित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से भी राज्य को उसका हिस्सा प्राप्त होगा।

शिल्पकारों के लिए पृथक कालोनियों की स्थापना

233. बाबा सुच्चा सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छोटे-छोटे शिल्पकारों की संख्या कितनी है और उनका कारोबार क्या है;

(ख) नगरों और गांवों में उनका कारोबार स्थापित करने, उनका पुनर्वास करने तथा उन्हें सहायता पहुंचाने की विभिन्न योजनाएं क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) नगरों में वाणिज्यिक स्थलों की उपलब्धता की स्थिति क्या है और इन शिल्पकारों को वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध कराने संबंध प्रस्ताव क्या है;

(घ) क्या शिल्पकारों को समेकित सहायता उपलब्ध कराने हेतु केवल उनके ही लिए पृथक कालोनियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो शिल्पकारों का समेकित विकास करने संबंधी प्रस्ताव क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एंव कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) 1988-89 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवसायों में लगभग 1,34,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था :—

—खादी (सूती तथा ऊनी),

—कुम्हारगिरी

—चूना विनिर्माण,

—कुटीर दियासलाई,

—हस्त निर्मित कागज उद्योग,

—बांस तसा बेंत व्यवसाय,

—मधुमक्खी पालन,

—घानी तेल,

—बेंत, गुड़ और खण्डसारी,

—अनाज और दाल प्रसंस्करण उद्योग,

—जंगली पौधे एवं फल,

—फल प्रसंस्करण,

—फाइबर उद्योग,

—कुटीर साबुन उद्योग,

—कुटीर चमड़ा उद्योग,

—गोबर गैस,

—बढ़ईगिरी एवं लुहारगिरी,

—ऐल्युमिनियम के घरेलू बरतन।

(ख) संशोधित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकलाप केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं। जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है

के० वी० आई० सी० अपनी परिसीमा के अंतर्गत भिन्न-भिन्न योजनाओं/ग्रामोद्योगों के लिए सहायता देता है। 1988-89 के दौरान के० वी० आई० कार्यकलापों के लिए पंजाब राज्य को 204.41 लाख रु० अनुदान के रूप में और 104.65 लाख रु० ऋण के रूप में वितरित किए गए थे।

(ग) क्योंकि के० वी० आई० कार्यकलाप केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं, अतः शहरों में वाणिज्यिक स्थलों की उपलब्धता का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) खादी संस्थानों के आसपास शिल्पकारों के लिए पहले से ही कालोनियां हैं जो के० वी० आई० कार्यकलाप करने के लिए शिल्पकारों को शेड प्रदान करती हैं। ये संस्थान नए माडल के चरखों, करघों, औजारों तथा उपकरणों का प्रावधान, कच्चे माल की आपूर्ति, प्रशिक्षण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 8वीं योजना के दौरान एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पंजाब में उद्योग द्वारा पैदा किए गए रोजगार के अवसर

234. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा किस सीमा तक रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में विभिन्न संगठन उद्योग पर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आदि की भांति स्थानीय श्रमिकों को ही नियोजित करने की शर्त लगाने की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब में पिछले 3 वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा उत्पन्न रोजगार इस प्रकार है :—

वर्ष	लघु क्षेत्र	बड़ा/मझौला क्षेत्र	जोड़
1987-88	37355	5150	42505
1988-89	39488	4356	43844
1989-90	38569	3560	42129

(ख) और (ग) पंजाब सरकार को कुछ संगठनों से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पंजाब सरकार ने इस संबंध में 12 जुलाई, 1990 को निम्नलिखित हिदायतें जारी की हैं :—

(1) 25 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को अपने रिक्त स्थानों के बारे में रोजगार कार्यालयों को सूचित करना होगा तथा इन रिक्त स्थानों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित-स्थानीय उम्मीदवारों में से भरना होगा।

(2) ये सभी डिप्लोमाधारी, आई० टी० आई०, कुशल, अर्ध-कुशल तथा अन्य श्रमिकों पर लागू हैं।

(3) यदि रोजगार कार्यालय में अनिवार्य योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ये संबंधित संगठनों को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करेंगे।

(4) रोजगार कार्यालय श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में वाणिज्य मंडल और ऐसे संघों से सहायता लेगा।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं होम मिनिस्टर साहब को बुला रहा हूं, वे हरिजनों से सम्बन्धित मसले पर कुछ बोलने वाले हैं, आप बैठ जाइये।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्यक्ष महोदय, आगरा में जो इंसीडेंट हुआ है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर साहब को कॉल किया है, आप बैठ जाइये। मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष जी, आगरा में जो घटना हुई है, उसमें एक क्लैश में, कुछ हरिजनों पर अत्याचार हुआ है, कुछ हरिजन मारे गए हैं। उस घटना के बारे में··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर वह दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि उसका विषय भी उसी में कवर हो जाये।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष जी, उस घटना में महिलाओं पर, डकैतों ने नंगा करके अत्याचार किए हैं, यह कितने शर्म की बात है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं । क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं नोटिस दे रहा हूं, आप मुझे पहले सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये, मैं आपको सुनूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आगरा की घटना के सम्बन्ध में मैं सदन में जल्दी हो वक्तव्य दूंगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल आप लोग जो यहां उठा रहे हैं, मैं देखूंगा कि नियमों के अंतर्गत क्या हो सकता है और मैं इस विषय पर किसी भी शक्ल में बहस की अनुमति दूंगा । यह मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं है कि किस तरह से वहां लोगों को मारा गया है । 100 से ज्यादा लोग गायब हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जग पाल सिंह जी, मैं इस पर एक बहस कराने की इजाजत दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आगरा की घटना के साथ राजस्थान में जो कंजड़ मारे गए, अनुसूचित जाति के लोग मारे गए, उनके सवाल को भी शामिल किया जाए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं । मैंने प्रो० कुरियन को बोलने के लिए इजाजत दी है ।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैंने सोचा था कि गृह मंत्री जब वक्तव्य देंगे तो वे गुजराला में 'ननों' पर किए गए घृणित अपराध और अत्याचारों की भी चर्चा करेंगे । मुझे बड़ा खेद है कि···(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय,···

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जाएं, आपको भी सुनूंगा।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, आगरा की घटनाओं के साथ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप अपनी बात समाप्त क्यों नहीं कर रहे?

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, यह मामला हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री ने गजरौला, उत्तर प्रदेश में हुए बलात्कार के घृणित अपराध की चर्चा करने की परवाह नहीं की। दो सप्ताह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है परंतु उन्होंने वहां जाने के बारे में नहीं सोचा। यह सदन यह जानना चाहता है कि उन्होंने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है। वह इसके बारे में इतने चिन्तित थे कि···(व्यवधान) उन्हें हर महिला को अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए और उनके लिए चिन्ता करनी चाहिए। उन्होंने इस घटना की चर्चा क्यों नहीं की? कल···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : परंतु आप अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। कृपया इसे समाप्त करिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैंने सोचा था कि वे इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं यह कहना चाहता था। मेरा विषय अलग है। कल मैं और श्री मैथ्यू संसद सदस्य वहां गए थे और वहां यह पता चला कि इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वे 'नन' आज भी अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान गृहण कीजिए। यह क्या कर रहे हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि सभी कान्वेंट स्कूलों तथा ननों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। हम यह भी जानना चाहेंगे कि जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं···(व्यवधान)

महोदय, वास्तव में मैंने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण का मुद्दा उठाने के लिए आपकी अनुमति ली थी क्योंकि वहां पर दो लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं। वे सब घबराए हुए हैं। उनके सभी संबंधी और परिवार भी भारत में चिन्ता में डूबे हुए हैं। कल यह दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था। समाचार पत्रों में भी इस संबंध में छपा है। यहां पर उनके संबंधी उनसे कुवैत में सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और न ही वे कुवैत से यहां पर अपने संबंधियों से

संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। कुवैत के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय लोगों की लगभग 6000 करोड़ रु० से अधिक की सम्पत्ति कुवैत में है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने न तो इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है और न ही यहां पर लोगों को यह आश्वासन देने के लिए कोई वक्तव्य ही दिया है कि उनके सम्बन्धी कुवैत में सुरक्षित हैं। महोदय, वहां पर बसे 2 लाख भारतीय लोगों में से एक लाख से भी अधिक केरलवासी हैं। मुझे बड़ा खेद है कि इस सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया···

एक माननीय सदस्य : वे सभी भारतीय हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार ने इराक की सरकार से कोई बातचीत की है। यह सत्य है कि हमने इराकी हमले की निन्दा की है। हम चाहते हैं कि भारतीय लोगों की जान और माल को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार इराक की सरकार से संबंध स्थापित करे और राष्ट्र को उसके सुरक्षित होने का आश्वासन देने संबंधी वक्तव्य दे। यह आपकी उत्तरदायित्व है। इस संबंध में वक्तव्य न देकर सरकार अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट रही है। (व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, लगभग 1 लाख केरलवासी वहां पर काम कर रहे हैं। वे लोग इस समय कहां पर हैं, इसका अभी तक कोई पता नहीं। उनके संबंधी भी उनका अता-पता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताया गया है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं।

श्री टी० बशीर : यह सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० उपेन्द्र की बात सुनिये।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : विदेश मंत्रालय ने इराक सरकार तथा कुवैत की सरकार दोनों से सम्पर्क स्थापित कर रखा है। सभी भारतीय सुरक्षित हैं। अगर वह कोई विशेष वक्तव्य चाहते है तो यह भी दिया जा सकता है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, विदेश मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह वक्तव्य देने के लिए सहमत हो गए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : मान्यवर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या बोलना है, बोलिए यादव जी।

श्री मित्रसेन यादव : मेरा निवेदन है कि माननीय मायावती जी आगरा कांड के बारे में चर्चा करना चाहती हैं। मेरा कहना है कि जब गृह मंत्री जी अपनी बात कहें तो पूरे हिन्दुस्तान में जहां-जहां हरिजनों के उत्पीड़न का सवाल हो, उन पर प्रकाश डालें। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : आगरा कांड के सवाल को सरकार दबाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप जो सवाल उठा रही हैं उसके बारे में बिजनस एडवाईजरी कमेटी में मैं देखूंगा कि किस तरह से आपका सवाल ला सकते हैं। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, सरकार आगरा कांड को दबाना चाहती है। आज हजारों आदमी यहां बोट-क्लब पर एकत्र हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आगरा कांड को पहले लिया जाये। गृह मंत्री जी इस कांड के बारे में यहां जवाब दें। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने गरीब लोगों को गोलियों से मारा। अब वह इस मामले को दबा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आपने यह तय कर लिया है कि आप व्यवधान डालेंगी। मैंने आपकी बात सुन ली है, अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपने बोलने के लिए मेरी अनुमति नहीं ली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हां, श्री सैफुद्दीन चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किसी दूसरे देश का मामला उठाना इस सदन की परम्परा नहीं रही है। इसलिए मैं यहां पर यह मुद्दा उठाना नहीं चाहता कि कल पाकिस्तान में क्या हुआ। परन्तु मैं अपने विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान में चुने हुए प्रधान मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया और इसका हमारे संबंधों पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्थिति का आकलन करने के पश्चात् क्या विदेश मंत्री अपने विचारों का सदन के साथ आदान-प्रदान करेंगे? महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

12.17 म० प०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं। क्या आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि' के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों से चार स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मिली हैं :—

1. श्री वसंत साठे

2. श्री पी० सी० थामस

3. श्री के० एस० राव .

4. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी

मैं श्री वसंत साठे को, जिन्हें बैलट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित रूप में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं :

"आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता।"

वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा को अनुमति देने पर आपत्ति है ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : जी हां महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : या तो उन्हें अपनी आपत्ति वापस ले लेनी चाहिए या··· **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : वह इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान करने का विरोध नहीं किया जा रहा है। अनुमति प्रदान की जाती है। नियम 61 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 4.00 म० प० पर की जायेगी। क्या सभा इस पर सहमत है ?

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : इस पर अभी चर्चा की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : विपक्ष के नेता से मेरा एक निवेदन है। हम किसी भी समय इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हैं। परन्तु इसमें केवल एक तकनीकी समस्या है। **(व्यवधान)**। कृपया मेरी बात सुनिए। यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी समस्या है।

महोदय, दूसरे सदन में उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि चर्चा 12-00 बजे, मध्याह्न पर करवाई जाए। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यदि दोनों सदनों में चर्चा के समय का समायोजन किया जा सके तो मेरे लिए काम आसान हो जायेगा क्योंकि··· **(व्यवधान)**। मैं विपक्ष के नेता से अपील कर रहा हूं : अन्तिम निर्णय मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि दोनों सदनों के समय का समायोजन किया जाए। वे चर्चा के लिए दोनों सदनों में कोई भी समय निश्चित कर सकते हैं; मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में दोनों ही सदन इस विषय में एक ही साथ चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर कल दे सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन आज खत्म होना चाहिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : हम सारी रात बैठने को तैयार हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राजीव गांधी जी कह रहे हैं कि हम रात भर बैठ जायेंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं । जब स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो जहां तक संभव हो सके, उस पर उसी दिन चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए । केवल विशेष मामलों में इसे जारी रखा गया । अत: मैं यह मानता हूं कि इसे पूरा करना है, किंतु इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री तो एक ही हैं । वित्त मंत्रालय में उप मंत्री भी तो हैं । किंतु कभी-कभी सदस्यगण आपत्ति करते हैं, अत: समय का समायोजन किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, कृपया आप चर्चा के लिए समय निर्धारित कीजिए कि आप कौन-सा समय चर्चा के लिए निर्धारित कर रहे हैं और साथ ही यह भी बताइए कि मंत्री को अब उत्तर देना चाहिए । इसी के अनुसार हम दूसरे सदन में भी व्यवस्था करेंगे । (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री यहां उत्तर दे सकते हैं और वित्त मंत्री वहां उत्तर दे सकते हैं ।

श्री पी० उपेन्द्र : यह तो सरकार को देखना है ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं समझता हूं कि सभा के समस्त सदस्यगण सहमत हैं और देश भी सहमत है । इस संबंध में कोई शंका नहीं है ।

श्री राजीव गांधी : हमें प्रयास करना चाहिए कि इसका उत्तर कोई वरिष्ठ मंत्री दें न कि वित्त मंत्रालय में उप मंत्री ।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अलग-अलग दोनों सदनों में जाना है ।

श्री राजीव गांधी : जब आप एक सदन में हैं तो प्रधान मंत्री दूसरे सदन में जा सकते थे । (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वरिष्ठ मंत्री का अर्थ केवल प्रधान मंत्री ही नहीं है । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने केवल यह निवेदन किया है कि उत्तर देने के समय को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। बस। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जवाब देते समय आप सरकारी बयान देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जब विपक्ष के नेता प्रधान मंत्री थे तब यह परम्परा नहीं थी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शुरू कर रहे हैं न, एडजर्नमेंट मोशन। पहले दो सेकेण्ड में पेपर्स लेड हो जाय तब बसन्त साठे जी बोलेंगे।

यस, मायावती जी, क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

कुमारी मायावती : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि देश में वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा महत्व इस देश के अन्दर गरीबों की जानों का है इसलिए महंगाई से पहले इस पर चर्चा कराई जाय। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। मैंने नोटिस दिया हुआ है···(व्यवधान)

कुमारी मायावती : महंगाई से ज्यादा महत्व गरीब की जानों का है।

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, आप हाऊस का ध्यान खींच चुकी हैं, मैंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर विचार करेगी। मायावती जी, मेहरबानी करके आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : आप आगरा काण्ड को इग्नोर करना चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी क्यों चुप हैं, गृह मंत्री जी क्यों चुप हैं ? इसका मतलब यह खुद दोषी हैं, चुप बैठे हुए हैं। बेकसूर लोग वहां मारे गए हैं, पहले इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरे पाइंट ऑफ आर्डर का क्या हुआ ?

कुमारी मायावती : आगरा काण्ड के ऊपर आपने कोई फैसला क्यों नहीं लिया अभी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, आप सीट पर जाइए।

कुमारी मायावती : आप पहले आगरा काण्ड को लीजिए, वहां बेकसूर लोग मारे गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मायावती जी, आप मेहरबानी करके सीट पर आइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

12.24 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई उद्घोषणा; जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा; राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 के आदेश के अनुसरण में दिया गया आदेश और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का प्रतिवेदन

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा 19 जनवरी, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 19 जनवरी, 1990 को जम्मू-कश्मीर राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 18 जुलाई, 1990 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 647 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को दिए गए आदेश, जो 18 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 648 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के 3 जुलाई, 1990 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1153/90]

भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990; सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990, आदि

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1990 को प्रख्यापित भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 2)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1153/90]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 3)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1154/90]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 30 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 4)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1155/90]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 30 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 5)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1156/90]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना जिसके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित वे अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनका औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पालन किया जाएगा

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11-ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 12 (3)/90-एस० एस० आई० (पी०), जिसके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित वे अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनका औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पालन किया जाएगा ताकि उन्हें उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन औद्योगिक उपक्रमों को सहायक अथवा लघु औद्योगिक उपक्रम समझा जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1157/90]

रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : महोदय, मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990, जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 552 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल (मुद्रा दायित्व का विस्तार और प्रभार प्रतिशतता विहित करना) नियम, 1990

जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 557(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1158/90]

12.25 म० प०

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आगरा कांड को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको कराने में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का हाथ है। (व्यवधान)

बेकसूर लोग मारे गए हैं, इसका जवाब दिया जाए। गृह मंत्रीजी वहां क्यों नहीं गए। आगरा कांड पर पहले फैसला दिया जाए, नहीं तो हम हाउस चलने नहीं देंगे। आगरा कांड पर पहले फैसला दिया जाए। महंगाई से ज्यादा गरीबों की जानें हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सवाल को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखकर विचार किया जाएगा कि इस पर किस तरह से बहस करवाई जा सकती है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : बेकसूर लोग मारे गए हैं। गृह मंत्री जी नहीं गए और प्रधान मंत्री जी नहीं गए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों, मैं उसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के संबंध में माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है, हमारा दल भी इस बात से चिन्ता में पड़ा हुआ है। चूंकि आपने पहले ही स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है, मैं सदस्य महोदया से निवेदन करता हूं कि हम इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के पश्चात् अगले विषय के तौर पर उठाएं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं आपकी अनुमति चाहती हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। मैं भी कुमारी मायावती जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हूं किंतु मैं ऐसा नहीं चाहती हूं।

हरिजनों और महिलाओं पर नृशंसताएं तो आजकल बार-बार होती हैं। पूरे देश में हो रही हैं। अतः इस सभा में इस विषय पर व्यापक विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए।

श्री राजीव गांधी : यह एक व्यापक विषय है। क्या हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि कल 3.30 म० प० पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। हमें जिस विषय पर यहां चर्चा करनी है उसमे हमें न्याय करना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति कोई अलग चीज नहीं है।

हां, श्री वसन्त साठे ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की सूचना दी है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब और काश्मीर से जो लोग यहां दिल्ली आये हैं, वे आज दिल्ली के अन्दर मर रहे हैं। बीमार पड़े हुए हैं। उनसे वायदा किया गया था कि उनको पांच सौ रुपया महीना दिया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आज तो शुरूआत है।

श्री मदन लाल खुराना : आज आप प्राइस को ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई सवाल को नजरअन्दाज नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि इस सदन के अन्दर हमारे होम मिनिस्टर ने कई बार कहा है कि उनको मंथली दिया जाएगा। पहले पांच सौ रुपए फिर कहा कि एक हजार रुपए होगा। मेरा यही कहना है कि आठ महीने हो गए हैं, केवल उनको दो बार पांच सौ रुपए दिए गए हैं, जबकि इस सदन के अन्दर होम मिनिस्टर ने एक लाइन में छः बार कहा कि मंथली देंगे, मंथली होगा। एडहॉक नहीं होगा, मंथली होगा। बेचारे जो लोग काश्मीर से आए हैं, पंजाब से जो लोग आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने ही देश में विस्थापित होकर जो लोग आए हैं, उनके लिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि मानवता के आधार पर कैलास एटीचूड को त्याग करके सरकार के अन्दर संवेदनशीलता होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि हरिजनों के साथ इस बारे में भी बातचीत होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे चर्चा जारी रखने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : हरिजनों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमने नोटिस दिया, इसका क्या फैसला हुआ ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : ग्रामीण बैंकों के 5,000 कर्मचारी दिल्ली आ गये हैं और बोट क्लब पर धरना दे रहे हैं। वे राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसमें चार महीने का समय पहले ही व्यतीत हो चुका है। सरकार ने अभी तक इस अधिनिर्णय को लागू नहीं किया है। वित्त मन्त्री महोदय सदन में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे इसका उत्तर दें।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि इस सरकार के समर्थक दलों द्वारा बढ़ती कीमतों

पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को जानबूझकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का निवेदन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम भी कीमतों में वृद्धि पर बहस कराना चाहते हैं। मैंने इस आशय का नोटिस दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने भी कीमतों में वृद्धि पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है। वे किसके बारे में बात कर रहे हैं ? क्या वे हमें सलाह देना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे, क्या आप अपना भाषण फिर से आरम्भ करेंगे ? उस ओर मत देखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है ? आज देश की जनता को महंगाई के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव आप लोग मान चुके हैं। स्थगन प्रस्ताव एक गंभीर सवाल पर है। मैं बसन्त साठे जी से कह रहा हूं कि वे इस पर बोलें।

12.33 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा अब स्थगित हो।"

[हिन्दी]

मैं देश के बहुत गम्भीर सवाल की ओर आपका और सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह अल्पसंख्यक सरकार हुकूमत में आई तो बड़े गरूर से उन्होंने यह कहा कि हमारा पहला काम होगा - देश की महंगाई को रोकना। दूसरा काम होगा—बोफर्स जैसे जो कांड हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जिससे महंगाई बढ़ी—उनके नाम का भण्डाफोर करना।

ये दो बातें जनता दल ने अपने मेनीफेस्टो में कही थी। सबसे ज्यादा जोर दिया गया था महंगाई पर और हमें लगा कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग, मधु दण्डवते जी जैसे यहां हैं और जरूर कुछ न कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाएंगे कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर काबू पाएंगे। उनका

समर्थन करने वाली बैसाखियां भी ताकतवर हैं, मजबूत लोग हैं, उनकी मदद से वे जरूर कामयाब होंगे, पर हमने बजट के बाद और बजट में भी जब दण्डवते जी ने कहा कि यह जो बजट मैं पेश कर रहा हूं, उसमें जो कदम उठा रहा हूं, खासकर पेट्रोल की दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे कि देश में हम पेट्रोल की खपत पर काबू पाएंगे और कीमतों को नीचे लाएंगे। ये सारे आश्वासन हमारे दण्डवते जी ने दिए और हम सोचते रहे कि चलो देखें ये जो कदम उठा रहे हैं, शायद कीमतें नीचे आएं देश का भला हो, जनता का भला हो, लेकिन आप देखिए कि हकीकत में क्या हुआ, एक-एक आंकड़ा मैं आपके सामने दूंगा। परसों दूरदर्शन पर भी दण्डवते जी ने यह बात कही, सारी बातें देश के सामने हैं, हम तथ्यों को लेकर चलें, उसमें कोई बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं है; हां कारणों पर बात हो सकती है। पर जहां तक तथ्यों का सवाल है, आप देखेंगे कि सितम्बर 1989 में होल सेल प्राइस इंडेक्स, जब हमारी सरकार हुकूमत में थी और 3 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, उस समय 168 था और हमने महंगाई रोकने के लिए जो कदम उठाए, भजन लाल जी ने तेल के बारे में जो कदम उठाए, अनाज का रिकार्ड उत्पादन और प्रोक्योरमेंट वगैरह जो हो रहा था, उसकी वजह से नतीजा आप देखेंगे कि दिसंबर, 1989 में होल सेल प्राइस इंडेक्स गिरकर 166 आया, मैं तो यह कहता हूं कि नीचे आया।

12.38 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

हमने जो कदम उठाए थे, उन्हीं कदमों को आप आगे चलाते, तब भी आप बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पा सकते थे। आपने जनता से कहा कि हमें वोट दीजिए, हम कीमतें और नीचे लाएंगे। मैं माननीय दण्डवते जी से और प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम जो काम हमने किए, जिनकी वजह से कीमतें नीचे आई दिसम्बर में, उतने काम ही आप करते और होल सेल प्राइस इंडेक्स 166 पर ही रुक जाता तब भी हम कहते कि शाबाश, बहुत बड़ा काम किया, पर आपने क्या किया। आप जोर देकर कहते रहे कि अब नीचे कीमतें आएंगी, एक महीने आएंगी, दो महीने में आएंगी, हम ताकीद दे रहे हैं, खबरदार, मैं कोट करना चाहता हूं, जो-जो वचन दण्डवते जी ने अखबारों में और जाहिर बयानों में दिए—

[अनुवाद]

22 जनवरी, को अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रो० दण्डवते ने कहा :—

"सरकार कीमतों को कम करने के लिए एक दीर्घकालीन परिणामोन्मुखी फार्मूले पर कार्य कर रही है। मुझे यकीन है कि आज से अर्थात् 22 जनवरी से अगले पांच महीनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आयेगी।"

तथ्य ये हैं।

उन्होंने 22 अप्रैल को मुम्बई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा :—

"बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम जल्दी ही सामने आयेंगे और मुझे यकीन है कि जून, 1990 तक चीनी, चाय, खाद्य तेल और दूसरी चीजों की कीमतों में गिरावट आयेगी।"

[हिन्दी]

एक-एक देखते जाइये ।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय मोर्चा सरकार कीमतों में कमी लाने के लिए अगले दो महीनों में सभी आवश्यक कदम उठायेगी।"

यह आश्वासन उन्होंने 21 अप्रैल, 1990 को श्रीमती दण्डवते के नेतृत्व में आये महिला आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल को दिया था ।

[हिन्दी]

मधु दण्डवते जी ने दो महीने कहा, प्राइम मिनिस्टर उनसे कम थोड़े रह सकते हैं । उन्होंने कहा :—

[अनुवाद]

"सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, सीमेंट और चाय आदि के मूल्य अब से एक महीने के भीतर कम करने के लिए अनेक उपाय किये हैं" – 26 अप्रैल ।

[हिन्दी]

जनवरी से मैंने बताया है । हमने बड़ी गलतियां कीं, हमने कीमतें बढ़ायीं, हमारी वजह से कीमतें बढ़ रही थीं । उनको नीचे लाने के लिए इन्होंने जनता से कहा कि हमें चुन कर भेजिए, देखना हम कीमतें नीचे लाते हैं । जनवरी माह से मैं इनका बयान दे रहा हूं । अब देखिए ।

[अनुवाद]

मई में प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विशाखापत्तनम में भाषण करते हुए कहा :—

"हाल ही में चीनी और सीमेंट के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि मई, 1990 के अन्त तक इनके मूल्यों में कमी नहीं होती है, तो हम कठोर कदम उठायेंगे ।"

[हिन्दी]

फिर वी० पी० सिंह जी गरज रहे हैं । गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं ।

[अनुवाद]

"मैं चीनी और सीमेंट उद्योगों को धोखाधड़ी में सम्मिलित होने के विरुद्ध चेतावनी देता हूं । यदि ये उद्योग इन वस्तुओं की कीमतों को तुरन्त कम करने के उपाय नहीं करते, तो सरकार दृढ़ता से हस्तक्षेप करेगी ।"—बंगलौर में जनता दल कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ।

[हिन्दी]

हाथ कंगन को आरसी क्या । आप रिकार्ड देख लीजिए जुलाई तक, आज अगस्त है ।

26 जुलाई तक के आंकड़े मेरे पास हैं, क्योंकि यह वीकली आता है, मैं उसके आधार पर आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कीमतों के बारे में ।

[अनुवाद]

वर्ष 1981-82 के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक जो बजट से पूर्व 169.5 था, बढ़कर 177.7 हो गया । अब यह 8.84 की बढ़ोत्तरी के साथ 178.5 हो गया है । अब यह 5 होगा जो वार्षिक आधार 16.4 प्रतिशत निकलता है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी अधिक हो गया है। मैं आशा करता हूं, वित्त मंत्री महोदय आप सुना रहे हैं । आप अपनी कार्य योजना के बारे में बाद में निश्चित कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते ने जब से भारी कर लगाकर अपना पहला बजट पेश किया है, तब से बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है । मुंबई के थोक बाजार में मूंगफली के तेल की कीमत राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता संभालने के समय 217.50 रुपये थी, यह बढ़कर 257.50 रुपए हो गयी । मैं जुलाई के आंकड़े बता रहा हूं; इसमें और भी वृद्धि हुई है । अब बजट पेश होता है । बजट पेश करने के बाद इसकी कीमत 297.50 रुपये करने से 300 रुपए हो गई । तब अचानक यह तो तेल के बारे में हो गया ।

कृपया आप ही देख लीजिए कि लगातार अच्छे मानसून के बावजूद भी खाद्यान्नों की कीमतों में भी पुनः वृद्धि हुई है ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, 1987 में सदी का सबसे बड़ा अकाल हुआ था । जब अंग्रेज थे तो हम कहते थे कि वे आए थे तो अकाल आया था । कई लाख बंगाल की सड़कों पर मरे । आज आजादी के बाद इस सदी का यह अकाल हुआ और काफी लोग जान से गए । आपके देश की सरकार ने और लोगों की सरकार ने जिस तरह से परिवर्तन का मुकाबला किया तो अकाल में एक आदमी भी हताहत नहीं हो पाया । सारे देश को अभिमान करना चाहिए कि हमने अकाल को कैसे काबू में लिया । यह समझ में आ सकता है कि ऐसा कोई संकट होता और मानसून ही खराब हो जाता तो एक बहस हो सकती है । लेकिन 6 अगस्त को मंत्री श्री वर्मा जी ने कहा कि इस समय फूड-ग्रेन का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है । 172.7 मिलियन टन और कॉटन का 115 लाख बेल्स और शुगर केन 200 मिलियन टन । तात्पर्य यह है कि जब प्रोडक्शन रिकार्ड हुआ है और मानसून बहुत अच्छा हुआ है, आप पर मेहरबानी हुई । आप चाहते हैं कि लड़ाई होगी और तैयार रहो—तैयार रहो । इतना गरजने वाला प्रधान मंत्री गरजता है और बरसता नहीं है और खाली आंसुओं में रोता है ।···(व्यवधान) पंजाब और कश्मीर के मामले में कोई ताकत बताते और लड़ाई के लिए तैयार रहो, नहीं तो वो बहाना मधु दंडवते जी को मिल जाता । कुवैत में तो परसों को दाम बढ़ गए तो आप दाम नहीं रोक सकते । कहने का मतलब यह है कि दंडवते जी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहाने के लिए कोई जगह नहीं है । चालीस साल का बहाना बना रहे हैं । आप चालीस साल को इतिहास में से नहीं निकाल सकते जिसमें से पच्चीस साल आपके प्रधान मंत्री भी यहां रहे और आखिर तक इस पार्टी में बैठे रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे । कब तक आप यह बहाना बनाते रहेंगे और क्या इससे लोगों का पेट भरने वाला है ? फिर ये कहते हैं कि तिजोरी

खाली दी हम को इसलिए हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, 80 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ दिया, हम क्या करें, कितना बोझ है।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : साल के आखिर में वैसे भी तिजोरी खाली होती है।

श्री बसंत साठे : व्यवहार की बात यह है कि जिसकी तिजोरी खाली होती है वह पैसा लुटाता नहीं है। आते ही छूट दे दी और लूट मचा दी। आपने कहा कि 10 हजार रुपए तक के कर्जे माफ करेंगे, 14 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, क्या यह आपकी तिजोरी खाली रहने का नतीजा है, यदि आपकी तिजोरी खाली है तो इसमें से क्या दोगे। (व्यवधान)

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : कर्जे माफी का विरोध कर रहे हो ?

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप लूट-लूटकर सारे देश को खा गए इसलिए तिजोरी खाली हुई। अगर हिम्मत हो तो किसानों के जो कर्जे माफ हुए हैं उसका विरोध करो।

श्री बसंत साठे : आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या उनका कर्ज माफ हुआ है ? दूरदर्शन पर वित्त मंत्री के साथ साक्षात्कार में एक किसान ने पूछा था कि हम बैंक वालों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि जब तक कोई निर्देश नहीं आता हम आपको अगला कर्जा नहीं दे सकते। किसान के लिए सीजन शुरू हो गया है, बीज कहां से लायेगा, खाद कहां से लायेगा, उसको बुवाई करनी है, कैसे करेगा अगर कर्जा नहीं मिलेगा। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, जिसकी पात्रता हो उसे ये कहते हैं कि अगर अगला कर्ज चाहते हो तो पिछला कर्ज माफ कराने के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर दो। देश के किसानों की जिनकी थोड़ी-बहुत ताकत है उनको दिवालिया बनाना चाहते हैं, तब अगला कर्जा देंगे। क्या यह मान्य है जोशी जी और बी० जे० पी० के साथियो कि उनको दिवालिया बनाया जाये ? क्या यही बख्शीश देना चाहते हो उनको जिन्होंने चुनाव में आपको वोट दिए हैं। इन्होंने जो घाटा बताया 7 हजार 5 सौ करोड़ का, इसमें इनके सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार माफी देने वाली है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है आप अपने भाषण से कहें।

श्री बसंत साठे : जो सब्सिडी वगैरह के खर्चे हैं यह सारे मिलाकर उनका केलकुलेशन था तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपए और यह हिडन खर्चा था जो डी० ए० देने वाले थे जिसको इन्होंने एक सौ करोड़ बताया है, लेकिन उससे ज्यादा है। यह सब आप देखेंगे तो घाटा बहुत बढ़ेगा। यह समझ कर चलें कि करीब पांच-छः हजार करोड़ रुपया जेनरेट होगा और हमें पब्लिक सेक्टर से मिलेगा तो यह सबका अनुभव है कि यह पैसा पब्लिक सेक्टर से नहीं आता है। खाली पेट्रोलियम में जहां एडमिस्टर्ड प्राइस है वहां बढ़ाकर आप कहते हैं कि हमको पैसा मिला है। और उसका असर क्या होता है ? आज देश इसको भुगत रहा है। इस तरह से जो स्टील, कोल और पावर के दाम जहां-जहां बढ़ेंगे, लेकिन उनका असर देश की हर चीज पर जायेगा। यह सब जानते हैं। लेकिन बताने के लिए लोगों को कहते हैं कि भाई मैंने डेफिसिट नीचे रखा है। उन्होंने कहा था कि हम कीमतों को कंट्रोल में लायेंगे, डेफिसिट को कम करेंगे और करने की कोशिश की परन्तु मुंह के बल गिर गए। मेरे ख्याल में पहले छः महीने में बजट में जितना डेफिसिट था, उससे भी ज्यादा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो यह सरकार कर रही है, उसमें मनी सप्लाई 17 परसेंट होना चाहिए था वह 19.4 परसेंट हो गया। अब आप देखिए कि यदि चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती जायेगी और देश के जिन लोग

को जो डी० ए० मिलता है और इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, उससे उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी लेकिन आप कहते हैं कि वह हम फ्रीज करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मधु जी से पूछना चाहता हूं कि इस मध्यम वर्ग और खासकर गरीब लोगों को इस देश में क्या दशा होगी ? यह तो सभी जानते हैं कि घर में कीमतों के बारे में पता लग जाता है। मैंने आज ही अपनी पत्नी से पूछा कि बाजार जाते हैं, चीजें खरीदने के लिए, क्या लेटेस्ट दाम हैं और कल क्या थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने राईटिंग में दिया है :

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या वे सही बता रही थीं ?

श्री बसंत साठे : आप अपनी पत्नी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कम से कम एक बात के लिए तो आप सभी पत्नी पर निर्भर रहते हैं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : हम सहमत हैं।

[हिन्दी]

दिसम्बर, 89 में जिस दाल का भाव 8.50 रु० प्रति किलो था, वह आज 12-13 रु० किलो हो गया है, चीनी 8 रु० किलो से 10 रु० किलो हो गयी है। मूंगफली का तेल 22 रु० किलो था जो अब बढ़कर 40 रु० प्रति किलो है, साबुन की एक बट्टी 3 रु० की थी जो अब 5 रु० की हो गयी है। गेहूं 4 रु० से 5 रु० प्रति किलो हो गया है। चाय 52 रु० पैकेट से 65 रु० पैकेट हो गया है, पैट्रोल 8 रु० से 11 रु० प्रति लीटर हो गया है। आलू तो मामूली गरीब आदमी की चीज है जो 2 रु० से 4 रु० किलो हो गया है। इसमें तो 100 प्रतिशत इंक्रीज हुई है। प्याज 2 रु० से 5 रु० हो गया, चना 15 रु० से 21 रु० किलो हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार देश के किसी भाग में ये कीमतें कम हैं तो कहीं ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ी जरूर हैं। इसमें कोई शुब्हा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री बसंत साठे : आपको यदि सस्ता मिलता है तो आप हमें बता दें, हम भी वहां से खरीद लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय; इनकी तमाम घोषणाओं के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं और आसमान को छूकर बढ़ रही हैं। सारे लोग कह रहे हैं :

[अनुवाद]

'आसमान को छूती हुई कीमतें।' सम्पूर्ण प्रचार तन्त्र और जनता की यही राय है।

[हिन्दी]

और जैसा आपने कहा कि आप हम लोगों को ही दोष दे रहे थे कि हमारी नीतियों की वजह से यह सब हो रहा है। यदि ये कहते हैं कि हमने किया तो इन्हें हम पर छोड़ देना चाहिए। यदि इतने नालायक हैं कि नहीं काबू कर सकते हैं तो छोड़ दो हम पर। आप कह देते···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं बार-बार कह रहा हूं।

श्री बसंत साठे : आप तो माइनरटी में हो यानि अल्पसंख्यक सरकार हो। लार्जेस्ट पार्टी

1.00 म० प०

तो आज भी हम हैं और आप बैसाखियों के ऊपर लड़खड़ाते हुए चलने की बजाये, आपकी हालत यह हो गयी है कि लंगड़ा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं है। अब तो आप बिना टांगों के, दोनों हाथों के सहारे ही चल रहे हैं, यह हाल है, एक तरफ बी० जे० पी० और दूसरी तरफ हमारे कम्युनिस्ट भाई आपको उठाकर चल रहे हैं। आपके पैर भी जमीन पर नहीं हैं, यहां तक नौबत आ गयी है। आप कह क्यों नहीं देते कि हमसे स्थिति सम्भल नही रही है, हमारी तिजोरी खाली थी, उपाध्यक्ष जी, मैं यहां कर्जे की बात कह रहा हूं। सभी उद्योगों से संबंधित व्यक्ति दुनिया भर में इस बात को जानते हैं कि बैंकों से कर्जा लेकर ही उद्योग चलाया जा सकता है, कोई अपने घर का पैसा लगाकर उद्योग नहीं चला सकता क्योंकि वह काफी नहीं होता, 10-20 परसेंस घर से पैसा लगता है, बाकी सारा पैसा बैंकों से कर्जा लेकर काम चलाया जाता है। कोई भी उद्योग हो व्यापार हो, सभी का यही नियम है। लेकिन यहां सवाल कर्जे का नहीं है, कर्जा वापस करने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए, जिसे कहते हैं—क्रैडिबिलिटी। हम इंकार नहीं करते कि जब हमारी सरकार थी तो हमारे ऊपर 80 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था; परन्तु आज दुनिया में पूछिये, भारत की स्थिति क्या हो गयी है। (व्यवधान) आप जितना कहना चाहो, कह लो, परन्तु एक बात ध्यान में रखो कि हमारे समय में भारत की ताकत को सारी दुनिया जानती थी, सभी विश्व के लोग जानते थे कि भारत एक पाई भी कभी बकाया नहीं रखेगा, एक-एक पैनी हम वापस करने की सामर्थ्य रखते थे। हमारी क्रैडिबिलिटी को सारी दुनिया जानती थी। हम आई० एम० एफ० को भी कह सकते थे और हमने कहा कि हमें तुम्हारा लोन नहीं चाहिए, हम अपने आपको खुद सम्भाल लेंगे। वह ताकत थी हमारी, जब सरकार हमारे हाथ में थी, लेकिन आपका हाल क्या है, आप आज खुद कह रहे हो कि हो सकता है, शायद हमें आई० एम० एफ० से लोन लेना पड़े, धीरे-धीरे कह रहे हो जबकि पहले कहते थे कि कोई बाहर से कर्ज नहीं लेंगे, परन्तु परसों दण्डवते साहब खुद कह रहे थे कि हो सकता है शायद हमें लेना पड़े। आप झुक रहे हो, दब रहे हो, मल्टी नेशनल्स को ला रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी इंडस्ट्रियल पोलिसी उत्पादन बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, क्या आप एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं चाहते, आखिर किस एरिया में ये मल्टी नेशनल्स आने वाले हैं, कहीं नानएसेंशिअल कमोडिटीज में तो नहीं आने वाले हैं, कहीं अनएसेंशिअल कमोडिटीज प्रोड्यूस करने वाले एरिया में तो आप उन्हें नहीं बुला रहे हो जिससे उनका ही उत्पादन बढ़े और दाम नीचे आयें, कहीं ऐसा तो नहीं करने वाले हैं आप। यदि लग्जूरियस आयटम्स की तरफ आपका ध्यान हो···

उपाध्यक्ष महोदय : साठे जी, आप कितना टाइम और लेंगे।

श्री बसंत साठे : मैं पूरा लंच आवर ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि 5-7 मिनट में खत्म करने वाले हों तो ठीक है, मैं लंच के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री बसंत साठे : अभी तो मैं कुछ समय और लूंगा, 5-7 मिनट में पूरी बात नहीं कह पाऊंगा।

[अनुवाद]

मैं मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

स्थगन प्रस्ताव—जारी

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता

सभापति महोदय : हां, श्री साठे, कृपया आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सामान्यतः जब ऐडजोर्नमेंट मोशन होता है तो मतदान कौन से समय पर होगा, वह घोषित होता है, लेकिन आज घोषित नहीं हुआ है। यदि आप घोषित करेंगे तो सदस्यों को भी सुविधा रहेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बात सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करती है। सामान्यतः हम समय निश्चित नहीं कर सकते। स्थगन प्रस्ताव के लिए सामान्यतः ढाई घण्टे का समय नियत किया जाता है, परन्तु यदि अधिक सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं; तो हम समय में वृद्धि भी कर सकते हैं। मैं आपको पांच मिनट का समय देने के लिए तैयार हूं, परन्तु आपको अपना भाषण इसी समय में पूरा करना होगा।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, श्री राम नाईक ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव के लिए ढाई घण्टे का समय आबंटित किया जाता है परन्तु इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और हम हमेशा इस समय से ही नहीं जुड़े रहते हैं। अस्थायी रूप से हम यह तय कर लेते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि यह निन्दा प्रस्ताव का ही एक रूप है और सभी सदस्यों को कक्ष में उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए, अस्थायी रूप से आप यह निश्चित कर सकते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा।

सभापति महोदय : अस्थायी समय ढाई घण्टे का है।

श्री बसंत साठे : मैं समझता हूं कि आप इसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निश्चित कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं कीमतों के बारे में बात कर रहा था । सारे देश को इससे चिन्ता है कि देश में कम से कम आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में आएं, आनी चाहिए । यह देखा जा रहा है कि कुछ नीतियों के चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में आना असम्भव हो रहा है हालांकि हमारे अर्थ मंत्री जी ने बार-बार कहा, परसों दूरदर्शन में भी कहा कि वे चाहते हैं कि कड़े कदम उठाएं, सौफ्ट औपशन्स न लें, हार्ड औपशन्स लें । उन्होंने कहा कि मुझे जब किसी ने पूछा तो मैंने यह कहा कि मैं भले ही लोकप्रिय अर्थमंत्री न बनूं लेकिन कामयाब अर्थ मंत्री बन पाऊंगा । कामयाब बनने के लिए कड़े कदम उठाना आवश्यक था और हम यही आशा कर रहे थे कि कड़े कदमों का कुछ असर भी होगा । क्या हो रहा है ? उनकी मंशा के बारे में मैं शंका नहीं करना चाहता, भले आदमी हैं, ऐसा मैं मानता हूं । लेकिन बावजूद इसके मुझे कलकत्ता से एक पत्र आया है और बंगाल में जो कुछ हो रहा है सब लोग जानते हैं । उस इलाके में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग मस्टर्ड आयल इस्तेमाल करते हैं । बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें शामिल है । उन्होंने लिखा है कि ड्राउट के काल में 1987 में मस्टर्ड आयल की कीमत 25 रुपये के० जी० रिटेल में थी जो आज आर्टिफिशियल शार्टेज तैयार करके 35 रुपये के० जी० हो गई है । यह खत उनका 27 जुलाई का है । बंगाल वाले लोग इसके बारे में शायद जानते होंगे । मेरे ख्याल में अब वह और ज्यादा हो गए होंगे । उनका यह भी कहना है कि हम यह मान सकते हैं कि 10 लाख टन उत्पादन पिछले वर्ष से कम हुआ लेकिन क्या यह जरूरी है कि इतने उत्पादन से इतनी कीमतें बढ़ जायें ।

एक न्यूज पेपर "व्यापार केसरी" जो कि दिल्ली से निकलता है उसके एक न्यूज आइटम में यह आया कि एक मिनिस्टर जिसका नाम नहीं है, के रिश्तेदार ने व्यापारियों से सांठ-गांठ करके करोड़ों रुपये का मस्टर्ड सीड खरीद लिया और उसको कार्नर कर लिया । फिर होर्डिंग करके आर्टिफिशियल स्कार्सीज पैदा किया । एन० डी० डी० बी० ने कीमतें कम करने की बजाय उस एजेंसी से हाथ मिला कर मस्टर्ड आयल को हायर रेट पर 25 रुपए के० जी० में होलसेल मार्किट में बेच दिया ।

[अनुवाद]

"कलकत्ता में एन० डी० डी० बी प्रति टन 4,000 से 5,000 रुपए का अधिकतम अतिरिक्त लाभ कमा रहा है ।"

[हिन्दी]

यह बात मेरे मित्र जिसने खत लिखा है, उसमें लिखी है ।···(व्यवधान)

एक "सनमार्ग" अखबार जो कि कलकत्ता से निकलता है । उसने अपने 20 जुलाई के अंक में कुछ क्वोट किया है । इसमें मंत्री जी का नाम भी दिया हुआ है । उसमें उसने यह क्वोट किया कि श्रीमान नाथू राम मिर्धा जी ने एक भाषण देते हुए कहा कि खाद्य तेलों की कीमतों की गिरावट का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है···(व्यवधान)···इरादा उनका भी नेक होगा । वह कहते हैं कि उसका असर यह हुआ कि···

[अनुवाद]

"परन्तु दुर्भाग्य में केन्द्रीय खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए ऐसे भाषण से बेईमान व्यापारियों, चोर बाजारी करने वालों और अवैध ढंग से जमाखोरी करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है और अब उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार स्वयं खाद्य तेलों की दरें बढ़ाने का प्रयास कर रही है। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि श्री मिर्धा ने उन लोगों के नाम, जो जमाखोरी करके इस कृतिम संकट को पैदा कर रहे हैं, उजागर करने के लिए कभी भी एक शब्द नहीं कहा।"

[हिन्दी]

अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कहें यह अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आपका इरादा बहुत नेक हो। नेक इरादे का मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे अर्थ मंत्री जी ने पैंट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। अभी कल ही आप कह रहे थे कि आंकड़ों और गणित के मुताबिक दो पैसे, हाफ परसेंट या एक परसेंट से ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप बड़े गणितज्ञ हैं। उन्होंने यह माना कि व्यवहार में यह उनका गणित काम में नहीं चला। उसका कैसकेडिंग इफैक्ट और स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है। जितने भी ट्रांसपोटर्स हैं, दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं कह देते हैं कि हम क्या जानें, पैंट्रोल के दाम बढ़ गये, डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई इसलिए दाम बढ़ गए···

एक माननीय सदस्य : रास्ता बताइये।

श्री बसंत साठे : आप गद्दी छोड़ दीजिए, हम रास्ता बता देंगे। आप यह चला नहीं सकते। मैंने तो कहा जाने दीजिए, आप ज्यादा बोलोगे तो आपकी बैसाखी वाले ज्यादा जोर लगाएंगे। मेरा यह कहना है, अर्थ मंत्री जी, कि इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, पैंट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपने जो काम किया उससे सारे देश में त्राहि-त्राहि मच गई। जितने सारे होर्डर्स थे और रिटेयर्स थे, सबने दाम बढ़ा दिये। आपमें तो ऐसी होड़ लगी हुई है, एक दूसरे में कि क्या कहें। आपने खुद कहा कि हम क्या करें, रेल्वे वालों ने गड़बड़ कर दी, उन्हें फुल रैक देना चाहिए नमक के लिए, तो ही ले जाएंगे, फिर आपके मध्यस्थी ने माना कि वैगन में ले जाय। आपके राज में रहते तो नमक तक के दाम बढ़ गए हैं, आपके काम से। आप मुझे बताइये आपका तालमेल, पैंट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने कहा, अच्छा कड़क कदम उठाएंगे। क्या कड़ा कदम उठाया, कड़ा कदम यह उठाया कि हफ्ते में 12 घंटे ही पैंट्रोल मिलेगा, 24 घंटे में से और इतवार को बन्द रहेगा। फिर आगे दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि इतवार को 12 बजे तक मिलेगा। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से यदि आप जवाब दें, आप दें या पैंट्रोलियम मिनिस्टर से जानकारी लेकर अर्थ मंत्री जी दें, इतने दिनों में, जब से यह व्यवस्था लागू हुई है, इसका क्या असर हुआ है ? पैंट्रोल और डीजल की खपत कितनी कम हुई है ? कितनी बचत देश को विदेशी मुद्रा के रूप में या अन्तर्देशीय मुद्रा के रूप में हुई ? लोगों का और अखबार वाले जो लिख रहे हैं, उन सब का यह कहना है कि इंडियन आयल कम्पनीज के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, कोई कमी तो हुई ही नहीं, डिमाण्ड में, उल्टे होर्डिंग हो गई और डिमाण्ड बढ़ गई, इस आशा से लोगों ने होर्डिंग की कि आगे चलकर और दाम बढ़ाएंगे। तो असर उल्टा हुआ। करने गए एक और सारे बेचारे आटोरिक्शा वाले, टैक्सी चलाने वाले सारे त्रस्त हो गए और इसमें आपने ऊपर से कमाया कुछ नहीं तो आप दोनों तरफ से गए, न घर के रहे न घाट

के । क्या मिला आपको, आपने लोगों को भी दुखी कर दिया और बचत कुछ नहीं हुई तो आपके यह जो सो काल्ड हाई आपक्षंस हैं, यह हार्डशिप क्रिएट कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलता । जो कुछ पहले कह रहे थे कि यह डैफीशिट का कन्सैप्ट आपने लगाया था कि हम डैफिशिट को काबू में लायेंगे तो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, बिजनेस एक्सप्रेस डेटिड जुलाई, 26, बम्बई से जो पब्लिश हो रहा है, मैं उसको कोट करता हूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको भी इससे लाभ होगा । आपने पढ़ा ही होगा शायद अर्थ मंत्री जी ।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है :

"पहली तिमाही में बजट घाटा 1990-91 के अनुमानों से बढ़ गया । वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही में (अप्रैल-जून) में बताया गया है कि बजटीय घाटा 7400 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है और इस प्रकार यह सम्पूर्ण वर्ष 1990-91 के 7206 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से अधिक हो गया । गत वर्ष पहली तिमाही में द्वितीय घाटा 9701 करोड़ रुपए था…"

"…और 1989-90 के संपूर्ण वर्ष में यह 11,750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था । केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रो० मधु दण्डवते ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि हाल में केन्द्रीय पूल में राज्यों को उनके हिस्से के वितरण के कारण ऐसा हुआ है । अब कुछ समय के लिए यह घाटा स्थिर रहेगा और तब कम होगा । वर्ष के अन्त में, बजट में की गई व्यवस्था के आस-पास रहेगा । वित्त मंत्री का विश्वास इस तथ्य पर आधारित था कि इस तिमाही में मौद्रिक विस्तार गत वर्ष की इसी तिमाही में 4.5 प्रतिशत की तुलना में 3.8 प्रतिशत कम था ।"

वास्तव में, यह सही नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : 4.00 प्रतिशत की तुलना में यह 5.8 प्रतिशत है ।

श्री बसंत साठे : इसमें आगे निम्न प्रकार बताया गया है :

"इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना रुचिकर है कि सरकार द्वारा तैयार नीति संबंधी पत्र को केन्द्रीय सरकार के द्वितीय घाटे के बारे में क्या कहना है । पत्र कहता है : हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इस घाटे को बजट अनुमान स्तर पर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है । यहां बजट पर रक्षा (500 करोड़ रुपए) अन्य आन्तरिक सुरक्षा आवश्यकताएं (500 करोड़ रुपए) कुछ केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं को कम धन दिए जाने (500 करोड़ रुपए) ऋण माफ किए जाने की योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं (लगभग 1200 करोड़ रुपए) से पैदा होने वाली कई अभिज्ञेय अतिरिक्त मांगें पहले ही हैं…"

उपर्युक्त पत्र स्वयं सरकार द्वारा तैयार किया गया था । यह अब 3000 करोड़ रुपए तक चला गया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह केवल ऋणों पर ब्याज है ।

श्री बसंत साठे : इसमें आगे निम्न प्रकार कहा गया है :

"···फसल बीमा योजना (250 करोड़ रुपए) और खाद्य राज सहायता (200 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं है। राज्यों में भी या तो प्राकृतिक आहृदाओं (जिसके लिए सीमित धन राशि की व्यवस्था की गई है) अथवा उनकी अनुमोदित योजना व्यय को पूरा करने के लिए भारी मांग होगी जो कि उनके स्वयं के संसाधनों के बारे में बहुत ही आशावादी अनुमानों पर आधारित रहा है। राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकताओं के आश्वासन के अतिरिक्त वर्तमान कमायी अतिरिक्त मागें पहले ही लगभग 3500 करोड़ रुपए तक जुड़ गई हैं जो कि वास्तव में अब 5000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी।

इसके अलावा हथकरघा बुनकरों के 10,000 रुपए तक के ऋण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 2000 रुपए तक ऋण माफ करने के प्रस्ताव हैं। इन सबसे राजकोष पर अतिरिक्त भारी बोझ पड़ेगा।"

[हिन्दी]

मैंने आज सुबह ही मनी-सप्लाई के बारे में बताया कि वह भी बढ़ रहा है। यह सारा डैफिसिट फाइनेंसिग नोन एंड हिडन—मैं आज सुबह ही आपसे कह रहा था कि जो आप पब्लिक सैक्टर से सरपल्स जनरेट करने की उम्मीद रख रहे हैं, आज तक हमारे रहते भी पब्लिक सैक्टर से जो हमने उनसे उम्मीद की थी, एक्सपैक्टेशन किया था, वह कभी नहीं आया। अब यह चमत्कार अगर आप कर पायें तो मैं आपको बहुत-बहुत शाबाशी दूंगा। लेकिन जिस तरह से पब्लिक सैक्टर चल रहे हैं, इनसे यह उम्मीद करना बेकार है कि कोई सरप्लस जनरेट होकर आपकी किट्टी में आने वाला है। यह भी छोड़िए, जिस तरह से अब ताऊ जी का घुटना, नौ तारीख को जो आप को वे झटका देने वाले हैं और सारे देश के किसान भाई आकर के मांग करेंगे···(व्यवधान)···वे जो मांगें और बढ़ेंगी, उनके लिए आप क्या करेंगे। इधर तो आप कह रहे हैं कि हार्ड आप्शन्स, यू-आर-स्टैप-बाई-स्टैप-स्कमिंग-टू-प्रैशर···(व्यवधान)···मैंने एक बात कही कि देश में काफी मक्कार लोग हैं और उन्हें दखल नहीं देनी चाहिए, तब बात देश की बनेगी।···(व्यवधान)···मैं यह कह रहा हूं कि आपने तमाम जो सो-कॉल्ड हार्ड-आप्शन्स लिए हैं, उससे फिन्ज यानि ऊपर का कवर भी खरोंच नहीं पाए, किया क्या कि इधर से एम्बैसी बन्द कर दी और उधर से दुकान बंद कर दी। आपने ऊपर-ऊपर का सब काम कर दिया लेकिन असली जो आप 10 परसेंट कम करने वाले थे, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक कितनी कामयाबी आपको गवर्नमेंट से नान एसेंशियल को कम करने में मिली है। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं कि खेतीहर मजदूर जो ज्यादा संख्या में इस देश में हैं उनको भी आप सब चीजें दो ताकि किसान अपनी उपज को बढ़ा सके। मेरा कहना यह है कि आज ही हमारे एक मित्र किसान भाई महाराष्ट्र से आये थे और बता रहे थे कि हमको फर्टीलाइजर नहीं मिलता और अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, पेस्टीसाइड महंगा हो गया, इस तरह से किसान को मिलने वालो हर चीज महंगी होती जा रही है। इस कारण से किसान आज बहुत दुखी है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान को हर चीज उचित दाम पर मिले ताकि वह अपनी उपज बढ़ा सके। ये सब चीजें जो उसके जरूरत की हैं, उसको मिलनी चाहियें। मेरे भाई, ये नाटक सब चीज का होता है, पैसे का नहीं होता। पैसा, रिसोर्स, ये तो लाना ही पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है।

एक बात अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं और यह बात परसों भी मैंने आपसे कही थी—वह है "काला धन" इसको दूर करना चाहिए। समानांतर अर्थव्यवस्था जो देश में चल रही है, आपने खुद कहा कि कम से कम 80 हजार करोड़ रुपए में से 40 हजार करोड़ अनएकाउंटेड मनी, 40 हजार करोड़ स्मगलिंग मनी के रूप में है ये शब्द दंडवते जी के हैं। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : आपको कैसे मालूम है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आपको इससे कुछ ज्यादा मालूम हो तो आप बता दीजिए। मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा है मक्कार, नहीं-नहीं मक्कासर साहब 80 करोड़ से ज्यादा हों, तो आप वह भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : 40 साल में आपको ब्लैक मनी दिखाई नहीं दी। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैं इन सदस्यों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मेरी किताब 1985 में जो मैंने लिखा है उसमें वह सब चीजें लिखी हैं, उसको आप देखें।

श्री महादेव शिवनकर (चिमूर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि साठे जी ने जो मक्कार शब्द का प्रयोग किया है यह पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है। इस शब्द को यहां इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने केवल उनका नाम का उल्लेख किया है। इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री बसंत साठे : खैर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मैं जानता हूं लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, यह मुझे जो कुछ भी कहें, क्योंकि इस समय इनका संतुलन बिगड़ा हुआ है।

प्रो० मधु दंडवते : सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि जानबूझकर साठे साहब ने यह शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने सम्माननीय सदस्य का जिक्र करते हुए कहा, मैंने जो स्मगलिंग के आंकड़े दिए, उनको साठे साहब ने कोट किया, सम्माननीय सदस्य ने उनको टोकने की कोशिश की तो साठे साहब ने कहा कि जो करता है, उसको मालूम है, आपको ज्यादा मालूम होगा, मैं समझता हूं कि अप्रत्यक्ष तरीके से भी इस तरह का संकेत नहीं देना चाहिए कि इस सदन में बैठने वाला कोई भी स्मगलर है या उसके पास स्मगलिंग की प्रापर्टी है।

श्री बसंत साठे : ऐसा मैंने नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन उसका मतलब यही होता है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : सत्ता के लिए ही आप पागल हो रहे हैं, आपको सत्ता ही सत्ता दिखायी दे रही है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, मैं संघर्षों में रहा हूं, आपकी सरकार के खिलाफ 40 साल से लड़ता आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि सत्ता के लालच ने आपके संतुलन को गड़बड़ा दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सभापति महोदय, मैंने हिन्दी में जो कुछ कहा है शायद आपने उसे न समझा हो। मैं नहीं समझता कि उनका वह मतलब है···(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : मैंने नहीं कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात की है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप कार्यवाहियों को देखें, आशय द्वारा, यह अर्थ हो सकता है कि माननीय सदस्य का तस्कर के रूप में अथवा एक व्यक्ति जिसने तस्करी की हो, के रूप में वर्णन किया गया है। मैं माननीय सदस्य को जानता हूं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शोवत सिंह मक्कासर : आपके कहने की यही मंशा थी, मैं जानता हूं, मैं इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। आप जैसे संजीदा आदमी, जो अपने आपको पालियामेंटेरियन कहते हैं, इस तरह से घबरा जाएं और सत्ता के लिए अपना संतुलन खो दें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपको बताता हूं कि जहां तक इस माननीय सदस्य का संबंध है, वह न केवल एक माननीय सदस्य हैं बल्कि वह जन आन्दोलन से आये हैं। हम उन्हें वर्षों से जानते हैं और मैं समझता हूं कि जो कोई भी उनका कामरेड है उसे दुख पहुचेगा। अतः आप स्वयं कार्यवाहियों को देखिए। मैं नहीं समझता कि श्री वसंत साठे का वही मतलब था। यदि उसमें कोई आपत्तिजनक बात है तो उसे कार्यवाही-वृतान्तों से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री साठे ने स्वयं उसका खण्डन किया है। उनका वह मतलब कभी नहीं था। मैं स्वयं कार्यवाही वृतान्तों को देखूंगा और यदि उसमें कोई आपत्तिजनक बात होगी तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : माननीय सदस्य का नाम मक्कासर है, वरिष्ठ सांसद के मुंह से मक्कासर के बजाए मक्कार शब्द शोभा नहीं देता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इसके बारे में सभा को पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं। श्री साठे ने इसका खंडन किया है। मैंने कहा है कि यदि यहां कोई बात असंसदीय है तो उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वसंत साठे : मैं इसे स्पष्ट करता हूं कि मैंने जो कहा था कि यदि जिन आकड़ों का मैं उल्लेख कर रहा हूं वह श्री दण्डवते के वक्तव्य पर आधारित हैं वह गलत है और यदि माननीय सदस्य कुछ बेहतर जानते हैं—मैंने यह नहीं कहा कि वह उस कार्य में लगे हुए थे। आप कार्यवाही वृतान्त को देख सकते हैं—और यदि आप समझते हैं कि वहां ऐसा कोई शब्द है जिसका उनको ठेस पहुंचाने के रूप में अर्थ लगाया जा सकता है, मैं स्वयं पहले उन्हें वापस लेता हूं और आप उसे कार्यवाही वृतान्तों से निकाल सकते हैं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं इसके बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं। मेरे लिए इसे एक बार फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जो काला धन और इसकी पेरलल इकानमी देश में बढ़ रही है, जिस पब्लिक फाइनांस इंस्ट्रीट्यूट की रिपोर्ट से हमारे अर्थ मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े 3-4 साल पहले के हैं। आज यदि उस अनुपात में देखा जाए तो शायद यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, स्मगलिंग प्रापर्टी और काला धन दोनों को मिलाकर और इसको कंट्रोल करते हैं देश के कुछ हजार लोग, जो इस धंधे में लगे हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका प्लान पोरशन, एनवल बजट यदि लिया जाय तो तकरीबन 35-36 हजार करोड़ या 39 हजार करोड़ है। अब आप देखिए सारे देश के लिए, 85 करोड़ आबादी के लिए एनवल प्लान, प्लान एलोकेशन 39 हजार करोड़ है और देश में निर्माण होने वाला काला-धन, पैरेलल इकोनॉमी, अन-एकाउंटिड 80-90 हजार करोड़ है। क्या हम इकोनॉमी की बात करें? कैसे कीमतों में रुकावट आएगी? कैसे करप्शन का रोका जाएगा? यह सवाल कोई किसी पार्टी का नहीं है। मैं बड़ी नम्रता से अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं इस बात को आज नहीं बल्कि 10-15 सालों से, मिनिस्टर होने के पहले और मिनिस्टर रहते हुए भी उठाता रहा हूं और लिखता रहा हूं। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है कि जब तक इसका दखल हम नहीं लेंगे, हल नहीं निकालेंगे, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। हम नहीं कर पाए, जो ठोस कदम हम इतनी ताकत रहते हुए उठा नहीं पाए मैं कहता हूं आप उठाइये। हम आपकी ताईद करते हैं। आपने क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? आपने कहा कि माफ कर देंगे। जैसे हमने कहा था बाण्ड्स ले लो, इन्दिरा विकास पत्र ले लो, हम नहीं पूछेंगे। अब आपने उसके साथ एक लाली-पाप और लगा दिया। आपने कहा भईया, तुम लोग यदि स्लम्स में मकान बनाने के लिए लगाओगे, हाउसिंग के लिए लगाओगे तो हम नहीं पूछेंगे।

मैं सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि काले-धन वाले स्लम्स में यदि पैसा लगाएंगे तो उनको इससे मुनाफा होने वाला है? लाभ मिलने वाला है? वे क्यों पैसा लगाएंगे। आपने कहा कि बाण्ड्स में पैसा लगाकर डबल कर लिया, जितना पैसा बाण्ड्स में लगाया उससे ज्यादा व्हाइट-मनी कनवर्ट कर दिया, खाम खेल गए। ऐसा आपको धोखा देंगे ये स्लम्स में मकान बनाने वाले। यह हाफ हार्टिड मेजर्स से नहीं होगा। एक तरीका है। आपको जंचता हो तो देखो। जर्मनी ने और दूसरे देशों ने हिम्मत से काम लिया था। यह मेरा ख्याल है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरी पार्टी को मंजूर नहीं हुआ तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आपको मंजूर होगा। मैं यह चीज एक सदस्य के नाते कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एक ही तरीका है इसको ठीक करने का कि एक्सपैंडीचर टैक्स इंटरोड्यूस करो और इनकम टैक्स एबोलिश करो। क्योंकि 100 रुपये का नोट काला या सफेद नहीं होता, नोट पहचान में नहीं आता कि एकाउंटिड है या उन-एकाउंटिड है। तो कैसे फर्क करेंगे, कैसे इस ओशियन आफ रिसोर्सिज को देश की भलाई के काम में लेंगे? बड़ी नम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि आज देश का सवाल है, पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, सब लोगों को विश्वास में लीजिए, विचार कीजिए और हिम्मत से कदम उठाइये ताकि इस ओशियन आफ रिसोर्सिज को काम में लिया जा सके। फिर आप कह सकते हैं कि यह पैसा उत्पादन के काम में लगाइये,

कारखाने लगाइये, पावर प्रोजेक्ट लगाइये, सीमेंट का कारखाना लगाइये, ब्रिजिज और रेलवे के लिए लगाइये, रोड्स बनाइये। इन सब कामों में लगाओगे तो हम नहीं पूछेंगे, बैकवर्ड एरिया में लगाओगे तो फरदर कंसेशन देंगे। प्रोडक्शन परपज के लिए यह पैसा लगाओ तब देश बनेगा। हार्टिकल्चर और खेती की तमाम चीजों में इस पैसे को लगाओ। आपको केवल एक डर है, आप सोचते हैं कैसे होगा, हमको लोग कहेंगे कि आपने इनकम टैक्स कैसे एबोलिश कर दिया, प्रीमियम आपने दिया। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, इसलिए डर के मारे आप यह नहीं कर पाएंगे। पापूलर मेजर्स और वीक मेजर्स, हाफ हार्टिड मेजर्स यदि आप लेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, ओशियन बढ़ता जाएगा। यह पैसा देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है। यह पैसा कोई तिजोरी में बन्द नहीं है, यह सारे समाज में फैला हुआ है, जगह-जगह फैला हुआ है। जरा-सी ओथोरिटी हो छोटे आदमी को भी तो आजकल अन-अकाउंटिड मनी लिए बिना काम नहीं करता। आप देखिए कि सारे देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और चरित्र को तहस-नहस कर दिया है। हमने कहा कि कुछ बुनियादी बात सोचिए और हम आपका साथ देंगे। इस काम में कुछ मजबूत कदम इन कीमतों को रोकने के लिए रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए और इसको देश के निर्माण में लगाने के लिए जुटाएं। यह अनुरोध है कि रिक्रिमिनेशन की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। आप जो हैं तो हम आपको छोटा या बड़ा नहीं बना सकते और न हम आपके सपोटर्स को बढ़ा सकते हैं और न कम कर सकते हैं। देश की तमाम पार्टियों को विचार करके इस पर गहराई से चिन्तन करना होगा। अगर यह गाड़ी पटरी पर से फिसल गई तो फिर नहीं संभलेगी, चल रही है या फिसल रही है तो यह आपको संभालेगी और आने वाला जो कोई भी होगा तो उसको तकलीफ संभालनी होगी। दिल्ली में आज बहुत बड़ा जुलूस इन कीमतों के सवाल को लेकर आया और उन्होंने अपनी बात कही है। इसकी जो तकलीफ है लोगों में, उसकी देश में क्या भावना है, यह आप जान सकते हैं। इसकी तकलीफ महिलाएं बता सकती हैं कि चावल बना है या नहीं। एक दिया दाना दबाकर आप देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि लोगों की भावना कितनी उत्तेजित है। सारा सेब सड़ रहा है और वहां कोशिश कर रहे हैं कि गोली चलाकर उनको मार दिया गया। ऐसा लगता है कि देश में आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, इसमें पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी आ जाता है। जितने क्रिमिनल्स हैं वे मूल्य लेते हैं और देते हैं और देश में अशांति भी कीमतें बढ़ने का सूत्र होता है। इसे व्यापक दृष्टि से और इस सवाल की तरफ देखा जाए, यह सारे सदन के सदस्यों को अनुरोध है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, जबकि विपक्ष के नेता ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मुझे स्वयं को इस बात की हैरानी हो रही थी, इसके पीछे क्या कारण होगा। एक कारण कुछ मदों में मूल्य वृद्धि का हो सकता है जिसके बारे में कोई मना नहीं कर सकता। वास्तव में मूल्य वृद्धि हुई है यद्यपि कुछ मदों पर नियंत्रण भी किया गया है। लोगों को यह बताने के लिए कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जिसे दो दलों - वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ है वह उस स्थिति को नियंत्रण करने में असफल रहे हैं जिनके लिए वे वर्षों संघर्ष करते रहे और कि वे पूरी तरह असफल रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष से माननीय वक्ता को सुनने के बाद, श्री वसंत साठे ने यद्यपि सरकार की निन्दा करने की कोशिश की और उन्होंने विस्तृत परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रस्ताव भी रखे, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं

कि वह स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यदि उन पर वाद-विवाद किया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे विचार से मूल्य वृद्धि पर अलग से चर्चा नहीं की जा सकती। जब सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में आई तब उस समय की राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, भुगतान संतुलन की स्थिति, काला धन, समानन्तर अर्थव्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन की स्थिति आदि को ध्यान में रखना होगा। मैं उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य से हूं। पश्चिम उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बिना नीतिगत मसलों में पड़े मैं आपको बता सकता हूं कि 1955 से वहां केवल एक सिंचाई परियोजना शुरू की गई और वह है हीराकुंड परियोजना। उसके बाद से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में तब से कोई योजना या परियोजना शुरू नहीं की गई। न ही वहां कोई औद्योगिक विकास हुआ है। सभी बड़ी-छोटी, मझोली परियोजनाएं, जिसमें राऊरकेला इस्पात संयंत्र भी शामिल है 1962 से पहले शुरू की गई। 1962 के बाद से वहां न तो कृषि और न ही औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। सिंचाई या औद्योगिक विकास किसी भी क्षेत्र में कोई नई योजना, परियोजना, शुरू नहीं की गई। मैं मात्र यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह राष्ट्र के एक बड़े हिस्से जिसमें मूंगफली का उत्पादन किया जा सकता था, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता था, बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जा सकता था उसे उपेक्षित रखा गया। हमारे क्षेत्र जिसे उपेक्षित रखा गया उसमें किसानों ने थोड़े से प्रयास से ही इस मौसम में मूंगफली का भारी मात्रा में उत्पादन किया। हम तेल की कमी की बात कर रहे हैं। फिर अन्य बातें है जैसे हमारे बहुमूल्य संसाधनों को विदेशों से आयात पर खर्च करना और रिश्वतें लेने पर बर्बाद करना। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ूंगा। किंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि लोगों की आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न नहीं किए गए। हालांकि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की लेकिन स्वयं उन्होंने इसे मजबूत करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किये। मात्र जुबानी सहानुभूति दिखाने के लिए वह यह सब कर रहे हैं। लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। राष्ट्र में काले धन को पनपने दिया गया। समानन्तर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का कभी प्रयास नहीं किया गया; उसके बजाए उन्होंने इस राष्ट्र में समानन्तर अर्थव्यवस्था के प्रवेश में मदद की। मेरे पास सभी कागजात और आंकड़े हैं चाहे वह पक्ष में हों या विरुद्ध वह वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। इसके कई कारण हैं। क्या यह केन्द्रीय सरकार की नीतियों या अकुशलता के कारण है या वर्तमान, भूतपूर्व राज्य सरकारों के कारण, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस तरह की स्थिति का हम आज सामना कर रहे हैं वैसी स्थिति क्यों है। मेरा विश्वास है कि विपक्षी सदस्यों या अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक प्रश्न का माननीय वित्त मंत्री उत्तर देंगे। यह कोई एक दो दिन या एक-दो महीनों का सवाल नहीं है। जो भी कोई कार्यवाही की गई या नहीं या जो गलतियां इन सब वर्षों में की गई हम सब उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम स्थिति पर काबू पाने के लिए या नीतिगत उपायों को बदलने के लिए कटिबद्ध है। एक बात पर कम से कम हम सहमत हैं वह है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ दे सकेंगे जिन्हें अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। यह सब मूलभूत और मुख्य प्रश्न है जिस पर राष्ट्रीय चर्चा शुरू की जानी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या यह सरकार तीन-चार महीनों में गिर जायेगी या हम पिछली बार कामयाब हुए थे या नहीं। हर जगह सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के एक घटक जनता दल के सदस्य के रूप में मुझे

यह खुशी है, माननीय सदस्य श्री साठे ने अभी बताया कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ सदस्यों ने ध्यान दिलाया है कि वह संसद भवन के गेट नं० 1 से आज दाखिल हो गए हैं। कुछ वर्ष 18-19 वर्ष पहले एक श्रमिक संघ के कार्यकर्ता के रूप में मुझे याद है कि कुछ राजनैतिक दलों के लोग या श्रमिक संघों के लोग दामों में बढ़ोत्तरी पर उत्तेजित थे और जब वह संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तब न जाने कितने सिर फूटे और कितनों की हड्डियां टूटीं। अब कम से कम हमारी सरकार ने उनके प्रदर्शन को हटाने, पीटने, लाठी चार्ज या गोली चलाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया।

यह हमारी सरकार है, यह लोकतांत्रिक सरकार है। आप अब कीमतों में वृद्धि की बात कर रहे हैं। आइये इस पर चर्चा करें। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है। यह पार्टी का सवाल नहीं है। यह पिछले कई वर्षों से जारी रखी गई गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इन गलत नीतियों के परिणाम-स्वरूप ऐसी स्थिति बन गयी है जिससे निश्चित रूप से वस्तुओं की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अन्य राज्यों में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सतत निगरानी की है और प्रभावी उपाय किए हैं और कई चीजों पर आपने इसका असर देखा होगा। लेकिन महोदय, हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम निष्ठावान और ईमानदार हैं और हम निगरानी द्वारा पहले की गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और कीमतों को नियंत्रित किया जायेगा और इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ किया जायेगा।

महोदय, मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर एक नीति के पक्ष में हूं और महोदय, आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वस्तु के दाम निश्चित करने की एक नीति बनायी जाये। महोदय, मैं सरकार से एक सवाल पूछता हूं कि मारुति कार की निर्माण लागत क्या है? लिखित उत्तर में यह दिया गया था "कि यह वाणिज्यिक गोपनीयता की बात है" यह संबंधित मंत्री का उत्तर था। परन्तु मेरा प्रश्न मौलिक है। एम्बेसडर कार की निर्माण लागत क्या है? क्या यह डीजल पर चलती है या पेट्रोल से? व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सविनय निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाये और कृषि उत्पादन जैसे धान, गेहूं या चीनी का उत्पादन लागत का पता लगाया जाये या कार, फ्रिज या रंगीन टेलीविजन या अन्य वस्तुओं की निर्माण लागत का पता लगाया जाये। किसी को भी उत्पादन लागत के ऊपर 15 प्रतिशत से ज्यादा लाभ न कमाने दिया जाये। अतः हमें एक मूल्य नीति बनानी चाहिए और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये। सभी दलों को मिलकर कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और प्रत्येक वस्तु की कीमत निर्धारित करनी चाहिये और फिर प्रत्यक्ष उपभोग पर व्यय कर लगाना चाहिये जैसे पांच तारा होटल में ठहरना, कार खरीदना, रेफ्रिजेटर खरीदना। आयकर को पूर्णतया: समाप्त कर देना चाहिये और इससे राष्ट्र में बढ़ते काले धन को धक्का लगेगा। इस पर चर्चा की जानी चाहिये और इसका हल निकाला जाना चाहिये और फिर पूरे विश्व और समूचे राष्ट्र को हमारे काम का पता लग जायेगा। कीमतों की यह स्थिति हो गयी है। हम निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ उपाय कर रहे हैं। कुछ जगह हमें सफलता मिली है और कुछ जगह असफलता जिसे हम छुपाना नहीं चाहते और हम अपनी असफलताओं को स्वीकारने के लिये तैयार हैं। हम अपने को शिक्षित करने को तैयार हैं, अतः ईमानदारीपूर्वक सदन से मैं अपील करूंगा कि वह सारी स्थिति को समग्र

दृष्टि से देखें और उस पर राष्ट्रीय चर्चा करके इसका हल निकालें। दलगत राजनीति और संकीर्ण विचारों में पड़े बिना हमें सभी लोगों की भलाई के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : सभापति महोदय, सदन को स्थगित करने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य की कम से कम एक अथवा दो बातों का मुझे समर्थन करना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, इस समय हम सभी पीठासीन अधिकारी से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं और यह वह अवसर नहीं है जिसमें मूल्य वृद्धि के बारे में बढ़-चढ़कर कहा जाये। महोदय, मैं उनकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूं कि यह वह प्रश्न नहीं है जो सीमित है अथवा केवल पार्टी के हितों से ही संबंधित है निश्चित रूप से मैं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की इस बात से सहमत हूं कि मूल्य वृद्धि के कारण जो स्थिति तथा कठिनाई उत्पन्न होगी तब वह स्वाभाविक रूप से इस स्थिति का राजनैतिक फायदा उठाना चाहेंगे। तथा मुझे अत्यधिक आश्चर्य होगा यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है चाहे वह सदन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे अथवा सदन के बाहर संसद के गेट पर लोगों को इकट्ठा करे। यह एक अभूतपूर्व परन्तु दुःखदायी घटना साबित होगी। (व्यवधान)

महोदय, मूल्य एक ऐसी मामला है जिसका हम पर सीधा असर पड़ता है चाहे हम इस सम्माननीय सदन के अन्दर हों अथवा इससे बाहर हों। यह नीति संबंधी इस प्रकार की गूढ़ चर्चा नहीं है जो अकसर हम यहां करते हैं और जिनका आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं होता। अत-एव उस रूप में सरकार ने बिल्कुल सही किया जो उसने सदन के कार्य को स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि सदन के दोनों पक्ष मूल्य वृद्धि के परिणामों के बारे में राजनैतिक रूप से जागरूक तथा सतर्क हैं।

महोदय, सदन के कार्य को स्थगित करने वाले संकल्प प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए सदस्य ने अत्यधिक व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग किया है परन्तु मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्यतः हम इस समय मूल्य संबंधी चर्चा के लिए यहां आए हैं। मैं उस चर्चा को भी पहले से आरम्भ नहीं चाहता जोकि माननीय वित्त मंत्री जी निःसंदेह यहां आरंभ करेंगे तथा लेखाओं इत्यादि के संबंध में अपना त्रैमासिक वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे जिससे कि सदन को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अथवा वित्तीय लक्ष्यों, जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित किए थे, को प्राप्त करने में वह कितना सफल हुए हैं। मूल्य संबंधित प्रश्न जो हम सभी से संबद्ध है उस पर स्वयं कुछ कहने से पूर्व मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। अपने सम्माननीय वरिष्ठ सहयोगी से असहमत होने तक की कीमत पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अपना मित्र कहता हूं जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था उस समय मैंने उन्हें डाक दरों, रेल भाड़ों, टेलीफोन, पेट्रोल इत्यादि अन्य सब वस्तुओं में हुई वृद्धि के बारे में सावधान किया था तथा यथासंभव मेरे नेक इरादों तथा उनके मंत्रालय में अत्यन्त सक्षम प्रशासन के बावजूद तथा अर्थव्यवस्था के घाटे को संतुलित रखने के अत्यन्त वास्तविक प्रशंसनीय प्रयासों के बावजूद मूल्य-वृद्धि होने के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है तथा वह मनोवैज्ञानिक दबाव आधार-भूत सुविधाओं के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण है तथा जिनमें चाहे टेलीफोन हो अथवा रेल अथवा पेट्रोल के मूल्य हों उन सबमें हुई वृद्धि का प्रभाव पड़ता ही है जिसे हम अक-गणनीय रूप से कम नहीं कर सकते परन्तु उसका असर तो अवश्य ही मूल्य-वृद्धि के रूप में पड़ता है।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह है कि मेरा जन्म भी एक गांव में हुआ है क्योंकि भजन लाल

जी ने अभी मुझसे मेरी अपनी भाषा में बोलने के लिए कहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी बी० जे० पी० है तथा मैं किसानों को और अधिक उचित कीमतें दिये जाने के पक्ष में हूं। अतएव, जब कभी भी आप, चाहे गेहूं हो अथवा चावल जो भी हो उनका समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। सर्वप्रथम, जब भी आप ऐसा करते हैं, जो भी सरकार ऐसा करती है तब दोनों सदनों में, एक मत से, बिना किसी प्रश्न अथवा वाद-विवाद के, इसके पक्ष में जोरशोर से स्वागत किया

3.00 म० प०

जाएगा। कृषकों को उचित दाम मिलने ही चाहिए। जैसे ही आप किसानों के लिए मूल्य बढ़ाते हैं जो उन्हें मिलने ही चाहिए, इन बढ़े हुए मूल्यों से कुल मूल्य सूची, जिसके बारे में अभी मैं अपने विचार रखूंगी, में वृद्धि हो जायेगी। भारतीय जनता पार्टी तथा मैं निजी तौर पर यह विश्वास नहीं करता हूं कि देश में कही ग्रामीण तथा शहरी विभाजन है। हम गांव की कीमत पर शहर को लाभ पहुंचाने में विश्वास नहीं करते हैं। मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता कि शहर की कीमत पर गांव को लाभ पहुंचायें। मेरा विश्वास है कि ऐसी नीति जो गांव के हित तथा शहर के अहित में हो अथवा शहर के हित तथा गांव के अहित में हो तो यह मूल्य-वृद्धि के मुद्दे को सुलझाने का उचित तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : ऐसा कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, यह भी बताएं न।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में यह आपका निष्कर्ष है।

श्री जसवंत सिंह : मैं सदन के सर्वाधिक वरिष्ठ सदयों को उचित सम्मान देते हुए उनके इस हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं परन्तु चूंकि मेरे पास समय सीमित है अतः इस समय मैं इस बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा।

3.02 म० प०

(**श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।**)

मैं अपनी अन्य बात भी कहूंगा। स्थिति जो भी हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस पर नियंत्रण करे। आप जो भी करते हैं तथा जो आप नहीं करते हैं उसके लिए आप इस सभा के प्रति जबावदेय हैं। अतः यदि हम सभी को मूल्य अखरते हैं तब यह आप सबको भी अखरेंगे। अतः जो भी सरकार में है वह उसे दोनों प्रकार से नहीं ले सकता। आप यह नहीं कह सकते कि हम सरकार में हैं परन्तु हम उत्तरदायी नहीं हैं। इतना कहकर मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय नीतियों के क्षेत्र में भी एक तर्क अपनाया जाता है। यह एक अखंडनीय तर्क है कि विपक्ष का यह कहना उचित ही है कि आप यह बहाना नहीं कर सकते कि हमें ये कठिनाइयां विरासत में मिली हैं। निश्चित रूप से नहीं। परंतु भारत जैसे विशाल, विविध तथा जटिल समस्याओं वाले देश के आर्थिक तथा वित्तीय संगठन के स्वरूप को पन्द्रह दिन के अंदर नहीं बदला जा सकता तथा जब कभी भी उसमें कुछ संशोधन करने का प्रयत्न किया जाता है तब संशोधन का जो भी परिणाम हो उसमें समय लगता है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूं कि यह एक सही प्रश्न है । यदि यह संभव होता कि इस वित्तीय तथा आर्थिक नीति को अंकगणितीय भाषा के अनुसार दिन, सप्ताह तथा महीनों में बताना संभव होता तो मैं तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था कि इस स्थिति को ठीक करने में कितना समय लगेगा । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मै आशा करता हूं कि आप 40 वर्ष का समय नहीं चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं और भी संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखने का प्रयत्न करूंगा । वास्तव में, मैं इतना धृष्ट नहीं हो सकता कि मैं अपने अत्यन्त समर्थ, सक्षम मित्र माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यों को अनधिकृत रूप से ग्रहण करूं । परंतु मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि विरासत में प्राप्त वित्तीय तथा राजस्व संबंधी असंतुलन जितने अधिक होंगे, राज्य को उन असंतुलनों में सुधार लाने में उतना ही अधिक समय लगेगा । इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता, जो सदन के एक अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं, देश में किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के बारे में काफी गंभीरता से विचार किया है तथा उन्होंने भी केवल तथ्य को ही आधार मानने की आवश्यकता के बारे में कहा है । केवल तथ्य पर ही विश्वास किया जाये यही मेरा सुझाव है । मैं तथ्यों पर विश्वास करूंगा तथा ये अखंडनीय तथ्य हैं ।

माननीय सदस्यों ने पूछा था कि आप इस स्थिति को ठीक करने में कितना समय लेंगे ? कुछ गंभीर आर्थिक समस्यायें हैं जो इस सरकार को विरासत में मिली हैं । दिसंबर, 1989 में बजट में घाटा 14,000 करोड़ रुपए का हुआ था जो हमें विरासत में मिला था तथा यह मैं आपको ठीक आंकड़े नहीं बता रहा हूं । पूरे वर्ष के लिए जितनी राशि की योजना बनाई गई थी, उसका लगभग यह दो गुना था । विदेशी मुद्रा के भंडार करीब 5,000 करोड़ थे जो दो महीने की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है । अनाज का भंडार 11 करोड़ टन पर पहुंच गया था जबकि पिछली बार यही लगभग 19-20 करोड़ टन था । यद्यपि इसके कोई सांविधिक सीमा नहीं है जो हमें अनाज मिला था, वह इस आंकड़े का आधा था । विदेशी कर्ज लगभग 82,000 करोड़ था । आंतरिक कर्ज 238,000 करोड़ रुपए था । वर्ष 1989-90 के बजट अनुमान में 17,000 करोड़ रुपए ब्याज में दिये गये थे । मैं ये आंकड़े आपको अनुमान से नहीं बता रहा हूं । इस सरकार को ये आंकड़े विरासत में मिले थे ।

मैं समझता हूं कि जब हम मूल्य वृद्धि की बात करते हैं उस समय हम वास्तव में अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव के बारे में बात कर रहे होते हैं । जबकि मैंने यह कहकर अपनी बात आरंभ की थी कि मैं चर्चा को पहले से आरंभ करना नहीं चाहता । चूंकि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने इन बातों का उल्लेख किया है तो यह चर्चा केवल आम मूल्यों तक ही सीमित न रहकर वित्तीय पक्ष तक पहुंच गई है कि चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं, गेहूं के मूल्य नहीं बढ़े हैं अथवा दिसंबर, 1989 के अंत तक खाद्य तेल के क्षेत्र में कौन-सी दिक्कतें आ रही हैं, प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता ने पहले नौ महीनों में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की है जबकि इससे पिछले वर्ष में 3.9 प्रतिशत वृद्धि की गई थी । मेरी इस बात पर भी विचार किया जाए कि यह मुद्रास्फीति संबंधी दबाव वित्तीय असंतुलन के कारण उत्पन्न हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार अधिक

बढ़ गया तथा वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया ऐसा उत्पादन में कमी के कारण तथा संभवतः पूर्ति संबंधी स्वामियों के कारण भी हुआ था तथा इसका एक अन्य पहलू मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। मैं चिन्तित हूं कि राजस्व घाटे में सरकार को पूर्व सरकार से कितना राजस्व घाटा विरासत में मिला है। मैं कुल घाटों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वे सामने आ जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद राजस्व घाटा जो 1985-86 में 2.21 प्रतिशत था वह बढ़कर वर्ष 1989-90 में 3.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार राज्यों की राजस्व स्थिति भी बिगड़ गई है। भारत में मूल्य स्थिति को देखने का कार्य केवल संघ सरकार के वित्त मंत्रालय प्रशासन का कार्य ही नहीं है। इस विशाल तथा विविध देश में जो हो रहा है तथा जो कुछ भी देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है उन सबका यह संचित परिणाम है। जहां तक राज्यों के राजस्व का संबंध है, उसमें भी सातवीं योजना के दौरान गिरावट आई है। मैं चर्चा को आंकड़ों से लादना नहीं चाहता परंतु यह तथ्य है। केंद्रीय बजट में इतने अधिक घाटे का मतलब है कि राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण अंश की आपूर्ति ऋण द्वारा की जाती है। यह सरकार को विरासत में मिली है। शायद केंद्रीय वित्त मंत्री अपने जवाब में हमें इस पर विशेष जानकारी देंगे।

संकल्प के प्रस्तावकर्ता ने धन की आपूर्ति का भी जिक्र किया है। सातवीं योजना के दौरान धन आपूर्ति की वार्षिक विकास दर 37.53 प्रतिशत थी। उस पर श्री सुखमय चक्रवर्ती की रिपोर्ट बहुत ही अच्छा दस्तावेज है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि धन आपूर्ति की वार्षिक विकास दर चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद की 5 प्रतिशत तथा मुद्रास्फीति की चार प्रतिशत वृद्धि दर भी शामिल है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था इस सरकार को विरासत में मिली है उसमें धन आपूर्ति की विकास दर पहले ही 17 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। घाटे की अर्थव्यवस्था और उसके कारण धन आपूर्ति में वृद्धि के सिद्धांत की बारीकियों में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए पहलू हैं। उद्देश्यहीन सरकार के पास चीनी और खाद्य तेल वस्तुओं की तात्कालिक कमी से निपटने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं था।

विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अस्सी करोड़ की आबादी भोजन बनाने के लिए पशुओं की चर्बी पर निर्भर नहीं कर सकती। विश्व में यही एक ऐसा देश है जो केवल वनस्पति तेलों का ही प्रयोग करता है। इसलिए खाद्य तेलों के मूल्य वृद्धि का मामला हमसे ही नहीं बल्कि देश की अस्सी करोड़ लोगों से जुड़ा है। दुनिया के अन्य देश भोजन बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए पशुओं की चर्बी का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मूल्य वृद्धि की स्थिति में खाद्य तेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह असंतुलन सरकार को विरासत में मिला है। यह जो स्थिति पहले से उत्पन्न की हुई है हमारे गांव में जहां तिल के सिवा अन्य किसी प्रकार का तिलहन नहीं पैदा होता, वहां अचानक खाद्य तेलों का मूल्य बढ़ कर 35 रुपये प्रति किलो हो गया है। यदि ऐसे आवश्यक वस्तु का मूल्य उपभोक्ता को इस तरह देना पड़े जिसके बदले पशु चर्बी का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो सरकार के पास क्या विकल्प है? इसके बदले आप यह कह सकते हैं कि "आप आयात क्यों नहीं करते?" सरकार आवश्यक वस्तुओं का आयात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि भुगतान संतुलन की खराब स्थिति विरासत में मिली हुई है। सरकार को एक ऐसी स्थिति विरासत में मिली है कि यदि वह आवश्यक वस्तुएं आयात करने के बारे में सोचती भी है तो अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए इसके पास धन नहीं होगा। मैं व्यापार घाटे या ऋण सेवा अनुपात के संपूर्ण पहलुओं का जिक्र करने नहीं जा रहा हूं लेकिन यह विकल्प भी हमारे लिए बंद हो गया है। लेकिन

सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से केवल यह कह कर नहीं बच सकती कि इसे खराब आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। यह हमारे मित्र माननीय वित्त मंत्री के समर्पण की भावना और निपुणता को चुनौती देती है चूंकि विरासत में जो बुरी स्थिति हमें मिली है वह इस माह तक चलेगी, हमेशा नहीं। मैं समझता हूं कि हम तेजी से उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां यह कहते रहना कि यह समस्या इसलिए है, क्योंकि हमें विरासत में यह मिली इस देश के लोग नहीं मानेंगे।

संकल्प के प्रस्तावक ने धन की अधिक आपूर्ति का जिक्र किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पहलू को स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं। धनपूर्ति का प्रश्न बहुत जटिल है और मैं इस बारे में किसी प्रकार का विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनमें एक धन की आपूर्ति हुई है जोकि प्रविष्टि मात्र नहीं है। यह भी एक तरह का बैंक ऋण ही है। यह भी संघीय सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अग्रिम राशि है। हम इन तीनों पहलुओं के आंकड़ों को देखें ताकि संकल्प के प्रस्तावक द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में यह समझ सकें कि क्या यह वास्तव में तथ्य पर आधारित है अथवा नहीं। (व्यवधान) केन्द्रीय वित्त मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें। मेरा कहना यह है कि धन के असन्तुलित लेन देन से मुद्रास्फीति बढ़ती है और सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि वह स्पष्ट करे कि किस तरह का असंतुलन इसे विरासत में मिला है और इसे ठीक करने के क्या उपाय आपने किए हैं। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा उपलब्ध है। यह एक लम्बा और पुराना विवाद है। जब मूल्यों के बारे में चर्चा होती है तो सरकार थोक मूल्य सूचकांकों के साथ सामने आ जाती है। लेकिन हमें सरकार की उन बातों पर गौर करना चाहिए जिनका उल्लेख इन महोदया ने किया है। वित्त मंत्री महोदय यह सब ठीक है। आपका कहना है कि थोक मूल्य सूचकांक की स्थिति चिंताजनक नहीं है। जबकि आपकी पत्नी का कहना है कि यह चिंताजनक है चूंकि वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार कह रही हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यह स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं कि एक विशेष स्थिति में और एक विशेष बिंदु पर य द थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता सूचकांक के समान नहीं होता है तो भी लोगों का यह मानना है कि उन दोनों में इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि थोक मूल्य सूचकांक के मामले में आपके हिसाब से तथा आपके मूल्यांकन के अनुसार आपने जो हाल ही में सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है उससे कृषि क्षेत्र के किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुआ। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि भाजपा गांव-शहर का अंतर करने में न तो विश्वास रखता है और न इसका समर्थन करता है। लेकिन साथ ही आय किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर वासियों का नुकसान नहीं कर सकते और न ही शहरवासियों का फायदा करके गांव वालों का नुकसान कर सकते हैं। आप कृप्या अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं कच्चे मालों का विवरण देने नहीं जा रहा हूं। फिर भी मैं कुछ वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, तेल, सीमेंट, नमक और कपड़ा का जिक्र करना चाहूंगा। मैं इन सभी वस्तुओं के बारे में विस्तृत उल्लेख करना चाहूंगा चूंकि कि इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम का प्रभाव दैनिक मजदूरी पर संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों पर पड़ता है। चुनाव के दौरान हमने चीनी की बदतर स्थिति को एक मुद्दा बनाया था। हमने चीनी के दाम को कम करने का वायदा किया था। लेकिन किस कारण इसका मूल्य फिर बढ़ गया? मैं इस अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की जटिलताओं को स्पष्ट नही कर सकता जोकि उतनी ही विस्तृत है जितना भारत। हम कहते है कि खाने पर स्वाद मिलता है।

लेकिन, जब चीनी का मूल्य एक सीमा को पार कर जाता है तो इसका स्वाद तीखा हो जाता है—तब हमें राजनीतिक मूल्य चुकाना होता है—जितना कि आपको चुकाना पड़ा और हमें भी चुकाना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, तेल, सीमेंट, नमक और कपड़े के मामले में आपके सामने कौन-सी समस्या है। जहां तक नमक का संबंध है मैं समझता हूं कि उसमें सुधार हुआ है। नमक के मूल्य में जो अचानक तेजी आई थी उसमें कमी आई है और वही स्थिति चीनी के साथ है। लेकिन खाद्य तेल की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। खाद्य तेल के मूल्य में जब कभी अधिक अन्तर आए तो उस स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए आपने एन० डी० डी० बी० के माध्यम से एक तन्त्र की स्थापना की थी। हमें यह स्पष्ट करें कि आपकी यह व्यवस्था कहां तक सफल अथवा असफल हुई है ?

सभापति महोदय : आप पहले ही पच्चीस मिनट का समय ले चुके हैं। आपको और कितना समय लगेगा ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं अनुग्रहीत हूं। मैं अब सीमेंट के मूल्य पर अपना विचार रख रहा हूं। मुझे यह पता चला है कि सीमेंट का मूल्य यातायात की कमी के कारण बढ़ा है न कि उत्पादन की कमी के कारण। उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। सीमेंट की कंपनियां अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हैं।

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : दक्षिण में यह सौ रुपये प्रति बैग के दर से बिक रहा है।

श्री जसवंत सिंह : मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है ? सीमेंट का मूल्य क्यों बढ़ गया है। माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मंत्री महोदय अपने स्पष्टीकरण के साथ यह भी फिर से आश्वासन दे कि वह सीमेंट तथा खाद्य तेल के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि यातायात की कमी के कारण सीमेंट सौ रुपए प्रति बैग की दर से दक्षिण में तथा एक सौ बीस रुपये प्रति बैग की दर से उत्तर पूर्व में बेचा जा रहा है। यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए यदि एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी को शेयर अधिक बिक रहे हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्यों ए० सी० सी० के शेयर अधिक क्यों बिक रहे हैं और साथ ही सीमेंट के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम पर आपने बहुत कृपा की। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मैं समझता हूं कि आपने 25 प्रतिशत जवाब दे दिया है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं नहीं मानता। कुछ प्रश्न और कुछ विचार मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप मेरे लिए यदि कुछ भी न छोड़ते तो मैं ज्यादा खुश होता। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : वित्त मंत्री पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मूल्य नियन्त्रण के लिए वित्तीय सन्तुलन सबसे आवश्यक है। आप वित्तीय सन्तुलन को फिर से बनाए रखने के लिए क्या

कर रहे हैं। मेरा विचार यह है कि सार्वजनिक उद्यम चाहे वह राज्य सरकार के हों अथवा केन्द्र सरकार के उन्हें अपनी कार्य क्षमता और बढ़ानी होगी। चाहे वह राज्य विद्युत बोर्ड हो या बस परिवहन सेवा या उपनगरीय रेल सेवा अथवा टेलीफोन निगम। इन सार्वजनिक उद्यमों को अधिकाधिक क्षमता का परिचय देना होगा। सार्वजनिक उद्यमों को अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। सरकार उसे प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहूंगा। मेरे विचार में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज अपने वितरण के अभाव के लिए नागरिकों के प्रति अपनी पूर्ण संवेदनशीलता के लिए वास्तव में विख्यात है। यह ऐसी कोई बात नहीं है जोकि आपने पैदा की है। यह ऐसी बात है जोकि आपको विरासत में मिली है। लेकिन जब तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं होगा, तब तक नागरिकों और अधिकतर सबसे निर्धन लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें कम नहीं किया जा सकेगा, नहीं वह इस सभा में अपनी आवाज ही पहुंचा सकते हैं और उनकी आय भी निर्धारित ही है।

जमाखोरी विरोधी कदम। मैं इनका विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि यह स्वतः प्रमाण है। मेरे विचार में करों को कुछ हद तक युक्तिसंगत बनाए जाने से मूल्यों में कमी आएगी। मैं बिक्री कर, उत्पाद और उन सभी किस्मों जैसे करों का विशेष रूप में उल्लेख करूंगा। कृपया उस पर विचार कीजिए।

अन्त में, हमारा विश्वास है कि सरकारी तौर पर अथवा गैर-सरकारी तौर पर मूल्यों के असन्तुलन की निगरानी के लिए माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाज ही एक बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। यदि ये गैर-सरकारी रूप से भी किए जाएं और यदि आप माल और वस्तुओं के आने-जाने पर प्रतिबन्ध रखेंगे तो आप कालाबाजारी में सहयोग कर रहे हैं। आप बहुत ही दयालु रहे हैं। जो समय मुझे मिला मैं इस विषय के पूर्ण विस्तार में नहीं जा पाया। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें से कुछ का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स इसकी अनुमति नहीं दी गई है। श्री एच० के० एल० भगत बोलेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मुझे अब श्री जसवन्त सिंह को सुनने का अवसर मिला था जिनके लिए और जिनकी योग्यता पर मुझे कभी संदेह नहीं रहा। अतः मैं उन्हें सन्देह के सभी लाभ देना चाहूंगा। मैं उन्हें एक श्रेय दूंगा कि उन्होंने कम से कम दिखावे के तौर पर यह कहने का प्रयास किया है जोकि दिखने में इसके बिल्कुल विपरीत है जोकि उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाहर से आभास दे रही है, मूल्य वृद्धि के विरुद्ध हर तरह से छाती पीटने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल्य वृद्धि के विरुद्ध हर तरह से छाती पीटने का कार्य कर रही है। मैं उनके प्रस्तावों से इसका उल्लेख कर सकता हूं। मैं श्री आडवाणी के भाषणों से उल्लेख कर सकता हूं जिन्हें मैं संसद में सबसे योग्य सदस्यों में से एक मानता हूं और जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मूल्य वृद्धि के विरुद्ध बहुत अधिक आवाज उठाई गई है, इतनी अधिक कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रमुख ने श्री आडवाणी को लिखा है कि उन्हें सरकार का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि मूल्य वृद्धि के कारण न केवल लोगों के बीच बल्कि

कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है—उन्होंने वास्तविकता लिखी है—श्री जसवन्त सिंह ने ऐसा लगता है कि कम से कम नागरिक रूप से थोड़ी देर के लिए इस सरकार का समर्थन करने का प्रयास किया है। और इसके बाद बुद्धिमानी से उन्होंने कुछ प्रश्न रखे हैं। उनका बचाव भी कमजोर और गलत था, किसी भी तरह यह छिछोरापन है। उन्होंने ऐसा आभास दिया है कि वह मूल्य वृद्धि के संबंध में इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें कुछ अलग स्थिति दे रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं।

हमारे समय में भी मूल्य वृद्धि थी। मैं स्वयं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री था। श्री दण्डवते विपक्ष में थे और मैं सत्ता पक्ष में था। मैं जानता हूं हमारे समय में मूल्य वृद्धि हुई थी, कौन कहता है कि मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी ? तब मूल्य वृद्धि थी, लेकिन अब अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि है। यही तो अन्तर है। तब महंगाई थी, और अब यह महा महंगाई है । यही तो अन्तर है।

वे कहते हैं कि यह अचानक मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था की वजह से है जोकि उन्हें हमसे विरासत में मिली है। लेकिन उसके बाद प्रो० दण्डवते आपको अन्यत्र स्थिति नहीं देखनी पड़ी। उन्होंने उन्हें बताया है और उन्हें चेतावनी दी है। इस क्षण तक आप के मूल्य वृद्धि का समर्थन कर रहे थे यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार से यह दिखाया है कि यह मूल्य वृद्धि के खिलाफ हैं। ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि आपने बजट का विरोध नहीं किया है, आपने बजट का समर्थन किया है, लेकिन आपने मूल्य वृद्धि का विरोध किया है, अधिकतर मूल्य वृद्धि जो हुई है उसके बारे में, श्री दण्डवते ने स्वयं इस सभा में इस बात को स्वीकार किया है कि यह बजट के कारण है। मुझे उनकी बात पसन्द है। जब वह विपक्ष में थे तो उनमें बुद्धिमता भरी हुई थी। मुझे याद है श्री दण्डवते विपक्ष में बैठकर हमें टनों के हिसाब से सुझाव दिया करते थे।...(व्यवधान)... मैं कोई सुझाव नहीं चाहता, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूं।

श्री दण्डवते एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं इसे खुलेआम कह सकता हूं यद्यपि मैं विपक्ष में हूं। वह एक बहुत ही सुलझे हुए वित्त मंत्री हैं। जब वह विपक्ष में थे तो उनके पास बहुत से सुझाव थे। वह हमें बताया करते थे कि हम यह गलती अथवा वह गलती कर रहे हैं; लेकिन वह सब कुछ भूल गए हैं। उन्हें अब याद आ रहा है क्योंकि मेरी बहन श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने उन्हें याद दिलाया है। उनकी बेलन बिग्रेड थी। मुझे मालूम नहीं कि क्या वह उनके घर में उनके विरुद्ध बेलन का इस्तेमाल कर रही हैं अथवा नहीं। मेरी पत्नी ऐसा किया करती थी। वह मुझे बताया करती थी कि मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मूल्य वृद्धि जारी है और खाद्य आपूर्ति मंत्री के नाते मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा कर रही होंगी। मैं इसे प्रकट रूप से नहीं जानता क्योंकि खुले आम उन्होंने बेलन का उपयोग नहीं किया है। यदि यह एक कांग्रेस महिला होतीं उन्होंने मेरे विरुद्ध खुले आम बेलन का उपयोग किया होता।

उनमें से 6 हजार को आज गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर 10 हजार को गिरफ्तार किया गया है। जनता दल अथवा राष्ट्रीय मोर्चा से मेरे मित्रों में से एक जो ठीक मेरे सामने से बोल रहे थे—वह मुझे माफ करेंगे क्योंकि मैं उनका नाम नहीं जानता लेकिन मैं उनका बहुत अधिक सम्मान करता हूं—ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें गुमराह कर दिया है, जैसाकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें से कुछ लोग यहां आए और कुछ गुण्डा-

गर्दी की। लेकिन यह इस सरकार के हक में गया कि उन्होने लाठी चार्ज नहीं किया। मुझे यह बात कार्यवाही वृत्तांत की खातिर बतानी है। मैं स्वयं प्रदर्शन में था। मुझे गिरफ्तार किया गया था और मुझे रिहा किए जाने के बाद मैं यहां आया हूं। मैं यह कह सकता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्वक, इतना बड़ा और अभूतपूर्व और बहुत ही उत्साहपूर्ण प्रदर्शन मूल्य वृद्धि के विरुद्ध जो आज हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ और लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया और दस लाख लोगों को शांतिपूर्वक गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान)

आप केवल बातें करते आएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। (व्यवधान)

मेरे पास दस्तावेज हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं। (व्यवधान)

आंध्र प्रदेश से लोग आए हुए हैं जो बाहर बैठे हैं। मैं उन्हें देख चुका हू, क्योंकि अज्ञान की वजह से और भारतीय जनता पार्टी से किसी ने आपको गुमराह कर दिया है उसकी वजह से आप गलत बात और गलत व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। (व्यवधान)

मैं जो कह रहा हूं वह यह है। मूल्य वृद्धि के उन प्रदर्शनकारियों में से सभी क्षेत्रों से कोई भी यहां नहीं आया। रिहाई के बाद केवल मैं यहां आया हूं। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मैंने इस सरकार की सहायता की है। पुलिस के पास हमारे लिए वैन नहीं थी। वहां सैकड़ों बसें थीं। जबकि जो लोग अपने आपको गिरफ्तार कराना चाहते थे वे 50 हजार से अधिक थे। उनके लिए पुलिस स्टेशनों में जेलों में कोई स्थान नहीं था। अन्ततः 10 हजार लोगों को तकनीकी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। दस हजार में से छः हजार महिलाएं थीं। वहां बेलन और ऐसी चीजें थीं। मुझे श्री जसवन्त सिंह का धन्यवाद करना है क्योंकि श्री जसवन्त सिंह के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मूल्य वृद्धि में, जनता दल सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है। उनका भाषण वित्त मंत्री का उत्तर नहीं है लेकिन उनके भाषण के एक भाग में उनकी ओर झुकाव स्पष्ट नजर आता है। आज एक नारा सामने आया है।

[हिन्दी]

"महा-महंगाई के तीन अवतार।"

[अनुवाद]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा इसे पसन्द नहीं करेंगे। श्री विजय कुमार मल्होत्रा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि वह और मैं बहुत छोटे हैं। यहां बड़े लोग बैठे हुए हैं। (व्यवधान) आज एक नारा सामने आया है।

[हिन्दी]

"महा महंगाई के तीन अवतार—लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ।"

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री विश्वनाथ। यह नया नारा देश को मिला है। (व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों आया है? क्योंकि वे इसके सहयोगी हैं। आप दुविधा में हैं। आप बजट का समर्थन करते हैं और आपमें यह कहने का साहस है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है लेकिन आप में वह करने का साहस नहीं है—

आपमें उसका विरोध करने का साहस नहीं है। आप दुविधा में हैं, आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। (**व्यवधान**) वामपंथी नारे के साथ वही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया है—मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बताया—क्योंकि वामपंथी आर्थिक मामलों के संबंध में थोड़े ईमानदार हैं जबकि आप नहीं हैं। मैंने समाचार पत्र में देखा, एक समाचार पत्र जोकि कांग्रेस-समर्थक समाचार पत्र नहीं है, एक कार्टून जिसमें श्री आडवाणी कह रहे हैं, "मूल्य वृद्धि में, हर बात बुरी है, कश्मीर में हर बात बुरी है, पंजाब में हर बात बुरी है, असम में हर बात बुरी है और तमिलनाडु में हर बात बुरी है" श्री आडवाणी ने यह कहा है। और इसके अलावा श्री आडवाणी यह कह रहे हैं कि हम जनता दल सरकार के साथ हैं। यह एक दोहरे चेहरे वाली पार्टी है। आप लोगों को नहीं स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा के साथी ने स्वयं यह कहा है। वस्तुत: उन्होंने कहा है। श्री मदन लाल खुराना ने श्री आडवाणी को लिखा है, "हमारी विश्वसनीयता कम हो रही है। यहां तक कि हमारे कार्यकर्ता जनता दल सरकार का विरोध करने के लिए हमसे अनुमति मांग रहे हैं।" मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आया हूं। आप निराशा से अपने हाथ झटक देंगे। मैंने आपको भी छोड़ दिया है क्योंकि आप भी प्रधान मंत्री की नीति का पालन करने के उत्तरदायी हैं। इसीलिए, मैंने नारे में आपका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने 9 महीनों में क्या किया है? एक सदस्य कह रहे थे, "आप प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित कीजिए" क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस सरकार ने 9 महीने की अवधि के दौरान क्या किया है? 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन आपने क्या साबित किया है? क्या आपने स्वेच्छा से एक भी वस्तु का मूल्य घटाने का कोई प्रयास किया? परन्तु हमने किया था। कृपया नागरिक पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की फाइलें देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी कठिनाइयां, आपकी समस्याएं जानता हूं। श्री जसवंत सिंह गलत उद्देश्य के अत्यन्त कुशल समर्थक हैं। वह सदा गलत उद्देश्य के अत्यन्त कुशल अधिवक्ता रहे हैं और मैं श्री जसवंत सिंह को याद दिलाता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : शांत रहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं राज्य सभा में कही गई उनकी बातों का उल्लेख नहीं कर सकता हूं। मैं श्री जसवंत सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि वह वहां पर बोलते हुए हमें क्या कहते थे। वास्तव में मैं आपको जान-बूझ कर याद दिला रहा हूं। आप भी वहां थे और मैं भी था। मैं जान-बूझकर किसी उद्देश्य से आपको बचा रहा हूं। यद्यपि आप नहीं चाहते हैं फिर भी मैं आपको बचा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मूल्यों में इस वृद्धि में आप बराबर के जिम्मेदार हैं। हम आपको इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आपके विचार उपयोगी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : फरिश्ता आ गया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : शांत रहिए।

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत : कौन-सी चीज है जिसके दाम नहीं बढ़े सिवाए हवा के, आप बता दीजिए। आप भी बढ़ा दें। कोई तूफान नही आया, कोई नेशनल कैटेस्ट्रोफी नहीं आयी। हमारी सरकार के समय में ड्राउट के जमाने में दाम बढ़े थे। मैं जानता हूं, मैं उस समय फूड

मिनिस्टर था। ड्राउट के जमाने में भी जितना ख्याल था कि दाम बढ़ेंगे, उतने दाम नहीं बढ़े। दुनिया भर के इंस्टीच्यूशन्ज ने कहा है कि आपसे हमको बैंकरप्ट इकोनामी नहीं मिली। आपकी मिनिस्टरी ने जो डाकूमेंट इश्यू किए हैं वह आपकी कंटेंशन बिलाई करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा कि महंगाई मेरे दम से बाहर है, उनके हाथ से बाहर है, राज्य सरकारों की मदद चाहिए। क्या आपने राज्य सरकारों की मदद ली? कितनी होर्डिंग ड्राईव की? आप देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कितना किया। मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर था···(व्यवधान)···मैं ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप फाइलें निकालिए···(व्यवधान)···हमारे जमाने में प्राईस राईज के खिलाफ कोशिश की गयी, लेकिन आपने कोशिश नहीं की।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल उस स्थिति में ही व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं जब किसी नियम का उल्लंघन हुआ है।

श्री राम नाईक : वक्ता अपनी भाषा नहीं बदल सकता है। उन्होंने अंग्रेजी में बोलना आरंभ किया था और अब वह हिन्दी में बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : वह इनमें से कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्य का आदर करता हूं।

[हिन्दी]

महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि ऐसे मैम्बर्स यहां आ गये हैं।

[अनुवाद]

वे कुछ नहीं समझते हैं। वह कुछ नहीं समझते हैं। मैं यही कह रहा हूं। मैं उनके संबंध में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अब मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह यह है।

[हिन्दी]

महंगाई बढ़ रही है, हर घर में कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। अपनी पत्नी से मैं पूछा करता था तो मेरी पिटाई होती थी। अब महंगाई बहुत बढ़ गयी है। (व्यवधान)···सोमनाथ चटर्जी की पार्टी कहती है, महंगाई बढ़ रही है, बी० जे० पी० कहती है, महंगाई बढ़ रही है, जनता दल के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, सारे कह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई रोकने में सरकार फेल रही है। सरकार को चलाना है, क्योंकि कांग्रेस न आ जाए। जसवन्त सिंह जी एक बात कह रहे थे, शहर और गांव के डिवाइड की बात कर रहे थे। शहर और गांव के डिवाइड की बात जिसने की है उससे शादी किसने की थी? ट्रिब्यून में कार्टून छपा था जिसमें देवी लाल जी को दुल्हा और वाजपेयी जी को दुल्हन दिखाया था। क्या आपको याद है? जनता

दल और बी० जे० पी० एलाइंस कार्टून था। ··(व्यवधान) ··आज आप हमको सिखा रहे हो। हम शुरू से देवी लाल के खिलाफ थे और हमने डिवाइड का हमेशा विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए। आज आप हमें सिखा रहे हैं। जिस बी० जे० पी० ने आज तक देवी लाल की खुशामद की, तीन महीने पहले तक खुशामद की, आज आप हमें समझा रहे हैं। क्या समझायेंगे आप ? ··(व्यवधान) ··जिस बात का जवाब न हो उसे हंसी-मजाक में न टालें। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। कड़वी आपको भी लग रही है, मुझे मालूम है। बहुत अरसा सहारा देकर चल रहे हो, आगे चुनाव आएगा तो होश आ जाएगा। हम भी ऐसे ही कहा करते थे, जैसे तुम कह रहे हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप मुझे बोलने का अवसर दें तो क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको दस बार बोलने का अवसर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल एक बार ही काफी है। मैं पीठासीन अधिकारी के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरी सरकार की गलतियों के लिए आप मुझे और मेरी सरकार पर भरपूर आक्षेप कर सकते हैं। किंतु आप उन समर्थन करने वाले दलों पर अनावश्यक आक्षेप क्यों कर रहे हैं जो मूल्यों में वृद्धि का समर्थन नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रो० दण्डवते को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समर्थक दलों के प्रति चिंता व्यक्त की है। आप उन्हें भले ही जिम्मेवार नहीं मानें। किंतु मैं उन्हें ऐसा मानता हूं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। मैं उन्हें जिम्मेवार मानता हूं। वे जिम्मेदार हैं और जनता भी उन्हें जिम्मेदार मानती है। वे शोर मचाना चाहते हैं कि वे जिम्मेवार नहीं हैं। वे कहते हैं कि आप जिम्मेवार हैं। जनता दल ही जिम्मेवार है, वे नहीं। वे कह रहे हैं कि जनता दल ही जिम्मेवार है, वे जिम्मेवार नहीं हैं। किंतु मैं कहता हूं कि वे जिम्मेवार हैं और आप भी जिम्मेवार हैं। इसलिए प्रो० दण्डवते, मुझे खेद है कि मैं आपको अनुगृहीत नहीं कर सकता हूं क्योंकि दिल्ली में मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मुझे उनके खिलाफ लड़ना है···(व्यवधान)···हां, मुझे उनके खिलाफ लड़ना है। मैं सच बोल रहा हूं और उनकी भांति नहीं हूं कि यह सरकार बुरी है किंतु वे इनका समर्थन करेंगे क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। क्या इससे अधिक धोखेबाजी या भय की और भी कोई स्वीकृति हो सकती है ? सपनों में भी आप श्रीमती इंदिरा गांधी से डरते थे। अब आप श्री राजीव गांधी से डरने लगे है। यहां कोई भी प्रधान मंत्री के रूप में बैठा हो। पर मैं चाहता हूं कि राजीव गांधी ही देश के नेता बने रहें। मूल्य वृद्धि के मामले में आपकी सरकार गिरने वाली है। मैं आपसे त्यागपत्र की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं श्री विजय कुमार के त्यागपत्र की मांग नहीं कर रहा हूं। आप इस प्रकार की मांग करते थे किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। श्री जसवंत सिंह कह रहे थे कि हमारे लिए संसद से बाहर आकर विरोध करना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी आज विरोध प्रकट करने नहीं आई है। आप त्यागपत्र की मांग करने नहीं आए थे, क्योंकि त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं था। वास्तव में मैंने जनता की उपस्थिति में भगवान से प्रार्थना की है कि यह सरकार थोड़ा समय और चले। (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : क्या आपने भूतपूर्व मंत्री महोदय को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने की अनुमति दी है ? (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे सदस्य को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने विपक्ष की मनोवृत्ति अभी भी बनाए रखी है और उनकी कृपा से मैं पुनः मंत्री बन सकता हूं··· (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस दल का एक अंग है जो जनता दल सरकार का समर्थन कर रहा है। मूल्य-वृद्धि के संबंध में उनके विरुद्ध हमारा स्थगन प्रस्ताव उचित है। यह उनके विरुद्ध अत्यन्त संगत है। आप अंतरात्मा में अपने आपको दोषी क्यों मानते हैं ? आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आपका भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसी पत्नी की भांति हैं जो कहती है कि वह अपने पति के प्रति निष्ठावान है किंतु फिर भी हर स्थान पर अतिरिक्त सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। कैसी पत्नी हैं आप ! बाहर हर जगह आप प्रयास करते हैं···(व्यवधान)···मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि अगली बार आप संसद में नहीं होंगे···(व्यवधान)···महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यदि वे मुझे बोलते हुए व्यवधान डालते हैं, मैं भाषण जारी रखूंगा और किसी में भी मुझे रोकने का साहस नहीं होगा। मैं यह बात इस सदन में कहता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस सरकार को थोड़े और अधिक समय तक बनाए रखें और थोड़ी अधिक बुद्धि दे इन्हें और थोड़ी बुद्धि भी चाहिए। मैं मालिक नहीं हूं। मैं केवल एक संसद हूं। यदि आपको थोड़ा लम्बा जीवन चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं मध्यावधि चुनाव से डरता हूं। यदि चुनाव आज ही होते हैं तो हम उनका सामना करेंगे—मैं श्री राजीव गांधी से निवेदन करूंगा कि आवश्यकता प ने पर आपको थोड़ा आक्सीजन दें ताकि आप थोड़े और समय के लिए सरकार चलायें। जनता को पता चलना चाहिए कि आप क्या हैं और वे क्या हैं। वे आपको समझेंगे और समझ रहे हैं। समय आ रहा है। हम आपके झगड़ों में नहीं पड़ रहे हैं। हम पड़ेंगे भी नहीं। हम सत्ता में चालबाजियों से नहीं आएंगे; हम जनता के समर्थन से आएंगे और मूल्य वृद्धि आपकी नाव को डुबा रही है। इसमें आपकी नाव आधी से अधिक पहले ही डूब गई है और शेष भी शीघ्र ही डूब जाएगी।

सभापति महोदय : श्री अमल दत्त।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदय, जहां हम इस सभा में मूल्य वृद्धि पर वाद-विवाद कर रहे हैं, बाहर बोट क्लब में इस मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित कुछ लोगों अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली की जा रही है, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है, केवल थोड़ा सा अल्प वेतन मिलता है जिसे मानदेय कहा जाता है जो उन लोगों द्वारा दिया गया था जो अब चिल्ला रहे हैं···(व्यवधान)···मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इनके लिए कुछ करें···(व्यवधान)···।

सभापति महोदय : माननीय महिला सदस्या कृपया इस बात को समझ लें कि मुद्दे उठाने का यह कोई ढंग नहीं है।

श्री अमल दत्त।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, कांग्रेस दल ने इस अधिवेशन के प्रथम दिन ही मूल्य वृद्धि का मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाकर भारतवासियों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। ऐसा करके उन्होंने अपने को अपराध भाव से मुक्त किया है। यह अपराध भावना

क्यों ? आप समझेंगे कि मूल्य वृद्धि से लगभग सभी प्रभावित होते हैं, किन्तु देश के शत-प्रतिशत नागरिक प्रभावित नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मूल्य वृद्धि से लाभ भी होता है। सदा दो पक्ष होते हैं। एक ओर तो सट्टेबाजों, कालाबाजारी करने वाले, व्यापारी और बिचौलिये होते हैं। इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है ? कौन-सा राजनीतिक दल इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ? यही वे लोग हैं जो इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उन्हें जनता के आगे अपने को अपराध भाव से मुक्त करना है ताकि उन्हें अगले चुनावों में मत प्राप्त हो सके (**व्यवधान**) मुझे इस अत्यन्त अहानिकर टिप्पणी के प्रति इस प्रतिक्रिया से आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वे अब विपक्ष में हैं। जब वे इस पक्ष में थे, तो उन्होंने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी··· (**व्यवधान**) मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने उस समय इसका विरोध नहीं किया जब वे भूमि स्वामियों, पूंजीपतियों, बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों के प्रतिनिधि कहलाते थे। उन्होंने कभी भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की, परन्तु आज उन्हें चिंता हो रही है क्योंकि उन्हें जनता के पास जाकर वोट प्राप्त करने हैं, उन्हीं लोगों के पास जो मूल्य वृद्धि के कारण भूखों मर रहे हैं··· (**व्यवधान**)

मुझे इन लोगों द्वारा शोर-शराबा करने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि मेरा समय समाप्त न हो···। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जब सदन में इतना अधिक शोर-शराबा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका भाषण अत्यधिक प्रभावी है।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री सोमनाथ, जितना शोर-शराबा आप कर रहे हैं, मैं तो उससे कम ही कर रहा हूं।

श्री अमल दत्त : अर्थव्यवस्था अभी भी उसी प्रकार चल रही है जैसी कांग्रेस सरकार के समय चलती थी परन्तु उससे अधिक अच्छे उद्देश्यों के साथ। प्रधान मंत्री और सभी दूसरे मंत्री मूल्यों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं जबकि पिछली सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया था।

महोदय, हमने अपने दल के माध्यम से मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे को पिछली लोक सभा के प्रत्येक सत्र और प्रत्येक ऐसी चर्चा में उठाया था, हमने हमेशा कुछ ठोस उपाय करने की मांग की थी। इन उपायों के अन्तर्गत हमने मांग की थी कि कराधान का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यक्ष करों से अधिक और अप्रत्यक्ष करों से कम धनराशि एकत्रित की जाए। परन्तु स्थिति अभी भी उसी प्रकार है। इसमें समय लगेगा परन्तु इसे करना ही होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक हम कभी भी ऐसी अर्थव्यवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जहां कि हम मूल्यों को नियंत्रण में रख सकें। कुल सरकारी राजस्व का केवल 17 प्रतिशत भाग ही प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। सरकार को अब यह प्रतिशतता ऊंची करनी चाहिए, अर्थात् प्रत्यक्ष करों से 35 से 40 प्रतिशत के आस-पास सरकारी राजस्व एकत्रित करना चाहिए। उन्हें ऐसा तुरन्त करना चाहिए। सरकार को दो या तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसके अन्तर्गत कराधान नीति का पुनर्निर्माण करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

दूसरी चीज जिसके लिए मैंने हमेशा मांग की है वह यह है कि उन 14 मदों को, जिसका हम सर्वदा जिक्र करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को एक ही मूल्य पर वितरित किया जाना चाहिए। महोदय, हमने इस मांग को प्रत्येक सत्र में उठाया था।

जब ये लोग सत्ता पक्ष में थे, इन्होंने हमारी इन मांगों को कभी नहीं सुना। मैं इसे अब पुनः उठा रहा हूं। मैं इस मांग के इतिहास की चर्चा करना चाहता हूं।

जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने यह समझकर कि यह मांग हमारी है, कभी भी इसे कोई महत्व नहीं दिया। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, जनता दल ने चुनाव से पूर्व एक वायदा किया था और मुझे यकीन है कि इसे पूरा किया जायेगा। मैं उनसे केवल यह निवेदन करता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए एक तिथि निश्चित की जानी चाहिए।

सरकार ने प्रधान मंत्री, दूसरे मंत्रियों और वित्त मंत्री के माध्यम से भी मूल्यों में हो रही वृद्धि के लिए अनेक बार अपनी चिन्ता व्यक्त की है और कुछ कार्य योजना तैयार की है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या वे मूल्य वृद्धि के बारे में वस्तुतः चिन्तित हैं?

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : यह एक हास्यपूर्ण हस्तक्षेप है।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं इस प्रकार नहीं बोल सकता।

सभापति महोदय : जब श्री भगत बोल रहे थे, तब आप भी यही कर रहे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्षपीठ इसे नोट नहीं कर सकती।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं कुछ ठोस सच्चाई बता रहा हूं।···(व्यवधान)···प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने अनेक बार मूल्य वृद्धि के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मुझे यकीन है कि कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं। इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि वित्त मंत्रालय और अनेक दूसरे मंत्रालयों द्वारा क्या कार्य योजनाएं बनायी गई हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी है। हम जानना चाहेंगे कि की गयी कार्यवाही के परिणामों की निगरानी कौन कर रहा है। मुझे यकीन है कि ये सभी कार्य किये जा रहे हैं परन्तु केवल सदन को ही ठीक प्रकार से सूचित नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि यह सूचना जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे, 'सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि की स्थिति से निपटना,' के बारे में सदन को हर समय पूर्ण रूप से सूचित करते रहना चाहिए। मैं ऐसा करने के लिए सरकार से कह सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं। हमने कांग्रेस सरकार से भी कुछ करने का निवेदन किया था परन्तु उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। पिछली कांग्रेस सरकार से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। इनके द्वारा कुछ कार्यवाही करना राजनैतिक रूप से आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि वे इसे शीघ्र करेंगे।

सरकार ने कुछ उपाय किये हैं और इनकी भारी आलोचना की गयी है। इनमें से कुछ आलोचनाएं सही थीं और हमने ये आलोचनाएं बजट सत्र में भी उस समय की थीं जब सरकार ने पैट्रोल और कुछ दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की थी। हमने तुरन्त यह कहकर सरकार के कार्य की आलोचना की थी कि सरकार सामान्य मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। अतः आम तौर पर कीमतों में वृद्धि हुई है। परन्तु इस बात की सही जानकारी नहीं है कि पैट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से किस सीमा तक अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। अनेक कारणों से इस बात का पता नहीं है परन्तु पिछली सरकार भी इसके लिए

उत्तरदायी है। यह इसलिए है क्योंकि मैंने केवल कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन पर साक्षात्कार के दौरान वित्त मंत्री को यह स्पष्ट करते सुना था कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि आंशिक रूप से ही उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसके पीछे एक अत्यधिक सही तर्क है। परन्तु बात यह है कि हमें कारणों का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी गणना नहीं की है। किसी ने भी इन आंकड़ों का पता नहीं लगाया है और इस बात की गणना नहीं की है कि पैट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से किस हद तक दूसरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। यह नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र में पैट्रोल की खपत को कम करने का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : मन्त्री महोदय ने सुबह कहा है कि यह 60 प्रतिशत है।

श्री अमल दत्त : पैट्रोल की खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का प्रभाव किस सीमा तक हुआ है?

पिछली सरकारों ने हमेशा ऐसा किया है और अब इस सरकार ने भी इसे पुनः यह कहते हुए कर दिया दिया है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति के कारण पैट्रोल और दूसरे उत्पादों की खपत में कमी करने के लिए पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि करना जरूरी हो गया था। हम भी इस देश में पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। कम से कम समुद्र तटों में तेल के विशाल भंडार क्षेत्र हैं। भंडार क्षेत्रों से तेल निकालने की नीति कुछ वर्ष पूर्व उस उसय निर्धारित की गयी थी जबकि विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। प्रत्येक भंडार क्षेत्र से तेल निकालने में लगभग 15 वर्ष या इससे अधिक का समय लगा ताकि इनसे 15 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक तेल निकाला जा सके। उसके लिए अब नीति में परिवर्तन की जरूरत है। उसे कौन करेगा? मैं समझता हूं कि केवल पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय को भी यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल होना चाहिए कि हम तेल निकालने में समर्थ हैं और हम अधिक पेट्रोलियम निकालेंगे क्योंकि हमारे यहां इसके भंडार क्षेत्र हैं, हम यहां से अधिक तेल निकालने की क्षमता रखते हैं। परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अलग स्थिति में पांच वर्ष पूर्व एक निश्चित नीति बनायी थी। यह स्थिति बदल गयी है, हमें विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने देश में ही अधिक पैट्रोल का उत्पादन किया जाए।

इसी प्रकार, जहां तक मैं अपने आस-पास देखता हूं, हमने पैट्रोल को बचाने के कोई कारगर उपाय नहीं किए हैं। यह उन संस्थाओं के लिए चिन्ता की बात है, जिनकी स्थापना पैट्रोल की बचत करने के लिए की गयी है। ये संस्थाएं कहती रहती हैं कि कोई भी उनकी बात नहीं मानता है। सरकार भी उनकी बात पिछले 10 वर्षों से नहीं सुन रही है जब से इनको स्थापित किया गया है। उन्होंने अनेक सिफारिशें की हैं, परन्तु अभी तक उनमें से किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। हम इन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं। यह प्रश्न केवल ऐसा करने की भावना का ही नहीं है, बल्कि उचित योजना, उचित कार्यक्रम बनाने और उचित प्रबन्ध का भी है और यह सुनिश्चित करने का है कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों को इस देश में कार्यान्वित किया जाए।

उसके लिए हमें ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो अपनी स्थिरता के बारे में आश्वस्त हो और हमेशा विपक्ष के द्वारा प्रभावित न हो। (व्यवधान)

हमारा बजट सत्र काफी शोर-शराबे वाला था। मैंने इससे पूर्व आठ बजट सत्रों में हिस्सा लिया है। यह सबसे अधिक हंगामे वाला सत्र था, चूंकि विपक्ष यह प्रयास था कि सरकार को जहां तक हो सके कठिन परिस्थिति में डाला जाए। लगता है कि हमें इतनी ही कठिन परिस्थिति का सामना मानसून सत्र में भी करना होगा। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें भी उत्तरदायित्व वहन करना होगा। वे सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) वे सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं (व्यवधान) संसदीय लोकतन्त्र में निश्चय ही विपक्ष को सरकार से वाद-विवाद करने का अधिकार होता है लेकिन उस अनुशासनहीन ढंग से नहीं जैसा उन्होंने संसद के पिछले सत्र के दौरान किया था। (व्यवधान) वे बहुत ही अनुशासनहीन, अव्यवस्थापूर्ण और बहुत ही असंसदीय तरीकों से वह पेश आ सके। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : चापलूसी···

श्री सोमनाथ चटर्जी : चापलूसी क्या है ? (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : चापलूसी का सबक हमें उनसे लेना होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति बनाए रखें। श्री अकबर, यह क्या है ?

(व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री अमल दत्त : अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार को कुछ दीर्घकालीन नीतियां बनानी होंगी ताकि सट्टेबाज और कालाबाजार करने वाले बच कर नहीं निकल सकें, कीमतें बढ़ाने के लिए वे अपने धन का उपयोग जमाखोरी के लिए नहीं कर सकें तथा काला बाजारी का लाभ नहीं ले सकें। इस नीति पर तुरन्त निर्णय लिया जाए ताकि उन्हें ये संकेत मिल सकें। महंगाई बढ़ने का कारण लागत में वृद्धि नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण सट्टे बाजी है चूंकि काला धन कुछ लोगों यानि देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सीमित है। वे लोग महंगाई बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं और उन लोगों का प्रतिनिधित्व इस गुट के द्वारा किया जाता है जो इस सदन में बैठे हैं। (व्यवधान)

आप उत्तेजित न हों, कृपया अपने ऊपर नियंत्रण रखें। आप बहुत बचकानी हरकत करते रहे हैं। (व्यवधान)

पिछली सरकार के नेतृत्व में देश में एक नई स्थिति पैदा हो गई थी। यह अधिक आयातोन्मुख हो गया था। हमें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए देश को आयात पर अधिक धन खर्च करना पड़ता था। उत्पादित वस्तुओं की लागत में वृद्धि का एक कारण रुपये की कीमत में कमी होना है। आयात पर निर्भरता के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट आई है। हम अपने निर्यात को आयात के बराबर नहीं ला सके। हमें विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर करना पड़ता था। यह दूसरा मुद्दा है जिसे अवश्यक समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य अधिक आत्मनिर्भरता

होना चाहिए; इस उद्देश्य को सरकार द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए तथा सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए।

पिछली सरकार ने भी हमें आत्मनिर्भरता के बारे में अपने नीति का आश्वासन दिया था। लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया। वर्तमान सरकार से हमारा यह निवेदन है कि वे अपने विचार को कथनी तक ही सीमित न रखें बल्कि उन्हें ठोस योजना और कार्यक्रम बना कर कार्यरूप भी दें ताकि देश का आयात एक राष्ट्रीय आय से कम हो ताकि आसानी से उसका वहन किया जा सके।

सरकार को ये उद्देश्य निश्चित करने चाहिए ताकि जो आज कीमतें बढ़ा रहे हैं उन्हें चेतावनी मिल जाए और उन लोगों को भी जो जन प्रतिनिधि के रूप में मौके का फायदा उठाकर पुन: सत्ता में आना चाहते हैं।

4.08 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, जब आदरणीय वसंत साठे जी स्थगन प्रस्ताव लाए तो सारे सदन के माननीय सदस्यों ने उनका स्वागत किया क्योंकि महंगाई बढ़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से, वसंत साठे जी से और एच० के० एल० भगत साहब से जो अभी बहुत बुलन्दी के साथ यह भाषण दे रहे थे कि महंगाई अपनी चर्म सीमा से आगे चली गई है वह बताएं कि आज से पन्द्रह बरस पहले चीनी का दाम एक रुपए था, 25 नए पैसे किलो प्याज इस देश में मिलता था, 12 रुपए का एक पीस कपड़ा गरीब को पहनने के लिए 10-15 बरस पहले मिलता था, किस नीति के तहत किस वजह से यह महंगाई इतनी गुना ज्यादा आगे चली गई है? यह तो आपने और आपकी सरकार ने गलत नीति की बुनियाद डाली है उसका परिणाम आज राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भोगना पड़ रहा है। मैं उदाहरणस्वरूप कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो उत्पादक हैं, उनका पिछली सरकार ने लगातार मजाक उड़ाया है। किसान आज सरसों, गन्ना और गेहूं आदि चीजों की खेती करते हैं लेकिन कांग्रेसी शासन काल में उनके द्वारा पैदा की गई चीजों के दाम व्यापारी लोग तय करते थे। इसकी वजह से किसानों को अपनी पैदा की गई चीजों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। कांग्रेसी शासन काल में महंगाई लगातार बढ़ती गई और उसको रोकने की तरह उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे राजीव गांधी जी यहां बैठे हुए हैं···(व्यवधान)···आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनें। इसके अलावा पिछले विदेशी कर्जों का भी भार हमें उठाना पड़ा। इसका भी असर महंगाई पर पड़ा। कांग्रेसी शासन काल में पैट्रोल के दाम बहुत अधिक बढ़ाये गये और वह 20 परसेंट बढ़ाये गये। इसकी सफाई में यह कहा गया कि इसे विदेशों से मंगाना पड़ता है। राजीव गांधी जी समय-समय पर यह कहते थे कि 15 परसेंट पैसा गांवों में खर्च करते हैं लेकिन आज तक वह एक भी पैसा गांवों में नहीं गया और न ही गांव के लोगों को इससे कोई फायदा हुआ। मैं राजीव गांधी जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ब्लैकमनी को निकालने का कोई प्रयास किया? अभी वह जब इस विषय पर बोलेंगे तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस बारे में अवश्य ही वह कुछ बतायें। इनके द्वारा किए गये कुकर्मों का आज हमें फल भुगतना पड़ रहा है। इसकी

वजह से जनता को आज कष्ट उठाना पड़ रहा है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कांग्रेस की अर्थ नीतियों की गलती की वजह से यह महंगाई बढ़ रही है कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों को आज तक उपेक्षित रखा। आज दिल्ली में बहुत से मजदूर बाहर से आये हुए हैं और वे झुग्गी-झोंपड़ियों में बसे हुए हैं। कांग्रेस ने उनको राशन-कार्ड देने का काम तक नहीं किया। हमने अपने इस छोटे से शासन काल में उनको राशन-कार्ड आवंटित किये। भगत जी उन गरीब मजदूरों का इस देश में प्रदर्शन करवा कर अब यह दिखा रहे हैं कि वह उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी सरकार को आये अभी 9 महीने ही हुए हैं, 9 महीने में तो बच्चा ही पैदा होता है। आपने तो करीब 42 वर्ष शासन किया लेकिन इस अवधि मे महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अब हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इन सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जनता से जो वायदा किया था, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वायदा किया था कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, वह हमने माफ किए, हमने वायदा किया था कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू करेंगे, उसकी अभी घोषणा होने वाली है। हमने काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का वायदा किया था, उसको भी हम शामिल करने जा रहे हैं। यह महंगाई का ढिंढोरा पीटने से जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। मुझे यह कहने में आज कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के कुकर्मों के चलते हमें महंगाई को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई को रोकने के लिए अगर आपको किसी वस्तु को निर्यात या आयात करना पड़े तो उसके करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप किसी भी तरह से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करिए। राजीव गांधी जी जो विरोधी दल के नेता हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इसमें वह हमारी सरकार को सहयोग दें। आपने बार-बार इस बात का आश्वासन दिया है कि हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देने का कार्य करेंगे। सरकार रचनात्मक कार्य करेगी तो हम उसे सहयोग देंगे, क्या सहयोग दिया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका यही सहयोग हुआ कि आप दिन रात गलत काम को गलत रूप में करवाने का प्रयास करते रहे।

मैं अब कुछ आंकड़े देना चाह रहा था कि महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बहुत वस्तुओं पर घटी भी है। कांग्रेसियों के राज में जो चीज 15 रुपये बिकती थी वही हमारी सरकार के राज में 6 रुपए है। कुछ चीजों में मूल्य वृद्धि हुई है तो कुछ चीजों की कीमत घटी भी है और बाकी चीजों पर भी कुछ दिनों के अन्दर मूल्य नियंत्रण कर लिया जायेगा। इससे आप लोगों को जो उम्मीद है कि लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा तो वह पड़ने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय द्वारा चर्चा का उत्तर 6.00 बजे म० प० निर्धारित किया है। मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् माननीय प्रधान-मंत्री मंडल आयोग की रिपोर्ट पर वक्तव्य देंगे।

श्री राजीव गांधी, आप कितना समय लेंगे?

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : मुझे आधा घंटा या चालीस मिनट लगेंगे।

सभापति महोदय, आज सुबह जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। कांग्रेस के विगत पांच वर्षों के शासन के दौरान यद्यपि कई मुद्दे उठाए गए परन्तु आर्थिक उपलब्धियों के प्रश्न पर कोई दो राय नहीं हैं और इस बात से सभी सहमत हैं। हर ओर से यह संकेत मिले हैं कि विकास दर, गरीबी उन्मूलन तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, शायद पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के विगत दस वर्षों के शासन के दौरान 1980-81 के वर्ष को छोड़ कर जबकि दो अंकों में मुद्रास्फीति का स्तर था, वह इकाई अंक तक नियंत्रित कर दिया गया था और 1980-81 में भी इसके दो अंकों में होने का कारण यह था कि उस समय हम जनता पार्टी शासन के प्रभाव से उभर रहे थे·· (व्यवधान) यहां तक कि वर्ष 1987-88 के अकाल के दौरान भी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और मुद्रा-स्फीति पर कड़ा नियंत्रण रखा था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच में न टोकें।

श्री राजीव गांधी : महोदय, सरकार द्वारा हाल ही में प्रभावित कतिपय दस्तावेजों में विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य का वर्ष 1989 और 1990 का तुलनात्मक आंकड़ा प्रकाशित किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष 1989 के पूर्वार्द्ध में हमने कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने का प्रयास किया था। उदाहरणार्थ, तिलहन के मूल्यों में वर्ष 1988 और 1989 के शुरू तक लगभग 23 प्रतिशत की कमी आई थी; मूंगफली, सरसों और रेपसीड तेल के मूल्यों में 20 प्रतिशत की कमी आई थी और मसालों के मूल्यों में नौ प्रतिशत की कमी आई थी। यह विश्वव्यापी मुद्रास्फीति की स्थिति के बावजूद की गई थी। हमें वर्ष 1980-89 की अपनी उपलब्धि की तुलना जनता पार्टी की वर्ष 1979 और जनता दल की वर्ष 1990 की उपलब्धियों से करनी चाहिये। जहां तक मुझे याद है, 1979 में मुद्रास्फीति लगभग 21 प्रतिशत थी और इस वर्ष भी आपकी व्यवस्था में मुद्रास्फीति दो अंकों के करीब पहुंच गयी है। वर्ष 1989 के मध्य में हमें यह नोट करके चिन्ता हुई थी कि कुछ मूल्यों में वृद्धि हो रही थी और उसमें चुनाव पूर्व मूल्य वृद्धि भी जुड़ गयी थी। लेकिन हमने इसके सुधार के लिए कठोर कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण किया गया। वर्ष 1989 की अंतिम तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आई थी। इस प्रकार हमने विरासत में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था दी थी जिसमें मूल्य पूरी तरह नियंत्रित थे और मैं यह भी कह सकता हूं कि हमने खाली नहीं बल्कि भरा हुआ खजाना छोड़ा था।

राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करेगी। प्रश्न यह है कि गड़बड़ी क्या हुई है? आठ माह की छोटी अवधि में ही दृढ़ अर्थ-व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई। मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है और तिजोरी खाली हो गयी है। यह कैसे हुआ? हम देखें कि क्या हुआ है। सितम्बर, 1989 में थोक मूल्य सूचकांक 168 पर था। दिसम्बर, 1989 में हमारे द्वारा अक्तूबर, नवम्बर में किये गये प्रयासों से यह 166 पर आ गया···(व्यवधान) आपने क्या किया है, मैं केवल यही बता रहा हूं। यह सब आपके समर्थन के कारण हो रहा है। यदि आपने अपने प्रभाव का थोड़ा भी प्रयोग किया होता जो करने में आप सक्षम हैं तो सत्ता पक्ष यह सब नहीं होने देता। आपके समर्थन से ही ऐसा हो रहा है······ (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप भी कराते हैं, वे भी कराते हैं, मैं कैसे तय करूं कि किसने कितना किया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री राजीव गांधी : सितम्बर, 1989 में थोक मूल्य सूचकांक 168 था। दिसम्बर, 1989 में हमारे दो महीनों के प्रयासों के बाद यह 166 पर आ गया। लेकिन आठ महीनों में आपने क्या किया। दिसम्बर, 1989 के 166 से बढ़ कर यह अब 178.5 पर पहुंच गया है। यह पिछले माह का आंकड़ा है। हो सकता है यह 179 से भी अधिक हो गया हो। यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण है। हमारे प्रयास से मूल्यों में कमी आती है जबकि आपके प्रयासों से मूल्यों में वृद्धि होती है···(व्यवधान) मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि तेजी से मूल्य वृद्धि के कारण वामपंथी दल स्वयं को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि सत्ता पक्ष बेचैनी महसूस कर रहा है। स्पष्टतः कहीं एक अपराध बोध है क्योंकि आप जानते हैं कि कि इसका कारण आपके द्वारा दिया हुआ समर्थन है। और यहां मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वास्तव में आप इन तरीकों का समर्थन नहीं करना चाहते किंतु आप एक दुविधा में फंसे हुए हैं आप नहीं जानते कि क्या करें। किंतु यही समय है कि आप अपना कुछ अधिकार जमाएं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि आप वही करें जो दूसरों ने किया है और न ही यह सुझाव दिया कि वे बैसाखी हटा दें और मध्यावधि कराएं। हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते। हम सरकार से बहुत खुश हैं। हम चाहेंगे कि सरकार पांच वर्षों तक चले। किंतु हम यह चाहेंगे कि वे नीतियां शायद 'चोट' पहुंचा रहीं हैं, सही नहीं है, जो गरीब जनता की जिन्दगी को नष्ट कर रही है, उन्हें सुधारना होगा। शायद, मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं वहां बैठे हुए मेरे मित्रों से अनुरोध करूं क्योंकि उनके पास एक समर्थन आधार है जो उसे उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। किंतु, मैं अपने वामपंथी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें—आप नियुक्तियों में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, अन्य कार्य करवाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, आप गरीबों के लिए कुछ करने में लिए अपने प्रभाव का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या यह सच नहीं है कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में···(व्यवधान) 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी कर्ज लिया और देश को इतने कर्ज के बोझ से दबा दिया। और अब आप विदेशी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो आप महंगाई कम कर सकते हैं किंतु किस कीमत पर ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे दल के खिलाफ विपक्षी नेता द्वारा कहे गए आक्षेप का मैं खंडन करता हूं। यह बिल्कुल अनुचित और आधारहीन है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अनुदार नहीं होना चाहती। किंतु, मैं सोचती हूं कि यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक है।

श्री राजीव गांधी : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। यह इस शताब्दी का मजाक

है जो कि आपका दल इस देश के साथ कर रहा है और यह मजाक सामने उन बैंचों पर बैठा है··· (व्यवधान) मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, यदि वे व्यवधान डालना चाहते हैं तो मैं हट जाऊंगा। किंतु मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, यदि मेरी स्मरण शक्ति सही है तो, इसी कुर्सी से, उन्होंने कहा था कि भ्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और यह भ्रम है कि वह ऐसी स्थितियां बनाते हैं जो वस्तुओं को सही दिशा में चलाती हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जब मैं अपने सुझाव देने का प्रयत्न कर रहा हूं मुझे भ्रमित करने की कोशिश न करें (व्यवधान) महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को दो बैसाखियों की जरूरत है। किंतु, जब भी प्रधानमंत्री उठते हैं, तो मैं देखता हूं कि बैसाखियां भी उठती हैं। महोदय, मुझे वामपंथी दलों के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाने दें कि सरकार को बैसाखियों की जरूरत है ताकि प्रधानमंत्री को···(व्यवधान)

महोदय, आज अंकों के आधार पर मुद्रा स्फीति लगभग दो अंकों तक पहुंच गई है। डब्ल्यू० पी० आई० आम आदमी की मुश्किलों का पैमाना नहीं है क्योंकि वह बाद की बात है। वास्तव में डब्ल्यू० पी० आई० व्यापारियों और तस्करों के मुनाफे का पैमाना है। इसलिए, जब हम इस तरह भी मुद्रास्फीति डब्ल्यू० पी० आई० पर देखते हैं, जब हम देख रहे हैं कि सरकार जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने में झिझक रही है, हमें आश्चर्य होता है कि सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। सरकार का क्या लाभ है; कौन से संबंध हैं ? शायद माननीय प्रधानमंत्री अपना उत्तर देते समय इसे स्पष्ट करें। महोदय, वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो गरीबों के कष्टों को प्रतिबिम्बित करता है। अगस्त, 1989 से नवम्बर, 1989 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्थिर था और नवम्बर, 1989 से जनवरी, 1990 तक यह 172 तक गिर गया। यह क्यों हुआ ? इसलिए नहीं क्योंकि आपने तभी सत्ता संभाली थी, बल्कि इसलिए कि हमने अगस्त से नवम्बर तक ऐसे उपायों की शुरूआत की थी, क्योंकि जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं, सी० पी० आई० एक अवधि के पश्चात् निश्चित रूप से आती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कोई बाधा न दें। अब हमारे ऊपर समय का बंधन है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वे कौन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : वामपंथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है आज। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मंहगाई में तकलीफ होती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि वे किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं औद्योगिक श्रम के बारे में बात कर रहा हूं। महोदय, जनवरी, 1990 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 172 तक गिर गया, और अप्रैल, 1990 में कुछ ही महीनों में यह 180 से ऊपर था। और यह अनुपालन किया जाता है कि आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगभग 185 है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता संभालने के ठीक बाद यह अचानक वृद्धि क्यों हुई ? हमें इसके बारे में सोचना है, आपको इस बारे में सोचना है। आप कांग्रेस को दोष देते रहिए

। कब तक कांग्रेस को दोष देंगे ? आपने शुरू किया । एक महीने, दो महीने, तीन महीने, आठ महीने हो गए हैं । और कितने महीनों तक आप यह करते रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : एक महीना और।

श्री राजीव गांधी : मुझे यह चिंता है कि अगले महीने भी शायद कोई परिवर्तन न हो । ादय, आम आदमी की व्यथा को दर्शाते है—वस्तुओं के मूल्य । व्यक्तिगत मूल्य आज वास्तव में ात पहुंचाते है । दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 तक सिर्फ सात महीनों में मूंगफली के तेल दाम अड़तालीस प्रतिशत बढ़ गए—21 रुपए से 32 रुपए प्रति किलो । और मुझे हमारे एक ष्ठ सदस्य ने बताया कि उसने एक दिन एक मूंगफली के तेल का टिन खरीदा और उसे उसके ए 600 रुपए देने पड़े । मैं देख रहा हूं कि सदस्यगण सहमति में अपना सिर हिला रहे हैं । तु इसके बारे में कुछ कीजिए । अरहर के दाम 51 प्रतिशत बढ़ गए हैं—5.30 रुपए से 8 ए प्रति किलो । बाजरे की कीमत 46 प्रतिशत बढ़ गई है—1.70 से 2.45 रुपए प्रति किलो । (व्यवधान) । मैं चीजों की बात कर रहा हूं जो गरीबों को प्रभावित करती हैं । आप इसका ाक उड़ा सकते हैं । आपके पास पहले से ही शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्रों की एक समस्या है, ास समस्या को बढ़ाना नहीं चाहता । मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सबसे अधिक जोर हैं और जो कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं । खांडसारी की कीमत 18 प्रतिशत बढ़ गई है—30 रुपए से 7.44 रुपए तक ।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने बाजरा देखा है ?

श्री राजीव गांधी : मैंने इसे खाया है, मैं इसे रखता हूं और मुझे बाजरे की रोटी खाना च्छा लगता है । फिर, महोदय, कई वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, अन्य खाद्य तेल, उड़द, और अन्य दालें जिनकी कीमत 10 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं । कांग्रेस सरकार के यंत्रित मूल्यों के दशक से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के आठ महीनों तुलना कीजिए । मानसून का अभाव, भण्डारों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय संकट या सैन्य तनाव जैसी ई बड़ी आपदा आयी होती तो इसे समझा जा सकता था । किंतु इस बार कम से कम तीन च्छी मानसून हुई हैं । पर्याप्त भण्डार हैं । कोई अन्तर्राष्ट्रीय संकट नहीं है । कोई सैन्य तनाव नहीं । फिर भी मैं कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्यों को जिस तरह बात करते सुनता हूं, वह भविष्य प्रति भयभीत क्यों हैं ? तब यह आशंका किस लिए है ? महोदय, दो मुख्य कारण है । पहला यह सरकार सिद्धांतों और कार्यक्रमों की अपेक्षा वाहवाही में अधिक विश्वास रखती है । दूसरा यह सरकार कमजोर विकल्पों को प्राथमिकता देती है । लोकप्रियता पाने के लिए सरकार ने राजस्व य इतना अधिक बढ़ा दिया है जिससे बजट घाटे में अपूर्व क्षति हुई है, इस प्रकार संपूर्ण असमन्वमित मुद्रास्फीति को बढ़ाया जा रहा है । किंतु क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अतीत को तोड़ रोड़ कर और भविष्य के बारे में झूठे वायदे करके टिकी हुई है आने वाला मुख्य खतरा है बहुत ी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और अगर शीघ्र ही सुधारात्मक कदम न उठाएं गए तो मुद्रास्फीति अंकों तक पहुंच जाएगी । इसीलिए हम इस विवाद को इतना महत्व दे रहे हैं । आज हम सिर्फ अंकों से बंधे हुए हैं । अगर इस वर्ष में अंत तक संशोधनात्मक उपाय न किए गए तो हम 20 तिशत मुद्रास्फीति तक पहुंच जाएंगे और अगर वाहवाही पाने के लिए और कदम उठाए गए

जहां हजारों करोड़ों में राशि खर्च की जाती है, कभी हम विभिन्न मंत्रियों के वक्तव्यों में यह सुनते हैं—तब वह 20 प्रतिशत बहुत ज्यादा हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : आपको याद रखना चाहिए आप इनके क्लच हैं, हमारे नहीं। जब वे बोलेंगे तब आप बोलिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, यह सरकार किस प्रकार के भंडार लेने की बात कर रही है ? महोदय, पेट्रोल की खपत के नियंत्रण के लिए···

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप कर्ज-माफी के विरुद्ध हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं आपको कर्ज माफी के बारे में बताता हूं। आपने क्या किया है ? आपने कर्ज माफी के बारे में कुछ नहीं किया है। आपने अब कर्ज रद्द कर दिया है। आज किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा। इसका कारण है अक्षमता और आपके द्वारा किए गए झूठे वादे। आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। गैर जिम्मेवारियों की बात मत कीजिए। (व्यवधान) श्रीमती दण्डवते वित्त मंत्री से मिलने के लिए महिलाओं का एक प्रतिनिधि-मंडल ले गई हैं। शायद आपको भी यही करना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पिछली बहस में, मैंने ही श्रीमती दण्डवते को बधाई दी थी और अपना भाषण शुरू किया था।

श्री राजीव गांधी : मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब आप श्री दण्डवते को कीमतों पर नियंत्रण करने पर बधाई देंगे, न कि श्रीमती दण्डवते को कीमतों के बारे में शिकायत करने पर बधाई देंगी। हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे और अगर श्री दण्डवते महंगाई कम करवाते हैं तो उन्हें भी बधाई देंगे।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : घर में झगड़ा क्यों करवाते हो।

श्री राजीव गांधी : मैं तो झगड़ा कम करवा रहा हूं क्योंकि आप ठीक कदम उठाएंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं।

[अनुवाद]

महोदय, पेट्रोल के संबंध में उन्होंने क्या किया है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अगर आप सोच सकते हैं तो दूसरी जगह आपको बैठना चाहिए। अगर आप सुझाव नहीं दे सकते हैं तो गलत जगह बैठे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, इस सरकार ने कौन से सरल विकल्प निकाले हैं ? उनके समक्ष पेट्रोल तथा डीजल की खपत की समस्या थी। इसके बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? उन्होंने पेट्रोल पम्पों को 12 घंटे खुले रखने का निर्देश दिया था। तत्काल उन्होंने कहा, 'रविवार को बंद रखिए। एक दिन बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कहा :—

[हिन्दी]

"नहीं, संडे को बंद नहीं होना चाहिए।"

[अनुवाद]

इससे क्या हुआ ? क्या पेट्रोल पम्पों को 12 घंटे तक बंद रखने से ईंधन की खपत में कोई कमी आयी है ? यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो मुझे संदेह है, शायद आंकड़े इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो सकते परन्तु आपको प्रतीत होगा कि खपत के स्तर में कमी नहीं आयी है, लोग पेट्रोल की अधिक जमाखोरी कर रहे हैं सामान सूचियों में वृद्धि हो रही है तथा पेट्रोल पर आप जो धनराशि खर्च कर रहे हैं उसमें वृद्धि हुई है कभी नहीं। इसलिए इस निर्णय का क्या उद्देश्य था ? सरकार में पेट्रोल की सबसे अधिक खपत होती है। ये आसान तरीके हैं। जब सरकार द्वारा पेट्रोल की सबसे अधिक खपत होती है तो औसतन आदमी को परेशानी क्यों होनी चाहिए ? परन्तु सरकार परेशान नहीं है क्योंकि इसके अपने गैरिज हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय मोर्चा और इसके सहयोगी दल के मुख्य मंत्री के लिए शाम के 7 बजे के बाद पेट्रोल पम्प खुलवाया गया था क्योंकि उनकी कार में पेट्रोल नहीं था। क्या यह विशेष सुविधा कुछ ही विशेष व्यक्तियों को दी जा रही है अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही नियम लागू हो रहा है ? (व्यवधान)

महोदय, एक तरफ औसत व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है। उससे पेट्रोल बचाने के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधान मंत्री विदेशी यात्रा के लिए एक नहीं बल्कि दो विमान ले जाते हैं। मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं हुआ है। महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं होता था मेरा विश्वास···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : छुट्टी पर मैं नहीं ले गया था।

श्री राजीव गांधी : छुट्टी पर मैं भी नहीं ले गया था, प्रधानमंत्री जी।

[अनुवाद]

महोदय, एक प्रश्न उठाया गया है, मुझे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : एक शेर मैं सुना रहा हूं :

"यूं तो बनाते हो पत्थर के सनम,
भगवान् बन गए तो मुझ पर बरस पड़े।"

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, पहले कभी भी मंत्री यात्रा के लिए वायुसेना के विमान तथा अन्य विमानों का प्रयोग नहीं करते थे। पहले कभी भी इनकी तरह मंत्रियों के परिवारों ने विदेशी यात्रायें नहीं कीं। ऐसा यह अचानक···(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : लक्षद्वीप में आप गए थे।

श्री राजीव गांधी : लक्षद्वीप में कार्माशियल एयर लाइन्स से फेयर पे करके मैं गया था। आप समझ लीजिए। पवन-हंस से मैं अकेला गया था। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : श्रीमान् अमिताभ बच्चन भी गये थे। केवल शेर देखने के लिए गए थे, राजस्थान का भला करने के लिए नहीं गये थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, विदेशी मुद्रा की कमी है। परन्तु कितने लोग सरकारी खर्चे से विदेशों में घूम रहे हैं? कितने परिवार विदेशी मुद्रा खर्च करके विश्व की यात्रायें कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु बेचारे तिपहिया स्कूटर वाले की रविवार की रोजी खत्म की जा रही है। यह अन्तर्विरोधी बात है जिसे आपको स्पष्ट करना है। आपको याद है कि सरकार की ओर से इसी अन्तर सत्रावधि में 100 सांसदों को विदेशी यात्रा पर भेजने का सुझाव दिया गया था परन्तु जब हमारे दल ने इस पर आपत्ति की तो इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रकार विदेशी मुद्रा को महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। मई के अन्त में आप यह नहीं जानते थे कि जून और जुलाई में विदेशी मुद्रा की समस्या पैदा होगी। आप 100 सांसदों को विश्व यात्रा के लिए भेज रहे थे। अब समस्या और गम्भीर हो गयी है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सोवियत संघ ने और अधिक पेट्रोल देने से इन्कार कर दिया है तथा खाड़ी संकट और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण यह समस्या और गम्भीर होती जा रही है, परन्तु इसके अतिरिक्त आप एक नयी समस्या का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आपको स्टाक बाजार से पेट्रोल खरीदना है। आपको साख की आवश्यकता है और हमें लगता है कि भारत की साख गिरती जा रही है। भारत की साख में गिरावट आने के क्या कारण हैं? क्या इसमें भी कांग्रेस सरकार का दोष है? (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बिल्कुल नहीं···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कांग्रेस सरकार के समय में विदेशों में भारत की साख बहुत अच्छी थी। आज तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को 150 मिलियन डालर का ऋण नहीं मिल सकता है। ऐसा भारत के साथ ही हुआ है, आप महीनों से इस ऋण को लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का क्या हो रहा है? सरकार बदलने के आठ महीने के अन्दर विश्व भारत की आर्थिक क्षमता में विश्वास क्यों नहीं करता है? यह ऐसा गंभीर प्रश्न है जिसके बारे में आपको विचार करके जवाब देना है। मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय मोर्चा के वायदों का क्या हुआ? राष्ट्रीय मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्यों को नियंत्रित किया जाएगा। यह पूरी तरह विश्वासघात किया गया है। मूल्यों पर कतई नियंत्रण नहीं

है। चुनाव के बाद के वायदों का क्या हुआ? 8 मई को नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा है: "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है।"

श्री पी० चिदम्बरम : सरकार लड़खड़ा रही है।

श्री राजीव गांधी : 19 जून को उन्होंने यह पुनः कहा है : "खाद्य मूल्यों में वृद्धि एक मौसमी बात है तथा मूल्य एक नियत समय में मूल्य स्थिर हो जाएंगे"। वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आज से अगले पांच महीनों में कमी आ जाएगी।" 22 जनवरी, 1990 को यह पक्की भविष्यवाणी की गयी है। 21 अप्रैल, 1990 को वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है : "मुझे विश्वास है कि आवश्यक वस्तुओं में चीनी, चाय और खाद्य तेलों के मूल्यों में जून, 1990 तक गिरावट आ जाएगी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अगले दो महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।" 21 अप्रैल, 1990 को वित्त मन्त्री महोदय ने यह बात पुनः कही है। प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा था, "सरकार ने आज से एक महीने के अन्दर मूल्यों में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।"

[हिन्दी]

लेकिन प्रधान मन्त्री बैठे नहीं थे। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं। आप प्रधान मन्त्री जी को सुन लेने दीजिए। आप अपने प्रधान मन्त्री को क्यों तंग कर रहे हैं?

[अनुवाद]

"यदि मई, 1990 के अन्त तक मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि को कम नहीं किया जाएगा तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे" 3 मई, 1990 को प्रधान मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था। प्रधान मन्त्री महोदय, मई समाप्त हो गयी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चीनी तथा सीमेंट के मूल्यों में गिरावट आयी है। हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : सीमेंट के गिरावट आयी है परन्तु इसमें अभी वृद्धि हो रही है। शायद वह यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है अथवा कमी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस समय एक विशेष उल्लेख किया गया था, चीनी 10 रुपए प्रति किलो थी। इसके बाद इसमें गिरावट आयी और 8 से लेकर 9 रुपए प्रति किलो हो गयी। उस समय सीमेंट 110 रुपए प्रति बोरी थी, सीमेंट 100 रुपए तक पहुंच गयी थी तथा कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में यह 110 रुपये तक पहुंच गयी थी। उसके बाद मुख्य क्षेत्रों में यह घटकर 85 रुपये से लेकर 90 रुपए प्रति बोरी तक बिकने लगी। दूर-दराज के क्षेत्रों में कुछ समस्या है।

हाल ही में हमें सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के बारे में बताया जा रहा है। हम इसके संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

परन्तु यह कहना पूरी तरह गलत है कि इसके बाद कुछ नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, प्रधान मन्त्री विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हम गरीबों के सीमेंट खाने के लिए कहेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

हम उनके पेट की बात कर रहे हैं और आप सीमेंट की बात कर रहे हैं। यही तो तकलीफ की बात है। आप जरा बाहर जाकर बाजार में देखिये तो सही……(व्यवधान)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : पिछले चुनावों में चीनी के दाम 14-15 रुपये प्रति किलो थे।

श्री वसन्त साठे : कहां ?

श्री नाथू राम मिर्धा : सारे हिन्दुस्तान में। यह मैं नहीं कर रहा हूं। आप सब जगह पूछ लें। चाय के भाव 80-90 रुपये प्रति किलो के भाव थे जो अब कम हैं। (व्यवधान)

राजीव गांधी के समय 97 लाख टन चीनी पैदा की गयी थी और अब यह 109 लाख टन चीनी पैदा की गयी है। इस सरकार ने रिकार्ड बीट किया है पिछले 6 महीनों में, इसलिए कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में चीनी 8-9 रुपये किलो के बीच में मिल रही है। चाय आज 40 और 55 रुपये के बीच में मिल रही है। ये दो चीजें असैन्शयल कमोडिटीज में आती हैं, हर गरीब आदमी चाय का प्याला पीता है और इसके दाम आपके वक्त की तुलना में काफी कम हो गये हैं। चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है इन 6 महीनों से अंदर, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। गेहूं और चावल के दामों का जहां तक ताल्लुक है, हमने किसान को गेहूं और चावल के दाम दिये हैं। हमने किसान को 32 रुपये क्विंटल गेहूं के दाम दिये और किसान को गेहूं का अधिक दाम मिलने के कारण ही कुछ दूसरी चीजों के दाम ऊंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, हमने गन्ने का दाम 40 रुपये दिया, जब कि आपके जमाने में 23 रुपये दिया गया था। किसान को अधिक दाम देने की वजह से कुछ चीजों में महंगाई आना स्वाभाविक है, इसे हम स्वीकार करते हैं। यदि आप किसान को दाम नहीं देना चाहते तो चीजों के दाम निश्चित रूप से सस्ते हो जायेंगे। आप लोग इस सिद्धांत को मानते नहीं थे, हम इसे मानते हैं कि किसान को ठीक दाम दिया जाए और यदि इससे थोड़ी महंगाई हो तो उसे बर्दाश्त किया जाये। हम किसान के हित की बात सोचते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने आपके बीच में कभी बाधा नहीं डाली। जब आपकी बारी आए तो आप बोलना।

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। व्यवधान नहीं। अपने तक सीमित रहिए। हम मूल्यों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : प्रधानमन्त्री ने जो बात कही है मैं उसे समझता हूं। परन्तु मैं देखता हूं कि सीमेंट के बारे में बोलने के पश्चात् जब मैंने उनसे लोगों के खाने के बारे में पूछा तो वह अधिक देर तक नहीं टिक सके और……

[हिन्दी]

मैदान छोड़ कर भाग गये।

[अनुवाद]

मिर्धाजी चाहे सीमेंट की बात करें अथवा चाय के कप की परन्तु आम आदमी मूल्यों के इस बोझ से पिसता जा रहा है ।

[हिन्दी]

मिर्धा जी, आज हम चाय की बात नहीं कर रहे हैं, चाय की बात तो तब ठीक थी जब उन्हें खाने को मिल रहा था, लेकिन आज अनाज इतना महंगा हो गया है, दालें इतनी महंगी हो गयी हैं कि उसके सामने खाने का सवाल उठ रहा है । इसलिये चाय के दाम का महत्व नहीं है··· (व्यवधान)··· मिर्धा जी, आप चाय तो पिलाना चाहते हैं, और चीनी का भाव कह रहे हैं कि कम हो गया लेकिन चाय का भाव क्या हो गया । क्या आम आदमी पानी में चीनी घोलकर पियेगा ?

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी, आप कृपया इन्हें बोल लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, आप इन्हें कहिये कि आपको सम्बोधित कर अपनी बात कहें ताकि बार-बार उनको उठने की तकलीफ न हो । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मुझे विश्वास है कि प्रधानमन्त्री पर्याप्त रूप से सक्षम हैं ।

सभापति महोदय : कृपया प्रत्येक व्यवधान का जवाब मत दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : जब आम आदमी पिस रहा है तो हम देखते हैं कि सरकार जमाखोरों और ठगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । ऐसा क्यों है ? मैं समझ सकता हूं कि धर्म निरपेक्षता का अनुयायी उचित बातों के लिए संघर्ष करता रहेगा ।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : हम धर्मनिरपेक्ष हैं । आप सांप्रदायिक रहे हैं ।

श्री राजीव गांधी : लेकिन साम्प्रदायिक और शायद निहित स्वार्थ ही सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी उनमें सबसे आगे है । पिछले बजट अधिवेशन के दौरान सदन में सभी ने, जिसमें सरकार का समर्थन करने वाले हमारे मित्र भी शामिल हैं, बजट में किये गये उपायों की आलोचना की थी । मात्र भाषण देने की बजाए कुछ कीजिये । सत्ता पक्ष पर आपका हम से ज्यादा प्रभाव है । हम यहां सदन में केवल बात कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ तो प्रत्येक सप्ताह भोज के बाद बैठक होती है, ऐसा मेरा विश्वास है ।

5.00 म० प०

मूल्यों पर आधारित राजनीति को धीरे धीरे त्यागा जा रहा है शायद मूल्य बहुत ऊंचे हो गये हैं और हमने अपना रुख मुद्दों पर आधारित राजनीति की ओर मोड़ दिया है । इन मुद्दों में से, आप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठा सकते हैं······(व्यवधान) आपको क्या कहना है बिना अधिकारों के आपके ऊपर उत्तरदायित्व है । कृपया इस उत्तरदायित्व को थोड़ी और गंभीरता

से लीजिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि सरकार सकारात्मक कार्यवाही करे और कीमतों को नियंत्रण में लाए।······(व्यवधान) सच्चाई यह है कि हमारी आर्थिक समस्याओं का मूल अभिशाप राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की दुविधा नहीं बल्कि अल्पमत की सरकार के कमजोर नियंत्रण है जो टिके रहने के लिए दो परस्पर विरोधी पक्षों पर, जो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आधार पर इसे अलग-अलग दिशाओं की ओर खींच रहे हैं, निर्भर है। उनमें एक वाम पक्ष और दूसरा दक्षिण पक्ष की ओर खींच रहा है।

महोदय, राष्ट्रीय मोर्चो की सरकार कांग्रेस सरकार के कार्य के विरुद्ध झूठा प्रचार करके सत्ता में आई है। आज यह झूठे आश्वासन के सहारे सत्ता में टिकी है। लेकिन कांग्रेस पर दोष लगाने से उनकी कोई साख नहीं बनी है।

5.02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोगों को आपके वायदे पर विश्वास नहीं है। लोगों को यह अहसास हो रहा है कि जब तक सत्ता दल अपने आंतरिक झगड़ों में उलझा रहेगा और इस प्रकार के समर्थन पर निर्भर रहेगा जो अपनी सहूलियत के अनुसार सरकार की नीतियों और कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर लेते हैं और सरकार के कार्यकलापों से बेदाग रहता है तब तक बढ़ती हुई कीमतें नहीं रुकने वाली हैं। यदि आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो आपको साहस कर के उनकी नीतियों का भी समर्थन करना चाहिए। आप इसका खंडन करते हैं, आप कहते हैं कि यह खराब है वह खराब है और फिर आप उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। गलत को गलत और खराब को खराब कहिए।······(व्यवधान)

अब वह यहां नहीं हैं उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : इन्होंने तेल में पैसा कमाया, आपने शुगर में।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : जब तक सरकार निहित स्वार्थों के दबाव में रहेगी यह कमजोरी जारी रहेगी या यह कमजोरी तब तक भी जारी रहेगी जब तक सरकार विदेशी शक्तियों के दबाव में रहेगी। लोकप्रियता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि वायदा खिलाफी हो रही है। युवकों को रोजगार देने का वायदा किया गया लेकिन उस ओर कुछ नहीं किया गया। पुरानी योजनायें धूल चाट रही हैं और रोजगार की कोई भी नई योजना शुरू नहीं की गई हैं। ऋण वायदों की स्थिति तो लागू ही नहीं की है। यह योजनाओं से भी बदतर है क्योंकि उसी वायदे के फलस्वरूप किसानों को आज ऋण नहीं मिल रहा है। "वह ऋण लेने के लि! बैंक जाता है, बैंक खातों को देखकर कहता है आपने बैंक ऋण अदा नहीं किया है।" उसे इस वर्ष की फसल के लिए ऋण नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? क्या यह किसान की गलती है? जी नहीं, तो महोदय यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की गलती है क्योंकि उन्होंने किसानों से किया अपना वायदा पूरा नहीं किया है।

फिर पेंशन का वायदा है। ऋण की स्थिति पर हम पहले ही बता कर चुके हैं, आठ माह पूर्व भारत की साख बहुत अच्छी थी। आज राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की विश्वसनीयता ने अब इस स्थिति तक गिरा दी है। हम राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का आह्वान करते हैं कि वह आपसी झगड़ों में राष्ट्र का समय नष्ट न करें और शासन करने का कार्य करें जिसकी शुरूआत वह कीमतों पर नियंत्रण रख कर कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में कदम उठाने के बजाए इस सरकार ने मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले उपाय किए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पन्ना पढ़ चुके।

श्री राजीव गांधी : अगर आप इतना नहीं समझते हैं तो हैड फोन लगा लीजिए तब पता चलेगा कि पन्ना पढ़ चुके या नहीं।

[अनुवाद]

मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। आज जो हम मुद्रास्फीति देख रहे हैं वह सरकार के कार्यों के परिणामस्वरूप है। रेलवे बजट राष्ट्रीय बजट और वित्तीय नीतियों ने धन की सप्लाई को 15 से 16 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। रेलवे बजट ने सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं बजट से पहले और बजट के बाद की कीमतें पढ़ देता हूं। यह मात्र एक बजट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका कांग्रेस से या बाद में आप क्या करेंगे इससे कोई संबंध नहीं है मात्र बजट के पूर्व और पश्चात् की स्थिति। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बीच में हस्तक्षेप न करें। यदि आपके पास कोई ठोस मुद्दा है तो आप उसे अपने भाषण के दौरान उठा सकते हैं। व्यर्थ में बार-बार कहने का कोई महत्व नहीं है।

श्री राजीव गांधी : मात्र बजट के कारण मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। (व्यवधान) बजट के कारण गेहूं के दामों में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जो 2.14 रुपए से बढ़कर 2 रुपए 44 पैसे हो गया। सिर्फ बजट के कारण, चीनी के दामों 17.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जीरे में 16.7 प्रतिशत की, काबुली चने में 38.5 प्रतिशत, अरहर की दाल में 30 प्रतिशत, मूंग की दाल में 18 प्रतिशत, मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं। मैं नवंबर से आज तक जो वृद्धि हुई है, जिसकी कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सरसों के तेल में 22.7 प्रतिशत, वनस्पति 14.8 प्रतिशत, परिष्कृत तेल 9 प्रतिशत, खुली चाय 18 प्रतिशत, पेट्रोल 13 प्रतिशत, मिट्टी का तेल जो सबसे निर्धन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसमें इस बजट से 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट के दौरान प्रधानमन्त्री ने सीमेंट का विशेष उल्लेख किया था। सीमेंट में 69.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईंटों के दाम में 106 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आज जो हम मुद्रास्फीति देख रहे हैं उसके लिये सरकार की वित्तीय नीतियां, रेलवे बजट और वर्तमान बजट उत्तरदायी हैं। और इसके लिए समर्थक दल बराबर के उत्तरदायी हैं। वह अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। आपने इस दौरान उनका जो समर्थन किया है उसका उत्तरदायित्व तो आपको वहन करना ही होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको सरकार को समर्थन देना बन्द कर देना चाहिए। आपको

नीति बदलने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए था; किन्तु ऐसा आपने नहीं किया। इसीलिए मुझे दुख होता है। जब आपने कहा था, जब यह स्वीकार किया था कि आपका उत्तरदायित्व है तो आपको उसका उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए; किन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप देश के गरीब लोगों के लाभ के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा अपनी स्वयं की समस्याएं सुलझाने के लिए कर सकते हैं, किसी को यहां से वहां करने के लिए, एक कुर्सी यहां और एक पद वहां किंतु ऐसा नहीं हैं।

मैं एक उद्धरण पढ़ रहा हूं।

"जन मोर्चा शासन के पिछले आठ महीने प्रशासनिक अनिर्णय, सकल आर्थिक कुप्रबंध, और नीति सम्बन्धी शून्यता के परिचायक रहे हैं। सरकार द्वारा जारी नीति सम्बन्धी वक्तव्य एक दूसरे के विपरीत हैं; यहां तक कि जन मोर्चा के विभिन्न नेता ही अलग-अलग बातें करते हैं। मई, 1990 में संसद में प्रस्तुत औद्योगिक नीति संकल्प आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पर में प्रति-प्राप्ति औद्योगिक नीति के विपरीत है।" (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

आप बस समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : बजट घाटों और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दी गई चेतावनियों की वित्त मन्त्रालय द्वारा उपेक्षा की जाती है। औद्योगिक और व्यापार नीतियां निर्धारित करने वाले अधिकारी भुगतान सन्तुलन की समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सुझावों की अनदेखी कर देते हैं। सर्वत्र आर्थिक अव्यवस्था फैल रही है। जहां एक ओर विकास डांवाडोल हो रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार लोकवादी चालों, अनावश्यक विलासितापूर्ण वस्तुओं और विभिन्न अनावश्यक अतिरिक्त वस्तुओं पर अन्धाधुन्ध खर्च कर रही है।

बढ़ते मूल्यों के भार तले जनता आर्तनाद कर रही है और राष्ट्रीय जन मोर्चा सरकार के मन्त्री किसी न किसी बहाने विश्व भर में विदेशी राजधानियों और विश्राम स्थलों पर मौज मस्ती के लिए जाते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, क्या आपने इस सदन में लिखित भाषण की अनुमति दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि उद्धरण पढ़े जा सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह किसका उद्धरण है ?

श्री राजीव गांधी : यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रख देता हूं... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान करने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राजीव गांधी : यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं इस पत्र को सभा-पटल पर रख देता हूं ।

एक ओर जहां आम नागरिक को पैट्रोल की राशनिंग से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन जन मोर्चा सरकार के मन्त्रियों के लिए विशेष हवाई जहाजों द्वारा जब भी जो चाहे चले जाना एक आम बात हो गई है ऐसा पिछली सरकार द्वारा केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाता था । अधकचरे चुनावी वायदों की तरह 10,000 रुपए तक के ऋणों को मुक्त करने के जनवादी वायदों ने कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादक क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋणों पर प्रतिबन्ध लग गया है । सर्वत्र व्याप्त अनिश्चितता के वातावरण में खरीफ फसल बोने के लिए बहुत से किसानों को बैंक ऋण नहीं मिल रहा है''' । पूरे भारत के किसानों की वही स्थिति है जो हरियाणा के किसानों की है । हरियाणा के किसानों को हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार किया है ।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री, जो यहां नहीं हैं, से निवेदन करता हूं, वित्त मन्त्री'''। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : यह किसका उद्धरण है ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यदि आप चाहते हैं तो मैं उस पत्र को सभा पटल पर रख दूंगा । यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आर्थिक संकल्प है। (व्यवधान) मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा । (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, क्या उन्हें अपने दल के संकल्प को पढ़ने की अनुमति है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि उनके दल के संकल्प का उद्धरण किया जाए या उसके दल के दस्तावेज का उद्धरण दिया जाए तो इससे सदन गुमराह हो जायेगा, (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संकल्प का ही हिस्सा है जिसका उद्धरण दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, उद्धरण के रूप में दल के संकल्प को पढ़ा गया है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं उनके दल के संकल्प का भी उद्धरण कर सकता हूं, ऐसी कोई बाधा नहीं है । (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : महोदय, परम्परा यह है कि किसी भी राजनैतिक दल के संकल्प सम्पूर्ण को उद्धृत नहीं किया जा सकता । आप इसका उल्लेख कर सकते हैं । और यह हमारे लिए बहुत खेदजनक है, क्योंकि यह उस दल का संकल्प है जिसके आप नेता हैं, वे अपने ही संकल्प का उद्धरण कर रहे हैं । यह बहुत आश्चर्यजनक है । (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं कांग्रेस दल की ओर से बोल रहा हूं । मैंने कांग्रेस दल के संकल्प के एक पैरा का उद्धरण किया है । उस संकल्प में कोई गलत बात नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई सदस्य अपने दल द्वारा पारित संकल्प का उद्धरण करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह अपने संकल्प में से उद्धरण कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें यह कहना चाहिए था कि 'यह उनके दल का संकल्प है'। उन्हें यह बात पूरी ईमानदारी से कहनी चाहिए थी। उन्होंने यह कभी नहीं कहा। वह यह अब कह रहे हैं। इस सदन की कुछ परम्परा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं आपका एक तर्क है और एक मुद्दा है। आप इसे अपने भाषण में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि कोई अपने दल का संकल्प, जो मूल्य-वृद्धि से सम्बन्धित है, पढ़ता है।

वास्तविकता यह है कि इन आठ महीनों के दौरान, गरीब लोगों के ऊपर जो मूल्यों का भार पड़ा है वह 1979 के जनता शासन के समय के सिवाए, अप्रत्याशित है। जब जनता सरकार सत्ता में आती है, तब गरीब लोगों को यह भार उठाना पड़ता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में गम्भीर कार्यवाही करें जैसा कि मूल्य-वृद्धि और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने वायदा किया था। और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालने हेतु इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अशोकराज बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, इस चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं समझता हूं कि उन्होंने 6.00 बजे का समय निश्चित किया है। परन्तु मैं नहीं समझ पा रहा कि हम इस चर्चा को पूरा कर पायेंगे क्योंकि मेरे पास काफी लम्बी सूची है तथा दूसरी तरफ के सदस्यों के पास भी काफी लम्बी सूची है।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, यदि दोनों तरफ से थोड़ा तालमेल बिठाया जाए तो मैं 6.00 बजे तक अपना उत्तर दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टी के सचेतक आपको सूचित करेंगे। मान लीजिए यदि कोई सदस्य कहना चाहता है तब मैं उसे कहने की अनुमति दे दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी को पौने तीन घण्टे दिए गए। आप और पार्टियों को टाइम देंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को इस प्रकार मत उठाइये। पार्टियों को उनका समय दे दिया गया है। वे इसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वास्तव में यह आपत्ति श्री गांधी के भाषण से संबंधित है। (व्यवधान) सबसे पहले तो उनका स्पष्टीकरण, तत्पश्चात् उद्धरण दोनों ही अर्थहीन हैं। वास्तव में यह समय बर्बाद करने वाली बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक राज।

श्री ए० अशोक राज (पेरम्बलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं मूल्य-वृद्धि के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान मूल्यों में 8.4 प्रतिशत वृद्धि मौसमी वस्तुओं जैसे दालें, चाय, तिलहन, मूंगफली का तेल, खांडसारी तथा गुड़ के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई थी।

अखाद्य मदें जैसे वस्त्र, कागज तथा कागज से बनी वस्तुएं, शीतल पेय, तम्बाकू तथा तम्बाकू से बनी वस्तुएं तथा बुनियादी धातुओं के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई।

चालू वर्ष 1990 की प्रथम तिमाही में थोक बिक्री मूल्यों में वृद्धि वर्ष 1989 की तुलना में काफी अधिक तेजी से हुई थी। सभी वस्तुओं का मूल्य-सूचकांक (वर्ष 1981-82 के आधार पर) 31 मार्च, 1990 तक 170.7 तक हो गया जो 30 जून, 1990 तक 177.5 तक पहुंच गया जबकि पिछले सप्ताह दिसम्बर, 1989 में यह 165.9 था।

30 जून, 1990 तक आंकड़ों पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 9 प्रतिशत थी जबकि 30 जून, 1989 तक पिछले वर्ष में यह 5.6 प्रतिशत थी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य 7.3 प्रतिशत तक बढ़े थे। आवश्यक वस्तुओं में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 9.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी। गेहूं के मूल्य 11 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। दाल के मूल्य 11.1 प्रतिशत तक बढ़े थे।

केन्द्र सरकार के बजट के पश्चात् 23 जून, 1990 तथा इसके बाद तथा दिसम्बर, 1989 तक थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि दालों में 10.7 प्रतिशत, फल तथा सब्जियों में 35.1 प्रतिशत, मसालों में 21.1 प्रतिशत, अन्य खाद्य वस्तुओं में 15 प्रतिशत, तिलहनों में 22.6 प्रतिशत, चीनी, खांडसारी तथा गुड़ में 10 प्रतिशत, खाद्य तेलों में 17.5 प्रतिशत, शीतल पेय, तम्बाकू इत्यादि में 11.8 प्रतिशत हुई थी।

हम कारण जानते हैं। वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट में करों में 1,790 करोड़ रु० की वृद्धि की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि संघीय रेलवे बजट में 847 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों तथा कच्चे तेल पर आयात शुल्क में 836 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसका आम मूल्यों पर काफी असर पड़ता है। राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लगाये गये अतिरिक्त करों से विद्युत शुल्क में भी वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को रोकने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनिच्छुक है। गेहूं तथा चावल के खरीद मूल्यों में अभी हाल ही में जो वृद्धि हुई है, इससे इन दोनों आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मैं आपको

बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिए चावल की खरीद की है। हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि इसमें घोटाला हुआ है। इन घोटालों को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की महासचिव कु० जयललिता ने बताया कि खरीद गलत आधार पर की गई थी तथा इसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है। वे सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जोर दे रही है। जब विपक्ष के नेता इस मामले तथा बड़ी रकम के बारे में बोलते हैं, तब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना के दो कारण हैं—एक तो बजट में लगाये गये कुछ करों के कारण तथा सरकारी व्यय में इसी प्रकार की वृद्धि के कारण मांग बढ़ने तथा बजट अनुमानों से अधिक खर्च करने के कारण। उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सिगरेट, शीतल पेय इत्यादि पर कर में वृद्धि से खपत कम होगी जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों पर बिना कोइ प्रभाव पड़े सरकार को काफी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। परन्तु दूसरी तरफ, कच्चे माल पर अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि अथवा इसके बिक्री मूल्य में वृद्धि से, सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों पर भी काफी असर पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्र की वास्तविक आय में वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की सुधरी हुई स्थिति को प्रकट करती है। एक तरफ देश की वास्तविक आय की वृद्धि दर तथा दूसरी तरफ कुल राष्ट्रीय व्यय तथा/अथवा धन आपूर्ति में वृद्धि की दर के बीच अन्तर से यह जाहिर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति तथा मांग के बीच में कितना अधिक असंतुलन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को जो ऋण दिया जाता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दिये गये ऋण तथा देश की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को दिये गये ऋण शामिल हैं, का क्या मिला जुला प्रभाव पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को 20 मई, 1990 को एक पत्र लिखा था जिसमें मूल्यों को रोकने के लिए उनका सहयोग तथा सहायता मांगी थी। केवल तमिलनाडु में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं। मूल्य वृद्धि रोकने के लिए एक अत्यन्त अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए तथा समय-समय पर बाजार में हस्तक्षेप भी किया जाना चाहिए। इन दोनों बातों को उचित रूप में व्यवहार में लाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि लोग माल की जमाखोरी कर रहे हैं। हमें जमाखोरी समाप्त करने के लिए तथा जमाखोरों को सजा देने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार जमाखोरी समाप्त करने के लिए तथा जमाखोरों को सजा देने के लिए कड़े नियम बनायें। विकास को बनाये रखने के लिए तथा सभी को लाभ उचित रूप में मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्य-स्थिरता आवश्यक है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव विशेष रूप से निर्धनों पर पड़ता है क्योंकि उनकी आय मूल्य-सूचकांक के अनुपात में नहीं होती। इससे वित्तीय परिसम्पत्तियों में पैसा लगाने की इच्छा भी कम हो जाती हैं, सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है तथा काला धन को बढ़ावा मिलता है और पूंजी निवेश संबंधी प्राथमिकताओं पर असर पड़ता है। मुद्रास्फीति का सबसे अधिक दबाव हमारे समाज के पहले से ही निम्न स्तर में रह रहे निर्धन तथा कमजोर तबकों पर ही पड़ता है। मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को भी देखना है तथा वित्तीय असंतुलन में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को उनकी गलतियों के लिए दोष देने का कोई फायदा

नहीं है परन्तु हमें अब देखना चाहिए कि मूल्य कम करने के लिए शीघ्र से शीघ्र उचित कदम उठाए जाएं।

अन्त में, मैं जनता दल को सचेत करना चाहूंगा कि वह इस खतरनाक स्थिति को समझे। आपने हमें संकट में डाल दिया है। आप कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि निर्धन व्यक्तियों में अत्यधिक आक्रोश है। हमें उनकी कठिनाइयां समझनी चाहिए अथवा उस संकट से न केवल आप बल्कि हम सभी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि अगले तीन महीनों में मूल्य गिरें अथवा हम खतरे में पड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन महंगाई के सवाल पर चर्चा कर रहा है। महंगाई से आज सारा देश दुखी है, खासकर गरीब जनता, निर्धन जनता को बहुत कष्टपूर्ण जिंदगी बितानी पड़ रही है। बंधी हुई आय प्राप्त करने वाले लोगों को बहुत कष्ट हैं। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिन चीजों को हर गरीब आदमी खरीदता है, उनकी कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए जिंदगी बिताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने देश भर में महंगाई का इसका विरोध किया, सरकार पर इसके लिए दबाव डाला, धरने दिए, प्रदर्शन किए, परन्तु जब कांग्रेस पार्टी और खासकर उसके नेता श्री राजीव गांधी, बसंत साठे और भगत जी इस सवाल पर अपने विचार रख रहे थे, सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, आंकड़े उन्होंने ठीक दिए हैं, परन्तु उनसे जो इनफरेंस निकालने की कोशिश की है, जिस निर्लज्जता से इस सरकार पर उन्होंने वह दोषारोपण किए, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, इससे मुझे खेद हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने इस महंगाई के सवाल पर सरकार की आलोचना की, वह तो समझ में आती है, कम्युनिस्ट पार्टी इसकी आलोचना करे तो वह भी समझ में आता है, परन्तु जो इस महंगाई के लिए मूल रूप में जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी आकर इनके ऊपर इलजाम लगाए, अपराधी अपने अपराध के लिए इस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाले, जिसने पाप किया है वह पापी उस पाप के लिए अपने को अछूता बताए, मैं समझता हूं कि यह बहुत निर्लज्जता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने जो आंकड़े दिए हैं, उनको देखिए। उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर होल-सेल प्राइस इंडेक्स दिसंबर, 1989 में 168 था, वह बढ़कर 175 हो गया, यह ठीक है, परन्तु 1982 से 1989, इन सात सालों में इसमें 68 परसेंट की वृद्धि हुई है। इस तरह से पिछले सात सालों में हर साल होल सेल प्राइस इंडेक्स में करीबन-करीबन 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और साठे जी ने यहां पर कहा कि इस सरकार में 6 परसेंट प्राइस इंडेक्स इन्क्रीज हुआ है। मैं इस 6 परसेंट को अस्टीकाई नहीं कर रहा हूं, परन्तु कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 7 वर्षों में 70 परसेंट जो वृद्धि हुई है और उसके नेता यहां पर अब इस सरकार पर इलजाम लगाते हैं तो बात समझ में नहीं आती।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि कंज्यूमर प्राइस इनडेक्स दिसंबर, 1989 में 180 था। 100 से 180 कैसे आ गया? 1982 से 1989 तक, सात साल में 80 प्रतिशत वृद्धि

कंज्यूमर प्राइस इनडैक्स में आ गयी। यह साढ़े ग्यारह परसेंट बैठती है। अभी साढ़े ग्यारह पर यह सरकार नहीं पहुंची। मैं मानता हूं कि कोई अपराध कांग्रेस सरकार ने किया है तो वर्तमान सरकार उस अपराध को बढ़ाती जाए, यह ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कोई पाप किया है तो उसी तरह से पाप करते जाएं इसकी कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। परन्तु राजीव जी या भगत जी आकर उन आंकड़ों को दें और उसके बाद कहें कि देखिए हमने बहुत काम किया था, आपने यह काम नहीं किया है, यह अनुचित है। भगत जी जब कह रहे थे और खासकर जनता पार्टी को कह रहे थे कि पत्नी की तरह से उस सरकार रूपी अपने पति के प्रति लायल्टी तो शो करती है परन्तु उसके साथ साथ वह उसे डिफेंट नहीं करना चाहती है। मैं भगत जी से कहना चाहता हूं, राजीव जी से कहना चाहता हूं खास कर महंगाई के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, ब्लैक-मार्किटियर्स के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में मेरा कहना यह है कि पिछले 10 सालों में पैदा की गई। उसके बारे में जब खड़े होकर कांग्रेस वाले बोलते है तो ऐसा लगता हैं जैसे वेश्या सतीत्व पर भाषण दे रही हो। आप इस बात को समझें। कांग्रेस पार्टी का पिछले वर्ष 13,500 करोड़ का घाटे का बजट था। राजीव गांधी का बजट 13,500 करोड़ रुपए के घाटे का बजट था। पिछले साल में 35 हजार करोड़ रुपए के घाटे के बजट इन्होंने बनाए। अगर पांच साल में 35 हजार करोड़ के घाटे का बजट बनाएंगे तो क्या यहां पर महंगाई नहीं होगी ? जुर्म इन्होंने किया, मूल रूप में इन पर जिम्मेदारी आती है, महंगाई की गाड़ी को इतने स्लोप पर इतना नीचे गिराते चले गए कि एकदम यदि ब्रेक लगायी जाती तो गाड़ी टूट जाती। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रेक लगायी न जाए, गाड़ी को गिरने दिया जाए। जनता दल और नैशनल फ्रन्ट की सरकार को इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार थी। लोगों ने इनको इनके पाप की सजा दे दी, विरोधी दल में बैठा दिया। इनको बोलने का कोई साहस नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि जनता दल इसको संतोष मान कर बैठ जाए, नैशनल फ्रन्ट इससे संतुष्ट हो कर बैठ जाए कि इन्होंने गलत काम किया था अब हम कर रहे हैं तो कौन-सी गलत बात है। जो गलत बात इन्होंने की उसको आगे दोहराया नहीं जाना चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। यह हमारा देश से वायदा है। इस सरकार ने देश से वायदा किया था और महंगाई के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर चुनाव लड़ा गया था। आज इस महंगाई को रोकना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तीन-चार बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिस पर यह सरकार कुछ कदम उठा सकती है। जब मधु दण्डवते जी ने बजट पेश किया था तो हमने यह बात कही थी कि यह बजट इनफ्लैशनरी है, यह बजट महंगाई बढ़ाएगा। उस समय इन्होंने यह कहा था इस बजट से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। हमारी आशंका ठीक साबित हुई। अगर आप पेट्रोल के दाम बढ़ायेंगे, डीजल के दाम बढ़ाएंगे, रेलवे का भाड़ा बढ़ाएंगे, लोहे के कीमत बढ़ाऐंगे, कोयले की कीमत बढ़ाएंगे, सभी चीजों की कीमतें बढ़ती ही जायेंगी तो उससे महंगाई बढ़ना लाजिमी है, महंगाई रुक नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि नेशनल फ्रन्ट की सरकार तीन-चार कदम निश्चित रूप से उठाए, यह ठीक है कि पांच वर्षों में 35 हजार करोड़ के घाटे का बजट पिछली सरकार ने दिया था, यह बात भी ठीक है कि विदेशों से 1 लाख करोड़ का कर्जा हिन्दुस्तान पर लाद दिया। राजीव गांधी यह कह रहे थे कि सितंबर और नवम्बर के बीच में हमने कीमतें कम कर दी थीं। लेकिन सितंबर तक ये कीमतें किस लेवल तक ले गए ? इन्होंने उन दिनों में विदेशों से असंख्य

रुपए का आयात करके दो महीने कीमतें इसलिए कम कीं चूंकि चुनाव आ रहे थे। चुनाव के बाद कीमतें बहुत तेजी से बढ़तीं, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि पाम आयल का आयात किया तो प्रधान मंत्री जी ने भाषण क्यों दिया कि इसको हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मधु दण्डवते जी कहते हैं कि इम्पोर्ट करेंगे। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि इम्पोर्ट नहीं करेंगे और किसी तीसरे मिनिस्टर ने कह दिया कि बहुत जल्दी तेलों का आयात कर रहे हैं। जब आपने कहा कि आयात नहीं करेंगे, उसी वक्त लोगों ने जखीराखोरी कर ली और उसके बाद इसके कारण बाजार में खाने के तेल की कीमतें बढ़ी हैं इसको रोकना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसको रोका जाना चाहिए। यह रुक सकती थी और इसके लिए वाजिब कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस पार्टी होर्डर्स और ब्लैक मार्किटियर्स से मिली हुई थी। उन्होंने अरबों रुपए का काला धन विदेशों में जमा कर दिया। परन्तु अब जमाखोरों के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। चोरबाजारी करने वालों पर जो कदम उठाए जाने थे, उस पर सरकार कमजोरी और लापरवाही क्यों कर रही है। इस तरह की जमाखोरी को खतम क्यों नहीं किया गया। किसानों को ज्यादा पैसा दिया गया जिससे गेहूं के दाम बढ़ गए। आपने कहा कि अरहर और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गए। जो चीजें मल्टी नेशनल्स कंपनियां बनाती हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, तेल, जूते, चिप्स या आलू की चीजें तो इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि क्यों हुई। अरबों रुपया मल्टी नेशनल कंपनियां एडवरटाइजमेंट पर खर्च करती हैं। जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वे दो रुपए में बनी चीजों को दस रुपए में बेचते हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे मिली हुई थी। आप उन पर कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। आपने किसानों के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनाया है उस तरह का इंडस्ट्रीयल प्राइस कमीशन क्यों नहीं बनाया। उसके बनाने से आपको पता लग जायेगा कि जो चीज दो रुपए में बनती है वह 10 रुपए में बिकती है। जो घाटे का बजट है तो 13,500 करोड़ का घाटा था अब सात हजार पांच सौ रह गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे विकास बंद हो जाए और लोगों को नौकरियां बंद हो जाएं। 75 प्रतिशत डी० ए० आप न्यूट्रलाइज करते हैं और उसका 40 परसेंट इन्कम टैक्स में चला जाता है। दूसरे कर्मचारियों के लिए यह महंगाई भत्ते की सुविधा भी नहीं है तो यह महंगाई जनता को पीड़ित करेगी। दी फेयर प्राइस शाप्स में आप ज्यादा चीजें क्यों नहीं दे रहे हैं। चाय सरकार के पास है उसके दाम आप कंट्रोल कर सकते हैं तो चाय और खाने के तेल क्यों उचित दर दुकानों में नहीं रखे जाते। नमक या अन्य कुछ चीजें हैं जिनके दाम आप सीधे कर सकते हैं। ज्यादा फेयर प्राइस शाप्स खोली जाएं तथा और चीजों के दामों को कंट्रोल किया जाए। विदेशों में जो रुपया जमा है उसको निकाला जाए। ब्लैक मनी को बाहर निकालिए उससे भी महंगाई कम हो सकती है। राजीव गांधी जी ने कहा कि ऐसी इकोनोमी हम दे गये वे वैसी पहले कभी नहीं थी। पिछले चालीस सालों में सन् 1978 का ही एक साल था जब होलसेल प्राइस इन्डैक्स तथा कन्ज्युमर प्राइस इंडैक्स एक प्वाइंट कम हो गया था। उसके बाद कांग्रेस ने अंधाधुंध कंपनियों से सांठगांठ की थी, भीषण भ्रष्टाचार किया गया और कांग्रेस देश को बर्बाद करके गई है। हमें यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का विरोध करते हुए उनके कदमों पर समर्थन की मोहर क्यों लगाती है। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेसी हुकूमत इस देश में दुबारा न आ जाए, यह असुरी राज दुबारा न आ जाए। इसलिए हम जनता दल का यहा समर्थन करते हैं। जनता दल को इस मजबूरी को ध्यान में रखना चाहिए कि यह हमारी मजबूरी तो जरूर है कि यह सरकार पांच साल चले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार इन चीजों को रोकने के लिए कोई कदम न उठाये। उसे

महंगाई रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी कि पिछले अधिवेशन के बाद सारे के सारे मंत्री विदेशों में सैर के लिए जायें। आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले करते थे। राजीव गांधी जी ने जो यहां पर कहा कि प्रधान मंत्री जी दो जहाज लेकर गये थे, उन्हें तो यह कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वे खुद जब विदेश जाते थे तो कई-कई जहाज लेकर जाते थे और केवल छुट्टी मनाने के लिए जाते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सरकार भी वही करे। उनके मंत्री सैर सपाटे के लिए घूमते थे तो हमारे भी घूमते रहें। मई में सत्र के बाद से लगातार मंत्री लोग विदेशों की यात्रा पर गये। जबकि विदेशों में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। देश में विदेशी मुद्रा की हालत वैसे भी खराब है और हम उस पर भाषण देते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री लोग विदेशों में जाते रहे, ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। आपको इन बातों पर रोक लगानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि अगर सरकार द्वारा सही कदम उठाए जाएं और औद्योगिक मूल्य कमीशन बनाया जाये, फेयर प्राइस शाप्स पर ज्यादा चीजें रखी जायेंगी और सरकार जिनकी कीमतें तय करती है उन पर कंट्रोल किया जायेगा तो देश में चीजों के दामों में स्थिरता आयेगी। यह राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा पत्र में है और हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में भी है। इसके लिए हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इस जवाबदेह पर संतोषजनक ढंग से आने वाले दिनों में कदम उठायें जायें, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री भोगेन्द्र झा। इनके दल के लिए चार मिनट हैं। आप कुछ समय और ले सकते हैं। मैं यह केवल आपकी जानकारी में लाना चाहता था।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : न तो मैं अधिक समय लेना चाहता हूं और न ही अपने मित्रों को लंबा चौड़ा भाषण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप यह चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय 6.00 बजे बोलें तो आपको कुछ सीमित बोलना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपको समय दूंगा। मैंने समय की कमी की बात आपके ध्यान में लाई है। आप अपना समय ले सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : इस मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर हमने अपने दल की ओर से कई प्रकार से अनेक प्रस्ताव पेश किए हैं। अतः यह स्वागत योग्य है कि हमने इस विषय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। चूंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ जमाखोरों, काला बाजारी करने वाले व्यक्तियों और उनके कुछ प्रतिनिधियों को छोड़कर जनता का एक बड़ा वर्ग अत्यन्त चिन्तित है, अतः यह एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में है।

कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यह सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है। यह सही है। जब हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो हम भी इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम इसकी अच्छी-बुरी नीतियों और कार्य से मुक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि हमें सत्तारूढ़ नेताओं और विपक्षी दलों से कहीं अधिक चिन्ता है। आखिरकार समर्थन का भी कुछ अर्थ है और मेरा विचार है कि इस सरकार और इसके मंत्रियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे एक सीमा से आगे हमारे धैर्य की परीक्षा न लें।

विपक्ष के नेता ने इस मूल्य के प्रश्न पर सरकार में सभी प्रकार के अंतर्विरोध पाए हैं। इन्होंने यहां अन्तर्विरोधियों की बात की है। जब वे सत्ता में थे तो इससे अधिक अन्तर्विरोध थे। इनके कहने पर इनकी सरकार के मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खान ने एक प्रस्ताव पेश किया और तब "मुस्लिम पर्सनल ला" पर उस प्रस्ताव को श्री राजीव गांधी ने वापस लेने को कहा।

इन्होंने अनेक अपराध किए। मैं इस सरकार की उस सरकार से तुलना करने नहीं जा रहा हूं। साधारण शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पिछली सरकार की विरासत की बात है। इस सरकार ने यह बिल्कुल सही कहा है कि यह विरासत कांग्रेस सरकार की देन है। विपक्ष के नेता ने भी यह गलत नहीं कहा कि वह विरासत इन्हें जनता पार्टी से मिली थी। कुछ सीमा तक ये विरासतें अपरिहार्य हैं। जिस बात की मुझे चिन्ता है, वह है इस सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति की विरासत। कांग्रेस पार्टी की मूल नीति इस देश के एकाधिकार रखने वालों, थोक विक्रेताओं और मुनफाखोरों के हितों की रक्षा करनी थी और मुझे यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ा घुमा-फिरा कर यह सरकार भी उसी नीति का पालन कर रही है। यह समस्या की जड़ है। मैं यहां इनके कार्य और गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु, इनकी नीति भी पूंजीपतियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के पक्ष में है। यही कारण है जब इन्होंने इस सरकार के कार्य से खुश होने की बात कही तो मैं देख रहा था कि ये कितने प्रसन्नचित्त थे।

जिस वर्ग के हितों की रक्षा की जा रही है और आम लोगों के हितों को नजरअन्दाज करते हुए जिस वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है, वह वही हैं। अतः वे उत्साहित हैं। वे इस सरकार की गलतियों से भी प्रसन्न हैं। विशेष रूप से मूल्यों के विषय पर की गई गलतियों से, ताकि यह कहा जा सके कि यह आकाश से गिरकर खजूर में अटकने का परिवर्तन है। यही कारण है कि वे खुश हैं और अपनी प्रसन्नता को छुपा पाने की स्थिति में नहीं हैं। श्री बसंत साठे भी यहां बैठे हैं? वे भी खुश हैं। मैं नहीं चाहता कि वे इतने उत्साहित हों। (व्यवधान)

बजट में ही 70 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं, जिससे सारा भार लोगों पर पड़े। इसमें धनी व्यक्तियों पर 30 प्रतिशत कर लगाए गए हैं। इससे आम उपभोग की वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि होना अनिवार्य था। यह अपरिहार्य है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते इस तथ्य को भुला नहीं सकते। अन्य कई लोग भुला सकते हैं, अन्य कई इस प्रकार की नीति का वित्तीय अर्थ नहीं समझ सकते, परन्तु प्रो० मधु दण्डवते ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अनेक बार इस सदन में मेरी उपस्थिति के दौरान इस प्रकार की नीति के बारे में बोले हैं। अतः यह उसी नीति का परिणाम है और यही नीति कुछ सीमा तक कांग्रेस पार्टी की सहायता कर रही है।

लोकतंत्र में मुझे किसी की मंशा पर सन्देह नहीं है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई कोई भी सरकार मूल्यों में वृद्धि नहीं होने देना चाहेगी। अतः, मैं इस सरकार या पिछली सरकार पर इसका आरोप नहीं लगाता। प्रश्न आपके द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का है। उसका परिणाम इन सब बातों में होता है। अतः यह भी लोगों के हित में होना चाहिए। यदि उस बात पर यह सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है, तो यह बात समझ में आती है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का उदाहरण ले लीजिए। मैं नहीं समझता कि इस देश और इस सदन में कोई भी इसके खिलाफ होगा। परन्तु, जब आप गेहूं के मूल्य में दूसरी बार

वृद्धि करते हैं तो वह समय कौन-सा था ? यह समय वह था जब वास्तविक किसान पहले ही अपना उत्पादन मजबूरन सस्ते में बेच चुका था। इस बारे में मैं यहां किसी का विरोध नहीं करना चाहता। परन्तु; मैं यहां यही जानना चाहता हूं।

आप सदा गांव की बात करते हैं। क्या देश में एक भी ऐसा गांव है जहां के अधिकतर लोग अपने उपभोग के लिए खाद्यान्न नहीं खरीदते ? परन्तु इन्हें मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है और अब भी मजबूरन बिक्री की जाती है, बाद में गेहूं के मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं। धनी ग्रामीणों, जिनमें जमाखोर और भूमि हथियाने वाले भी शामिल हैं, द्वारा जब गेहूं का भंडार रख लिया जाता है, तो मूल्य बढ़ जाते हैं। अतः हम यह विश्वास नहीं करना चाहते कि यह किसानों के हित में किया गया था। यह तो जमाखोरों और भूमि हड़पने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। मैं इस दूसरी मूल्य वृद्धि की बात कर रहा हूं। इस पर आपको विचार करना होगा कि क्या आपको इससे कोई लाभ होगा। इससे किसको सहायता या लाभ मिलता है ? इस उद्देश्य के लिए देश का कस्बों और गांवों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। भूमि हड़पने वाले और जमाखोरों के एक छोटे से वर्ग को इससे लाभ हुआ है और ये ही ग्रामीण लोगों के शोषक हैं। इनमें से कई तो बस और ट्रक के भी मालिक हैं। इसी प्रकार कस्बों में भी, अधिकांश जनसंख्या गरीबों की है। कस्बों और गांवों के हितों में आपस में टकराव का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु सामान्यतः कस्बे के शोषकों और जनता विशेषतः गांव के लोगों में संघर्ष है। लोगों के बीच यह अन्तर है, चाहे हम इसे पसन्द करें या नहीं। यदि आपसे यह प्रश्न किया जाए कि क्या हम इसे कम करना चाहते हैं, तो मेरा विचार यह है कि प्रत्येक का उत्तर 'हां' में होगा। तब नीति भी उसके अनुकूल होनी चाहिए।

इसी प्रकार जब आपने गेहूं का वितरण मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ाया तो यह स्वाभाविक ही है कि उसका प्रभाव अन्य मूल्यों पर भी पड़ेगा, चाहे थोक विक्रेता कितने ही ईमानदार क्यों न हों ? इस सन्दर्भ में सरकार की नीति इस प्रकार होनी चाहिए और वह इस प्रकार कार्य करे कि मूल्यों को कम किया जा सके और उन ताकतों पर अंकुश लगाएं जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं फिर से अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये मेरे मित्रों ने पहले ही कह दी हैं।

जब इसी सभा में थोक व्यापार का प्रश्न आया, तो मैंने अपने मित्र प्रो० मधु दण्डवते से पूछा कि क्या इससे खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि होगी। मैं सरकार से खाद्यान्न के थोक व्यापार को राष्ट्रीयकृत करने की आशा नहीं करता। हम इस सरकार का अपनी नीति के आधार पर समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि, हम ऐसा उनके चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर कर रहे हैं। अतः मूल्यों के सम्बन्ध में मैंने इनसे जोर देकर कड़े उपाय करने के लिए कहा है और यह भी जिक्र किया कि वे इस व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, आप जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की सहायता नहीं करते, सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए। यही एक उपाय किया जाना चाहिए। आपको थोक व्यापार को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने की नीति भी त्याग देनी चाहिए। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वह भी यही चाहते हैं। यह सभा के कार्यवाही वृत्तांत में मौजूद है ? क्या ऐसा कर दिया गया है ? कश्मीर से कन्याकुमारी अथवा मणीपुर से गुजरात तक, सारे देश में एक भी ऐसा थोक विक्रेता नहीं है जो बैंक-वित्त अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्त पर निर्भर न रहता हो। आप यह उपलब्ध करा दीजिए, फिर एक सप्ताह

के अन्दर देखेंगे कि भूल्य गिर आएंगे। देश के एक भी थोक विक्रेता को गिरफ्तार किए बगैर भी ऐसा किया जा सकता है। आप ऐसे कदम उठाए बगैर ही थोक बाजार से अपना रुपया वापस ले लीजिए। मैं खुदरा विक्रेताओं की बात नहीं कर रहा। आप थोक बाजार से अपना रुपया वापस ले लीजिए। आप कुछ समय, पन्द्रह दिन या एक महीना दें कि उन्होंने जो धनराशि ले रखी है, उसे ब्याज बगैर ही अदा कर दिया जाए। आप उन्हें ब्याज बगैर ही अपना रुपया अदा करने के लिए कहें और फिर बाजार पर इसका प्रभाव देखें। उन्हें अपना माल बाजार में लाना पड़ेगा। इससे काले धन में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको यह रुपया अदा करने के लिए उन्हें अपना माल बाजार में लाना पड़ेगा।

साठे जी इसका उल्लेख कर रहे थे और यह पूछ रहे थे कि इसका समाधान क्या है। यही समाधान है। इसे एक बार 1974 में आंशिक रूप में लागू किया गया था।

6.00 म० प०

सरसों के तेल का मूल्य 14 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होकर 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था जबकि इसे आंशिक रूप में लागू किया गया था। अतः मैं चाहता हूं कि प्रो० दण्डवते इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा।

पिछली सरकार की तरह ही यह सरकार सप्लाई तथा मांग और सप्लाई प्रबन्ध पर निर्भर है। श्री मिर्धा यह दावा कर रहे थे कि चीनी का उत्पादन बढ़ कर एक करोड़ टन हो गया है; खाद्यान्न उत्पादन 17 करोड़ टन हो गया है। इसके फलस्वरूप सप्लाई हो रही है। लेकिन, मांग में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य बढ़ गए हैं। क्यों? जमाखोर काले धन की मदद से बैंक के गोदामों में माल की जमाखोरी कर रहे हैं। उपभोक्ता गोदामों में नहीं जाते। वे असहाय रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अत्यन्त संक्षेप में बोलना है। आपने रुपए पर नियंत्रण तथा इसकी सप्लाई पर अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कही है।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं एक उपाय सुझा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अत्यन्त संक्षेप में बोलें।

श्री भोगेन्द्र झा : अतः मेरे विचार से यह नीत विफल रही है। सप्लाई तो है। मांग में वृद्धि नहीं हुई है और मूल्यों में वृद्धि हुई है। हमारे थोक व्यापार में एक प्रकार का गुट बन गया है। हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है। सीमेंट का उत्पादन कम करना होगा। मूल्यों में कमी आ सकती है। सीमेंट का उत्पादन बढ़ा तथा इसके मूल्यों में वृद्धि हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार की गुटबन्दी को तोड़ सकते हैं। मुझे डर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उनके आगे झुक गए हैं।

तेल संकट हमारे कारण नहीं आया है बल्कि और अधिक बुरे दिन आने वाले हैं।

माननीय युवा मंत्री महोदया यहां पर बैठी हैं। बिहार के चम्पारन जिले में पर्यावरण के नाम पर 17 वृक्षों को बचाने के लिए, गैस उत्पादन में देरी की गई। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने स्पष्टतः यह कहा कि वह 17000 पौधे लगाएगा। पारिस्थितिकी हठधर्मिता बन गई है। आप इस हठधर्मिता के नाम पर गैस का उत्पादन नहीं कर सकते। आप तेल की खोज के

कार्य को अनुमति नहीं देते। अतः मैं समझता हूं कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक ध्यान देना होगा।

लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसा कि हमारे मित्रों ने अनेक वस्तुओं का उल्लेख किया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम में सप्लाई की जानी चाहिएं। इसके लिए आपको भंडारण की जरूरत है। अतः वास्तविक मूल्य तथा जो कुछ लाभ औद्योगिक उत्पादकों को मिलता है, इन दोनों के आधार पर आपको माल मिलना चाहिए। थोक बाजार पर नियंत्रण सुनिश्चित कीजिए तथा नगरों, गांवों में अर्थात देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए आपको किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने चाहिएं तथा पहले ही अच्छी तरह सोच विचार कर मूल्यों की घोषणा होनी चाहिए ताकि वे उस मद का उत्पादन कर सकें। हमारा देश दलहन के मामले में भी आत्म-निर्भर बन सकता है। कृषकों को दिए गए मूल्य तथा वास्तविक उपभोक्ताओं से लिए जा रहे मूल्य के बीच अन्तर सीमित होना चाहिए और मेरे विचार से यह 20 प्रतिशत होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कृषकों को कम मिले और उपभोक्ताओं को ज्यादा अदा करना पड़े और बिचौलिए दोनों तरफ के लोगों को लूटते रहें। इस सम्बन्ध में एक सुसंगत नीति बनाई जाए।

इस बात पर खुश मत होइए कि अब चीनी के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है। इस समय बरसात का मौसम होने के कारण इसकी मांग नहीं है। बाद में इसमें वृद्धि हो जाएगी। अन्य मदों की भी ऐसी ही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा। श्री राजीव गांधी ने हमें मत देने की अपील की है। हम इस पर मत नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी नीति को उचित सिद्ध किया है। मैं श्री राजीव गांधी को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा कि इस नीति में कुछ गलत है। उन्होंने उन नीतियों को उचित ठहराया जो आज बुरी तरह विफल हो रही हैं। अतः हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हमें इस नीति के विरुद्ध मत देना है। लेकिन यह सरकार यह न समझे कि हम सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं···**(व्यवधान)**···हम कह रहे हैं कि या तो आप अपनी नीति को बदल कर लोगों के पक्ष में तथा शोषकों के विरुद्ध बनाइए अन्यथा लोग इसका खुला विरोध करेंगे। हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जनता तो खुलकर विरोध करेगी। वे संघर्ष करेंगे तथा प्रदर्शन करेंगे। वे यह सहन नहीं करेंगे कि वे उत्पादन करते हैं और फिर भी उन्हें अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ता है और बिचौलिये उन्हें लूटते हैं। यह चेतावनी है लेकिन फिर भी हम इस सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह सरकार गिरे। हम चाहते हैं कि यह सरकार पूरे पांच वर्ष की अवधि तक चले···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक लम्बी सूची है और सबको बोलने का अवसर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : हमें भी दो मिनट बोलने का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल बोलिएगा और जिस विषय पर आपको बोलना है, जमकर बोलिएगा ? आपको दूसरे ओकेजन्स में चांस देंगे। आपको अगर चांस दें तो चित्त बसु जी को, शीला कौल जी को क्यों न दें।

श्री राम कृष्ण यादव : कृपया दो मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समझिए मुझे टाइम देने में बड़ी खुशी होती है। आपको कल पूरा समय दिया जाएगा। आप बिना वजह ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह बहस न करें। माननीय वित्त मन्त्री, कृपया···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं उन्हें समय देता हूं तो मुझे दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वसंत साठे और अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर इस वाद-विवाद में भाग लिया। महोदय, मुझे सभा को यह बात कहने की अनुमति दी जाए कि विगत में कई बार कीमतों के सम्बन्ध में यहां स्थगन प्रस्ताव उठाये जाने पर सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि जब मूल्य वृद्धि की समस्या एक निरन्तर चलने वाली समस्या है तो उस मामले में इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि इसमें कुछ दम भी है लेकिन इसे नियम 193 के जरिए उठाया जा सकता है। महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस वक्त यह अनुमति मांगी गई थी, सरकार ने घोषणा की थी कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हम इसे एक ज्वलन्त समस्या मानते हैं और इसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ···(व्यवधान) मैंने स्वयं पांच बार इजाजत मांगी थी। यह व्यक्तिगत बात थी, अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री वसंत साठे ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

महोदय, यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सभा में उठाये गये प्रत्येक मुद्दे पर मैं ध्यान दूंगा। मैं मूल्य वृद्धि की इस ज्वलन्त समस्या को दबाना नहीं चाहता। आज जो समस्या है, मैं उसका विश्लेषण भी करना चाहता हूं और सरकार की ओर से मैं सभा को उन ठोस कदमों और उपायों के बारे में बताना चाहूंगा जिन्हें हमारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाने का विचार है कि बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। महोदय, मैं यह वेमन से नहीं कर रहा हूं बल्कि यह तथ्य सामने लाने के लिए कह रहा हूं कि यदि मूल्यों पर नियंत्रण रखना है तो यह मुख्य

रूप से देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने का प्रश्न है क्योंकि जब हम देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की बात करते हैं, तो जो वित्तीय अड़चनें अर्थव्यवस्था के आड़े आती हैं वे बहुत प्रासंगिक हैं। मैं इसे पुनः फलां-फनां की गलतियां निकालने की भावना से नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि किन वित्तीय अड़चनों के होते हुए हमने अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध संभाला। दिसंबर के शुरू में घाटा 13790 करोड़ रुपए था। विदेशी ऋण 83000 करोड़ रुपए का था, जिसमें अप्रवासी भारतीयों की जमा पूंजी भी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि ऋण का अनुपात 27 प्रतिशत था। तीसरे, 1989-90 के बजट में आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण पर कुल 17000 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान करना था। जब कतिपय वस्तुओं की कमी होती है और हमें बाध्य होकर आयात करना पड़े तो हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और विदेशी मुद्रा संसाधन होने चाहिएं। हमारे पास 5000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रह गयी थी जोकि दो महीने के लिए वस्तुओं का आयात करने के लिए भी कम है और सही मामने में डेढ़ महीने के लिए भी कम है। उस वक्त मुद्रा स्फीति की दर 8 प्रतिशत थी और खाद्यान्न भंडार 20 मिलियन टन से घट कर 11 मिलियन टन आ गया था। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि इस पृष्ठभूमि में हमें अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी थी। अब इस पृष्ठभूमि में तो समस्त सभा इस बात पर सहमत होगी कि यदि अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक मुद्रा स्फीति के दबाव को निरस्त करना है, तो पहली प्राथमिकता तो इस बात को देनी पड़ेगी कि हमारे बजट और अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे से दूर रहा जाये। महोदय, बजट पेश करने से पहले हमने अर्थशास्त्रियों और केंद्रीय मजदूर संघों, मौजूदा व्यापार संगठनों, महिला संगठनों, उपभोक्ताओं, लघु उद्योगों और व्यापारिक समूहों से परामर्श किया था और वे सब एक बात पर सहमत हुए थे कि हमें घाटे की अर्थव्यवस्था में सुधार करने को प्राथमिकता देनी होगी और इसी बात को हमने प्राथमिकता दी।

अब, एक अन्य पहलू भी है। कुछ अन्य अतिरिक्त अड़चनें भी थीं जिनका मैंने जिक्र किया है और यह प्रतिरक्षा व्यय है. अतः मैं नहीं चाहता हूं कि सभा इसे लापरवाही से ले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पक्ष के हैं लेकिन, हम सब देश की रक्षा के प्रति निष्ठावान और वचनबद्ध हैं। देश में सुरक्षा के माहौल की वजह से हम देखते हैं कि जहां पिछले बजट में प्रतिरक्षा व्यय 13,000 करोड़ रुपए था वहीं यह संशोधित आकलन के तहत 14,500 करोड़ रुपए हो गया और इस सुरक्षा के माहौल की वजह से मुझे मजबूरन इसे बजट में 15750 करोड़ रुपए करना पड़ा हमारे प्रतिरक्षा व्यय में इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि की गई। कुछ लोगों ने प्रश्न किये कि हम प्रतिरक्षा व्यय को कम कर सकते थे। किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रखते हुए मैं 1962 की बात पुनः याद दिलाना चाहूंगा। जब हमें नेफा में हार का सामना करना पड़ा था और देश के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर रक्षा मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा था, उस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष ने यही आलोचना की थी कि हमारी कोई रक्षा तैयारी नहीं थी और नेफा की हार के बाद वे सभी किताबें जो लिखी गयी थीं, में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि रुपए पैसे का हिसाब रखते हुए हमने देश के सुरक्षा माहौल का जायजा नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप हमें नेफा में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और उसके परिणामस्वरूप रक्षा मन्त्री को पद त्याग करना पड़ा। अतः, यह एक अन्य अड़चन है जिसके रहते हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना है। इस प्रकार, हमने उस घाटे को पूरा करने को प्राथमिकता देने का निश्चय किया है।

पिछले बजट में घाटा 7337 करोड़ रुपए का था और संशोधित आकलन के तहत यह 11750 करोड़ रुपए था तथा सभी के सहयोग से मैंने इसे 7206 करोड़ रुपये तक सीमित करने की कोशिश की है। अब लोग कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि घाटे को 7206 करोड़ रुपये तक बरकरार रखने पर आगे हम मुद्रा स्फीति को रोक सकेंगे······(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : राजस्व घाटे के बारे में क्या करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे परेशान न करें। मैंने आपको कभी भी इस तरह परेशान नहीं किया है।

श्री जनार्दन पुजारी : परन्तु मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया था···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसलिए, महोदय जहां तक घाटे की बात है, यह स्थिति थी—पहले 7,337 करोड़ रुपए, फिर 11,750 करोड़ रुपए और हमने इसे 7,206 करोड़ रुपए तक सीमित करने की कोशिश की। श्री साठे को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि सभा यह वैधानिक प्रश्न कर सकती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि हम इस घाटे को इस स्तर पर बनाए रखेंगे। अतः, मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि हर चार महीने में हम सभा के समक्ष आयेंगे और राजस्व एकत्र करने और व्यय को कम करने के अपने प्रयत्नों को आपके सामने रखेंगे। वित्त मन्त्रालय में हम यह हर महीने कर रहे हैं और सभा में मैं इस मानसून सत्र में पहले चार महीने की रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा।

मेरे मित्र श्री साठे ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उन्होंने एक आर्थिक पत्रिका को उद्धृत किया था और कहा था कि पिछले महीने की तुलना में, पिछले वर्ष इसी समय घाटा 9000 करोड़ रुपए था जो अब निःसंदेह कम हो गया है। यह 7400 करोड़ रुपए या इसके लगभग था। लेकिन फिर इसके और अधिक होने का अनुमान था। अब ऐसी आम भ्रांति है कि यदि घाटा दो महीने या तीन महीने के बाद बढ़ जाता है तो अन्ततः वित्तीय वर्ष के अन्त में अन्तिम घाटा निश्चित रूप से उससे ज्यादा हो जाएगा। यदि आप विभिन्न घाटों का, जिनमें महीनेवार वृद्धि या कमी आई है, दस वर्षीय ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि इस घाटे में आमतौर पर यह प्रवृत्ति रही है कि शुरू में इनमें कोई राशि एकत्र नहीं होती है। व्यय होना शुरू हो जाता है तथा घाटा बढ़ जाता है। और जब हम विभिन्न राज्यों को उनका शेयर देना शुरू करते हैं तो यह एक निश्चित समय में एक निश्चित उच्चतम बिन्दु पर पहुंच जाता है और फिर एक प्रकार से घाटे की निरन्तरता की स्थिति आ जाती है या यह बढ़ता और घटता रहता है। बाद में जब लगभग सभी व्यय खत्म हो जाते हैं, राज्यों के शेयर पहले ही पूरे हो चुके होते हैं और अन्तिम चरण में हमें राजस्व मिलता है परन्तु यहां व्यय कम होने से पुनः आप देखेंगे कि घाटा नीचे आने लगता है। यदि हमें अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करना है, हो सकता है यह 7206 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा जाए। मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि घाटा 7206 करोड़ रुपए तक बना रहे। अब चूंकि यह 7400 करोड़ रुपए हो गया है अतः इसका मतलब यह नहीं है कि आगे घाटे और अधिक जायेंगे। हमेशा यही प्रवृत्ति रही है और पिछले दस वर्षों में घाटे की यही प्रवृत्ति रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

जहां तक संसाधनों का संबंध है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। बजट चर्चा

का उत्तर देते हुए मैंने यह बात काफी स्पष्ट की थी। हमारी योजना यही रहती है कि यदि घाटे कम करने हैं तो व्यय कम करना होगा और राजस्व को बढ़ाना होगा। तभी हम संसाधन जुटा सकेंगे। और जब हमें संसाधन बढ़ाने होते हैं तो हम सारे समाज पर कर लगाने की बजाय उन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जो अमीर लोगों के उपयोग की होती हैं। हम उन करों में संशोधन करने की कोशिश करेंगे जो अमीर लोग देते हैं, अमीर वर्ग और बड़ी पूंजी निवेश वाली कम्पनियां देती हैं और इस तरह इन लोगों को कर के दायरे में लाया जाता है, क्योंकि पहले निवेश की घोषणा करने, अन्य सुविधाओं और प्रोत्साहनों की वजह से इन पर लगभग नगण्य कर लगता था और ये कर से पूरी तरह बच जाते थे और अब ये अमीर वर्ग भी कर का भुगतान करेंगे। हम निगमित कराधान के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछली बार यह राशि शून्य थी। इस बार यह 800 करोड़ रुपए होने जा रही है और हम इन संसाधनों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तिमाही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बहुत प्रसन्नता है जोकि आपके समक्ष आ जायेगी। परन्तु जहां तक व्यय का संबंध है श्री साठे को प्रसन्नता होगी कि एक के बाद एक हम गणना कर रहे हैं और ये हमारे प्रयत्न हैं। हम व्यय को कम कर पाये हैं। राजस्व में अभी और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि जहां तक संभव हो सके, घाटे को कम से कम रखा जाए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, अन्ततः बजट लक्ष्य ही परिलक्षित हुआ था तथा पैसे की बाजार में ज्यादा सप्लाई और घाटे से ही अन्ततः यह निश्चित होगा कि कितनी बढ़ोतरी होगी। जहां तक मुद्रा स्फीति की बात है, मैं श्री जसवन्त सिंह की बात दोहराना नहीं चाहता हूं। ये असंतुलन, घाटे और अन्य वजहों से हैं और बाहर से पैदा किए असंतुलनों के कारण हैं, कतिपय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आने से हैं, तीसरे, पिछले बकाया कर्ज को चुकाने की वजह से हैं। ये मुख्य संसाधन हैं और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन संसाधनों को समुचित ढंग से जुटाया जाए।

जहां तक धन की सप्लाई की बात है, श्री साठे ठीक ही कह रहे थे कि धन की सप्लाई बढ़कर 19.1 प्रतिशत हो गई है। परन्तु यह 1989-90 के लिए था और मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जहां तक प्रथम तीन महीनों में धन की सप्लाई में वृद्धि का संबंध है, इस तिमाही में पिछले वर्ष की 5.8 प्रतिशत धन सप्लाई की तुलना में वृद्धि 4 प्रतिशत है और ऐसा नहीं है कि हमने पिछले वर्ष की वृद्धि की पूरी भरपाई कर दी है और हम अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि धन की सप्लाई में वृद्धि, जिसके बारे में श्री जसवंत सिंह और श्री साठे ने तथा अन्य सदस्यों ने जिक्र किया है, का हम ध्यान रख सकें।

श्री वसन्त साठे : पहली तिमाही में यह कितना थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : पहली तिमाही में यह 4 प्रतिशत है और पिछली बार यह 5.8 प्रतिशत थी। यह एक मान्य परम्परा है कि हम एक जैसे आंकड़ों से तुलना करते हैं। इसलिए पिछली बार यह 5.8 प्रतिशत थी और अब यह 4 प्रतिशत है। मैं तो वर्ष की समाप्ति पर इस प्रतिशतता में भिन्नता का जिक्र कर रहा था। मैं विपक्ष के नेता से जब वह बोल रहे हों तो यह चर्चा करना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि इस परिणामों से मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं ? लेकिन जब हम ऐसी स्थिति प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हों जोकि धुंधली हो—जैसे कि पिछली तस्वीर बहुत बेहतर थी—तो हमें दो धुंधली तस्वीरों की तुलना करनी पड़ती है न कि एक

साफ और दूसरी धुंधली की। सभी दस्तावेजों से ये आंकड़े उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए हमने हाल के यानी 21 जुलाई, 1990 के उपलब्ध आंकड़े लिए हैं और वार्षिक परिवर्तन की दर की गणना करने के लिए हम 22 जुलाई, 1989 के आंकड़े लेंगे।

जहां तक खाद्यान्नों, अनाज और दालों की बात है इस समय यह 4.2 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख में यह 4.4 प्रतिशत थी। अनाज के लिए इस समय यह 3 प्रतिशत है और पिछले वर्ष यह 4.6 प्रतिशत थी। निःसंदेह दोनों में वृद्धि हुई है। जहां तक सब्जियों की बात है, इस बार यह 18.3 प्रतिशत है तथा पिछली बार यह 25.6 प्रतिशत थी। चाय के लिए यह इस समय 18.8 प्रतिशत है, पिछले वर्ष 44.1 प्रतिशत थी। निर्मित खाद्य उत्पादों के लिए इस वक्त यह 8.8 प्रतिशत है, पिछली बार यह 9.6 प्रतिशत थी। चीनी के मामले में इस समय (—)0.2 प्रतिशत है और पिछली बार इसमें (+) 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि श्री साठे को स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार होगा और मैं सोचता हूं वह मुद्दों का ध्यान रखेंगे······

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : यह सब काल्पनिक नौकरशाहों का कार्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, बिल्कुल नहीं। यह काल्पनिक नौकरशाहों का कार्य नहीं है। मैंने भी इसकी गणना की है। मैंने अपने हाथ से ये आंकड़े नोट किए हैं।

और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इन बातों के लिए मधु दण्डवते को नौकरशाहों की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं जैसे कि मैं आज कर रहा हूं। (व्यवधान) यहां तक कि आपकी भी कीमत बढ़ी है। मैं इसे एक अच्छी भावना में कह रहा हूं।

खांडसारी इस समय (—) 3 प्रतिशत है, पिछली बार यह 24.3 प्रतिशत थी। नमक में इस बार 8.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, पिछली बार यह यह 17.9 प्रतिशत थी। कपड़ा इस बार 8.4 प्रतिशत और पिछली बार 10.3 प्रतिशत थी। मैं इन परिणामों से भी प्रसन्न नहीं हूं। जैसे कि मैंने एक बार कहा था, यदि मेरा प्रदर्शन और परीक्षा असफल रहती है तो मैं खुश नहीं रह सकता हूं क्योंकि मैं असफल रहने वालों में प्रथम होऊंगा। मैं इससे संतुष्ट बिलकुल नहीं हूं। हम स्थिति में और आगे सुधार करना चाहते हैं। यह स्थिति है।

जहां तक चल निधि आधिक्य की बात है, जिसका श्री साठे ने जिक्र किया है, निःसंदेह यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और हमने वैधानिक चल निधि अनुपात को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत कर दिया है। मुझे आशा है कि इससे हमें कुछ लाभ होगा।

कई व्यक्तियों ने एक प्रश्न उठाया था और मैं समझता हूं कि जसवन्त सिंह जी ने बहुत लाक्षणिक तरीके से कहा था कि ऐसा क्यों है कि आपने केवल उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक का ही जिक्र किया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नहीं ? और उन्होंने कहा था कि इनमें एक यदि सुन्दर स्त्री है और तो दूसरी पत्नी है। मैं ऐसी सादृश्य बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं सुन्दर महिला और पत्नी के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। उन्होंने थोक मूल्य सूचकांक की तुलना एक सुन्दर स्त्री से की थी और पूछा था कि आप उस बात का सहारा क्यों लेते हैं ? अच्छा होगा कि आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें। और उन्होंने इसे पत्नी कहा। मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक थोक मूल्य सूचकांक की बात है, सावधिक

परिवर्तन भी समय-समय पर उपलब्ध होते रहते हैं, जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात है, सभी शहरी, ग्रामीण और विभिन्न वर्गों के लिए और भिन्न अवधियों के लिए यह आसानी से उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि दुर्भाग्य से हमें थोक मूल्य सूचकांक का सहारा लेना पड़ता है लेकिन मैं सभी सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध होते हैं तो फिर स्थिति का अच्छी तरह से पता चल सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा······

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलिकारा) : अब पत्नी को छोड़कर सुन्दर स्त्री के पीछे जाना क्या बेहतर है ?

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। यह तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में है। विजय कुमारी ने इसका जिक्र किया था, जसवन्त सिंह जी ने जिक्र किया था और श्री भोगेन्द्र झा तथा श्री साठे, अपने इसका जिक्र किया था। और हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा विपक्ष के नेता ने भी इसका उल्लेख किया था। वे ठीक कह रहे थे। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, इनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि से हमारी परिवहन लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आवश्यक है। परन्तु मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि मैंने गणना के मुताबिक जो संभावित वृद्धि थी और जो वास्तव में हुई है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। उदाहरण के लिए पैट्रोल की कीमतों में 15 प्रतिशत डीजल की कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि आप इसके मुताबिक गणना करें तो इस पैट्रोल मूल्य सूचकांक का एक तिहाई तो परिवहन लागत की वृद्धि में चला जाएगा और इस प्रकार परिवहन लागत 5 प्रतिशत बढ़ेगी और उस 5 प्रतिशत का 10 प्रतिशत वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि में परिलक्षित होगा और 5 प्रतिशत के लगभग 10 प्रतिशत का मतलब है केवल आधा प्रतिशत। लेकिन जैसा कि भोगेन्द्र झा ने उचित ही कहा है, अधिकांश व्यापारी, व्यवसायी अथवा कोई उद्यमी जब यह देखते हैं कि उनके उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए आवश्यक साधनों के मूल्य बढ़ गए हैं तो वे इस संबंध में गणितीय गणना नहीं करते, बढ़े मूल्यों के अनुसार ही मूल्य बढ़ा देते हैं, लेकिन वे आधुनिक गणित जानते हैं और उन्हें गुणक तत्व का ज्ञान है और यदि वृद्धि आधा प्रतिशत ही है तब भी यह 5 प्रतिशत हो जाती है और इसलिए उन्होंने इस वृद्धि का बहाना लेकर मूल्य और अधिक बढ़ा दिए हैं और श्री साठे का यह विश्लेषण बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल तथा डीजल की इस वृद्धि से उन्होंने भी अनेक वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सम्मुख कुछ मजबूरियां थीं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बजट मे घाटा न्यूनतम हो। इसीलिए हमने अधिक पूंजी वाली कंपनियों पर ही कार्यवाही की। हमने सम्पन्न वर्ग समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली विलासिता की वस्तुओं पर कर का भार बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बजट घाटा आवश्यक सीमा तक नहीं रखा जा सकता, इसलिए न चाहते हुए भी बजट घाटे को कम करने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल पर कर लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा, मैं इस कार्यवाही के परिणामों को जानता हूं। निःसन्देह ऐसा करते समय मैंने कुछ चुनिंदा उत्पाद ही लिए। हमने उर्वरकों में प्रयुक्त होने वाले नेफ्था पर वृद्धि कम करने का प्रयास किया। हमने यह प्रयास भी किया कि मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल और गैस तथा खाने पकाने की गैस में वृद्धि न की जाए। इसके बावजूद भी मैं पूर्णतया सहमत हूं कि बाकी उत्पादों पर जो वृद्धि हुई उसके कारण निश्चित रूप से मूल्यों में वृद्धि हुई और हमें यह सुनिश्चित करना था कि इस विशेष प्रभाव को निष्प्रभावी किया जाए। आपमें से हरेक ने इसकी

आलोचना की है। मैं इस आलोचना को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। चूंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था इसीलिए हमें यह अरुचिकर कार्य करना पड़ा। स्थगन प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य तथा अंतिम वक्ता विजय कुमार जी सहित आप सबने कहा था कि जब आप पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करते हैं तो आपको इनके उत्पादों में वृद्धि करनी पड़ेगी, इसके लिए विशेष क्षण आ रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : इसके लिए आपने क्या तरीका निकाला है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह तरीका निकालेंगे कि इसे किस प्रकार निष्प्रभावी किया जाए। मैं इसका उल्लेख करूंगा। जहां तक इस विशेष वृद्धि का लाभ उठाने वालों का संबंध है जिन्होंने मूल्य बढ़ाए हैं तो हमारा यह अनुभव है कि यदि हम इस वृद्धि को समाप्त कर दें तो भी वे पहले के मूल्य लागू नहीं करेंगे। फिर, जहां तक तत्काल उपाय करने का संबंध है, मैं आपको कुछ पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए चीनी को लीजिए। यह एक तथ्य है कि गत वर्ष जब चीनी का उत्पादन 92 लाख टन से कम होकर 87 लाख टन रह गया था तब आपके शासन के दौरान उत्पादन में कमी के फलस्वरूप चीनी के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई थी। हमने अपने शासन के दौरान यूनियनों, उद्योगपतियों से बातचीत की और चीनी उद्योग में कार्यरत यूनियनों को कहा कि उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। सौभाग्यवश हमारा अनुमान था कि चीनी उत्पादन 105 से 107 लाख टन होगा। हमें खुशी है कि उत्पादन लगभग 110 लाख टन हुआ है और इसके फलस्वरूप हम चीनी के मूल्यों को बहुत कम नहीं कर सके हैं लेकिन हम उन्हें बढ़ने से रोकने में सफल हुए हैं। हमें सावधान रहना है। हमें 1977 की गलती से बचना है। हमें चीनी के मूल्यों को इतना ज्यादा नहीं गिरने देना है कि गन्ना उत्पादक और किसान उचित मूल्य ही प्राप्त न कर सकें और यदि वे लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहेंगे तो वास्तव में वे अपना गन्ना जला देंगे और उसके बाद लाभप्रद मूल्य न दिलाने के लिए उत्तरदायी हमको जला देंगे। अतः दोनों के बीच एक सन्तुलन कायम करना है। फिर, जहां तक चाय का संबंध है, मैंने पहले-पहले भी कहा है, मैंने आपको आश्वासन दिया था और हमने इसे पूरा किया है। पहली सरकार ने एक समझौता किया था कि सोवियत संघ को चाय का निर्यात किया जाएगा, मैं इस बारे में उन पर आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि ये मित्र देशों के प्रति हमारे दायित्व हैं। हमारे भी बहुत अच्छे संबंध हैं और हमने इन संबंधों को बनाए रखा है। हमने उन्हें बताया कि हमारे सम्मुख कुछ कठिनाइयां हैं; इस बार चाय की फसल कम हुई है और इसलिए इसका निर्यात घटाने दें। हमने ऐसा ही किया और इसके फलस्वरूप चाय का मूल्य स्थिर हो गया है। ये मूल्य कुछ हद तक कम हुए हैं।

नमक के संबंध में मैंने पिछली बार कहा था कि कुछ सदस्यों ने मुझे अनुरोध किया था कि मैं इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की जांच कराऊं कि नमक के आयोडीनीकरण के कारण नमक की कीमत बढ़ गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आयोडीनीकरण के कारण नमक की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इस वृद्धि का कारण कुछ और ही है। यदि आप एक टन नमक का आयोडीनीकरण करें तो वास्तव में इस पर 40 से 42 रुपए प्रति टन का खर्चा होता है। हम इस कार्य पर 20 से 22 रुपए प्रति टन राज-सहायता देते हैं। यदि आप इस संबंध में गणना करें तो देखेंगे कि आयोडीनीकरण के कारण नमक के मूल्य में वृद्धि केवल दो या तीन पैसे प्रति किलो-

ग्राम ही होगी। लेकिन इस संबंध में गड़बड़ी कहां हुई ? हमने पाया कि इसके परिवहन में कुछ कठिनाइयां हैं। हमने रेल मंत्रालय से सम्पर्क किया। प्रारम्भिक कठिनाई यह थी कि रेलवे ने कुछ प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। यदि आप नमक उत्पादन संयंत्र से नमक प्राप्ति के स्थान तक नमक ले जाना चाहते हैं तो आपके पास नमक की मात्रा इतनी हो कि पूरी रेक भर जाए, तभी सभी वैगन भरे जाएंगे। इसके कारण उन्हें नमक के लदान हेतु इन्तजार करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वैगनों द्वारा हुई आय बदल गई। इसके फलस्वरूप प्राप्ति केन्द्रों को नमक प्राप्त हुआ। हमने इस मामले को निपटा लिया है। आपको इस संबंध में एक और पहलू पर गौर करना है। गावों में अनेक स्थानों पर खूबसूरत थैलियों में बन्द नमक की बजाय इसके ढेर लगे होते हैं जो बहुत सस्ता होता है और यदि आप खूबसूरत थैलियों का आग्रह करेंगे तो इससे नमक की कीमत महंगी होगी। हमने इस संबंध में हिदायतें दी हैं कि जो बगैर थैली नमक चाहते हैं उन्हें ऐसा ही दिया जाए, थैली में बन्द करने पर जोर न दिया जाए। ऐसी स्थिति में बिना पैकेट वाला नमक 80 पैसे से लेकर 1 रुपए किलो तक उपलब्ध होगा। निःसंदेह दुर्भाग्य से पैकेज के कारण इसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी कारण हम नमक की समस्या का समाधाना करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, प्रधानमंत्री ने इस बारे में सही कहा है। हमने सीमेंट उद्योग से यह समझौता किया था कि वे सीमेंट के मूल्य मार्च के स्तर तक लाने का प्रयास करें। कुछ समय बाद, आमतौर पर इसके मूल्यों में कमी आई। लेकिन इसके बाद हमने पता लगाया और पाया कि कुछ संयंत्रों में खराबी आ गई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे खराब संयंत्रों को ठीक करेंगे। अब, दो या तीन क्षेत्रों में सीमेंट के मूल्य कम होकर मार्च के स्तर तक आ गए हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसके मूल्य बढ़े हैं। विपक्ष के नेता ने यह कहकर मजाक उड़ाया : कीमत कम हुई और फिर अधिक हो गई। आपके मजाक को छोड़िए, हमने आपकी आलोचना को स्वीकारा है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो सीमेंट संयंत्र खराब हो गए हैं उन्हें ठीक किया जाए। हम सुनिश्चित करेंगे कि न सिर्फ दो क्षेत्रों बल्कि सभी क्षेत्रों में सीमेंट कम मूल्य पर उपलब्ध हो। (व्यवधान)

कल यह खबर आई है कि कुछ गुटों ने इस संबंध में एक संघ बना रखा है। हम संघ के संबंध में बहुत सख्त रवैया अपनाएंगे और इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

लेकिन केवल एक मद ने हमें तथा देश को कठिनाई में डाल दिया है। यह मद खाद्य तेल है। मैं विनम्रता से यह स्वीकार करता हूं कि हम अभी तक खाद्य तेल के मूल्य नियंत्रित करने में बुरी तरह असफल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश तिलहन का उत्पादन कम हुआ है। हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह दीर्घकालीन उपाय है। लेकिन फिलहाल लोग क्या करेंगे ? हमने कुछ इन्तजाम किए हैं। हमने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से बात की है, हमने डा० कुरियन से बात की और एक व्यवस्था की है। कुछ देशों के पास काफी मात्रा में दूध के पैकेट अनबिके रखे हैं। मुझसे इन देशों के नाम न पूछें। हमने कुछ इन्तजाम किए हैं। इन दूध के पैकेटों को उन्हें दिया जाएगा। इसके बदले कुछ विदेशी मुद्रा मिलेगी। हम विदेशी मुद्रा लेने की बजाय पामोलीन तेल यहां पर लाएंगे। प्रारम्भ में हमारी योजना थी कि प्रधानमंत्री की हिदायतों के अनुसार हम यह तेल लाएंगे, इसे परम्परागत तेल के साथ मिलाकर, शोधन करके इसे सस्ते मूल्य पर बेचेंगे। सौभाग्यवश हमें यह नई सूचना मिली है कि हमें शुद्ध किया हुआ पामोलीन तेल मिलेगा जिसे हम सीधे ही

बेचेंगे। हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि त्यौहारों के मौसम से पहले सस्ते किस्म का तेल उपलब्ध कराया जाए। निःसंदेह, कभी-कभी स्वाद के साथ समझौता करना पड़ता है।

मैं समझता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में जब उत्पादन कम हुआ हो तो हमें अपनी खाने-पीने की आदतें बदल लेनी चाहिए और हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। (व्यवधान) आप इस पर हसेंगे। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब मिटटी के तेल और पैट्रोल में काफी अन्तर था, तो बहुत से देशों ने मिट्टी के तेल का प्रयोग करने की कोशिश की और इस उद्देश्य से कुछ परिवर्तन भी किए गए। इतना ही नहीं बल्कि मैं 1965 का हवाला भी देना चाहूंगा जब प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी : "क्योंकि हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें अपने खाने-पीने की आदतों को बदलना होगा और इसकी शुरूआत मैं भी करूंगा और मैं सारे राष्ट्र से भी यह निवेदन करता हूं कि जब तक वर्तमान सुरक्षा वातावरण जारी है, तब तक हम शाम को उपवास करें।" बहुत से लोगों ने इसका पालन किया। जब हम अपनी खाने-पीने की आदतों में परिवर्तन की बात करते हैं तो इसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। (व्यवधान)

हममें से जो लोग जेलों में रहे उन्हें अपने खाने-पीने की आदतों को बदलना पड़ा क्योंकि जो कुछ भी खाने को दिया जाता था, हमें खाना ही पड़ता था।

श्री योगेन्द्र झा ने एक बहुत ही अच्छा तथा रचनात्मक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि व्यापारी तथा उद्योगपति वस्तुओं की जमाखोरी के लिए जिम्मेवार हैं और जमाखोरी के कारण कीमतों में कृत्रिम वृद्धि होती है। ऐसे मामलों में उनका सुझाव यह है कि हमें आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने संबंधी अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए बेशक इसको लागू करना राज्य सरकार का कार्य है। हम अपनी गतिविधियों में उनसे सहयोग कर रहे हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् 914 जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इसके लिए हम अपनी मशीनरी को और सुदृढ़ बनायेंगे और मैं सभी स्वार्थी तत्वों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने जमाखोरी करने की कोशिश की तो राज्य सरकार के सहयोग से उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी और चाहे राज्य कांग्रेस की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, सभी राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में सहयोग करने को तैयार हैं। उनकी सहायता से हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजीव गांधी ने कुछ आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत की ऋण दर कम हो गई है। मैं तथ्यों को स्पष्ट रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। 1985 और 1990 की घटनाओं के परिणामस्वरूप ऋण देने के मामले में हमारे ऊपर निगरानी रखी गई। मेरे पास तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध हैं। इसका सबसे पहला कारण निरन्तर आर्थिक घाटा था जिसकी पूर्ति आन्तरिक ऋण से की गई और इससे ऋण बढ़ गया। दूसरे वह बढ़ता हुआ आर्थिक घाटा है जिसकी पूर्ति विदेशों से ऋण लेकर की गई। उससे भी कुछ समस्यायें उत्पन्न हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप बढ़ते हुए ऋण पर नजर रखी जा रही है। परन्तु मैं विपक्ष के एक सदस्य से सहमत हूं कि जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमारा कर्जा अधिक हो सकता है। 31 मार्च, 1989 को यह राशि 83,000 करोड़ रुपए थी। अब यह राशि 100,000 करोड़ रुपए है।

ऋण सेवाओं के अनुपात की दर 30 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना निर्यात हम करते हैं उसकी आमदनी का एक तिहाई भाग भारत के कल्याण और विकास पर खर्च न होकर के ब्याज देने में चला जाता है। चाहे हमारी सरकार है या आपकी, इसके बावजूद, हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि इतनी बड़ी राशि के कर्ज के बावजूद हम कभी भी दूसरे ऐसे देशों की तरह अपने वायदों से फिरे नहीं जिसके ऊपर कुल कर्जे का लगभग 75 प्रतिशत है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम पर केवल 20 प्रतिशत ऋण है। मैं इस पर भी प्रसन्न नहीं हूं और हमें इसे कम करना होगा। मैं इस पहलू पर जोर देना चाहूंगा।

श्री राजीव गांधी ने एक और आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नई सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या किया गया। उनका कहना है कि दिसम्बर, 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई तब से लेकर जुलाई, 1990 तक थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है। यह सच है। सितम्बर और दिसम्बर, 1989 के दौरान कीमतों में कुछ हद तक गिरावट आई थी। यह सच है और आप सच कह रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को आदर देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सितम्बर तथा दिसम्बर, 1989 के दौरान का समय खरीफ की फसल का समय है और इस दौरान हमेशा ही कीमतें गिरती हैं। जनवरी तथा अगस्त, 1989 के दौरान कीमतों में 60 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई। 1990 में जो परिस्थिति रही, यह उससे कोई बहुत अधिक मिल नहीं है। कुछ एक आर्थिक नियम हैं। चाहे प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हों या श्री राजीव गांधी, आर्थिक नियम नहीं बदलते। यह नियमों के समक्ष समानता की बात है और, इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है तो इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मैं इन दोनों में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहता। मैं तथ्यों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि यही राष्ट्र हित में है। एक प्रकार का डर पैदा किया जा रहा है कि कुवैत में युद्ध चल रहा है। "ओपेक" ने मूल्यों में कुछ वृद्धि की है; जिसके परिणामस्वरूप स्थिति बहुत ही भयानक रूप धारण करने वाली है। हमारा यह अनुमान था कि हम पर्याप्त आपात नहीं कर पायेंगे तथा इसलिए हमने ऐसी गलती नहीं की। फिर मैं चाहता हूं कि हम पर कोई दोषारोपण नहीं हो क्योंकि क्योंकि "कुओं तेल समझौते" के सम्बध में बनी सर्वदलीय लोक लेखा समिति ने कुछ टिप्पणियां की हैं। श्री के० पी० उन्नीकृष्णन वहां पर उपस्थित हैं। यह समिति जिसमें कांग्रेस दल के सदस्य भी शामिल थे, इसकी सर्वसम्मत टिप्पणियां हमें दिशा निर्देश प्रदान करेंगी। कुओं तेल समझौता होने के समय उन्होंने कहा कि "जब वास्तव में सिंगापुर में तत्काल मूल्यों में गिरावट आ रही थी तो उस समय यह सौदा अधिक मूल्य पर किया गया।" उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि :

> "समिति की समझ में यह नहीं आया कि इस प्रकार का सौदा करते समय सरकार ने किस सूझबूझ से काम लिया।"

और, इसलिए, पिछली सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में हम गिरती हुई कीमतों का ध्यान रखेंगे ओर उस समय आयात और खरीदारी करेंगे जब हमारा आयात बिल जारी होगा। इस मुद्दे को सामने रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष में रह कर हमने जो कुछ किया, वह हमें इस समय सहायता कर रहा है जबकि हम सत्ता में हैं। हमने देखा कि जब हमें तेल खरीदना हो, तो कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बिल की राशि बढ़ सकती है, इसलिए, पूरी सावधानी से हमने उस समय अधिक तेल खरीदा जबकि पेट्रोलियम की कीमत बहुत कम थी। हमारे

भण्डार भरे हुए थे। इसलिए कुवैत में चाहे जो भी हुआ हो आप इस बात से आश्वस्त रहें कि अभी तक इससे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तथा आप भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भय पैदा करने का प्रयत्न मत कीजिए। उनको लाभ पहुंचाने का प्रयत्न मत कीजिए जो हमें पेट्रोल भेज रहे हैं। भय का वातावरण मत बनाइए। किसी को हतोत्साहित मत कीजिए। हमारा यह अनुमान था कि कीमतों में कुछ परिवर्तन होगा परन्तु इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हमारा यह अनुमान था कि कुछ दूसरे कारणों से कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए हमने समझदारी से काम लेते हुए अपने भण्डार पूरी तरह भर कर रखे। इसलिए इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक कुवैत में हो रही घटनाओं का हम पर प्रभाव का सम्बन्ध है तो हमें उन पर नजर रखनी होगी कि इनका हम पर क्या प्रभाव हो सकता है। परन्तु हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि हम इन घटनाओं के कारण घबराएं नहीं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं।

महोदय, कभी-कभी हमारा आपस में टकराव होता है। जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ-साथ होंगे, वहां टकराव होना स्वाभाविक है। मैं आप पर दोषारोपण नहीं करना चाहता क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तो हम भी मुद्दों को पूरे ज़ोर-शोर से उठाते थे। वास्तव में विपक्ष का काम ही विरोध करना तथा सरकार की कमजोरियों का पर्दाफाश करना है। जब भी सत्ता दल द्वारा अथवा किसी और द्वारा कोई गलती की जाती है अथवा किसी सरकारी नीति में कोई कमी रह जाती है तो सजग विपक्ष का यह कार्य है कि वह इसे सरकार की जानकारी में लाए। परन्तु मेरी शिकायत यह है कि आप हमें पर्याप्त समय नहीं देते। 13 नोटिस देने के लिए चाहे आप जितनी भी मेहनत प्रतिदिन करते हैं परन्तु उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। परन्तु इस जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। परन्तु मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, आयात और जमाखोरों के सम्बन्ध में तथा राजनीतिक प्रतिबन्धों को समाप्त करने के बारे में और अनुमत भण्डार से अधिक जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में हमें दोनों पक्षों से रचनात्मक समाधान तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम इन सभी सुझावों का ध्यान रखेंगे चाहे वे विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा दिए गए हों अथवा सत्ता पक्ष या उसके समर्थक दलों के सदस्यों द्वारा।

मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं किसी पर कोई दोष लगाना नहीं चाहता। परन्तु विपक्ष के मेरे एक मित्र जब बोल रहे थे तो मैंने केवल इतना निवेदन किया था कि अगर मैंने या मेरी सरकार ने कोई नीतिगत गलती की है तो आप मेरी या मेरी सरकार की आलोचना कीजिए। परन्तु उन पर प्रहार मत कीजिए जो सरकार से बाहर रहकर हमारा समर्थन कर रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर प्रहार मत कीजिए। (व्यवधान) इसके लिए आपको पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। कृपया, इस समय ऐसा मत कीजिए। मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है मैंने केवल इतना कहा है कि हम अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : हमें आपसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। हम आपका समर्थन करेंगे। आपकी नीतियों के लिए भी हम जबावदेह हैं। नैतिक जिम्मेवारी हमारी भी है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है। मैं अति प्रसन्न हूं कि श्री भोगेन्द्र झा ने अच्छी भावना से यह कहा है कि "यद्यपि हम आपका समर्थन बाहर से कर रहे हैं, फिर भी आप जो भी करते हैं उसकी जवाबदेही में हम भी सहभागी हैं।" इसलिए यह बात उन्होंने मित्रतापूर्वक तरीके से कह डाली है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मित्रतापूर्वक हो या शत्रुतापूर्वक, मैं विपक्ष को शत्रु नहीं मानता चूंकि आप कभी विपक्ष में तो कभी सत्ता में भी हो सकते हैं। विपक्ष देश का दुश्मन नहीं है। वे देश के मित्र हैं, वे लोकतंत्र के मित्र हैं चूंकि सत्ता पक्ष की असफलताओं को वही उजागर करते हैं। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लाने के लिए श्री साठे को बधाई देता हूं। मैंने यह आश्वासन दिया है कि जो भी रचनात्मक सलाह दी जाएगी हम उस पर विचार करेंगें और उसे लागू करने का तथा बढ़ती महंगाई को रोकने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। मेरा आपसे अंतिम निवेदन यह है कि उन सभी मुद्दों को जिन्हें वह सदन की जानकारी में लाना चाहते थे, श्री साठे से मेरा निवेदन है कि वे स्थगन प्रस्ताव पर दबाव न डालें और इसके बावजूद भी यदि वे स्थगन प्रस्ताव पर दबाव डालना ही चाहते हैं, तो सभा से मेरा निवेदन है कि उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति के लिए नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। यदि आप अभी कोई मुद्दा उठाते हैं, तो उन्हें फिर जवाब देना होगा और फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। आप कृपया मुझे अनुमति दें। उन्होंने सभा को गुमराह किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री साठे से कहें, वह करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आप कृपया मुझे अनुमति दें। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि विगत 42 वर्षों में राजस्व घाटा, उनके बजट में अधिकतम रहा है··· (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं। आप यह श्री साठे को दे दें और वह ही इसे करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने सभा को गुमराह किया है।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। श्री साठे अब आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने यह सोचा था कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा के अंत में माननीय वित्त मंत्री से यह आशंका की थी कि निकट भविष्य में मूल्यों में कमी लाने का वह कोई आश्वासन देंगे। लेकिन, अपने पूरे भाषण में उन्होंने क्षमा मांगी है और अंत तक वह इस बात को उचित और न्यायसंगत ठहराते रहे कि आर्थिक नियम सबके लिए समान हैं, चाहे कोई भी प्रधान मन्त्री हो तथा कोई भी सरकार हो, यह तो चलेगा ही। आपने चुनाव के दौरान हमारी आलोचना करते समय क्यों नहीं सोचा कि आर्थिक नियमों के तहत ही हमें मूल्य वृद्धि करनी पड़ी थी। आपने आर्थिक नियमों के बारे में क्यों नहीं सोचा था जबकि जनवरी से हर महीने लगातार आपने और आपसे संकेत पाकर प्रधान मन्त्री ने भी आश्वासन देना शुरू कर दिया था कि तीन महीनों में या फिर चार महीनों में मूल्यों में कमी आएगी। आपने जितना आश्वासन दिया मूल्य उतने ही बढ़ते गये। इसीलिए शायद दण्डवते जी ने इस सभा को कोई आश्वासन नहीं दिया।

दूसरी बात जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि वह यह कि वह एक उदाहरण उद्धृत कर रहे थे और मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा था और मैंने भी नोट किया है कि आपके वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा वार्षिक बजट की पूरी पुनरीक्षा, और उस समय का अनुमानित घाटा जो भी हो, के बारे में पहली तिमाही में ही अनुमान लगा लिया जाएगा।

मैं यह समझना और जानना चाहता हूं कि यदि यह सत्य है तो पहली तिमाही में ही यह घाटा अत्यधिक हो गया और बाद में यह कम किया जाएगा ताकि वार्षिक घाटा बजट अनुमान तक सीमित रहे। यही मैंने समझा है। यदि यह सही है तो आपकी अन्य बातों, जिनका उल्लेख किया जा रहा है, तथा जिन्हें बजट घाटे में अतर्निहित किया जाता है, अन्य बातों का क्या ध्यान रखा जाएगा ? ऐसा कैसे है फिर तो बजट-दर-बजट अनुमानित घाटा और अधिक होगा ? यदि यह सच था तो अनुपूरक बजट क्यों प्रस्तुत किया गया और आपने तत्पश्चात् उसकी आलोचना क्यों की ? इस प्रकार कुछ गलती हुई है। इतना विश्वास मत कीजिए कि आप बजट घाटे को पूरा कर देंगे जैसा कि आपने कहा है। क्योंकि यह सभी आर्थिक नियमों के विरुद्ध है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आपने हमारी उपलब्धि का विश्लेषण करते हुए कहा था तथा वित्त मन्त्री महोदय ने इसे दोहराया कि उन्हें यह घाटा विरासत में मिला है और बार-बार यही दोहराया जा रहा है कि उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा गया इसलिए वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदारी लेने और यह कहने के बजाय कि हमने गलती की थी आपने बजट भाषण के दौरान बिल्कुल सही कहा था और मैं सुन रहा था जब आपने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि यद्यपि हम पेट्रोल, डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं परन्तु इसका प्रभाव— उन्होंने सदन तथा प्रत्येक व्यक्ति से कहा था—उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर नगण्य पड़ेगा हालांकि वे यह जानते थे कि आंकड़े सच नहीं होते और संभावनाओं के विपरीत बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

मुझे एक बुद्धिमान गणितज्ञ की प्रतिशत के बारे में कहानी याद है जो एक नदी पार करने गया। उसने नदी की औसत गहराई का हिसाब लगाया और पाया कि यह चार फीट गहरी है। वह स्वयं श्री दण्डवते जी की तरह पांच फुट छह इन्च लम्बा था। उसने सोचा कि औसत और प्रतिशत के नियमों के आधार पर वह आसानी से नदी पार कर सकता है। वास्तव में क्या हुआ ?

वह नदी पार करने लगा और डूब गया। यही आपके साथ भी हुआ है। यही इस सरकार के साथ भी हुआ है। बैसाखियों के बावजूद यह मूल्यों की नदी के बीच डूब गयी है।

जहां तक घाटे की प्रवृति का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि आपको औसत निकालना होता है—पांच वर्ष का समय लेते हैं या जब आप दस वर्ष का औसत निकालते हैं। 1980-81 से 1988-89 तक आप विगत वर्षों में इस प्रवृत्ति को देखेंगे। वर्ष 1980-81 में बाजार मूल्य तथा बजट घाटे के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद 1.9 प्रतिशत था क्योंकि इसे प्रतिशत के रूप में लिया गया है। तत्पश्चात् वर्ष 1985-86 में यह 1.9 प्रतिशत था। 1986-87 में यह बढ़ कर 2.8 प्रतिशत हो गया, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं क्योंकि माननीय प्रधान मन्त्री उस समय वित्त मंत्री थे। उसके बाद जब वह वित्त मंत्री के पद से हट गये तो 1987-88 में यह घट कर 1.7 प्रतिशत हो गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह वह समय था जब विपक्ष के नेता विभिन्न राज्यों को हजारों करोड़ रुपये देने का वायदा कर रहे थे।

7.00 म० प०

श्री वसंत साठे : पिछली बातों का बहाना बनाना बहुत गलत बात है। कल यदि वह भी प्रधान मन्त्री नहीं रहते हैं तो वह ऐसा ही बहाना दूसरों से बनाएंगे। इसलिए यह उचित नहीं है। **(व्यवधान)** इसलिए इस तरह के तर्क देना कि पिछले वर्ष में ऐसा हुआ था और हमें विरासत में यह मिला है ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या उन्होंने पहले कहा था कि विगत वर्ष का बजट, जो उन्हें मिला था या जो घाटा हुआ था वह उन्हें विरासत में मिला था? क्योंकि यह वही सरकार है; अगले वित्त मंत्री को यह कहना चाहिए कि यह 2.8 हमें विरासत में मिला है? इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह यही है। जब आप पूरे राष्ट्र और इसके बजट की बात करते हैं और जब आप इस संदर्भ में बात करते···**(व्यवधान)** यह दूरी का प्रश्न नहीं है। आपको यह दायित्व अपने ऊपर लेना ही होगा। आपमें यह विश्वास होना चाहिए कि आप इसे संभाल सकते हैं। और आपको आर्थिक उपाय करने होंगे, जैसा कि आपने देश को बताया, आपने सदन को भी यही बताया है कि आप इसे संभाल सकते हैं। दुर्भाग्यवश पूरी तरह असफल होने के बाद आप यह तर्क देना चाहते हैं और जैसा कि कहा भी जाता है कि "हारने के बावजूद भी तर्क तो दिया ही जा सकता है।"

[हिन्दी]

यह तो यही हुआ "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की" ये जितना कहते हैं कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, वह मर्ज बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है। मेहरबानी करके अब आपकी यह जो दवा है, इसे बंद कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : आप डाक्टर बदल दीजिए।

श्री वसंत साठे : आपको डाक्टर बदलना है। **(व्यवधान)** श्री मधु दण्डवते सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे और मैं अपने पक्ष की ओर से बोल रहा था। हम चर्चा को एक बुद्धिजीवी स्तर पर बनाए हुए थे। परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब मैं और मेरा नेता बोल रहे थे तो सरकार के कुछ सहयोगी दल वस्तुतः बहुत अधिक व्यवधान डाल रहे थे। उन्हें किस बात की परेशानी हो रही थी? **(व्यवधान)** उन्हें क्या फिक्र थी **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हम लोग बाण्डेड लेबर नहीं हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मैं इस 'बंधुआ मजदूर' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। (व्यवधान) आप एक सुन्दर महिला की बात कर रहे हैं। परन्तु मुझे दोनों तरफ से इसका विरोध दिखाई देता है। उन्होंने 'पत्नी' अथवा 'सुन्दर महिला' कहे जाने पर एतराज किया है। (व्यवधान) श्री मधु दण्डवते बचाव करने का प्रयास कर रहे थे और यह अनुरोध कर रहे थे, कि 'कृपया उनसे कुछ मत कहिए'। (व्यवधान) आपका उनसे क्या सम्बन्ध है ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पुन: कहता हूं कि मेरे घर में समस्याएं पैदा मत कीजिए (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : किसी ने कहा है, 'जब भी कोई बात कही जाती है तो माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी तुरन्त खड़े होने वाले पहले व्यक्ति होते हैं तथा नाराज व्यक्ति की भांति सरकार का बचाव करते हैं।' (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : वह नए ताऊ हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : किसी ने कहा है कि वह नये ताऊ हैं। (व्यवधान)

परन्तु एक ताऊ का क्या हुआ ? (व्यवधान) जिस तरह से वे सरकार को खुश करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसे देखते हुए किसी ने कानाफूसी की है कि 'ताऊ' नहीं बल्कि**···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने हमेशा यही भूमिका निभायी है···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने कहा है कि किसी ने कानाफूसी की थी। मैंने उसे सुना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : चर्चा का यह स्तर है। यह बुद्धिजीवी स्तर है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उस स्तर तक मत जाइए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : शब्द वापस लिया जाता है। मैं इसे 'ताऊ' तक ही सीमित रखता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके कुछ सिद्धांत हैं, किसी व्यक्ति के प्रति अपनी तथाकथित निष्ठा का उल्लंघन मत कीजिए। (व्यवधान) उनका कोई अन्तर्विवेक नहीं है। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री वसंत साठे ने शब्द वापस ले लिया है। हमें 'ताऊ' पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अपने आपसे क्यों नहीं पूछते ? उन्हें प्रत्येक व्यक्ति ने छोड़ दिया है। (व्यवधान) वे हमारी सहायता चाहते हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप बोफोर्स के ताऊ हैं ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मक्कासर, कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आपने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया है । मैंने आपसे भी कुछ नहीं कहा था । मैं अनुरोध करता हूं कि सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मामले को जटिल मत बनाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मक्कासर, आपको बैठना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आप पहले मेरी बात सुनिए और मैं अपनी बात कहने के बाद आपको बोलने का चांस भी दे दूंगा । वह शब्द इस्तेमाल करने के बाद मैंने इम्मीजेटली कहा है कि वह पार्ट आफ दी रिकार्ड नहीं होगा । दूसरी बात यह है कि श्री साठे ने कहा है कि अपने शब्द वह वापिस ले रहे हैं । अब आप इसको लम्बा मत खींचिए···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मुझे ऐसा अनेक सदस्यों के विरुद्ध करना पड़ेगा । कृपया आप बैठ जाइए । चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो चाहिए था वह हो गया है । अगर इस प्रकार से किसी पर ऐक्शन लेना है तो बहुत से मैंबरों पर ऐक्शन लेना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मैं फिर कहता हूं कि मैं वह शब्द वापस लेता हूं परन्तु मैं 'नये ताऊ' शब्द पर कायम रहूंगा । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वे 'ताऊ' की सहायता चाहते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने 'पत्नी' और 'सुन्दर महिला' की बात की है । आप दोनों गुणों को एक में ही समाविष्ट क्यों नहीं कर देते ?

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं । अब मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अर्द्धनारी नटेश्वर, क्या होगा मालूम नहीं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि का यह प्रश्न आर्थिक ढांचे और उसमें सुधार करने के व्यापक प्रश्न से जुड़ा हुआ है । जब तक सरकार पार्टियों का ध्यान किए बगैर हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार करने तथा इसे विकासोन्मुखी बनाने की समझदारी और साहस नहीं दिखाएगी तब तक हम वस्तुओं के उत्पादन की समस्या हल नहीं कर सकते । मुख्य रूप से मुद्रा स्फीति क्या है ? यह प्रचलन में मुद्रा के अनुपात में वस्तुओं की कमी है, इसलिए हमें अन्ततः उस आर्थिक ढांचे के संदर्भ में सोचना होगा जिससे इस देश में विशिष्ट वर्ग की उपभोक्ता वस्तुओं की नहीं बल्कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि यह सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने तथा विद्यमान ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए साहसिक कदम उठाएगी । वास्तव में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या देश इन मूल्यों और मूल्य वृद्धि से संतुष्ट है अथवा नहीं । यह स्थगन प्रस्ताव व्यक्तिगत न होकर वर्तमान सरकार की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध अपना विरोध करने तथा निंदा करने के लिए है । उन नीतियों के परिणामस्वरूप ही देश में इतनी अधिक मूल्य वृद्धि हुई है । जनता को जानना चाहिए तथा जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारा तथा हर उस व्यक्ति का जो ईमानदारी से यह महसूस करता है कि यह मूल्य वृद्धि

अनुचित है, का यह कर्तव्य है कि वह इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करे तथा इसके पक्ष में मतदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब यह मतदान हेतु रखता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : वित्त मन्त्री जी ने हस्तक्षेप किया था तथा प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने अभी-अभी अपना उत्तर पूरा किया है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि मूल्य वृद्धि को रोका जाना चाहिए। मैंने उनसे अर्ज किया था कि इस प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए वह जोर न डालें।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता है। प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 1 **समय 7.24 म० म०**

पक्ष में

अन्बारासु, श्री इरा

अम्बरी, श्री लेइता

अरुणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

कामसन, प्रो० मिजिनलंग

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कोंतल, श्री राम कृष्ण

कोडिकुन्नील, श्री सुरेश

कौल, श्रीमती शीला

गजपति, श्री गोपी नाथ

गांधी, श्री राजीव

गाडगिल, श्री वी० एन०

गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब

गावीत, श्री माणिकराव होडल्य

गुप्त, श्री जनकराज

गोमांगो, श्री गिरिधर

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०

चार्ल्स, श्री ए०

चिदम्बरम्, श्री पी०

चेन्नीथाला, श्री रमेश

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चौधरी, श्री कमल

जग पाल सिंह, श्री

जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०

जमुना, श्रीमती जे०

जयमोहन, श्री ए०

जामोद, श्री शशिभाई

जीवरत्नम, श्री आर०

डामोर, श्री सोमजीभाई

तम्बि दुरै, डा०

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

दिनेश सिंह, श्री

देब, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

नन्दी, श्री येल्लैया

नेताम, श्री अरविन्द

पांजा, श्री अजीत

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव

पाटिल, श्री शंकरराव

पुजारी, श्री जनार्दन

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम

पुक्मान, डा० पी० वल्लल

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

बंसी लाल, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बशीर, श्री टी०

बागा रेड्डी, श्री एम०

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बासवराज, श्री जी० एस०

बेंजामिन, श्री एस०

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री एच० के० एल०

भजन लाल, श्री

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

मुथिया, श्री आर०

मुरलीधरण, श्री के०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

याजदानी, डा० गुलाम

यादव, श्री राम कृष्ण

रंगा, प्रो० एन० जी०

राकेश, श्री आर० एन०

राजू, श्रीमती उमा गजपति

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

राठौड़, श्री उत्तम

राम प्रकाश, चौ०

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामदास, डा० आर०

राव, श्री के० एस०

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री श्रीनिवास

रावत, श्री हरीश

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर

रेड्डी, श्री बोजा वेंकट

रेड्डी, श्री राजमोहन

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विश्वनाथम, डा०

वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री धर्म पाल

शिगडा, श्री डी० बी०

षण्मुख, श्री पी०

समद, श्री अब्दुल

साठे, श्री वसंत

सिमरायडीवेल, श्री एस०

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह, श्री आनन्द

सिंह, प्रो० एन० तोम्बी

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सुंदरराज, श्री एन०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुम्बरुई, श्री बागुन

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेमा, श्री शिकिहो

सेलवम, श्री कांशी पन्नीर

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हान्डू, श्री प्यारे लाल

विपक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अमात, श्री डी०

अर्गल, श्री छबिराम

अहमद, श्री अनवार

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कमान्डर, श्री मोहम्मद हसन

कापसे, प्रो० राम गणेश

कावडे, डा० वेंकटेश

कालका दास, श्री

कालवी, श्री कल्याण सिंह

कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह

केशरी लाल, श्री

कोटड़िया, श्री मनुभाई

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल

खां, श्री सुखेन्दु

खां, हाजी जी० एम०

खान, श्री आरिफ मोहम्मद

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गांधी, श्रीमती मेनका

गिरि, श्री सुधीर

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार

गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कांति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई

चौधरी, श्री ईश्वर

चौधरी, श्री बसई

चौधरी, श्री राम प्रसाद

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री प्रभात सिंह

जटिया, श्री सत्यनारायण

जसवन्त सिंह, श्री

जांगड़े, श्री रेशम लाल

जायनल अबेदिन, श्री

जोरावर राम, श्री

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

टंडेल, श्री डी० जे०

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डोम, डा० राम चन्द्र

ढाकणे, श्री बबनराव

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास

तारीफ सिंह, श्री

तिवारी, श्री बृज भूषण

तीरकी, श्री पीयूष

तोपदार, श्री तरित बरण

त्यागी, श्री के० सी०

थापा, श्री नन्दू

दंडवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री भक्त चरण

दीक्षित, श्री नरसिंहराव

देशमुख, श्री चन्दूभाई

धूमाल, श्री प्रो० प्रेम कुमार

नाईक, श्री राम

नीतीश कुमार, श्री

नेमी, श्री सी० एम०

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० ए० के०

पटेल, श्री अर्जुन भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री राम पूजन

पटेल, श्री सोमाभाई

परास्ते, श्री दलपत सिंह

पांडे, श्री राजमंगल

पाटिल, श्री बासवराज

पाणि, श्री रवि नारायण

पाण्डेय, प्रो० यादुनाथ

पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

प्रेम प्रदीप, श्री

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फर्नान्डीज, श्री जॉस

बंगाली सिंह, डा०

बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव

बाला, डा० असीम

बीरेन्द्र सिंह, राव

बेग, श्री आरिफ

बेहेरा, श्री भजमन

बैठा, श्री महेन्द्र

ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भागेय गोबर्धन, श्री

भाटिया, श्री राम सेवक

भारतीय, श्री सन्तोष

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मक्कासर, श्री शोपत सिंह

मणवर, श्री बलवन्त

मन्टोष, श्री पाल आर०

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मलिक, श्री सत्यपाल

मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाता, श्री चित्त

महाले, श्री हरि शंकर

महेश्वर सिंह, श्री

मायकर, श्री गोपालराव

मिश्र, श्री जनेश्वर

मिश्र, श्री बालगोपाल

मिश्र, श्री राज मंगल

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, श्री नन्दलाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मेघवाल, श्री कैलाश

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राजवीर सिंह, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रावत, प्रो० रासा सिंह

लोढा, श्री गुमान मल

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री शिव शरण

वेकारिया, श्री एस० एन०

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शाक्य, श्री राम सिंह

शास्त्री, श्री कपिल देव

शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद

सरताज सिंह, श्री

सरवर हुसैन, श्री

सरोज, श्री सरजू प्रसाद

सहाय, श्री सुबोध कांत

साय -श्री ए० लरंग

सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे

सिंह, श्री अजय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री ललित विजय

सिंह, श्री जगन्नाथ

सिंह, श्री तेज नारायण

सिंह, श्री धनराज

सिंह, श्री के० मानवेन्द्र

सिंह, श्री मानधाता

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री राम बहादुर

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सुखेन्द्र

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हर गोविन्द

सुमन, श्री रामजी लाल

सुर, श्री मनोरंजन

सूबेदार, श्री

सोमकर, श्री कल्पनाथ

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हीरा भाई, श्री

हीटा, श्री भवानी शंकर

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 117

विपक्ष में : 202

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, वक्तव्य का हिन्दी रूपान्तर पटल पर नहीं रखा गया है ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री पी० सी० थॉमस, श्री गोविन्दराव निकाम, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल, श्री पलाई के० एम० मैथ्यू, श्री, सी० पी० मुदाल गिरियप्पा, श्री राजा अम्बान्ना नायक डोरे, डा० बासवराज जावाली, श्री पीटर जी० मरबनिआंग, श्री मानकूराम सोढ़ी, श्री ए० एस० गौडर, श्री पी० नरसा रेड्डी, श्री एम० जे अकबर

विपक्ष में : श्री अजित सिंह, श्री श्रीकांत जेना, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री युसुफ बेग, श्री जमनाभाई रायचा, श्री मंगाराज मलिक, श्री सैयद मसूदल हुसैन, श्री डी० डी० खनोरिया, डा० विप्लव दासगुप्त, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह तथा श्री कंकर मुंजारे ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

7.27 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस महान सदन में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय देने के संबंध में मेरी सरकार द्वारा लिए गए अति महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

2. माननीय सदस्यों को विदित है कि जो संविधान हमने आज से 40 वर्ष पूर्व अंगीकार किया था, उसमें यह परिकल्पना की गयी है कि "अनुच्छेद 340 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जाएगी, उनकी कठिनाइयां दूर की जायेंगी तथा उनकी दशा को बेहतर बनाया जाएगा।" यह अपेक्षा आज तक पूरी नहीं की जा सकी जो कि हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे के विपरीत है।

3. द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति स्वर्गीय श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में तारीख 1 जनवरी, 1979 को की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 31-12-80 को प्रस्तुत की। जनता से किए गए अपने वायदे के अनुसार हमने इसे अपनी कार्य योजना में शामिल किया है। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि मेरी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार करने के संबंध में अनेक राज्यों के दीर्घ अनुभव का लाभ उठाने तथा सामंजस्यपूर्ण और त्वरित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में उन सभी जातियों को लिया जाए, जो मंडल आयोग की सूची और राज्यों की सूचियों में समान हैं।

(ख) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27 प्रतिशत होगा।

(ग) यह आरक्षण भारत सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन सेवाओं पर लागू होगा।

माननीय सदस्यों को यह विदित है कि 14-4-90 को भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर के जन्म दिवस को मनाने के लिए अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित शासकीय समारोह में मैंने अम्बेडकर शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने की घोषणा की थी और इसे "सामाजिक न्याय वर्ष" नाम दिया था। हमने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के अनेक उपाय किए हैं यथा नव-बौद्धों के प्रति किए गए अन्याय का निराकरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त अधिकार देते हुए उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, डा० अम्बेडकर को समुचित सम्मान देना, जो उन्हें बहुत पहले प्रदान किया जाना था, इत्यादि इत्यादि। वर्तमान निर्णय इसी कड़ी में आते हैं और अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितों के प्रति इस सरकार की समर्पण भावना की परम्परा के अनुरूप है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में कोई नारेबाजी नहीं होगी।

(व्यवधान)

बनातवाला जी, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम सरकार से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि मन्त्री जी के वक्तव्य पर हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।

अब विधेयक पुरःस्थापित किए जायेंगे। श्री श्रीधरण।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, अब सभा की बैठक स्थगित की जाए।

7.29 म० प०

रबड़ (संशोधन) विधेयक*

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरण) : श्री अरुण कुमार नेहरू की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, इसके पश्चात् सभा की बैठक स्थगित कर दी जानी चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह बताया गया था कि मण्डल आयोग के बारे में घोषणा करने के पश्चात् सभा की बैठक स्थगित कर दी जाएगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं?

श्री पी० एस० थामस (मुवत्तुपुजा) : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे कल कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। आप कल भी अपनी बात कह सकते हैं। मैं श्री पी० उपेन्द्र अथवा डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय, जिन्हें

---

*दिनांक 7-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड में प्रकाशित।

कार्य मन्त्रणा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है उनके अलावा किसी अन्य माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

7.30-1/2 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

7.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 अगस्त, 1990/17 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्री राम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53